राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 184

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 12 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

डोप प्रतिबंध के बाद लौटे पृथ्वी शॉ ने जड़ा दोहरा शतक

>> 14

राज्यसभा की अग्निपरीक्षा में भी पास नागरिकता विधेयक

ऐतिहासिक दिन ▶ उच्च सदन में मैराथन बहस के बाद 105 के मुकाबले 125 मतों से पारित हुआ बिल, विधेयक पर विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव खारिज

गृह मंत्री शाह ने विपक्ष के सवालों की उड़ाईं धज्जियां

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा में जबरदस्त सियासी गहमागहमी के बीच चर्चित नागरिकता संशोधन विधेयक 125 के मुकाबले 105 मतों से पारित हो गया। इसी के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम छह समुदायों को भारत की नागरिकता देने का कानूनी रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विधेयक पर हुई मैराथन चर्चा का जवाब देते हुए विपक्षी दलों पर नागरिकता बिल के नाम पर देश के मुसलमानों में भय और संशय पैदा करने का आरोप लगाया। उनका साफ कहना था कि यह विधेयक भारत के किसी मुसलमान की नागरिकता छीनने नहीं बल्कि इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से जुड़ा है। गृह मंत्री ने यह भी दोहराया कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होता तो इस विधेयक को लाने की जरूरत ही नहीं होती।

राज्यसभा में करीब सात घंटे की चर्चा के बाद विपक्ष के दर्जनों संशोधनों और विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को बहुमत से खारिज कर दिया गया। राज्यसभा में विधेयक पर मतदान के दौरान शिवसेना ने सदन से बाहर रहकर इसमें हिस्सा नहीं लिया। सदन के कुल 240 में से 10 सदस्य अलग-अलग वजहों से अनुपस्थित रहे। सरकार और विपक्ष के बीच बिल को लेकर सदन में जमकर सियासी संग्राम हुआ। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रवर समिति में भेजने और अपने संशोधनों के लिए विपक्ष ने पांच बार सदन में मत विभाजन करा सरकार को वोटिंग के लिए बाध्य किया।

दिखा सियासी कौशल : विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने संयम, आक्रामकता और सियासी कौशल का जबरदस्त मेल करते हुए विपक्षी दलों के सभी सवालों का जवाब दिया। विधेयक को मुस्लिम विरोधी बताने पर उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री के नाते वह सभी मुस्लिम भाई-बहनों से कह रहे हैं कि वे इस देश के सम्मानित नागरिक हैं और उनकी नागरिकता का इस बिल से कोई लेना-देना नहीं।

गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार तथ्यों के साथ कांग्रेस को आईना दिखाया। उन्होंने सदन को बताया कि किस तरह 1947 की कांग्रेस कार्यसमिति में पाकिस्तान में प्रताड़ित सिखों और हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी तरह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मांग पर 13 हजार सिखों और हिंदुओं को नागरिकता दी गई थी। शाह ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 2003 में बांग्लादेश से उत्पीड़न के शिकार होकर आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की संसद में बात कही थी। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देने के क्रम में कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव को जब मोदी सरकार लागू कर रही है तो फिर कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है?

नागरिकता बिल (विशेष) पेज>>5
गुमराह राजनीति (संपादकीय) पेज>>8

भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। खुशी है कि यह बिल राज्यसभा से पारित हो गया। मैं इसके पक्ष में मतदान करने वाले सभी सांसदों का आभारी हूं। यह बिल वर्षों से प्रताड़ना झेल रहे लोगों का दुख दूर करेगा। – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

आज भारत के संवैधानिक इतिहास में काला दिन है। नागरिकता संशोधन विधेयक का पारित होना तुच्छ सोच वाली और कट्टर ताकतों की भारत के बहुलवाद पर जीत है। – सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष

राज्यसभा में बुधवार को नागरिकता बिल पर सवालों का जवाब देते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

शाह बोले, कानून और संविधान सम्मत है यह बिल

अमित शाह ने बिल को संविधान के अनुच्छेद 14 समेत तमाम प्रावधानों के खिलाफ बताने और सुप्रीम कोर्ट में इसके खारिज होने के विपक्षी दलों के तर्क को नकारा। कहा, बिल कानून व संविधान सम्मत है। श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को शामिल नहीं करने पर कहा, समस्या विशेष के हल के लिए यह बिल लाया गया है। ऐसा पहले बांग्लादेश व युगांडा से आए भारतीय मूल के लोगों के लिए हो चुका है। ऐसे में जब श्रीलंका का मसला आएगा तो सरकार उसका समाधान करेगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च सदन में यह भी कहा

- यह जल्दबाजी नहीं है। हम चाहते तो आपकी तरह सत्ता का सुख भोग सकते थे, लेकिन मोदी सरकार सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए आई है। चुनाव साढ़े चार साल बाद है, इसके बावजूद हम लगातार काम कर रहे हैं।
- 1947 में बंटवारे के बाद एक प्रार्थना सभा में खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान में रह गए हिंदू और सिख चाहें तो आ सकते हैं और भारत को उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
- आप मुझे आइडिया ऑफ इंडिया मत सिखाइए। हम सात पुश्तों से यहीं हैं। यहीं जन्मे हैं और यहीं मरेंगे। जिनको सिखाना है उनको जाकर आइडिया ऑफ इंडिया सिखाइए।
- आपके दिए जख्मों के कारण भय की वजह से लोग खुद को खुलकर शरणार्थी नहीं बताते थे। संशोधन पास होने के एक साल बाद देखिएगा, निर्भीक होकर करोड़ लोग सामने आएंगे। आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे।
- शिवसेना किस तरह से रंग बदलती है। रातों-रात क्या हुआ कि सुर बदल गए। कल लोकसभा में विधेयक का समर्थन किया और अब रुख अलग है।
- आपने विवेकानंद के शिकागो सम्मेलन में प्रताड़ित यहूदी व पारसी शरणार्थियों को शरण देने का जिक्र करने की बात कही। यहूदी और पारसी की तरह पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण दे रहे हैं। फिर विरोध क्यों है।
- सावरकर के एक भाषण से देश का बंटवारा हुआ या नहीं, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सच्चाई यही है कि जिन्ना बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। सवाल यह है कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा स्वीकार क्यों किया।
- विपक्षी नेताओं को शरणार्थियों की चीख नहीं सुनाई देती। मोदी सरकार अंधी और बहरी नहीं है। इसीलिए हमें उनकी चीख सुनाई देती है।

पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं कांग्रेस के नेता

अमित शाह ने कहा कि यह संयोग है या कुछ और मगर सच्चाई यह है कि कांग्रेस के नेताओं की भाषा और पाकिस्तान की भाषा एक जैसी दिखती है। पाकिस्तान के पीएम का बयान और कांग्रेस के एक नेता का सदन में बयान बिल्कुल एक जैसा है। सर्जिकल स्ट्राइक और अनुच्छेद 370 के समय भी इन दोनों के बयान इसी तरह एक समान थे। गृह मंत्री के इस आरोप का कांग्रेस सदस्यों ने जोरदार विरोध करते हुए हंगामा भी किया। हालांकि इसके बावजूद गृह मंत्री ने कहा कि नेहरू-लियाकत समझौते का पड़ोसी देश पालन करता, तो इस विधेयक की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने आंकड़ों और तथ्यों के साथ यह बताया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों पर भयंकर अत्याचार हुए हैं और इन समुदायों को नागरिकता देना भारत का कर्तव्य है।

सरोकार

बस एक 'सुपर फूड' चॉकलेट खाओ, लंच भूल जाओ

पालमपुर : हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर ने रागी, ज्वार, बाजरा, मक्की, भूरे चावल, शहद, स्टीविया व गुड़ से चॉकलेट तैयार की है। इसे खाने के बाद चार घंटे तक भूख नहीं लगेगी। कीमत है 40 रुपये। यह चॉकलेट आपकी शुगर की मात्रा को नियंत्रित करेगी। (पेज-10)

जागरण विशेष

सूखा या बाढ़ में भी ले सकेंगे सब्जी की किफायती पैदावार

भागलपुर : सूखे और बाढ़ से जूझने वाले क्षेत्रों के कम जोत वाले किसान और पशुपालक कम लागत, कम पानी, बिना जमीन और मिट्टी के भी सब्जी चारा का उत्पादन कर सकें, इसके लिए बिहार कृषि विवि पॉली हाउस आधारित सस्ती और कारगर कृषि तकनीक सुलभ कराने पर काम कर रहा है। (पेज-10)

डाटा प्रोटेक्शन बिल संयुक्त संसदीय समिति के हवाले

नई दिल्ली : देश के नागरिकों के निजी डाटा के चोरी होने या गलत इस्तेमाल की विपक्ष की आशंकाओं के बीच डाटा प्रोटेक्शन बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। सरकार ने स्वयं ही इसे संयुक्त समिति को सौंप दिया। सूचना प्रौद्योगिकी व संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से लोस में प्रस्ताव पेश किया गया। (पेज-3)

विश्वास. News

दो हजार के नोट बंद होने की जानिए असलियत ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 10

असम-त्रिपुरा में कैब के विरोध में हिंसा-आगजनी

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में बुधवार को गुवाहाटी में हिंसक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रेट्र

गुवाहाटी, एजेंसियां : पूर्वोत्तर के राज्यों असम और त्रिपुरा में बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध तेज हो गया है। दोनों ही राज्यों में जमकर आगजनी और हिंसा हुई है। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों और रेलवे स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा और आगजनी के चलते सुरक्षा बलों को फायरिंग तक करनी पड़ी। लिहाजा असम के शहर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया और चार जिलों में सेना तैनात कर दी गई। त्रिपुरा में भी सेना के नियंत्रण वाले अर्धसैनिक बल असम राइफल्स को तैनात कर दिया गया है। राज्य में एक प्रदर्शनकारी के मारे जाने की बात भी कही जा रही है।

पूर्वोत्तर का सेना मुख्यालय पूरे हालात पर नजर रखे हुए है। हालांकि, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने दावा किया है कि ज्वाइंट मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ने अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन वापस ले लिया है। सेना के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल पी. खोंगसई ने बताया कि गुवाहाटी शहर में सेना की दो टुकड़ियां तैनात की गई हैं और वे शहर में फ्लैग मार्च कर रही हैं। तिनसुकिया, जोरहट और डिब्रूगढ़ जिलों में भी सेना तैनात की गई है।

इंटरनेट सेवा निलंबित : असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण ने बताया कि राज्य के 10 जिलों में बुधवार शाम से इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है ताकि प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं कर सकें। ये जिले हैं- लखीमपुर, धीमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चरायदेव, शिवसागर, जोरहट, गोलाघाट, कामरूप (मेट्रो) और कामरूप। जबकि पूरे त्रिपुरा में मंगलवार से ही 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा निलंबित है। त्रिपुरा सरकार ने एक आदेश जारी एसएमएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

- असम के गुवाहाटी व डिब्रूगढ़ में वेमियादी कर्फ्यू, चार जिलों में सेना तैनात
- पूरे त्रिपुरा में असम राइफल्स की तैनाती, एक के मरने की खबर

कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर प्रदर्शनकारी : बुधवार को हजारों कैब विरोधी प्रदर्शनकारी असम की सड़कों पर उतर आए और कई जगहों पर उनका पुलिस के साथ संघर्ष हुआ। असम के छात्र आंदोलन के बाद राज्य में पहली बार इस तरह के हालात बने हैं। गुवाहाटी में कर्फ्यू की अवहेलना करके प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमे हुए हैं और शहर की ज्यादातर सड़कों को उन्होंने ब्लॉक कर रखा है।

दो रेलवे स्टेशनों को लगाई आग पेज>>5

गुजरात दंगों के आरोपों से बरी हुए मोदी-शाह

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगा मामलों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अमित शाह को नानावटी आयोग ने क्लीन चिट दी है। आयोग ने कहा, दंगों की साजिश नहीं रची गई थी और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, जबकि गोधरा कांड को साजिश के तहत अंजाम दिया गया था।

गोधरा कांड और गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित पूर्व न्यायाधीश जीटी नानावटी और पूर्व न्यायाधीश अक्षय मेहता ने अपनी ढाई हजार पेज की रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा राज्य के तीन पूर्व मंत्रियों दिवंगत हरेन पंड्या, दिवंगत अशोक भट्ट और भरत बारोट को भी आरोप मुक्त कर दिया है। करीब 12 साल तक चली जांच के बाद आयोग ने 18 नवंबर, 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल को फाइनल रिपोर्ट सौंपी थी जिसे बुधवार को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार ने विधानसभा के पटल पर रखा।

- नानावटी-मेहता आयोग की रिपोर्ट राज्य विधानसभा में पेश
- कहा, दंगों की साजिश नहीं हुई थी और न ही इसमें सरकार की भूमिका थी

तीन आइपीएस अधिकारियों की भूमिका नकारात्मक : रिपोर्ट में तीन आइपीएस अधिकारियों आरबी श्रीकुमार, राहुल शर्मा और संजीव भट्ट की भूमिका को नकारात्मक बताया गया है। गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने बताया कि गोधरा कांड और उसके बाद भड़के दंगा मामलों की जांच के बाद आयोग ने साफ कर दिया है कि मोदी, उनके मंत्रिमंडल के किसी सदस्य, पुलिस और प्रशासन की दंगे में कोई संलिप्तता नहीं थी। मोदी पर दंगाइयों को खुली छूट देने के आरोप भी बेबुनियाद साबित हुए। आइपीएस संजीव भट्ट ने ऐसे दावे किए थे, लेकिन उसके पक्ष में दिया गया फैक्स भी फर्जी निकला।

आयोग की नसीहत, उकसावे में न आएं गरीब और अनपढ़ पेज>>3

44,445 शपथ पत्रों के आधार पर नौ खंडों में 2,500 पेज की रिपोर्ट।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- दंगों के बाद कांग्रेस, कई एनजीओ और विदेशी संस्थाओं ने मोदी की छवि बिगाड़ने का प्रयास किया। इनमें तीस्ता सीतलवाड़ का नाम प्रमुख है
- दंगों की जांच खुफिया ब्यूरो (आइबी) के पूर्व निदेशक आरके राघवन की अध्यक्षता में बनी एसआइटी ने की
- हाई कोर्ट ने 2017 में 11 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी थी।
- पूर्व कांग्रेस सांसद अहसान जाफरी की मदद के लिए भेजा गया था पुलिस बल
- दंगाइयों को खुली छूट देने के सीएम के निर्देश की बात कोरी अफवाह
- आयोग ने 25 सितंबर, 2009 को सौंपी थी गोधरा कांड पर पहली रिपोर्ट

अयोध्या पर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा विचार

नई दिल्ली : अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को विचार करेगा। कोर्ट तय करेगा कि याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की जरूरत है कि नहीं। कुल 18 याचिकाएं गुरुवार की सूची में सुनवाई के लिए लगी हैं। इस बीच बुधवार को निर्मोही अखाड़ा ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कोर्ट से कुछ पहलुओं पर फैसले को स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। (पेज-7)

रक्षा उपग्रह की लांचिंग के साथ पीएसएलवी का अर्धशतक

श्रीहरिकोटा : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार को दोहरी उपलब्धि हासिल की। इसरो के सबसे कामकाजी कहे जाने वाले रॉकेट पोलर सेटेलाइट लांच व्हीकल (पीएसएलवी) ने एक महत्वपूर्ण रक्ष उपग्रह की लांचिंग के साथ अपनी 50वीं उड़ान पूरी कर ली है। इस दौरान पीएसएलवी ने नौ विदेशी सेटेलाइट को भी कक्षा में स्थापित किया। (पेज-16)

विमान सुरक्षा खतरे में डालने पर एक करोड़ जुर्माना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार ने एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें विमान में हथियार, गोला बारूद या खतरनाक वस्तुएं ले जाने अथवा विमान की सुरक्षा को किसी भी प्रकार से खतरे में डालने के दोषी व्यक्तियों पर सजा के अलावा दस लाख के मौजूदा जुर्माने को बढ़ाकर एक करोड़ करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विधेयक को एयरक्राफ्ट (संशोधन) विधेयक 2019 के नाम से संसद में पेश किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये मंजूरी दी गई। एयरक्राफ्ट संशोधन बिल में एयर नेविगेशन के सभी क्षेत्रों के नियम-कायदों को एक्ट के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है। संशोधन से इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन आइसीएओ की सुरक्षा संबंधी शर्तें भी पूरी होंगी। इससे भारत के तीनों विमानन नियामकों-उड्डयन महानिदेशालय, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तथा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंवेस्टीगेशन ब्यूरो को अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट के फैसले

- दिल्ली मेट्रो के फेज-4 में केंद्र सरकार का योगदान बढ़ेगा

कैबिनेट ने केंद्र व दिल्ली सरकार को दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के वित्तपोषण के तौर-तरीकों में बदलाव की भी अनुमति दे दी है। इसके तहत केंद्र और दिल्ली सरकार फेज-4 के तीन कॉरिडोर के निर्माण के लिए आवश्यक जमीन की लागत में भी 50:50 फीसद हिस्सेदारी निभाएंगी। इन कॉरिडोर में एरोसिटी-तुगलकाबाद, आरके आश्रम-जनकपुरी (पश्चिम) तथा मुकुंदपुर-मौजपुर के कॉरिडोर शामिल हैं।

ये कदम मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 में संशोधन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत केवल दिल्ली के लिए उठाया है। इसके परिणामस्वरूप 24,948.65 करोड़ की कुल लागत वाले चौथे चरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन केंद्र का योगदान 4,154.20 से बढ़कर 4,643.63 करोड़ हो जाएगा।

कैबिनेट ने एनएचएआइ को इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट के गठन की अनुमति भी दे दी है। इससे एनएचएआइ को पूरी हो चुकी सड़क परियोजनाओं के मौद्रीकरण में सुविधा होगी जो कम से कम एक साल से टोल संग्रह कर रही हों। कैबिनेट ने ब्राजील के साथ सामाजिक सुरक्षा के समझौते को भी मंजूरी दी है। इससे दोनों देशों में काम कर रहे कर्मियों को दोहरे कराधान व आव्रजन से छूट दी जाएगी। साथ ही इस्पात (स्टील) के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुए समझौते तथा चिकित्सा उत्पादों के नियमन को लेकर सऊदी अरब से हुए समझौते को भी हरी झंडी दे दी है।

माता-पिता का ध्यान नहीं रखा तो अब काटनी होगी जेल

नई दिल्ली : लोकसभा में बुधवार को 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक-2019' पेश किया गया। इसमें माता-पिता या अपने संरक्षण वाले वरिष्ठ नागरिकों के साथ जानबूझकर दुर्व्यवहार करने या उन्हें उनके हाल पर अकेला छोड़ देने वालों के लिए छह महीने के कारावास या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। (पेज-3)

पहले इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने कनाडा में भरी उड़ान

वैंकूवर : दुनिया के पहले पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने मंगलवार को कनाडा के वैंकूवर शहर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। विमान में छह यात्री सवार थे। लगभग 15 मिनट से कम समय तक यह विमान हवा में रहा। 62 साल पुराने डीएचसी-2 दि हावीलैंड बीवर विमान में 750 हॉर्सपॉवर की इलेक्ट्रिक मोटर लगाकर इसका परीक्षण किया गया। (पेज-16)

वीआइपी सिंड्रोम

दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक जाम से निपटने को संसदीय समिति का सुझाव, पार्किंग स्पेस व पुरानी गाड़ी को डिस्पोज किए बिना वाहन पंजीयन न करने का सुझाव

माननीयों को लुटियन जोन में भी चाहिए अपने लिए अलग लेन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भले ही देश की राजधानी दिल्ली में अभी तक लेन ड्राइविंग सुनिश्चित न हो पाई हो, लेकिन माननीय लुटियन जोन में भी अपने लिए अलग लेन चाहते हैं। संसदीय समिति का मानना है कि दिल्ली को जाम से निजात दिलाने के लिए गणमान्य लोगों (वीआइपी) के लिए अलग लेन होनी चाहिए। संसदीय समिति के मार्फत ये सुझाव दिया गया है। यही नहीं, उन्होंने दुपहिया वाहन चालकों के लिए भी अलग लेन की सिफारिश की है। उन्होंने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई कि दो या तीन लेन की सड़कों पर दो लेन आरक्षित होने पर बाकी चालकों के लिए कितनी जगह बचेगी।

समिति की चिंता इस बात पर है कि वीआइपी के लिए लुटियन जोन तो बना दिया गया है, परंतु उनके सुरक्षित आवागमन के लिए अलग लेन का प्रावधान नहीं किया गया। इसलिए गृह मंत्रालय को इमरजेंसी वाहनों की तरह वीआइपी वाहनों के लिए अलग लेन पर विचार करना चाहिए।

कांग्रेस के आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मंत्रालय की इस समिति में 31 संसद सदस्य हैं। समिति ने बुधवार को संसद के दोनो सदनों में अपनी रिपोर्ट पेश की है। समिति ने दिल्ली में वाहनों की बढ़ती संख्या पर चिंता प्रकट करते हुए इस पर अंकुश लगाने के लिए क्रांतिकारी कदमों का सुझाव दिया है। इनमें वीआइपी और दुपहिया वाहनों के लिए अलग लेन के अलावा बिना पार्किंग स्पेस वाले घरों के लोगों, बिना पुराने वाहन को डिस्पोज किए बगैर नया वाहन खरीदने वालों के वाहनों का पंजीकरण न करने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से अधिक इंश्योरेंस प्रीमियम वसूलने जैसे सुझाव शामिल हैं।

एनसीआर से पुराने पेट्रोल-डीजल वाहन हटाने की सिफारिश पेज>>3

दिल्ली-एनसीआर में यातायात समस्या के विविध पहलू

संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में यातायात जाम के कई अन्य पहलू और कारण उजागर किए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

यातायात घनत्व वाले 7 स्थान : कनाट प्लेस, लाजपत नगर, नेहरू प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस, करोल बाग, कमला नगर मार्केट और कृष्णा नगर

ऑड-इवेन पर सवाल : दिल्ली में दो बार लागू की जा चुकी ऑड-ईवेन स्कीम की सफलता पर सवाल उठाते हुए समिति ने इसके प्रभाव का शीघ्रातिशीघ्र अध्ययन कराने को कहा है।

दिव्यांगों को असुविधा : समिति ने सड़क, फुटपाथ, बस स्टॉप और बसों आदि में उपयुक्त इंतजाम न होने से दिव्यांगों को आवागमन में होने वाली असुविधा का उल्लेख किया।

मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन : दिल्ली में वाहन स्वामियों के मोबाइल नंबरों का वेरीफिकेशन पूरा न होने पर चिंता प्रकट करते हुए समिति ने दिल्ली परिवहन विभाग से बाकी 28 लाख मोबाइल नंबरों का वेरीफिकेशन कराने को कहा है। अभी तक 78 लाख नंबर वेरीफाई हो चुके हैं।

डेडीकेटेड पार्किंग स्थल : समिति ने अदालतों, अस्पतालों, कमर्शियल कांप्लेक्सों आदि के निकट डेडीकेटेड पार्किंग स्पेस सृजित करने को कहा है।

बढ़ते वाहन, सिकुड़ती सड़कें : समिति के अनुसार दिल्ली में इस समय 112 लाख वाहन पंजीकृत हैं। जो देश के कुल वाहनों का 12.5 फीसद है। रोजाना 1700 वाहन और बढ़ जाते हैं। वर्ष 1901 में दिल्ली की जनसंख्या 4 लाख थी जो अब बढ़कर 192 लाख हो गई है। वर्ष 2025 तक इसके बढ़कर 225 लाख हो जाने की संभावना है। वाहन और जनसंख्या के मुताबिक सड़कों का विस्तार नहीं हुआ है।

आतंकी फंडिंग में हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान में आरोप तय

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के लाहौर स्थित आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने बुधवार को मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद और उसके तीन करीबियों हाफिज अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद, मुहम्मद अशरफ और जफर इकबाल के खिलाफ आतंकी फंडिंग के मामले में आरोप तय किए।

जस्टिस अरशद हुसैन भुट्टा ने अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग ने 17 जुलाई को सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में आतंक के वित्तपोषण को लेकर 23 एफआइआर दर्ज की थीं। इसके बाद सईद की गिरफ्तारी की गई थी। फिलहाल वह कोट लखपत जेल में बंद है। लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान शहरों में ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन के नाम पर आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए धन इकट्ठा किया गया। इसमें अल-अनफाल ट्रस्ट, दावातुल इरशाद ट्रस्ट और मुआज बिन जबल ट्रस्ट शामिल हैं।

हाफिज सईद(फाइल) प्रेट्र

पंजाब पुलिस ने आतंकी फंडिंग में 23 एफआइआर दर्ज की थीं

अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव में पाकिस्तान ने लश्कर, जेयूडी और उसकी चैरिटी शाखा फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के खिलाफ जांच शुरू की। इसमें सामने आया कि आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए धन जुटाने के लिए इन ट्रस्टों का इस्तेमाल किया गया है। सईद के नेतृत्व वाला जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा का सबसे प्रमुख संगठन है। यह आतंकी संगठन 2008 के मुंबई हमलों के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमे 166 लोगों की हत्या कर दी गई थी।

3.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया बुधवार को। न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से एक डिग्री कम है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान महज 11 डिग्री रह सकता है। दिन भर बादल छाए रहेंगे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 12 दिसंबर 2019

रेलवे ने नहीं दी ट्रेन, सीएम तीर्थ यात्रा स्थगित

अड़चन ▶ उपमुख्यमंत्री ने कहा– सरकार कर रही रेलवे से बात, वैकल्पिक उपायों पर भी किया जा रहा विचार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे से ट्रेन नहीं मिल पाने की वजह से दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। सरकार इसके लिए रेलवे से भी बात कर रही है और वैकल्पिक उपायों पर भी विचार कर रही है।

सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना रेलवे के साथ हुए दिल्ली सरकार के एक समझौते के तहत चल रही है। लेकिन रेलवे ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें तीर्थ यात्रा के लिए ट्रेन उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है।

सिसोदिया ने कहा कि यह यात्रा तब तक स्थगित रहेगी, जब तक रेलवे ट्रेन उपलब्ध नहीं कराता है या फिर दिल्ली सरकार कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो भी तकनीकी दिक्कत होगी, रेलवे उसका पता लगा कर फिर से इस यात्रा की शुरुआत करेगा। रेलवे के अधिकारियों से बात चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 12 रूटों पर 63,432 लोगों ने तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 32,828 लोग यात्रा कर चुके हैं। 30,877 यात्री प्रतीक्षा सूची में हैं।

सिसोदिया के मुताबिक इस योजना के तहत पहली ट्रेन 12 जुलाई को गई थी। तब से अब तक 34 ट्रेनें यात्रियों को लेकर तीर्थ यात्रा पर जा चुकी हैं और अभी 30 ट्रेनें अगले दो महीने में जाने वाली थीं। 18 इसी महीने जाने वाली थीं। इसमें से कुछ ट्रेन गई भी हैं जबकि बाकी की ट्रेनें रद करनी पड़ी है। 12 ट्रेन दिसंबर और 18 ट्रेन जनवरी में जानी थी।

सबसे अधिक रामेश्वरम जा रहे यात्री : उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने बताया कि सबसे ज्यादा आठ हजार यात्री रामेश्वरम यात्रा पर गए हैं। इस रूट के 12,963 यात्रियों की सूची अभी लंबित है। द्वारकाधीश दूसरा सबसे लोकप्रिय स्थान है। इसके बाद जगन्नाथपुरी, शिरडी, अजमेर व वैष्णो देवी की मांग है।

रेलवे ने ट्रेन उपलब्ध न कराने का नहीं बताया कारण : उपमुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे ने ट्रेन उपलब्ध नहीं कराने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। रेलवे ने लिखा है कि अभी ट्रेन उपलब्ध नहीं है। जैसे ही ट्रेन की व्यवस्था हो जाएगी, दिल्ली सरकार को सूचित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ रूटों पर बसें जा सकती हैं, लेकिन रामेश्वरम के रूट पर बस जाने में दिक्कत है।

सीएम ने कहा, बुजुर्ग निराश न हों : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। तीर्थ यात्रा से बुजुर्ग बहुत खुश हैं। जिनकी टिकट बन गई थी और अब ट्रेन रद हो गई, वो कितने दुखी होंगे। आप लोग निराश न हों। मैं केंद्र सरकार से बात करके हर हालत में इसको दोबारा शुरू करवाऊंगा। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए।

दिल्ली सचिवालय मे पत्रकार वार्ता को संबोधित करते उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (बाएं) और तीर्थ यात्रा समिति के अध्यक्ष कमल बंसल। जागरण

इन रूट पर लंवित ट्रेन और यात्रियों की संख्या

रूट	ट्रेन लंबित	यात्री
रामेश्वरम	12	12963
द्वारकाधीश	6	5376
तिरुपति	4	2890
जगन्नाथपुरी	4	2682
शिरडी	2	2135
उज्जैन	1	689
अजमेर	1	1414
वैष्णो देवी	--	1076
बोधगया	--	820
अमृतसर	--	832

तीर्थ यात्रा ट्रेन के लिए अभी रेक उपलब्ध नहीं : उत्तर रेलवे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उत्तर रेलवे का कहना है कि कोहरा, झारखंड विधानसभा उपचुनाव व सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जवानों के स्थान परिवर्तन की वजह से फिलहाल अतिरिक्त रेक उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के लिए वह विशेष ट्रेन चलाने में असमर्थ है।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार का कहना है कि कोहरे में रेल परिचालन बड़ी चुनौती होती है। उत्तर भारत में कोहरे का प्रकोप ज्यादा रहता है जिस कारण ट्रेनें लेट चलती हैं। इसे ध्यान में रखकर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त रेक की व्यवस्था करनी पड़ती है जिससे कि ट्रेनों को यथासंभव समय पर चलाया जा सके। इसके साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए देश के कई हिस्से से अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को झारखंड पहुंचाने के लिए भी रेक उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह से कर्नाटक में उपचुनाव के लिए तैनात अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को उनके मूल स्थान पर पहुंचाने के लिए भी रेक उपलब्ध कराना पड़ा है। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों का वार्षिक स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी करने में भी रेक का इस्तेमाल हो रहा है। इन कारणों से दस दिसंबर और उसके बाद की तिथियों के लिए निर्धारित मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा विशेष ट्रेनें रद करनी पड़ी हैं।

भाजपा ने बौखलाहट में रोकी यात्रा : राय

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के लिए ट्रेन उपलब्ध न कराने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राय ने कहा कि बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना भाजपा की बौखलाहट को दर्शाता है। केंद्र सरकार को बुजुर्गों की बददुआ लगेगी।

राय ने बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 22 नवंबर को रेलवे की तरफ से दिल्ली सरकार को एक दिसंबर से 28 जनवरी तक की यात्रा का शेड्यूल भेजा गया था। समझौते के अनुसार दिल्ली सरकार ने इस शेडयूल को 28 नवंबर को ही स्वीकृति दे दी थी। एक दिसंबर से इसी समझौते के अनुसार यात्रा हो रही थी। तीर्थ यात्रियों को 14 दिसंबर तक की टिकट भी जारी कर दी गई थी, लेकिन अचानक से ट्रेन रद कर दी गई।

राय ने कहा कि अभी तो होली, दीवाली, ईद या कोई त्योहार भी नहीं है, जिसकी वजह से ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई हो। राय ने बताया कि दिल्ली को चार ट्रेनें दी गई थीं, उनसे ही यात्रा कराई जा रही थी। अब केंद्र सरकार बताए कि इन चार ट्रेनों का उपयोग कहां किया जा रहा है।

दिल्ली में प्रदूषण के कारण शिक्षिका ने मांगा वीआरएस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से परेशान शिक्षिका अनिता जून ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) की मांग की है। 28 वर्षों से शिक्षण कार्य से जुड़ी 50 वर्षीय अनिता उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शालीमार बाग के बीबी ब्लॉक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं। उन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद पीएचडी करने की इच्छा जताई है।

निगम के अधिकारियों और शिक्षा उपनिदेशक को लिखे पत्र में शिक्षिका ने कहा है कि प्रदूषण की वजह से उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं हो रही हैं और अब वह दिल्ली में शिक्षण कार्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं। पत्र में उन्होंने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र किया है और यह बताया है कि वह सिक्किम या किसी अन्य राज्य में बसना चाहती हैं। बतौर खेल शिक्षक अनिता बच्चों को सदैव फिटनेस से जुड़े मंत्र देती रहती हैं। वह बच्चों को दौड़, योग, खो-खो, कबड्डी, नृत्य, एथलीट सिखाती हैं। साथ ही उन्हें नैतिक शिक्षा से जुड़ी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में भी बताती हैं। अनिता इसको लेकर भी चिंतित हैं कि दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वह तैराकी भी जानती हैं और योग के माध्यम से उन्होंने अपना वजन कम किया, लेकिन प्रदूषण के कारण अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं।

अनिता ने बताया कि बस और मेट्रो से यात्रा के बाद जब उन्हें पैदल स्कूल या घर जाती हैं, तब उन्हें प्रदूषण के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। पिछले कुछ वर्षों में सांस की तकलीफ के साथ थकावट भी होती है। जाम में फंसने पर यह परेशानी आती है। डॉक्टर ने भी उनकी इस समस्या के लिए प्रदूषण को वजह बताया। इस कारण वह कई बार स्कूल से छुट्टी ले चुकी हैं। अनिता ने लिखा है कि वह पीएचडी करना चाहती हैं। वक्त के अभाव में अब तक नहीं कर पाईं।

फिर गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : ठंड और कोहरे में इजाफे के बीच दिल्ली-एनसीआर में हवा भी बुधवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। दिन भर स्मॉग छाया रहा। दिसंबर में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। हालांकि गुरुवार को तेज हवा चलने और बारिश होने के आसार हैं। इससे प्रदूषण कम होगा और उम्मीद है कि अगले कई दिनों तक कम ही रहेगा। बुधवार को सुबह से ही दिल्ली-एनसीआर के आसमान पर स्मॉग की चादर छाई हुई थी। यूं तो पिछले सप्ताह भर से प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ ही चल रहा है, लेकिन बुधवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 408 पहुंच गया। सबसे खराब हालात ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के रहे। ग्रेटर नोएडा में एयर इंडेक्स 449, गाजियाबाद में 441, नोएडा में 426, फरीदाबाद में 390 और गुरुग्राम में 370 रहा। पीएम 2.5 का स्तर 233, जबकि पीएम 2.5 का स्तर 387 दर्ज किया गया।

चार कैदियों को फांसी देने में लग सकते हैं छह घंटे

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली

फांसी से बचने के लिए निर्भया के दोषियों की ओर से दाखिल दया और पुनर्विचार याचिका पर अब तक कोई फैसला नहीं आया है। इसके बावजूद जेल प्रशासन अपनी ओर से हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। जेल सूत्रों के अनुसार, दोषियों के लिए यदि डेथ वारंट जारी होता है तो फांसी की प्रक्रिया पूरी होने में करीब छह घंटे लगेंगे। यह पहला मौका होगा, जब तिहाड़ जेल संख्या-3 में बना फांसी घर इतनी देर के लिए खुला रहेगा। इस दौरान जेल संख्या तीन बंद रहेगा।

जेल सूत्रों के अनुसार किसी दोषी को जिस दिन फांसी दी जाती है, उसे सुबह पांच बजे उठा दिया जाता है। नहाने के बाद उसको फांसी घर के सामने खुले अहाते में लाया जाता है। यहां जेल अधीक्षक, उप अधीक्षक, मेडिकल ऑफिसर, सबडिविजनल मजिस्ट्रेट व सुरक्षा कर्मचारी मौजूद रहते हैं। मजिस्ट्रेट दोषी से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। इस दौरान आमतौर पर संपत्ति किसी के नाम करने या किसी के नाम पत्र लिखने की बात सामने आती रही है। करीब 15 मिनट का वक्त दोषी के पास रहता है। इसके बाद जल्लाद दोषी को काले कपड़े पहनाता है। उसके हाथ को पीछे कर रस्सी या हथकड़ी से बांध दिया जाता है। यहां से करीब सौ कदम की दूरी पर बने फांसी घर पर कैदी को ले जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। वहां पहुंचने के बाद दोषी कैदी को छत पर ले जाया जाता है। वहां जल्लाद उसके मुंह पर काले रंग का कपड़ा बांधकर गले में फंदा डालता है। इसके बाद दोषी के पैरों को रस्सी से बांध दिया जाता है। जब जल्लाद अपने इंतजाम से संतुष्ट हो जाता है, तब वह जेल अधीक्षक को आवाज देकर बताता है कि उसके इंतजाम पूरे हो चुके हैं। आगे के लिए आदेश दें। जब जेल अधीक्षक हाथ हिलाकर इशारा करते हैं, जल्लाद लीवर खींच देता है। एक ही झटके में दोषी फंदे पर झूल जाता है। इसके दो घंटे बाद मेडिकल ऑफिसर फांसी घर के अंदर जाकर यह सुनिश्चित करते हैं कि फंदे पर झूल रहे शख्स की मौत हुई है या नहीं। आखिर में मेडिकल ऑफिसर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करता है। कैदी को मजिस्ट्रेट के सामने लाने और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी होने तक की प्रक्रिया में करीब तीन घंटे का वक्त लग जाता है।

तिहाड़ जेल संख्या तीन में जो फांसी घर बना है, उसमें एक बार में अधिकतम दो दोषियों को फंदे पर लटकाने का प्रावधान है। यदि निर्भया के दोषियों को फांसी दी जाएगी तो यह कार्य दो अलग-अलग चरणों में ही हो सकता है। इस तरह से चार दोषियों को फांसी देने की पूरी प्रक्रिया में करीब छह घंटे लग जाएंगे।

फांसी के दौरान जेल रहता है बंद : फांसी के दौरान जेल में आवाजाही बंद कर दी जाती है। कैदियों को उनकी बैरक या सेल में बंद कर दिया जाता है। सभी जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है। जेल का मुख्य दरवाजा इस दौरान बंद रहता है।

निर्भया के हत्यारों को फांसी पर लटकाएंगे उप्र के जल्लाद!

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : तिहाड़ जेल प्रशासन ने कारागार मुख्यालय को पत्र लिखकर जल्लाद मांगे हैं। पत्र में कहा गया है कि कुछ दोषियों को फांसी पर लटकाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि बहुचर्चित निर्भया कांड के दोषियों को फांसी उत्तर प्रदेश के जल्लाद दे सकते हैं। निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। ऐसे ही अन्य जघन्य अपराधों में संलिप्त कुछ दरिंदों को भी अदालत मृत्यु दंड दे चुकी है। हर स्तर पर अपील खारिज होने के बाद इन दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने की तैयारी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के अधीक्षक ने कारागार मुख्यालय को पत्र लिखकर जल्लाद (हैंग मैन) उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। बताया गया कि दिल्ली की जेलों में कोई जल्लाद नहीं है। कारागार मुख्यालय को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि तिहाड़ में कुछ ऐसे सजायाफ्ता मुल्जिम हैं, जिन्हें मृत्यु दंड की सजा दी जा चुकी है और उनकी सभी स्तर से दया याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। उन्हें फांसी देने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश से जल्लाद भेजे जाने की अपेक्षा की गई है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने जल्लाद के आने-जाने के सभी खर्चों का भुगतान किए जाने की बात भी कही है। डीजी जेल आनंद कुमार ने बताया कि लखनऊ व मेरठ जेल में दो जल्लाद हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर जब कोई तिथि निर्धारित की जाएगी, तब उन्हें जल्लाद उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तिहाड़ जेल प्रशासन को लखनऊ व मेरठ जेल में दो जल्लाद उपलब्ध होने की सूचना दे दी गई है।

एक ही बिल्डिंग में थीं 18 फैक्ट्रियां

अनाज मंडी अग्निकांड

रिहान के साले सोहेल को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, भाई की तलाश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में अनाज मंडी की जिस इमारत में आग लगी थी, उसमें कुल 18 फैक्ट्रियां थीं। इनमें रिहान के छोटे भाई इमरान और साले सोहेल की भी तीन-तीन फैक्ट्रियां थीं। बची हुई 12 फैक्ट्रियां रिहान की थीं। उसने 10-12 लोगों को ये फैक्ट्रियां चलाने का ठेका दे रखा था, लेकिन दस्तावेजों में मालिकाना हक इनके पास है।

क्राइम ब्रांच ने बुधवार शाम सोहेल को आइएसबीटी के पास से गिरफ्तार कर लिया। अब इमरान की तलाश की जा रही है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्रियों में पहली और दूसरी मंजिल पर आइना बनाए जाते थे। दूसरी और तीसरी मंजिल पर पिट्ठू बैग, रेक्सीन की डायरी, ट्रेवल बैग और प्लास्टिक के खिलौने बनाए जाते थे। चौथी मंजिल पर भी बैग, टोपी व रेक्सीन के जैकेट आदि बनाए जाते थे। भूतल पर तीन मोल्डिंग मशीनें मिली हैं। इमारत में 100 से ज्यादा सिलाई मशीनें थीं। इनमें कई मशीनें आग में पिघल गईं। हर फ्लोर पर 15 बाई 20 वर्गफुट के तीन-तीन कमरे व दो बड़े बड़े हॉल थे। इमारत में स्थित फैक्ट्रियों में सबसे अधिक आइना में इस्तेमाल होने वाला शीशा तैयार किया जाता था। आग दूसरी मंजिल से शुरू हुई थी, लेकिन सबसे अधिक नुकसान तीसरी मंजिल पर हुआ। आग लगने से जिन 43 लोगों की मौत हुई है, उनमें चार को छोड़ बाकी सभी की दम घुटने से मौत हुई है। मरने वालों में दो-तीन ठेकेदार भी बताए जा रहे हैं।

मजदूर फैक्ट्रियों में ही खाना बनाकर खाते थे, लेकिन रात में सोने के लिए किसी के पास निर्धारित जगह नहीं थी। जिसे जहां जगह मिल जाती थी, वह वहीं पर सो जाता था। इमारत में सीढ़ियों के कर्व के पास अधिक जगह होती है। इसलिए अधिकतर मजदूर उसी जगह पर सोते थे। फैक्ट्री में ठहरने के कारण मजदूरों के किराये के पैसे बच जाते थे। यहां मिलने वाली आठ-दस हजार की तनख्वाह वे घर भेज देते थे।

इमारत में हर फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। दूसरे तल पर आग लगने के कारण इस तल व इससे ऊपर की मंजिलों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे जल गए। भूतल और चौथी मंजिल पर एक-एक डीवीआर था, चौथी मंजिल का डीवीआर भी जल गया। क्राइम ब्रांच ने उसे जब्त कर जांच के लिए सीबीआइ की लैब में भेज दिया है। वहां टेक्निकल एक्सपर्ट उसे रीट्रीट करने की कोशिश करेंगे। यदि वे इसमें सफल होते हैं, तो आग लगने से फैलने तक की पूरी जानकारी मिल सकती है।

अनाज मंडी में जानलेवा फैक्ट्री के बाहर के खंभे पर बिजली की तारों को ठीक करते बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारी। जागरण

500 से अधिक इमारतों में चल रहीं अवैध फैक्ट्रियां

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

फिल्मिस्तान की अनाज मंडी में 500 से अधिक बहुमंजिला इमारतों में सारे नियम-कानून को ताक पर रखकर अवैध रूप से फैक्ट्रियां चल रही हैं। करीब 200 वर्ग गज में बनी, जिस इमारत में गत दिनों आग लगने से 43 लोगों की मौत हुई, उसमें अवैध रूप से 18 छोटी-छोटी फैक्ट्रियां चल रही थीं। इसी तरह अन्य इमारतों में 10-20 फैक्ट्रियां चल रही हैं।

यह पूरा इलाका रिहायशी है। दिल्ली फायर सर्विस एक्ट के मुताबिक इमारतों की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन करीब हर इमारत की ऊंचाई इससे अधिक है, क्योंकि घर-घर में अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं। पांच से छह मंजिला इमारतें भी बनी हुई हैं। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी नहीं दी जाती है, सिर्फ छोटे-मोटे धंधे के लिए ही एनओसी मिल सकती है। जिस इमारत में आग लगी उसकी ऊंचाई 17 मीटर है और उसमें बिजली कंपनी बीएसईएस के सात व्यावसायिक मीटर लगे थे, जबकि 18 फैक्ट्रियां हैं इसलिए इतने ही औद्योगिक मीटर होने चाहिए। क्राइम ब्रांच का कहना है कि रिहान इन सात मीटरों से अवैध तरीके से सभी को बिजली दे रहा था और सबमीटर लगवाकर उनसे प्रति यूनिट वसूली कर रहा था। व्यावसायिक मीटरों से औद्योगिक इकाइयां भी नहीं चलाई जा सकती हैं।

क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि घटना के बाद सीलिंग को लेकर फैक्ट्री मालिकों में भय है। इसलिए सैकड़ों फैक्ट्रियों में ताले डाल दिए गए हैं। इस हादसे से सभी संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हादसे के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। ऐसे में फैक्ट्री मालिकों ने अनाज मंडी से पलायन शुरू कर दिया है। इसकी वजह से रात-रात भर फैक्ट्री मालिक फैक्ट्रियों से सामान निकाल रहे हैं। रात में ही क्रेन मंगवाकर फैक्ट्रियों से मशीनों को निकाला जा रहा है। ताकि सीलिंग होने पर उनकी करोड़ों की मशीनें व सामान बच जाए। इसके बाद भी नगर निगम व अन्य संबंधित विभागों की आंखें नहीं खुल रही हैं। यही नहीं सामान ले जा रहे फैक्ट्री मालिकों को भी कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि कहीं संबंधित एजेंसियां ही कार्रवाई से पहले उन्हें पलायन का मौका तो नहीं दे रही हैं।

अनाज मंडी के आसपास अवैध फैक्ट्रियां लगाने का मुख्य कारण यह है कि यहां पास में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के अलावा सदर बाजार है। इससे आसानी से फैक्ट्रियों में तैयार किए गए सामान को बेच दिया जाता है। व्यापारी कम दरों में सामान खरीद ट्रेन के जरिये गंतव्य स्थानों पर लेकर चले जाते हैं। सघन आबादी वाले इस इलाके में संबंधित एजेंसियों की निगरानी न के बराबर रहती है।

तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटा विमान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली से हैदराबाद जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के यात्री विमान को उड़ान भरने के बाद कुछ देर बाद ही वापस लौटना पड़ा। विमान में आई तकनीकी खराबी की सूचना मिलने पर विमान की वापस आइजीआइ एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। इसके बाद यात्रियों को दूसरे विमान के जरिये रवाना किया गया। मामला मंगलवार की सुबह का है।

दिल्ली से हैदराबाद जा रहे इंडिगो यात्री विमान ए 320 के उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही तकनीकी खराबी की कुछ सूचना मिली। इसके बाद विमान को वापस दिल्ली लौटाया गया। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उड़ान भरने के बाद विमान को दिल्ली जांच के लिए लाया गया था। यात्रियों को दूसरे विमान के जरिये हैदराबाद के लिए रवाना किया गया। पिछले सप्ताह भी इंडिगो के एक और विमान में गड़बड़ी की खबर सामने आई थी। इसके बाद विमान को मुंबई एयरपोर्ट पर वापस लौटना पड़ा था। इंडिगो का यह यात्री विमान मुंबई से बेंगलुरु के लिए उड़ान पर था। विमान के इंजन में खराबी की शिकायत आई थी।

सोशल मीडिया पर पुरी को सीएम पद का चेहरा बनाने का अभियान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा में मुख्यमंत्री पद का चेहरा को लेकर केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक बार फिर से चर्चा में हैं। पिछले दिनों वह एक कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताकर चर्चा में आए थे। इस बार उन्हें खुद मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा है। इसके लिए 'हरदीप पुरी4सीएम' नाम से एक ट्विटर हैंडल भी बनाया गया है और इससे दिल्ली के कई नेताओं को फॉलो किया जा रहा है। पुरी के नजदीकियों ने इसे किसी की शरारत करार दिया है।

हरदीप सिंह पुरी

शहरी विकास राज्य मंत्री दिल्ली भाजपा के चुनाव सह प्रभारी भी हैं। अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके साथ ही वह दिल्ली सरकार व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले करते रहते हैं। पिछले दिनों उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भाजपा शहरी केंद्र के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया था। हालांकि कुछ घंटों में ही उन्होंने अपने बयान से पलटते हुए ट्वीट किया था कि पार्टी ने अब तक किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है। अभी यह मामला किसी तरह से शांत ही हुआ था कि 'हरदीप पुरी4सीएम' ट्विटर हैंडल से भाजपा नेताओं को फॉलो किए जाने से एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस ट्विटर हैंडल से पुरी के ट्वीट को भी रीट्वीट किया जा रहा है। राज्यसभा में होने के कारण पुरी का पक्ष नहीं मिल सका है, लेकिन उनके करीबी लोगों ने इस तरह के ट्विटर हैंडल को लेकर अनभिज्ञता जताई। उनका कहना है कि पार्टी में गलतफहमी पैदा करने के लिए किसी ने यह शरारत की है।

जेएनयू में छात्र के साथ मारपीट का वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में बुधवार के दिन सोशल मीडिया पर छात्र के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। इसमें हाथ में डंडे लिए कुछ लोग एक छात्र को दौड़ाकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर वामपंथी छात्र संगठनों के प्रतिनिधि, जेएनयू छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। वामपंथी छात्र संगठन आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसाई बालाजी ने इस वीडियो का हवाला देते हुए एबीवीपी पर हिंसा करने के आरोप लगाए हैं।

वहीं एबीवीपी के जेएनयू इकाई के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि कैंपस में वामपंथी छात्र संगठन के गुंडे हॉकी और लाठी लेकर घूम रहे हैं। यह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मारने की धमकी दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में सुचारू रूप से परीक्षाएं आयोजित हों।

राहत

डासना के चार गांवों में सभी किसानों को बांटा गया मुआवजा, प्रशासन ने 71.14 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा लेकर एनएचएआइ को सौंपा

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे बनने का रास्ता हुआ साफ

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के चौथे चरण में डासना से मेरठ तक होने वाले निर्माण में आने वाली सभी अड़चनों को दूर कर लिया गया है। प्रशासन ने चारों गांवों के सभी किसानों को मुआवजा बांट दिया है। एक्सप्रेसवे की जद में आ रहे मकान मालिकों को भी मुआवजा देकर भूमि पर कब्जा ले लिया गया। प्रशासन ने 71.14 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा लेकर एनएचएआइ को सौंप दी है। अब डासना में एनएचएआइ ने एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। हालांकि एक समान मुआवजे की मांग को लेकर मोदीनगर के 13 गांवों के किसानों ने तय किया है कि वे काम नहीं रोकेंगे, लेकिन आठ दिन के बाद उनकी समस्या का हल नहीं निकला तो काम को पूरी तरह बंद करा देंगे।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना में चौथे चरण का काम मुआवजे के विवाद में प्रभावित हो रहा था। डासना के चार गांव कुशलिया, डासना, नाहल और रसूलपुर-सिकरौड़ा और मोदीनगर के 13 गांव इस परियोजना में रोड़ा अटका रहे थे। डासना के चार गांवों में पूर्व में हुए भूमि अधिग्रहण के दौरान गड़बड़ी की जांच शासन स्तर पर लंबित होने से भूमि पर कब्जे में देरी हो रही थी। वहीं मोदीनगर के 13 गांवों के किसान समान मुआवजे व सर्विस रोड बनाने समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही यहां कई जगह भूमि का मूल्यांकन नहीं हो पाया था। इसके चलते भूमि की कमी आड़े आ रही थी। केंद्र सरकार ने 45 दिन के भीतर योजना में आ रही अड़चनों को दूर करने के निर्देश दिए थे।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को चार चरणों में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जागरण

जिलाधिकारी अजयशंकर पांडेय ने बताया कि प्रशासन ने बुधवार तक सभी किसानों को मुआवजा बांट दिया। अब किसानों की मांग पर चारों गांवों के लिंक मार्गों पर अंडर पास बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। जिन लोगों के एक्सप्रेसवे की जद में आ रहे मकानों को तोड़ा गया था, उनको भी मुआवजा दे दिया गया है।

बता दें कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को चार चरणों में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। इन चार चरणों में सराय काले खां-यूपी गेट, यूपी गेट-डासना, डासना-हापुड़ व डासना-मेरठ शामिल हैं। इनमें सराय काले खां-यूपी गेट और डासना-हापुड़ के चरण का काम पूरा हो चुका है, जबकि यूपी गेट-डासना का 80 फीसद और डासना-मेरठ का 60 फीसद काम पूरा हो चुका है। दोनों चरणों का काम अभी चल रहा है, लेकिन 17 गांव इसके निर्माण में बाधा बने हुए थे। मोदीनगर के 13 गांवों में 3600 और 4000 रुपये के हिसाब से जमीन अधिग्रहण कर मुआवजा बांटा गया था, लेकिन यहां के किसान समान मुआवजे की मांग कर रहे थे।

एलटीसी घोटाले में मदनी के खिलाफ एफआइआर रद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ हाई कोर्ट ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया

एलटीसी (अवकाश यात्रा रियायत) घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य महमूद ए मदनी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर एफआइआर को रद करने का आदेश दिया। हालांकि, पीठ ने लापरवाही से हुई गलती के लिए पांच लाख रुपये का भुगतान करने और अतिरिक्त रकम वापस करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।

न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ ने मदनी की एफआइआर रद करने की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि यात्रा भत्ता के रूप में पांच लाख रुपये का अतिरिक्त दावा उनके निजी सहायक की तरफ से लापरवाही के कारण हुआ था। याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई षड्यंत्र और अपराध साबित नहीं हुआ। पीठ ने कहा कि आदेश की प्रति मिलने के एक सप्ताह के अंदर उक्त रकम वापस करें। पीठ ने साथ ही लापरवाही के कारण सरकारी व्यवस्था को हुई परेशानी व लोगों का समय बर्बाद होने को लेकर उन पर 5 लाख रुपये जुर्

72 हजार से ज्यादा अमेरिकी राइफलों को तीन भागों में बांटा गया है। इनमें से 66 हजार राइफलें थलसेना को, 2000 नौसेना और 4000 वायुसेना को मिलनी हैं।

डाटा प्रोटेक्शन बिल जेपीसी के हवाले

खींचतान ▶ लोकसभा में रविशंकर प्रसाद ने पेश किया बिल, विपक्ष का हंगामा

अगले बजट सत्र में विधेयक को पारित करवाने की सरकार की मंशा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा में बुधवार को डाटा प्रोटेक्शन बिल पर बोलते केंद्रीय कानून, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद। एएनआइ

देश के नागरिकों के पर्सनल डाटा के चोरी होने या उसके गलत इस्तेमाल की विपक्ष की आशंकाओं के बीच डाटा प्रोटेक्शन बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। सरकार ने स्वयं ही इसे संयुक्त समिति को सौंप दिया। इस बारे में केंद्रीय कानून, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया गया जिसे ध्वनिमत से स्वीकृति मिल गई। प्रसाद ने उम्मीद जताई कि संयुक्त समिति इस पर अगले बजट सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट दे देगी। मकसद है बजट सत्र में इस बहुप्रतीक्षित विधेयक को पारित करवाना।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जैसे ही इस विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा में खड़े हुए विपक्षी दलों की तरफ से इसका विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके के सांसदों ने सरकार पर आरोप लगाया कि जिस तरह से मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लोगों की जासूसी करवाने का उद्योग फलफूल रहा है उसे यह विधेयक कानूनी जामा पहनाने का काम करेगा। विपक्ष की तरफ से विरोध होते ही प्रसाद ने कहा कि सरकार इसे अपनी तरफ से संयुक्त समिति को सौंपने को तैयार है। जब सभापति ने विधेयक पेश करने के लिए वोटिंग कराने का निर्देश दिया। सत्ता पक्ष की गिनती को देखते हुए विपक्ष फिर वाकआउट ही कर गया।

बाद में लोकसभा सचिवालय की तरफ से यह जानकारी दी गई कि डाटा प्रोटेक्शन बिल को लोकसभा के 20 सदस्यों और राज्य सभा के 10 सदस्यों वाली संयुक्त समिति को सौंपा जा रहा है। इसमें लोकसभा से मीनाक्षी लेखी, पीपी चौधरी, एस एस अहलूवालिया, तेजस्वी सूर्या, अजट भट्ट, राज्यवर्द्धन राठौर, संजय जायसवाल, कृतिभाई सोलंकी, अरविंद धर्मापुरी, हीना गवित, उदय प्रताप सिंह, राजीव रंजन सिंह, गौरव गोगोई, एस जोथी मणि, स्वागत राय, कानीमोरी, पीवी मिथुन रेड्डी, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, भर्तृहरि महताब और रितेश पांडे शामिल हैं। राज्य सभा सचिवालय से आग्रह किया गया है कि वह भी समिति के लिए अपने सदस्यों की घोषणा करे। समिति से कहा गया है कि वह बजट सत्र, 2020 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंप दे।

विधेयक पेश करने के वक्त अपने संक्षिप्त वक्तव्य में प्रसाद ने कहा कि यह विधेयक कोई जल्दबाजी में नहीं लाया जा रहा है बल्कि कई वर्षों तक विचार विमर्श के बाद लाने का फैसला किया है। इस पर सुझाव देने के लिए गठित पूर्व न्यायाधीश श्रीकृष्णा समिति ने सभी पक्षों से लंबे विमर्श के बाद इसे तैयार किया है। इस बात का पक्का प्रबंध किया जा रहा है कि किसी भी देशवासी का पर्सनल डाटा का कोई गलत इस्तेमाल न हो। इसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि किसी भी तरह का जोखिम पैदा करने वाले डाटा को देश से बाहर कोई भी कंपनी नहीं ले जा सके। इसी तरह से संवेदनशील डाटा के बारे में यह व्यवस्था की जा रही है कि उसे ग्राहक की अनुमति से ही इस्तेमाल किया जाए। अगर ग्राहक की अनुमति के बगैर उससे जुड़े डाटा का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो ग्राहक को करोड़ों रुपये का हर्जाना दिलाने का प्रावधान है।

विपक्षी दलों का कहना है कि यह विधेयक सरकारी एजेंसियों के जरिए लोगों की जासूसी करवाने का रास्ता साफ कर देगा क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों से सरकारी एजेंसियों को बाहर रखा गया है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आम जनता के पर्सनल डाटा के सुरक्षा के अधिकार को उनका सार्वभौमिक अधिकार माने जाने के आदेश का भी उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड में रेलवे को 450 पेड़ काटने की दी इजाजत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- शीर्ष अदालत ने बदले में पौधरोपण की शर्त पर दी इजाजत
- कोर्ट में तीन महीने में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने ताज संरक्षित क्षेत्र (टीटीजेड) में रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे को सशर्त 452 पेड़ काटने की इजाजत दे दी। रेलवे को पेड़ काटने के बदले में पौधरोपण कराना होगा। रेलवे ने याचिका दाखिल कर आगरा दिल्ली के बीच अतिरिक्त रेल लाइन बिछाने के लिए कोर्ट से करीब 30 किलोमीटर क्षेत्र में पड़ रहे करीब 452 पेड़ों को काटने की इजाजत मांगी थी।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पेड़ काटने के बदले रेलवे को पौधे लगाने होंगे। कोर्ट ने नालसा से कहा है कि वह एक अधिकारी नियुक्त करे जो वहां जाकर मौके का मुआयना कर रिपोर्ट देगा कि रेलवे ने बदले में जो पौधरोपण किया है, उनमें पानी दिया जा रहा है और वे बढ़ रहे हैं। क्या लगाए गए पौधे मर गए और अगर वे मर गए हैं तो क्या उनकी जगह नए पौधे लगाए गए हैं? अधिकारी इस बारे में कोर्ट में तीन महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगा साथ ही यह भी बताएगा कि पेड़ काटने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है या नहीं।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताज संरक्षित क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा रखी है इसलिए किसी भी परियोजना के लिए पेड़ काटने से पहले कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। इसके अलावा कोर्ट ने आगरा में खुले नालों और सड़क पर बहते सीवर के पानी से हो रहे प्रदूषण और बढ़ती बीमारियों पर चिंता जाहिर करते हुए पर्यावरणविद् एमसी मेहता और नीरी को आदेश दिया है कि वह मौके पर जाकर मुआयना करें और छह सप्ताह में कोर्ट को रिपोर्ट देकर बताए कि इस बारे में क्या उपाय किए जा सकते हैं।

इकबाल मिर्ची परिवार की 600 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग मामले में गैंगस्टर इकबाल मिर्ची की 600 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। इन संपत्तियों में मुंबई के वर्ली क्षेत्र में स्थित सीजे हाउस की तीसरी और चौथी मंजिल, ताड़देव में अरुण चैंबर्स में स्थित दफ्तर, क्राफोर्ड मार्केट में तीन प्राइम कामर्शियल दुकानें, लोनावला में बंगले और जमीन (पांच एकड़ से अधिक) शामिल हैं।

जांच एजेंसी ने बुधवार को कहा कि संपत्तियां कुर्क करने के लिए मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत दो अस्थायी आदेश जारी किए गए। इन संपत्तियों का बाजार कीमत 600 करोड़ रुपये है। ईडी ने आरोप लगाया था कि मिर्ची ने ये संपत्तियां 'अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर' अर्जित की थी। ईडी ने हाल में मुंबई में एक विशेष कोर्ट के समक्ष इस मामले में एक आरोप पत्र दाखिल किया था। मिर्ची की लंदन में 2013 में मौत हो गई थी। उस पर मादक पदार्थों की तस्करी और वसूली के अपराधों में वैश्विक आतंकी दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ होने का आरोप था। ईडी ने कहा, 'वह (मिर्ची) एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ डीलर और तस्कर था जिसने भारी संपत्ति जुटाई थी और दुनिया भर में विभिन्न अचल संपत्तियों का मालिक बन बैठा था।'

लोकसभा में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधेयक पेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : विपक्षी दलों के विरोध के बीच लोकसभा में बुधवार को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 और उससे संबंधित विधेयक पेश किया गया। विधेयक पेश करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इसमें श्रम कानूनों की जटिलताओं को कम करने और उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि हमने विधेयक लाने से पहले मजदूर संगठनों से गंभीर चर्चा की।

इसके तहत 44 कानूनों को चार कानूनों में बदलने की महत्वपूर्ण पहल की गई है। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने जून, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसने सिफारिश की थी कि श्रम विधियों को औद्योगिक संबंध, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा तथा कल्याण एवं कार्य स्थितियां समूहों के तहत रखा जाना चाहिए।

आयोग की सिफारिशों पर तथा सरकार, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय बैठक में प्रस्तावित विधान लाने का निश्चय किया गया था। इसमें कहा गया है कि विधेयक प्रौद्योगिकी के उपयोग को आसान बनाएगा और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

माता-पिता का ध्यान नहीं रखा तो होगी जेल

- 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक-2019' लोकसभा में पेश

थावरचंद गहलोत फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा में बुधवार को 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक-2019' पेश किया गया। इसमें माता-पिता या अपने संरक्षण वाले वरिष्ठ नागरिकों के साथ जानबूझकर दुर्व्यवहार करने या उन्हें उनके हाल पर अकेला छोड़ देने वालों के लिए छह महीने के कारावास या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने निचने सदन में उक्त विधेयक पेश किया। इसमें वृद्धाश्रमों और उसके जैसी सभी संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही उन्हें न्यूनतम मानकों का पालन भी करना होगा।

'दुर्व्यवहार' में अनदेखी भी शामिल : विधेयक में 'दुर्व्यवहार' को परिभाषित किया गया है जिसमें शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार के साथ-साथ अनदेखी और उन्हें उनके हाल पर अकेला छोड़ना शामिल है। इसके अलावा हमला करना, चोट पहुंचाना, शारीरिक या मानसिक कष्ट देना भी दुर्व्यवहार में शामिल है।

'बच्चों' में दामाद व बहू भी : बिल में माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों के 'बच्चों' से आशय उनके पुत्र-पुत्री (जैविक, दत्तक या सौतेले), दामाद, बहू, पोते, पोती और नाबालिग बच्चों के कानूनी अभिभावक शामिल हैं।

हर राज्य में भरण पोषण अधिकारी : भरण पोषण आदेश के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार भरण पोषण अधिकारी नियुक्त करेगी। माता-पिता या बुजुर्गों के लिए उक्त अधिकारी समन्वयक के तौर पर कार्य करेगा। जरूरत पड़ने पर ट्रिब्यूनल भरण पोषण का मामला मध्यस्थता अधिकारी को संदर्भित कर सकेगा जिसे 15 दिनों के भीतर सिफारिशें देनी होंगी। भरण पोषण राशि तय करते समय ट्रिब्यूनल बुजुर्गों के जीवन स्तर,उनकी आय या उनके बच्चों की आय पर विचार कर सकता है।

भरण पोषण राशि नहीं देने पर जुर्माना : ट्रिब्यूनल को माता-पिता या बुजुर्गों का भरण पोषण नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी होगा। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें राशि अदा करने तक या अधिकतम एक माह जेल काटनी पड़ सकती है।

हर प्रदेश में हेल्पलाइन नंबर : सरकार को यह सुनिश्चित करने का हक दिया गया है कि अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए बेड आरक्षित हो। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के लिए अलग से एक हेल्पलाइन नंबर होगा।

प्रत्येक थाने में नोडल अधिकारी

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों के लिए हर पुलिस थाने में एक नोडल अधिकारी तैनात होगा जो एएसआइ रैंक से नीचे का नहीं होगा। साथ ही हर जिले में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक विशेष पुलिस इकाई होगी जिसका प्रमुख कम से कम डीएसपी रैंक का अधिकारी होगा।

ट्रिब्यूनल 90 दिनों में करेगा निपटारा

वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और सहायता के दावे दाखिल करने के लिए एक ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। 80 साल से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों के दावों का निपटारा 60 दिन के भीतर किया जाएगा। सिर्फ अवपाद वाले मामलों में यह अवधि केवल एक बार अधिकतम 30 दिन के लिए बढ़ाई जा सकेगी। लेकिन इसके लिए ट्रिब्यूनल को कारण लिखित में दर्ज करना होगा। 80 साल से कम के वरिष्ठ नागरिकों के दावों का निपटारा ट्रिब्यूनल को 90 दिनों के भीतर करना होगा।

बुजुर्गों की स्थिति

हेल्प एज इंडिया द्वारा 2018 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक :-

- 69 फीसद बुजुर्गों के पास अपने नाम पर एक घर है
- 7 फीसद के पास पति या पत्नी के नाम घर है
- 3 फीसद दूसरों के साथ रह रहे हैं
- 20 फीसद किराए पर रह रहे हैं
- 85 फीसद बुजुर्ग परिवार के साथ रह रहे हैं
- 6 फीसद अकेले रह रहे हैं
- 2 फीसद रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं
- 56 फीसद बुजुर्गों ने माना उनका अपमान किया गया
- 49 फीसद ने माना उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ
- 33 फीसद उपेक्षा के शिकार हुए
- 52 फीसद : गाली देने वालों में लड़के आगे
- 34 फीसद : बहुओं ने दी गाली
- 35 फीसद बुजुर्गों को पुलिस हेल्पलाइन के बारे में पता है
- 11 फीसद को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण कानून के बारे में पता है

उज्ज्वला योजना में छोटे सिलेंडर ज्यादा कारगर

- उज्ज्वला योजना में कम होने लगी रीफिल
- एलपीजी कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों के बीच साल में रीफिल की संख्या औसतन 3.66 से घट कर 3.21 हुई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

उज्ज्वला योजना के तहत बांटे गए सिलेंडर की रीफिल में लगातार आ रही कमी का निराकरण छोटे सिलेंडर हो सकते हैं। सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया है कि जहां जिन दस जिलों में पांच किलो के छोटे सिलेंडर दिए जा रहे हैं वहां लोग पहले के मुकाबले ज्यादा रीफिल कराने लगे हैं।

इस सर्वे का एक दूसरा पहलू भी है। वह यह है कि तकरीबन 31 उज्ज्वला ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने साल में 51 से 85 बार सिलेंडर रीफिल कराया है। 157 ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने 41 से 50 बार रीफिल कराए, 353 ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने 31 से 40 बार रीफिल कराए, 4053 ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने 21 से 30 और 1,93,870 ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने 13 से 20 बार रीफिल कराए हैं। सर्वे में यह भी पाया गया है कि तकरीबन 3.44 लाख उज्ज्वला कनेक्शन में एक दिन में दो से 20 रीफिल जारी किए गए हैं। सीएजी ने पहले भी इस समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराया था और ऐसी व्यवस्था लागू करने को कहा था कि जिससे कोई भी ग्राहक एक दिन में एक बार ही बुकिंग करा सके। बुधवार को पेश सीएजी रिपोर्ट में सामने आया है कि दोबारा सिलेंडर रीफिल कराने वालों की औसत संख्या घट रही है। हकीकत यह है कि 17.61 फीसद उज्ज्वला ग्राहकों ने कभी भी दोबारा रीफिल नहीं कराया जबकि 33.02 फीसद कनेक्शन धारकों ने महज एक से तीन बार रीफिल कराया है। इस योजना पर सीएजी की नई रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है।

सीएजी ने 31 मार्च, 2018 तक के 1.93 करोड़ ग्राहकों के बीच सर्वे किया तो पाया कि उन्होंने पिछले एक वर्ष में औसतन 3.66 बार रीफिल कराया था। दिसंबर, 2018 में फिर 3.18 करोड़ उज्ज्वला ग्राहकों के बीच सर्वे किया गया तो यह पाया गया औसतन रीफिल संख्या 3.21 रह गई। इसमें से 0.56 लाख ग्राहकों ने तो पिछले एक वर्ष में दोबारा रीफिल कराया ही नहीं जबकि 1.05 करोड़ ग्राहकों ने महज एक से तीन बार रीफिल कराया। इस बारे में तेल मार्केटिंग कंपनियों (गैस कनेक्शन देने वाली सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां) से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खाना या खाना बनाने की आदतों या एलपीजी की कीमतों में होने वाली वृद्धि की वजह से रीफिल कराना कम हुआ है।

इकोनॉमी को गति देने का प्रयास कर रही सरकार : गोयल

- मंत्री ने लोस में गिनाए सरकार के सुधारात्मक कदम
- गोयल ने कहा, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सुधार की दिशा में बड़ा कदम

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में बोलते केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार इकोनॉमी में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने लोकसभा को बताया कि इकोनॉमी को गति देने के लिए कई सेक्टर में सुधार किए गए हैं और यह सिलसिला जारी है। वाणिज्य मंत्री ने उद्योगों से जुड़े कानून में सुधार का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने फाइनेंस विधेयकों, विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक और जीएसटी एक्ट में सुधार के जरिये इकोनॉमी को बल देने का प्रयास किया है। इसके अलावा उन्होंने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को भी सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया।

गोयल ने कहा कि सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स सुधार पर जोर दिया है। इसके लिए कॉरपोरेट टैक्स को 30 से घटाकर 22 परसेंट कर दिया गया है। इसके अलावा नई घरेलू कंपनियों के मामले में कॉरपोरेट टैक्स की दरें घटाकर 15 परसेंट के निचले स्तर तक कर दी गई हैं। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार में वृद्धि होगी। गौरतलब है कि इकोनॉमिक सुस्ती को खत्म करने के लिए सरकार लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है। इसके लिए सरकारी बैंकों को आपस में जोड़ने, बैंकों को आर्थिक सहायता देने और टैक्स में कटौती जैसे प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा आगे भी ऐसे प्रयास किए जाने की बात भी कही जा रही है।

आयोग की नसीहत, उकसावे में न आएं गरीब-अनपढ़

प्रथम पृष्ठ से आगे

गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए राज्यव्यापी दंगों की जांच के गठित नानावटी आयोग ने सरकार और प्रशासन को तमाम नसीहतें भी दी हैं। आयोग ने पुलिस फोर्स की संख्या में इजाफे, उसे आधुनिक प्रशिक्षण देने और हथियारों से लैस करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ स्वार्थी नेता गरीब और अनपढ़ लोगों को उकसाकर हिंसा और उपद्रव को अंजाम देते हैं जिससे लोगों को सतर्क रहना चाहिए।

ये था गोधरा कांड : 27 फरवरी, 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगाकर अयोध्या से लौट रहे 58 कारसेवकों को जलाकर मार डाला गया था। इस घटना के बाद गुजरात के विभिन्न जिलों में दंगे भड़क उठे थे। हिंसा की विभिन्न वारदात में 1,044 लोग मारे गए थे। इनमें 790 मुस्लिम, 254 हिंदू शामिल थे। दंगों के दौरान 223 लापता हुए थे, जबकि 2500 घायल हुए थे। इस मामले से जुड़े गुलबर्ग सोसायटी, नरोदा पाटिया, बेस्ट बेकरी, बिल्किस बानो, दीपड़ा दरवाजा आदि केस खूब चर्चित रहे।

पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को एनसीआर से बाहर करने की सिफारिश

- संसदीय समिति ने एनजीटी के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देने के बजाय स्वच्छ डीजल पर ध्यान देने का निर्देश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आनंद शर्मा (फाइल फोटो)

पुराने और अनफिट वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए संसदीय समिति ने 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर करने के एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने की सिफारिश की है।

कांग्रेस के आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मंत्रालय की इस समिति ने दिल्ली में रोजाना तकरीबन 12 नए माल वाहनों के प्रवेश पर चिंता जताते हुए पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों पर अंकुश के लिए एक सुव्यवस्थित फ्रेट ट्रैफिक रेग्युलेशन पॉलिसी की आवश्यकता निरूपित की है। ऐसे वाहनों को केवल बाहरी सड़कों से गुजरने की अनुमति होनी चाहिए। दिल्ली में 18 फीसद मालवाहक वाहन चलते हैं। समिति ने दिल्ली के यातायात में दिल्ली सरकार और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों की भूमिका का भी विश्लेषण करते हुए विशिष्ट सिफारिशें की हैं। समिति ने गृह मंत्रालय की ओर से 2020 तक प्रस्तावित अल्पकालिक तथा 2025 तक प्रस्तावित दीर्घकालिक कदमों को समय पर लागू करने को कहा है। जबकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिक जोर देने के बजाय स्वच्छ डीजल पर ध्यान देने को कहा है। अन्यथा ऑटोमोबाइल कंपनियों की हालत और खराब होगी। समिति ने शहरी आवासन मंत्रालय से साइकिल जैसे गैर-मोटर वाहनों के यातायात के लिए डेडीकेटेड ट्रैक के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित करने को कहा है। समिति ने दिल्ली में पिछले दस वर्षों के दौरान बसों की संख्या न बढ़ाए जाने पर अफसोस जताया है और दिल्ली सरकार से 6000 बसें तुरंत खरीदने तथा 1000 बसों की पार्किंग के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। समिति के अनुसार यदि दिल्ली पीडब्लूडी चौराहों और सड़कों के डिजाइन में साधारण परिवर्तन करे और बेकार पड़ी सर्विस लेनों को सड़क में मिला दे तो भी यातायात की स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। समिति ने दिल्ली पुलिस से महज ट्रैफिक लाइट के उल्लंघनों पर ध्यान देने के बजाय लेन ड्राइविंग सुनिश्चित कराने, जबकि दिल्ली मेट्रो से यातायात के विभिन्न साधनों के बीच संतुलन स्थापित करने और फीडर बसों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है। डीएमआरसी से किरायों को युक्तिसंगत बनाने की अपेक्षा भी की गई है।

समिति ने अतिक्रमण हटाने में विफलता के लिए डीडीए तथा कंप्यूटर आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट तथा एरिया ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम न लागू कर पाने के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना की है। जबकि दक्षिण एशियाई देशों में ये प्रणालियां 30 वर्ष पहले लागू हो चुकी हैं।

आइआइटी में एमटेक के शुल्क में वृद्धि का फैसला टाला

नई दिल्ली, प्रेट्र : मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने आइआइटी में एमटेक के शुल्क वृद्धि का फैसला टाल दिया है। इस मुद्दे पर आइआइटी परिषद में आगे की चर्चा के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार का यह कदम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में शुल्क वृद्धि के खिलाफ हो रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच सामने आया है।

रमेश पोखरियाल निशंक फाइल

एचआरडी मंत्रालय के अधिकारियों ने हालांकि फैसला रोके जाने के पीछे के कारणों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक परिषद की अगली बैठक की तारीख तय नहीं की गई है।

आइआइटी-दिल्ली के निदेशक वी. रामगोपाल राव ने कहा था कि आइआइटी के एमटेक प्रोग्राम में रिकार्ड 50 फीसद से ज्यादा ड्रापआउट है। इसका कारण यह है कि नौकरी पाने या प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने तक छात्र इस कोर्स को 'ठहराव की व्यवस्था' के रूप में लेते हैं। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता वाली परिषद ने सितंबर में मास्टर प्रोग्राम के लिए शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव किया था। इसे बीटेक कोर्स के स्तर पर लाने का फैसला लिया गया था। यह फैसला आइआइटी में एमटेक प्रोग्राम पर सुधार के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था। आइआइटी परिषद सभी 23 आइआइटी के बारे में फैसला लेने वाला सर्वोच्च निकाय है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

मिली मजबूती

सरकार भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने के प्रयासों में जुटी है, इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ को रोकने और पाकिस्तानी सेना से मुकाबले के लिए फौजियों को अमेरिकी राइफलों से लैस कर दिया गया है

कश्मीर में सेना को मिलीं दस हजार अमेरिकी राइफलें

- पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में आतंकियों पर ढाएंगी कहर
- एसआइजी सौर राइफलों के लिए गोलियां भी मिलनी शुरू

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली, एएनआइ : जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ और पाकिस्तानी सेना से मुकाबला कर रही भारतीय सेना की ताकत और बढ़ गई है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के तहत भारतीय सेना ने 10 हजार अमेरिकी एसआइजी सौर राइफलों का इस्तेमाल अभियानों में शुरू कर दिया है।

भारतीय सेना के एक वरिष्ठतम सूत्र ने बताया कि भारतीय सेना को अपने स्नाइपर राइफलों के लिए गोलियां भी मिलनी शुरू हो गई हैं। 21 लाख से अधिक राउंड की गोलियों का ऑर्डर दिया गया है। मालूम हो कि भारत ने अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं के तहत 72,400 एसआइजी सौर राइफलों का ऑर्डर दिया है।

पहली खेप में 10 हजार सौर 716 असाल्ट राइफलें भारत पहुंचा दी गई हैं और इन्हें नार्दर्न कमांड को भी सौंपा जा चुका है। यह कमांड जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों को देख रही है। यही नहीं यह कमांड पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकियों और पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर से होने वाली घुसपैठ को रोकने का भी काम करती है।

700 करोड़ में राइफल सौदा : इन अत्याधुनिक राइफलों का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में आतंकरोधी अभियान में किया जाएगा। ये राइफलें पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में आतंकियों का काल बनेंगी। भारत ने अमेरिका के साथ 700 करोड़ रुपये की राइफलों की डील की थी। इसके तहत अमेरिका से भारतीय सेना को 72,400 नई असॉल्ट राइफलें मिलनी हैं। ये राइफलें अमेरिका में बनी हैं। फास्ट ट्रैक प्रॉक्योरमेंट के तहत इनकी आपूर्ति एक साल के भीतर होनी है।

एके-203 राइफलें भी मिलेंगी : अमेरिका से खरीदी जाने वाली इन 72,400 राइफलों को तीन भागों में बांटा गया है। इनमें से 66 हजार राइफलें भारतीय सेना को जबकि 2000 राइफलें नौसेना और 4000 भारतीय वायुसेना को मिलनी हैं। एसआइजी सौर राइफलें भारत में बनी 5.5677 (38) 7745 मिमी इंसास राइफलों की जगह लेंगी। यही नहीं भारतीय सेना को सात लाख से अधिक एके-203 असॉल्ट राइफलें भी मिलनी हैं। इससे भारतीय सेना की ताकत में अभूतपूर्व इजाफा होगा। इनका उत्पादन भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के तहत हो रहा है।

DR. RAMASWAMY IAS ACADEMY
FREE COACHING
IAS, SSC, JUDICIARY AND GROUP-A, B & C
SC/ST /EWS/OBC DELHI RESIDENCE ONLY
9350933144, 9958589406
Centre-1 1418, Dr. Mukherjee Nagar, 4th Floor, Main Road, New Delhi-09
Centre-2 4-A/17, Old Rajendra Nagar Main Market, New Delhi-110060

अहम फैसला ▶ कमलनाथ सरकार ने लैंड पूल योजना को दी मंजूरी

मध्य प्रदेश के अधूरे प्रोजेक्टों की जमीन किसानों को वापस होगी

वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 से बढ़ाकर 33 वर्ष की गई, स्थाईकर्मी भी 62 साल में होंगे रिटायर

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश के विकास प्राधिकरणों ने जिन किसानों की जमीन विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित की थी और बरसों से उनमें कोई काम नहीं हुआ या मात्र 10 फीसदी तक हुआ है, ऐसी जमीन किसानों को वापस की जाएगी। बुधवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में कई अहम फैसले किए गए। किसानों को जमीन वापस लौटाने के लिए 46 साल बाद नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में संशोधन करने का बड़ा फैसला लिया। इसके तहत लैंड पुलिंग योजना लागू होगी, जिसमें हजारों एकड़ जमीन किसानों को वापस मिलेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में वर्दीधारी पदों पर भर्ती की अधिकतम आयु सीमा पांच साल बढ़ाकर 33 साल करने और स्थाईकर्मी की सेवानिवृत्ति उम्र 60 की जगह 62 साल करने को भी मंजूरी दे दी।

जमीन के बदले 50 फीसदी विकसित भूखंड मिलेंगे : कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा व नगरीय विकास तथा आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि निर्माण उद्योग की गतिविधियां बंद हो गई हैं। मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा। जमीनें खाली पड़ी हैं। इसे देखते हुए नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में संशोधन करने का फैसला कर लैंड पुलिंग पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसके तहत विकास प्राधिकरणों के ऐसे प्रोजेक्ट, जिनमें कोई काम नहीं हुआ है, उनमें अधिग्रहित किसानों की जमीनें वापस लौटाई जाएंगी। 84 में से ऐसे करीब 66 प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं। वहीं, योजना में अब जो भी प्रोजेक्ट आएगा, उसमें जमीन अधिग्रहण की जगह लैंड पुलिंग योजना के तहत किसानों से जमीन लेकर उसे 50 प्रतिशत विकसित भूखंड दिया जाएगा।

कई अन्य अहम फैसले भी

रिटायरमेंट अब 65 में : अनुदान प्राप्त कॉलेजों के शैक्षणिक स्टाफ की सेवानिवृत्ति आयु 62 की जगह 65 वर्ष रहेगी।

उद्योगों को जमीन : उद्योगों को सेवा देने वाली इकाइयों को भी उद्योग का दर्जा देकर विकसित भूखंड दिए जाएंगे। लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग हब के लिए पहले आओ, पहले पाओ की पद्धति पर जमीन दी जाएगी।

मप्र में मंदिरों के पुजारियों की नियुक्ति प्रक्रिया तय होगी

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार संधारित मंदिरों के पुजारियों का मानदेय बढ़ाने के बाद अब मंदिरों के लिए एक्ट भी लाने की तैयारी कर रही है। देवस्थानों में पुजारियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने संबंधी प्रक्रिया भी तैयार की जा रही है। इसमें पुजारियों की वंश-परंपरा और गुरु-शिष्य परंपरा को प्रमुखता देने का प्रावधान भी रहेगा। प्रदेश में नवगठित अध्यात्म विभाग इन दिनों शासन से संधारित देव स्थानों के लिए अधिनियम बनाने की कवायद में जुटा है। इसके अलावा पुजारियों की नियुक्ति के लिए पात्रता भी तय की जा रही है। इसके साथ ही चयन की प्रक्रिया भी तय की जाएगी। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि न्यूनतम शिक्षा, स्वास्थ्य, उम्र और पूजा विधि की प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया जा रहा है। संबंधित पुजारी के लिए पूजा विधि का पूरा ज्ञान और शाकाहारी होना भी आवश्यक है। आपराधिक चरित्र और मद्यपान की आदत होने पर आवेदन की पात्रता नहीं होगी। यह नियम-शर्तें भी रहेंगी कि किसी भी स्थिति में देव स्थान बिना पूजा के नहीं रहना चाहिए, पुजारी के न होने पर अस्थायी पुजारी की व्यवस्था का प्रावधान रहेगा। देव स्थान की साफ-सफाई के संदर्भ में भी विस्तृत एडवायजरी बनाई जा रही है।

राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के लगेज से मिले 38 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, रांची : रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बुधवार को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के लगेज में 38.5 लाख रुपये मिले। वह इसे लेकर दिल्ली जा रहे थे। सीआइएसएफ की सूचना पर आयकर विभाग की एयर इंटेलिजेंस टीम ने पूरे मामले की छानबीन की और उन्हें रुपयों के साथ दिल्ली जाने दिया और इसकी सूचना दिल्ली की एयर इंटेलिजेंस टीम को दी गई।

दिल्ली में हवाई अड्डा पर उतरने के बाद एयर इंटेलिजेंस ने रुपये के बारे में उनसे विस्तार से पूछताछ की, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद आयकर विभाग, दिल्ली की टीम ने उक्त राशि को जब्त कर लिया है। राज्यसभा सदस्य धीरज साहू रुपयों के बारे में अगर ठोस जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहेंगे, तो वह राशि जब्त कर ली जाएगी।

आयकर विभाग के संयुक्त आयकर निदेशक, (अन्वेषण) रांची मनीष कुमार झा ने बताया कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर सीआइएसएफ ने राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के लगेज में रुपये होने की जानकारी एयर इंटेलिजेंस को दी।

एयर इंटेलिजेंस ने पूरे मामले की छानबीन की और दिल्ली स्थित एयर इंटेलिजेंस को इसकी सूचना देकर राज्यसभा सदस्य धीरज साहू को दिल्ली जाने दिया। दिल्ली में उनसे पूछताछ की गई है। वहां उन्होंने रुपयों के स्रोत के बारे में ठोस जानकारी नहीं दी, जिसके चलते उक्त राशि जब्त कर ली गई।

झारखंड में तीसरे चरण का मतदान आज

महासमर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड विधानसभा चुनाव की तीसरे चरण में गुरुवार को 17 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में रांची, हटिया, कांके, खिजरी सहित 17 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। मतदान के लिए लगभग 40 हजार चुनाव कर्मी लगाए गए हैं। इस चरण में भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कई क्षेत्र नक्सल प्रभावित तथा हजारों बूथ संवेदनशील और अतिसंवेदनशील हैं, इसे ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सभी संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को लगाया गया है। इस वहीं, तीन हेलीकॉप्टर से निगाहबानी होगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए रांची एयरपोर्ट पर एक एयर एंबुलेंस भी तैनात किया गया है।

एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर से बुधवार को हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड के अतिसंवेदनशील बूथों के लिए रवाना होते मतदानकर्मी। जागरण

इनकी प्रतिष्ठा दांव पर

तीसरे चरण में 309 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 56,18,267 मतदाता करेंगे। इनमें 32 महिला तथा 99 निर्दलीय हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो, मंत्री सीपी सिंह, नीरा यादव, पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, जेपी पटेल जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है।

यह भी जानिए

सबसे अधिक 31 उम्मीदवार ईचागढ़ तथा सबसे कम रांची और कांके में महज बारह-बारह हैं।

तीन सीटें ऐसी हैं जहां कोई महिला प्रत्याशी नहीं हैं। इनमें बरकट्ठा, सिमरिया तथा धनवार शामिल हैं। दूसरी तरफ, कांके में कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है।

चार सीटों रामगढ़, बड़कागांव, सिमरिया तथा कांके को छोड़कर सभी सीटों पर वर्तमान विधायक चुनाव लड़ रहे हैं।

सरयू राय के मंत्री पद से इस्तीफे पर विवाद

राज्य ब्यूरो, रांची

मुख्यमंत्री रघुवर दास के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर सुर्खियां बटोरने वाले मंत्री सरयू राय अब नए विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने 17 नवंबर को फैक्स और ईमेल के जरिए राजभवन को इस्तीफा भेजा था, जिसका आज राजभवन ने खंडन कर दिया। राजभवन ने बुधवार को आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, राजभवन को अभी तक उनके मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र संबंधी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही सरयू राय ने मंत्री और विधायक पद से इस्तीफे का दावा किया था। उन्होंने त्यागपत्र की प्रति भी मीडिया को जारी की थी।

राज्यपाल को संबोधित करते हुए उन्होंने पत्र में लिखा था कि वे झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे रहे हैं, जिसे तात्कालिक प्रभाव से स्वीकृत करने की कृपा करें। त्यागपत्र नहीं मिलने की राजभवन की स्वीकारोक्ति के बाद इस मामले में अजीब स्थिति पैदा हो गई है। सरयू राय ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ने के दौरान मंत्री पद और विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र को जनसमर्थन और सहानुभूति हासिल करने का आधार बनाया था।

सरयू राय। फाइल

कैबिनेट सचिवालय और मुख्यमंत्री सचिवालय के पास भी नहीं त्यागपत्र : सरयू राय का त्यागपत्र मंत्रिमंडल सचिवालय और मुख्यमंत्री सचिवालय को भी प्राप्त नहीं हुआ है।

नियम से मंत्रिमंडल से त्यागपत्र मुख्यमंत्री सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय के संज्ञान में होना चाहिए, क्योंकि इसपर फैसले के लिए मुख्यमंत्री की सिफारिश आवश्यक है।

राज्यपाल से मिलकर देंगे त्यागपत्र : **सरयू राय** : सरयू राय का कहना है कि उन्होंने 17 नवंबर को फैक्स और ईमेल के जरिए राजभवन को त्यागपत्र भेजा था। उन्होंने राजभवन के अधिकारियों से मुलाकात का भी वक्त मांगा है, ताकि वे राज्यपाल से मिलकर त्यागपत्र दे सकें। शुक्रवार को वे राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान वे इस्तीफा स्वीकृत करने का आग्रह करेंगे।

चुनाव कार्य से हटाए गए शिकायत करने वाले सीआरपीएफ कमांडेंट

राज्य ब्यूरो, रांची : चुनाव आयोग ने सुविधाओं को लेकर शिकायत करनेवाले सीआरपीएफ के कमांडेंट को चुनाव कार्य से हटा दिया है। उसके विरुद्ध कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही धनबाद के बाघमारा स्थित जोगता थाना के प्रभारी चंदेश्वर प्रसाद सिंह को निलंबित कर दिया है। आयोग ने थाना प्रभारी के विरुद्ध मिली कई शिकायतों तथा पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर थाना प्रभारी के विरुद्ध यह कार्रवाई की। थाना प्रभारी द्वारा आचार संहिता उल्लंघन की लगातार शिकायत आयोग को मिल रही थी। इससे पहले आयोग ने निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय के समर्थक के रेस्टोरेंट में गलत ढंग से छापेमारी करने पर जमशेदपुर स्थित साकची थाना के प्रभारी राजीव कुमार सिंह को निलंबित कर दिया था। चुनाव आयोग ने जवानों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने की शिकायत करनेवाले सीआरपीएफ के कंपनी कमांडेंट को चुनाव कार्य से हटा दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने कहा कि अखबारों में इस आशय की खबर प्रकाशित होने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी एसएसपी तथा आइजी से ली। दोनों पदाधिकारियों ने उनके आरोप को गलत ठहराया। यह भी बात सामने आई कि कंपनी कमांडेंट को इस तरह की गलत शिकायत करने की आदत है और पहले भी ऐसी हरकतें की है। उनके विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश भी सीआरपीएफ के शीर्ष पदाधिकारियों को दिया गया है।

खेमका ने हरियाणा में भ्रष्टाचार खत्म होने के दावों पर उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा के वरिष्ठ और चर्चित आइएएस अधिकारी अशोक खेमका ने प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार खत्म करने के दावों पर कटाक्ष किया है। खेमका ने ट्वीट के जरिये कहा कि 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। सच कहूं तो सच्चाई का अनुभव नहीं हुआ। क्या ऐसे आयोजनों से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? सरकार सिर्फ यही पता लगा ले कि आयोजन में कुल कितना खर्च हुआ।

अशोक खेमका का यह ट्वीट काफी कुछ बयां कर रहा है। राज्य सरकार ने 9 दिसंबर को पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प लिया था। साथ ही एक वाट्सएप नंबर जारी कर जनता से भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना देने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए थे कि किसी भी तरह की रेड बिना कैमरे के नहीं मारी जा सकेगी।

खेमका चर्चित अधिकारी हैं। कांग्रेस सरकार में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को जमीनों के लाइसेंस देने के मामले में खेमका ने नियमों की अनदेखी का मुद्दा उठाया था। तब वह राष्ट्रीय फलक पर चर्चा में आए थे।

कौशल्या मंदिर निर्माण पर योगी ने छत्तीसगढ़ सरकार को सराहा

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम (बीच में) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (दाएं) को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आमंत्रण दिया। बाएं हैं छत्तीसगढ़ के संचालक, समग्र शिक्षा, पी दयानंद। सौ. डीपीआर

नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ में 27 से 29 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का न्योता लेकर बुधवार को स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। योगी ने नृत्य महोत्सव की शुभकामनाएं दी। मंत्री प्रेमसाय ने बताया कि जब सीएम योगी को भगवान राम के ननिहाल रायपुर के चंद्रखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर के जीर्णोद्धार और राम वन गमन पथ के विस्तार की छत्तीसगढ़ सरकार की योजना बताई गई तो उन्होंने सरकार की सराहना की। इस दौरान योगी ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में पूजा के लिए चढ़ाए जाने वाले फूलों का उपयोग अगरबत्ती और धूप बनाने में किया जा रहा है। उन्होंने यह काम छत्तीसगढ़ में भी करने का सुझाव दिया। सुझाव दिया कि भविष्य में कौशल्या मंदिर में कोई आयोजन किया जाए, तो उसमें उत्तरप्रदेश सरकार की सहभागिता भी सुनिश्चित करने का प्रयास हो।

आजम और शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, रामपुर : यतीमखाना प्रकरण में सांसद आजम खां, शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी, पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में इन सभी को एक सप्ताह में बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है।

शहर कोतवाली पुलिस ने यतीमखाना प्रकरण में 12 मुकदमे दर्ज किए थे। इन सभी में आजम व आले हसन खान नामजद हैं। कई मामलों में वसीम रिजवी और जुफर फारूकी भी नामजद हैं। इन पर गैर इरादतन हत्या, मकान तोड़ने, जमीन कब्जाने, गाय चोरी, भैंस व बकरी चोरी के आरोप हैं। पुलिस ने पहले भी आजम को नोटिस जारी किया था, लेकिन वह बयान दर्ज कराने नहीं आए। इस मामले में आजम के करीबी ठेकेदार इस्लाम को पुलिस तीन दिन पहले गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। शहर कोतवाल राज कुमार शर्मा ने बताया कि नोटिस डाक से भेजे गए हैं। उनके घरों पर पुलिस कर्मी भी नोटिस लेकर गए हैं। सांसद के अलावा अन्य नामजद आरोपितों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

इमरान की भाषा बोल रही कांग्रेस : शिवराज

जागरण संवाददाता, धनबाद

कांग्रेस व विपक्षी दल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भाषा बोल रहे हैं। यह कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान का। वे बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चौहान ने कहा कि पाकिस्तान में जहां प्रतिदिन हिंदू महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है, अल्पसंख्यकों की हत्याएं हो रही हैं। उस देश के पीएम को हमारे देश में मानवाधिकार हनन की चिंता हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस और मानवाधिकार वादी उसके बयान के आधार पर हाय-तौबा मचा रहे हैं।

शिवराज ने कहा कांग्रेसनीत महागठबंधन भ्रष्टाचारियों की जमात है। झामुमो, कांग्रेस, राजद ने कोड़ा को सीएम बनाया और राज्य में लूट मचाई। 2014 तक कांग्रेस ने सरकार चलाई और भ्रष्टाचार के मामले अभी तक खुल रहे हैं। कांग्रेस शुरू से ही धोखेबाज पार्टी है। झारखंड में आदिवासियों के मसीहा आदिवासियों की जमीन लूटकर अपना घर भरने में लगे हैं। पहली बार पिछले पांच सालों में स्थायी सरकार रही और लोगों ने विकास की गति देखी।

जामताड़ा के नाला प्रखंड में चुनावी सभा को संबोधित करते शिवराज सिंह चौहान। जागरण

सरयू स्वभाव से ही विरोधी

एक सवाल के जवाब में शिवराज ने कहा कि सरयू स्वभाव से ही विरोधी हैं। सरकार में रहते भी वे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। जब अति हो गई तो पार्टी ने एक्शन लिया।

भाजपा ने दी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार

गिरिडीह : जमुआ प्रखंड क्षेत्र के कौआआम मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि आपने रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाई और पांच साल भ्रष्टाचार मुक्त व विकासयुक्त स्थिर सरकार मिली। अब देश बदल गया है। मोदी के नेतृत्ववाली सरकार में कोई भारत के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने लोगों को मामा और भांजा के रिश्ते से जोड़ते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में लोग मुझे मामा कहते हैं। यहां भी जनता के साथ मेरा वही रिश्ता है। कहा कि झारखंड में नक्सलवाद था। शाम को यहां घूम नहीं सकते थे। आज लोग सरेआम घूम रहे हैं। इस बार फिर हमारी सरकार बनी तो नक्सलवाद को नेस्तनाबूद कर देंगे।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नहीं किया एक भी वादा पूरा : शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने न तो किसानों का कर्जा माफ किया न ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया। बावजूद इसके यहां आकर वे फिर से वही वादे कर रहे हैं। ये पूरी तरह धोखेबाज पार्टी है।

शिवराज ने कर्नाटक को देखते हुए मध्य प्रदेश में तख्तापलट की किसी भी संभावना को खारिज किया है। उन्होंने कहा वहां ढाई मुख्यमंत्री की सरकार है। ये कमलनाथ, दिग्विजय और सिंधिया हैं। ये स्वयं में लड़ते रहते हैं।

सक्रिय राजनीति में आएंगे भीम आर्मी के चंद्रशेखर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने अब सक्रिय राजनीति में उतरने की तैयारी की है। जल्द ही वह अपने नए राजनीतिक दल का एलान करेंगे। चंद्रशेखर ने बताया कि लखनऊ में वह पार्टी का ऑफिस बनाएंगे, जिला पंचायत व विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे और प्रदेश की राजनीति में मजबूत विकल्प बनेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति से उभरे चंद्रशेखर बुधवार को राजधानी में पहली बार अपने सियासी एजेंडे के साथ मौजूद थे। वीवीआइपी गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता की अनुमति न मिलने के बाद गोमतीनगर के एक आवास में पत्रकारों से बातचीत में चंद्रशेखर ने बताया कि वह अब सक्रिय राजनीति में आएंगे और बहुजन समाज के लिए राजनीतिक दल बनाएंगे। कहा कि उनकी पार्टी भाजपा से लड़ेगी और उसे सत्ता से बाहर करेगी। उन्होंने बताया कि बसपा के साथ तालमेल पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है लेकिन, बसपा चाहेगी तो राजनीति में साथ आएंगे। किसानों, दलितों व बहुजन समाज की समस्याओं को लेकर उन्होंने विधानभवन के घेराव की भी चेतावनी दी। साथ ही नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन करने का एलान किया।

भाजपा के हिंदुत्व के जवाब में बंगाली हस्तियों की प्रतिमाएं स्थापित करेगी तृणमूल कांग्रेस

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- नगर निकाय चुनाव से पहले धर्मनिरपेक्षता व समावेशिता के संदेश का करेगी प्रचार
- क्राउड फंडिंग का होगा इस्तेमाल, 20 से 30 लाख रुपए का आएगा खर्च

ममता बनर्जी। फाइल

तीन विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में मिली जीत के बाद अब तृणमूल कांग्रेस की नजर अगले साल होने वाले 107 नगर निकाय चुनाव पर है। इस चुनाव को 2021 विधानसभा चुनाव से पहले का मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जा रहा है। इसी के साथ कोलकाता नगर निगम के लिए भी होने हैं ऐसे में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को मात देने के लिए मशहूर बंगाली हस्तियों की प्रतिमाएं लगाने और धर्मनिरपेक्षता और समावेशिता के संदेश के प्रचार में लगी है।

तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमने बंगाल की महान हस्तियों की प्रतिमाएं राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने सदियों से धर्मनिरपेक्षता और समावेशिता का प्रचार किया है। उनके संदेश प्रतिमाओं की पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण किए जाएंगे।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर रवींद्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, राजा राममोहन राय से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर तक की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। उनके अलावा उत्तम कुमार, सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक जैसी फिल्मी हस्तियां और गोष्ठ पाल और सैलेन मन्ना जैसे फुटबॉल खिलाड़ियों की प्रतिमाएं भी शहर के विभिन्न हिस्सों में लगाईं जाएंगी।

इन प्रतिमाओं को लगाने का लक्ष्य भाजपा के आक्रामक हिंदुत्व एजेंडे का जवाब देना है। तृणमूल के वरिष्ठ नेता एवं कोलकाता नगर निगम के उप महापौर अतीन घोष ने कहा कि यह हमारे सौंदर्यीकरण अभियान का हिस्सा है। लेकिन साथ ही हम धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सुधार और समावेशिता के संदेश का प्रचार भी करना चाहते हैं, जिनका राज्य की इन महान हस्तियों ने प्रचार किया और उसके साथ खड़े रहे। अब समय आ गया है कि हम उनकी दी शिक्षा को याद करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलें।

उन्होंने कहा कि हमने देखा कि इस साल मई में भाजपा ने विद्यासागर की आवक्ष प्रतिमा तोड़ी थी। यह उनकी बंगाल विरोधी भावना और हमारी महान हस्तियों के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है। पार्टी नेता ने कहा कि इस अभियान में 20 से 30 लाख रुपए का खर्च आएगा। इस राशि को तृणमूल नेताओं ने लोगों से एकत्रित (क्राउड फंडिंग) किया है।

बड़ा मामला

आइपीएस भारती अरोड़ा के नेतृत्व में कमेटी अनुसूचित जाति के अफसरों की अनदेखी मामले की करेगी जांच, पुलिस महकमे के बाद आइएएस अधिकारियों का भी मांगा गया ब्योरा

हरियाणा में अफसरों की अनदेखी पर कमेटी गठित

दीपक बहल, अंबाला

प्रदेश में अनुसूचित जाति के इंस्पेक्टरों की अनदेखी के मामले में उलझी राज्य सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। आइपीएस भारती अरोड़ा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिनमें एक कानूनी विशेषज्ञ भी शामिल है। इंस्पेक्टरों के अलावा प्रदेश में आइपीएस अधिकारियों की तैनाती का मामला अभी उलझा पड़ा है। इसी बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने आइएएस अफसरों की तैनाती को लेकर मुख्य सचिव से ब्यौरा मांग लिया है।

डीजीपी मनोज यादव ने इंस्पेक्टरों के मामले में कमेटी गठित कर दी है, जबकि आइपीएस और आइएएस का मामला सीधे सरकार से जुड़ा होने के कारण लंबित है। जांच रिपोर्ट की तारीख तय नहीं की गई है, जबकि जल्द ही रिपोर्ट सबमिट करने के आदेश हैं। दैनिक जागरण ने भी अनुसूचित जाति के अधिकारियों की अनदेखी का मामला प्रकाशित किया था।

जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गत 12 अक्टूबर को डीजीपी हरियाणा मनोज यादव को पत्र लिखकर पूछा था कि प्रदेश में एससी वर्ग से संबंधित इंस्पेक्टर रैंक के अफसर, जो एसएचओ तैनात किए गए हैं, का ब्यौरा दिया जाए।

प्रत्येक जिला के अनुसार इसे लेकर जानकारी मांगी, जो विभिन्न बिंदुओं पर थी। इनमें इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों के प्रदेश स्तर पर हुए पांच ट्रांसफर आदेशों की प्रतिलिपि के अलावा प्रदेश स्तर पर इंस्पेक्टर रैंक पर ट्रांसफर करने वाले अधिकारी का रैंक, जो इसके लिए अधिकृत हो, जिला स्तर पर एसएचओ की तैनाती करने वाले अधिकारी का रैंक व पुलिस कमिश्नरी में एसएचओ की पोस्टिंग करने वाले अधिकारी के रैंक की जानकारी मांगी गई थी। इसके लिए बाकायदा फारमेट भी भेजा गया है।

प्रदेश में हैं 646 इंस्पेक्टर

आंकड़ों की बात करें, तो प्रदेश में इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की संख्या 646 है। इनमें से एससी इंस्पेक्टरों की संख्या 75 है। थाना प्रभारी के रूप में 269 इंस्पेक्टरों की तैनाती है, जिनमें से एससी वर्ग के एसएचओ की संख्या 30 है। पुलिस मुख्यालय से जो रिपोर्ट आयोग को भेजी गई थी, उसके मुताबिक कई जिलों में एससी वर्ग के थाना प्रभारी जिलों में तैनात नहीं थे, जिसे लेकर आयोग ने नाराजगी जताई थी। इनमें चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हांसी, हिसार, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़ शामिल हैं।

आइपीएस की तरह आइएएस पर भी मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में पुलिस महकमे का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि अब आइएएस को लेकर भी आयोग ने रिपोर्ट मांग ली है। यह रिपोर्ट 22 नवंबर 2019 तक आईएएस अफसरों की तैनाती की तलब की है। इस बारे में आयोग ने मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है। इस मामले में पहले भी रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर दिए गए आंकड़ों पर आयोग ने नाराजगी जताई थी। आयोग ने इस को लेकर 20 दिसंबर 2019 तक रिपोर्ट तलब की है। पूछा गया है कि प्रदेश में कितने मंडल और जिलों में एससी वर्ग के आयुक्त अथवा उपायुक्त की तैनाती है।

छग में नक्सल क्षेत्रों में आदिवासियों पर दर्ज मुकदमों की वापसी शुरू

नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासियों पर दर्ज फर्जी मामलों को सरकार ने वापस लेना शुरू कर दिया है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री के भावनाओं के अनुरूप आठ मार्च को उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एके पटनायक (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समीक्षा समिति का गठन किया गया था। समिति की अनुशंसा पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों को वापस लिया गया। विधि विभाग द्वारा आठ जिलों के कलेक्टरों से प्रकरणों को वापस लिए जाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। पटनायक की अध्यक्षता में समिति की पहली बैठक 24 अप्रैल और दूसरी बैठक 30 एवं 31 अक्टूबर को हुई। इसमें आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 313 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा की गई।

प्रियंका गांधी का योगी को पत्र किसानों को दिलाएं सही दाम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- कांग्रेस महासचिव ने उठाया गन्ना और धान का सही मूल्य न मिलने का मुद्दा
- हाल ही में मैनपुरी की घटना में न्याय के लिए भी लिखा था मुख्यमंत्री को खत

प्रदेश की राजनीति में लगातार सक्रियता बढ़ा रहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने पंद्रह दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरा पत्र लिखा है। अब उन्होंने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए उन्हें फसलों के सही दाम दिलाने का आग्रह किया है।

प्रियंका ने बुधवार को लिखे पत्र में कहा है कि आपकी सरकार ने अभी गन्ना मूल्य घोषित किया है। आश्चर्य है कि पिछले पेराई सत्र से गन्ना मूल्य एक रुपया भी नहीं बढ़ा है, जबकि आपकी सरकार में खाद का दाम दोगुना हो गया। बिजली के बिल में लगातार वृद्धि हुई है। निराई-गुड़ाई में मजदूरी बढ़ी है। किसानों की लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपया भी बकाया है। प्रियंका ने धान का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने लिखा है कि सरकार ने धान मात्र 1850 रुपया प्रति क्विंटल खरीदने की घोषणा की है। धान के किसानों की भी लागत लगातार बढ़ी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि प्रदेश का किसान संकट की घड़ी में है। उसे उसकी लागत भी नहीं मिल पा रही है। किसानों के दर्द और संघर्ष को समझते हुए सरकार का कर्तव्य बनता है कि उन्हें उनकी फसलों के सही दाम दिए जाएं।

पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव ने मैनपुरी नवोदय विद्यालय छात्रा प्रकरण में कार्रवाई को लेकर योगी को पत्र लिखा था, जिस पर तुरंत कार्रवाई भी हुई थी।

नागरिकता विधेयक पर चर्चा में राजग हुआ हमलावर

बैकफुट पर पहुंचाया ▶ नागरिकता पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयानों का हवाला देकर कांग्रेस को घेरा

भाजपा ने दिग्गज नेताओं को उतारकर विपक्षी दलों को दिया जवाब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान भाजपा समेत उसके घटक दलों ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सरकार की तरफ से विपक्षी सदस्यों के तर्कों व बयानों के खिलाफ जवाब देने के लिए भाजपा ने अपने सधे हुए सदस्यों को उतारा। भाजपा नेता व पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राज्यसभा में दिए गए एक बयान का जिक्र कर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया।

नड्डा ने पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों की दयनीय दशा का विस्तार से जिक्र करते हुए कांग्रेस की आशंकाओं पर उसे आड़े हाथों लिया। विधेयक की मंशा पर कांग्रेस के सवाल खड़ा करने पर नड्डा ने राज्यसभा में 18 दिसंबर, 2003 को दिया गया मनमोहन सिंह का बयान पढ़ दिया। सदन में उस समय मनमोहन सिंह ने कहा था, 'विभाजन के बाद बांग्लादेश जैसे देशों से बहुत सारे लोग भारत आए थे। यह हमारा नैतिक दायित्व है कि अगर परिस्थितियां इन दुर्भाग्यशाली लोगों को भारत में शरण लेने के लिए बाध्य करें तो हमारा रवैया इनके प्रति और अधिक उदार होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि उप प्रधानमंत्री नागरिकता कानून से संबंधित भविष्य के कदम उठाते समय इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे।' नड्डा ने कहा कि पार्टी का स्टैंड स्थान बदलने से नहीं बदल जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ऐसा ही कर रही है, जो उचित नहीं है। भाजपा नेता ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की साल दर साल घट रही संख्या पर सदन का ध्यान आकर्षित किया। उनके साथ वहां होने वाले उत्पीड़न का ब्योरा भी विस्तार से दिया। पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर विपक्ष की आशंकाओं पर नड्डा ने कहा कि सबकी पहचान बरकरार रहेगी। इन राज्यों में 'इनर लाइन परमिट' का प्रावधान जारी रहेगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा ने विपक्ष को बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस की निष्ठा केवल एक परिवार के लिए है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों देशवासियों के साथ-साथ देश के अंदर और बाहर दोनों जगहों के अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम कर रहे हैं।'

राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर बोलते भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा। साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (दाएं) और गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (शाह के पीछे)। प्रेट्र

विपक्ष को उसके बयानों से ही घेरा

भाजपा नेता भूपेंद्र यादव कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से विधेयक के प्रावधानों की आलोचना पर जमकर बरसे। यादव ने इस मसले पर विपक्षी नेताओं के बयानों का तिथिवार जिक्र उन्हें कठघरे में खड़ा किया। इनमें तीन जून, 2012 को माकपा नेता प्रकाश करात के पत्र का हवाला देकर वामपंथी नेताओं का दोहरापन उजागर किया। करात ने पत्र लिखकर बांग्लादेश से आए लोगों को मानवाधिकार के चलते नागरिकता की जरूरत बताई थी। यादव ने कहा कि करात ने पश्चिम बंगाल में चुनाव को नजदीक देखकर यह दांव खेला गया था। भाजपा ऐसा करने में यकीन नहीं रखती है।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों की ओर से उठाए गए कानूनी मुद्दों पर एक-एक कर जवाब देते हुए उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया। उन्होंने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का जिक्र करते हुए विपक्ष से कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पूरी तरह संविधान सम्मत बनेगा। प्रसाद ने कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों पर कहा कि हमारी सरकार में हर विधेयक कानून मंत्रालय से विचार करने के बाद ही लाया जाता है। प्रसाद ने विपक्ष से पूछा कि पीड़ित लोगों को जगह और उन्हें मानवीय हक देना कैसे असंवैधानिक हो सकता है।

भ्रम फैलाने वालों पर बरसे सांसद: जद (यू) के नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि मुस्लिमों को डरने की बात करने वालों की बातें बेबुनियाद हैं। राजग सरकार के दौरान मुस्लिमों का वैसे ही विकास हो रहा है, जैसे अन्य समुदायों का हुआ है। एआइडीएमके की नेता विजिला सत्यनाथ ने विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार से यहां रहने वाले तमिल शरणार्थियों को दोहरी नागरिकता देने का आग्रह किया। भाजपा सदस्य केजे अलफांस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करने वालों पर हमलावर अंदाज में कई सवाल पूछे। शिरोमणि अकाली दल के नेता सरदार बलविंदर सिंह भुंडर ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा, 'देशहित में सिखों ने काम किया है। बाहर से आने वाले सिखों को शरण के साथ नागरिकता मिलनी चाहिए। 31 दिसंबर, 2014 के बाद आने वाले सिखों को भी यह लाभ मिलना चाहिए।' सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता हिस्सेला चुंगप्पा ने समर्थन देने के साथ कहा कि इस विधेयक से पूर्वोत्तर के राज्यों को जो सुरक्षा दी गई है, वह बंगाल एक्ट के तहत है। यही सुरक्षा कवच सिक्किम के लोगों को भी मिलना चाहिए।

विधेयक पर पाकिस्तान की भाषा बोल रहा विपक्ष : मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल नागरिकता संशोधन बिल पर बिना कामा फुलस्टाप बदले पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि बुधवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर कुछ राजनीतिक दलों के नेता वैसी ही भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जैसी भाषा का उपयोग पाकिस्तान करता है और पार्टी सांसदों को इससे जनता को अवगत कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और यह धार्मिक प्रताड़ना के पीड़ित शरणार्थियों को स्थायी राहत देगा।

गौरतलब है कि लोकसभा ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी थी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन के लिए पात्र बनाने का प्राविधान है।

पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी सांसद आगामी बजट के बारे में समाज के विभिन्न वर्गों की राय लें और इसके बारे में वित्त मंत्री को बताएं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले छह महीने में सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जा संबंधी प्राविधानों को समाप्त करने, अर्थव्यवस्था की मजबूती, किसानों सहित विविध क्षेत्रों में 'ऐतिहासिक कार्य' किए हैं और पार्टी सांसद इन कार्यों को जनता के बीच ले जाएं। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक उपचुनाव में भाजपा की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश की जनता, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और प्रदेश नेतृत्व को बधाई भी दी।

नई दिल्ली में बुधवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एएनआइ

विपक्ष ने सरकार पर लगाया हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- विधेयक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने वाला : आजाद
- भारत का कोई मुसलमान आपसे नहीं डरता, न मैं डरता हूं : सिब्बल

नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को संविधान की मूलभावना के खिलाफ बताते हुए विपक्ष ने बुधवार को सरकार पर तीखा हमला बोला। विधेयक को जहां हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया, वहीं संविधान के अनुच्छेद-14 के मूल अधिकारों और समानता के अधिकारों का उल्लंघन बताया। साथ ही विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की भी मांग की।

राज्यसभा में विधेयक पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने वाला विधेयक है। इसमें सिर्फ तीन देशों के चुनिंदा धर्मों के लोगों को नागरिकता देने की ही बात क्यों? उन्होंने कहा कि श्रीलंका, भूटान और म्यांमार में भी हिंदू रहते हैं, उन्हें क्यों नहीं? इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान के मुस्लिमों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां मुस्लिम महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है फिर उन्हें विधेयक में शामिल क्यों नहीं किया गया।

कांग्रेस की ओर से चर्चा में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस विधेयक के जरिये हिंदुत्व के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। जो गलत है। देश सभी धर्म के लोगों का है। कांग्रेस के ही आनंद शर्मा ने कहा कि किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र संविधान से ऊंचा नहीं हो सकता। उन्होंने सरकार से राजहठ छोड़कर विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। कपिल सिब्बल ने कहा, गृह मंत्री ने कहा कि मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान आपसे नहीं डरता। न मैं डरता हूं। हम डरते हैं तो संविधान से डरते हैं।

राज्यसभा में शिवसेना के तेवर भी अलग दिखे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हम कितने कठोर हिंदू हैं, इसके लिए हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमने अनुच्छेद 370 पर आपका समर्थन किया, लेकिन नागरिकता विधेयक को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले देश के नागरिक हैं, वे कोई देशद्रोही नहीं हैं। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उसके हम हेडमास्टर हैं। हमारे स्कूल के हेडमास्टर बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने विधेयक को भारत विरोधी और बंगाल विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस सरकार की नीति तीन मुख्य बातों पर टिकी है- झूठ, झांसा और जुमला। एनआरसी पर उन्होंने कहा कि जो एक राज्य में सफल नहीं हो सका, उसे 27 राज्यों में लागू करने की बात की जा रही है। लेकिन बंगाल में इसे कहीं भी लागू नहीं होने देंगे।

आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सरकार से पूछा कि क्या वे घुसपैठियों का कोई अलग देश बनाने जा रहे हैं। वैसे भी देश को तोड़ने की आपकी संस्कृति है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने सवाल किया कि विधेयक में नागरिकता के लिए 31 दिसंबर, 2014 की कटऑफ तिथि क्यों रखी गई है।भाकपा के विनोय विस्वम ने कहा कि नागरिकता उनके धर्म को देखकर नहीं दी जा सकती। यह हिंदुत्व के एजेंडे की ओर ले जाने वाला विधेयक है।समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह कानून की नजर में ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इससे हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना-देना नहीं है।

पूर्वोत्तर के 'नस्ली सफाये' का प्रयास है कैब : राहुल

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर आरोप लगाया, 'कैब मोदी-शाह सरकार की ओर से पूर्वोत्तर के नस्ली सफाये का प्रयास है। यह पूर्वोत्तर के लोगों, उनकी जीवन पद्धति और भारत के विचार पर हमला है। मैं पूर्वोत्तर के लोगों के साथ खड़ा हूं और उनकी सेवा के लिए हाजिर हूं।'

निकट भविष्य में कैब को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी : सिंघवी

नई दिल्ली, प्रेट्र : वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक को निकट भविष्य में अदालत में चुनौती दी जाएगी क्योंकि संवैधानिकता के दृष्टिकोण से यह बेहद संदेहास्पद है। उनसे पहले पार्टी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने भी कहा था, 'हम सभी संभावनाओं को टटोलेंगे।'

चार वर्षों में 2903 पाक-अफगान नागरिकों को मिली नागरिकता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: नागरिकता कानून में संशोधन से पहले भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जा रही है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले चार वर्षों में इन दोनों देशों से आए तीन हजार से अधिक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी गई है। इनमें अकेले 2019 में इन दोनों देशों से आए 917 हिंदुओं और सिखों को नागरिकता दी गई है। राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2018 के पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान से नागरिकता पाने वालों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और इसाई समुदाय के लोगों का आंकड़ा अलग से नहीं रखा जाता था। 2018 में इसे अलग से रखने का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि 2016 से 2018 के बीच तीन वर्षों में पाकिस्तान से आने वाले कुल 1595 और अफगानिस्तान से आने वाले कुल 391 लोगों को नागरिकता दी गई है। वहीं नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 566 मुस्लिमों को भी भारत की नागरिकता दी गई है।

बांग्लादेश ने कहा, नागरिकता कानून से भारत की पंथनिरपेक्ष छवि कमजोर होगी

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक से भारत की ऐतिहासिक पंथनिरपेक्ष छवि कमजोर होगी। उन्होंने अपने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताए जाने के आरोपों का भी खंडन किया।

उल्लेखनीय है कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक में 31 दिसंबर 2014 तक भारत में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से धार्मिक आधार पर सताए जाने के कारण आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।

मोमेन ने कहा, 'ऐतिहासिक रूप से भारत सहिष्णु देश है जो पंथनिरपेक्षता में भरोसा करता है लेकिन यह छवि कमजोर होगी अगर वे इससे हटेंगे।' उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के मित्रवत संबंध हैं और इसे द्विपक्षीय संबंधों का 'सुनहरा अध्याय' करार दिया जाता है। इसलिए स्वभाविक है कि हमारे लोग (बांग्लादेशी) उम्मीद करते हैं कि भारत ऐसा कुछ नहीं करे जिससे उनमें व्यग्रता पैदा हो।' मोमेन ने भारत के गृहमंत्री के बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के सताए जाने के आरोप को झूठ करार दिया। उन्होंने कहा, 'जिन्होंने भी उन्हें यह सूचना दी वह सही नहीं है।' उन्होंने कहा, 'हमारे देश के कई अहम फैसले विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की ओर से लिए जाते हैं... हम किसी का भी आकलन उनके धर्म से नहीं करते।'

मोमेन कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व भी उनके दावे की पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश धार्मिक सौहार्द को कायम रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार मिलें। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा कि गुरुवार को उन्होंने ढाका में अमेरिकी राजदूत अर्ल आर मिलर से बात की और उन्होंने भी नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर चिंता जताई।

जनमत
मुद्दा

क्या नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत तीन पड़ोसी मुल्कों के गैरमुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का सरकार का प्रस्ताव उचित है?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे 10 सांसद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राज्यसभा में बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक पर वोटिंग के दौरान सदन से 10 सदस्य अनुपस्थित रहे। हालांकि इनमें से शिवसेना के तीनों सांसद सदन में चर्चा के दौरान मौजूद थे, लेकिन वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जो अन्य सात सदस्य अनुपस्थित थे, उनमें से ज्यादातर खराब स्वास्थ्य के चलते नहीं आए थे। सभी ने सदन को इसकी पूर्व सूचना दी थी।

अनुपस्थित रहे सदस्यों में एनसीपी के दो सदस्य माजिद मेनन और वंदना चौहान के अलावा सपा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा, भाजपा सांसद अनिल बलूनी, असंबद्ध सदस्य अमर सिंह, निर्दलीय सदस्य वीरेंद्र कुमार और एक अन्य निर्दलीय सदस्य शामिल थे। बता दें कि राज्यसभा में मौजूदा समय में शिवसेना के कुल तीन सदस्य हैं, इनमें संजय राउत, राजकुमार धूत और अनिल देसाई शामिल हैं। यूं तो कांग्रेस का दबाव था कि वह विपक्ष में वोट करे लेकिन शिवसेना ने वोटिंग से बायकाट किया। पार्टी के रुख को सही ठहराते हुए राउत ने कहा कि सरकार ने विधेयक को लेकर पार्टी की चिंताओं का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।

मुस्लिमों के लिए रास्ता बंद नहीं

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि मुसलमानों को देश में शरण मांगने का रास्ता बंद नहीं किया गया है। मोदी सरकार इन तीनों देशों में व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित होने वाले मुसलमानों की भी चिंता करती है और पिछले पांच वर्षों में वहां से आने वाले 566 मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी गई है। उन्होंने विपक्ष पर पंथनिरपेक्षता को सीमित दायरे में देखने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे सिर्फ मुसलमान को शामिल होने को ही पंथनिरपेक्षता मानते हैं। भारत को मुस्लिम मुक्त करने के आरोपों पर गृह मंत्री ने कहा कि ऐसी बचकानी बातें विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। शाह ने कहा कि यह देश मुसलमान मुक्त नहीं होगा क्योंकि हमारा एक ही धर्म है, वह है संविधान, जो देश को कभी भी मुस्लिम मुक्त बनाने की इजाजत नहीं देता।

मुस्लिम विरोधी नहीं है सरकार : कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करने के लिए एक के बाद एक विधेयक लाने के आरोप का अमित शाह ने तीखा प्रतिकार किया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370, तीन तलाक और नागरिकता कानून में संशोधन मुस्लिम विरोधी नहीं हैं। मोदी सरकार ने मुस्लिम माताओं व बहनों को उनका अधिकार दिया है। इसी तरह से कश्मीर में मुस्लिम के अलावा हिंदू, सिख, जैन व बौद्ध सभी धर्म को मानने वाले रहते हैं। अनुच्छेद 370 हटाने को मुस्लिम विरोधी कैसे बताया जा सकता है। इसी तरह नागरिकता कानून में संशोधन किसी को नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है।

दो रेलवे स्टेशनों को लगाई आग

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि असम में प्रदर्शनकारियों ने बुधवार रात डिब्रूगढ़ के चाबुआ रेलवे स्टेशन और तिनसुकिया जिले के पानीटोला रेलवे स्टेशनों को आग लगा दी। डिब्रूगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का गृह नगर है।

प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच राज्य सचिवालय के सामने झड़प भी हुई। । त्रिपुरा की राजधानी में भी ऐसी ही घटनाएं हुई हैं। असम की राजधानी दिसपुर में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को फायरिंग तक करनी पड़ी। असम में प्रदर्शन के चलते परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और 31 ट्रेनों को रद या उनका गंतव्य बदल दिया गया है।

इस बीच, त्रिपुरा में कांग्रेस ने गुरुवार को बंद का आह्वान किया है, हालांकि असम में किसी पार्टी या छात्र संगठन ने बंद का आह्वान नहीं किया है जबकि प्रदर्शकारियों में ज्यादातर छात्र हैं।

प्रशांत किशोर ने जदयू नेतृत्व को फिर दी नसीहत, 2015 के चुनाव परिणाम पर सोचें

राज्य ब्यूरो, पटना

नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के समर्थन के सवाल पर जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर नेतृत्व को फिर नसीहत दी कि समर्थन देने से पहले कुछ देर के लिए 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सोचें। लोगों ने किस आस्था और विश्वास के साथ जदयू के पक्ष में मतदान किया था। वहीं, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद बशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि पार्टी में पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मर्यादा का पालन किया जाता है। किसी भी निर्णय से पहले विचार किया जाता है। संबंधित लोगों की राय ली जाती है। लेकिन, एक बार अगर कोई फैसला हो गया तो दल से जुड़े हर आदमी को उसका सम्मान करना चाहिए। प्रशांत किशोर (पीके) का यह ट्वीट बुधवार के दिन करीब तीन बजे आया। उससे पहले राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता आरसीपी सिंह विधेयक के पक्ष में बोल चुके थे। नई बात यह है कि जदयू विधायक मुजाहिद आलम ने भी विधेयक को समर्थन दिए जाने का विरोध किया है।

दो दिन पहले भी किया था ट्वीट : विदित हो कि दो दिन पहले भी पीके ने अपने ट्वीट में इस विधेयक के समर्थन के फैसले पर विचार करने की राय दी थी। उस दिन लोकसभा में विधेयक पेश किया गया था। वहां जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने विधेयक के समर्थन में भाषण किया। रात में जदयू सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान भी किया। इस बीच कोचाधामन से जदयू के विधायक मुजाहिद आलम ने कहा कि वह विधेयक के समर्थन के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने इतना तक कहा कि मैं नहीं कह सकता कि अगली बार चुनाव लड़ूंगा भी या नहीं।

पार्टी फोरम पर रखें बात : बुधवार को प्रदेश जदयू अध्यक्ष ने पीके का नाम लिए बगैर कहा कि हर किसी को अपनी निजी राय जाहिर करने का अधिकार है। यह लोकतंत्र की खासियत है। लेकिन, किसी मसले पर विचार के लिए पार्टी में फोरम होता है। यह आदर्श स्थिति होती है कि पार्टी से जुड़े लोग उस फोरम पर अपनी बात रखें। निर्णय होने के बाद उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है।

प्रशांत किशोर। फाइल

विरोध में बिहार में सड़क पर उतरा महागठबंधन

राज्य ब्यूरो, पटना : केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के विरोध में बुधवार को महागठबंधन राजधानी पटना में सड़क पर उतरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने जेपी गोलंबर के पास धरना दिया तो कांग्रेसियों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से जुलूस निकाला और कारगिल चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। बाद में दोनों दल गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास इकट्ठा हुए और आगे भी विधेयक का विरोध करते रहने का संकल्प लिया।

तेजस्वी ने केंद्र के साथ राज्य सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खुद को गांधी, जेपी और लोहिया का शिष्य बताते हैं, लेकिन अब संघी हो चुके हैं। तेजस्वी ने नागरिकता संशोधन बिल को देश तोड़ने वाला काला कानून बताया और कहा कि संविधान सबको बराबर का हक देता है। किंतु केंद्र ने एक समुदाय को टारगेट पर लिया है। सारे फैसले आधी रात में लिए जा रहे हैं। फिर भी नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है।

आसार

15 से 17 दिसंबर के बीच होने वाली है भारत व जापान के पीएम की सालाना बैठक, भारत की तरफ से जापान को बताया गया है कि बैठक अभी भी गुवाहाटी में करवाई जा सकती है लेकिन अगर जापान पक्ष चाहे तो उसे बदला भी जा सकता है

असम हिंसा से बदल सकती है मोदी-शिंजो बैठक की जगह

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

असम में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों और अशांति को देखते भारत व जापान के बीच होने वाली सालाना शीर्षस्तरीय बैठक की जगह में बदलाव किया जा सकता है। वैसे विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो के बीच होने वाली सालाना बैठक के लिए गुवाहाटी का चयन किया गया था। लेकिन असम में आंदोलन को देखते हुए बैठक के स्थल पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में दोनों देशों के अधिकारी संपर्क में हैं। भारत की तरफ से जापान को बताया गया है कि बैठक अभी भी गुवाहाटी में करवाई जा सकती है लेकिन अगर जापान पक्ष चाहे तो उसे बदला भी जा सकता है। दोनों पक्षों के बीच भुवनेश्वर या नई दिल्ली दो ऐसे शहर हैं जहां मोदी-शिंजो की इस बैठक को आयोजित करवाने का विकल्प है।

मोदी और शिंजो के बीच यह बैठक 15 से 17 दिसंबर, 2019 के बीच होनी है। वैसे विदेश मंत्रालय की तरफ ले अभी तक गुवाहाटी में ही यह बैठक होगी, इसका खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन गुवाहाटी से जो सूचनाएं आ रही हैं, वहां बैठक की पूरी तैयारी कर ली गई थी। सड़कों के दोनों तरफ मोदी और शिंजो के पोस्टर लगाने का काम भी हो रहा था। बुधवार को यह सूचना आई है कि वहां प्रदर्शनकारियों ने गुवाहाटी की सड़कों पर मोदी-शिंजो बैठक की तैयारियों से जुड़े पोस्टर आदि को भी आग के हवाले कर दिया। गुवाहाटी में इस बैठक को आयोजित करने का अपना कूटनीतिक संदेश था। माना जा रहा था कि पड़ोसी देश चीन को एक मजबूत संकेत देने के लिए भारत और जापान के बीच गुवाहाटी का चयन किया गया था। हाल के वर्षों में भारत और जापान के बीच रिश्ते बहुत तेजी से प्रगाढ़ हुए हैं। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि पिछले साढ़े पांच वर्षों से मोदी और शिंजो सरकार चला रहे हैं। इस साल की सालाना बैठक को रणनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने की तैयारी है।

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर बुधवार को असम के डिब्रूगढ़ में सेना की सहायता ली गई। प्रेट्र

- भुवनेश्वर या नई दिल्ली दो ऐसे शहर हैं जहां इस बैठक को आयोजित कराने का है विकल्प
- गुवाहाटी में इस बैठक को आयोजित करने का अपना कूटनीतिक संदेश था

मणिपुर में इनर लाइन परमिट लागू राष्ट्रपति ने आदेश पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दस्तखत करने के साथ इनर लाइन परमिट (आइएलपी) व्यवस्था बुधवार को मणिपुर में लागू कर दी गई। इसके दो दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में घोषणा की थी कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के बारे में पूर्वोत्तर के राज्य के लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए मणिपुर में आइएलपी को लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।

आइएलपी व्यवस्था वाले राज्यों में देश के दूसरे राज्यों के लोगों सहित बाहर के लोगों को अनुमति लेनी पड़ती है। भूमि, रोजगार के संबंध में स्थानीय लोगों को संरक्षण दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम के बाद मणिपुर चौथा राज्य है जहां आइएलपी को लागू किया गया है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर नियमन 1873 के अंतर्गत आइएलपी व्यवस्था लागू की गई थी। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर नियमन 1873 की धारा दो के तहत अन्य राज्यों के नागरिकों को इन तीनों राज्यों में जाने के लिए आइएलपी की जरूरत पड़ती है। आइएलपी व्यवस्था का मुख्य मकसद मूल आबादी के हितों की रक्षा के लिए तीनों राज्यों में अन्य भारतीय नागरिकों को बसने से रोकना है।

दीमापुर को आइएलपी व्यवस्था के तहत लाया

कोहिमा : नगालैंड सरकार ने आइएलपी व्यवस्था को दीमापुर तक बढ़ा दिया है। दीमापुर राज्य में एकमात्र व्यावसायिक केंद्र है जहां राज्य के अन्य क्षेत्रों की तरह आइएलपी लागू नहीं था। नौ दिसंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए नगालैंड के राज्यपाल तत्काल प्रभाव से पूरे दीमापुर जिले को आइएलपी में लाने के लिए सहमत हैं।

18 रिमाइंडर भेजे जाने के बाद भी राजस्थान में पीएम ग्रामीण आवास का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में अब करीब 25 हजार लाभार्थियों को दूसरी और तीसरी किश्त के रूप में मिलने वाली राशि अटकने की नौबत आ गई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 12 दिसंबर 2019

हैदराबाद मुठभेड़ की जांच पूर्व जज को सौंपी जा सकती है

तैयारी ▶ सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को मामले की फिर करेगा सुनवाई

शीर्ष अदालत ने पक्षकारों से सुझाव मांगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट हैदराबाद में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के चार आरोपितों को पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपने पर विचार कर रहा है। कोर्ट ने इस संबंध में पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं। मामले पर गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। शीर्ष कोर्ट में दाखिल तीन याचिकाओं में हैदराबाद पुलिस मुठभेड़ में चार आरोपितों के मारे जाने की जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

बुधवार को याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस तथ्य से वाकिफ हैं कि इस मामले पर तेलंगाना हाई कोर्ट विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि

▶ तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच दिल्ली में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करें

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

उनका प्रस्ताव है कि इस मामले की जांच दिल्ली में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करें। जस्टिस बोबडे ने कहा कि उन्होंने इस बारे में एक न्यायाधीश से बात भी की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक स्थगित करते हुए पक्षकारों से कहा कि वह गुरुवार तक न्यायाधीश का नाम सुझाएं।

इस बीच तेलंगाना सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मुठभेड़ के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले में तय व्यवस्था के मुताबिक, काम किया है और घटना की जांच राज्य सीआइडी को सौंप दी है।

मालूम हो कि हैदराबाद में सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला डॉक्टर की हत्या की गई और शव को जला दिया गया था। हैदराबाद पुलिस ने इसमें चार आरोपितों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पुलिस आरोपितों को घटना स्थल पर सीन रीक्रिएट करने के लिए ले गई थी। पुलिस का कहना है कि उसी दौरान आरोपितों ने पुलिस के हथियार छीन कर हमला किया और भागने की कोशिश की जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और आरोपित मारे गए।

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की कब्र पर धरने पर बैठा परिवार

जागरण संवाददाता, उन्नाव

▶ आरोपितों को फांसी और मुख्यमंत्री के गांव आने की जिद पर अड़ा परिवार

उन्नाव में जिंदा जलाई गई दुष्कर्म पीड़िता की कब्र के पास बुधवार तड़के उसके परिजन बेमियादी धरने पर बैठ गए। उनके मुताबिक, जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे और आरोपितों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, तब तक नहीं उठेंगे। मृतका की बहनों, पिता, मां और बच्चों के धरने पर बैठने की सूचना पर एसडीएम-सीओ की टीम ने मौके पर जाकर परिवार को समझाना चाहा लेकिन वे मांगों पर अड़े रहे।

बिहार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती पांच दिसंबर की भोर में बैसवारा रेलवे स्टेशन जा रही थी। तभी दुष्कर्म मामले में आरोपित शिवम त्रिवेदी ने साथियों के साथ मिलकर उसे जिंदा जला दिया था। दूसरे दिन ही दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

धरने पर बैठी पीड़िता की बड़ी बहन का कहना है कि आरोपितों को फांसी दी जाए या हम सभी को मारकर बहन के पास दफन कर दिया जाए। एसडीएम दयाशंकर पाठक, सीओ एके राय ने समझाने का प्रयास किया। कहा कि आप सभी से जो कमिश्नर साहब से बात हुई थी वह पूरी हो रही है। आरोपितों को सजा के लिए भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता की बहन ने कहा कि हम लोग अब एक बात भी नहीं मानेंगे। अधिकारियों ने कहा कि चलो आप सबको लेकर मुख्यमंत्री से बात करा दूंगा, अपनी बात उनसे कह देना। इस पर भी वह राजी नही हुई और कहा कि मुख्यमंत्री यहीं आएं, हम लोग नहीं जाएंगे। देर रात तक पीड़ित परिवार धरने पर बैठा था। बताते चलें कि परिजनों ने दुष्कर्म पीड़िता की कब्र पर चल रहे पक्के काम को रोकते हुए ईंटें आदि फेंक दी थीं। परिवार ने मृतका की बहन को नौकरी देने की मांग रखी थी।

मुकदमा चलने तक तैनात रहेगी फोर्स

दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की सुरक्षा के लिए उसके घर और गांव में फोर्स तैनात रखने के साथ स्वजनों को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि जेल में बंद आरोपितों के हितैषी और नाते-रिश्तेदार उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एसआइटी प्रभारी और एएसपी विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़िता के घर सीओ की निगरानी में इंस्पेक्टर और दारोगा के साथ महिला और पुरुष सिपाही तैनात किए गए हैं। भाई और बहन के अलावा अन्य सभी को गनर उपलब्ध कराए गए हैं।

जिंदा जलाई गई दुष्कर्म पीड़िता मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट

जागरण संवाददाता, रायबरेली

उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता की जलाकर हत्या का मामला तूल पकड़ने के बाद अब रायबरेली पुलिस ने भी तेजी दिखाई है। मृतका की ओर से दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के दो मुकदमों को एक केस में तरमीम करके नौ दिसंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।

सामूहिक दुष्कर्म के उक्त मामले में पीड़िता के गांव के ही शिवम और शुभम को आरोपित बनाया गया था। शिवम ने कोर्ट में समर्पण कर दिया था। बाद में उसे जमानत मिल गई थी। एक दिसंबर को लालगंज पुलिस ने पहले शुभम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उसके बाद नौ दिसंबर को इस पूरे प्रकरण की चार्जशीट दाखिल कर दी गई, जिसमें सामूहिक दुष्कर्म, जानमाल की धमकी और आरोपित की फरारी का जिक्र है। कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने निष्पक्षता के साथ विवेचना करके रिपोर्ट प्रेषित की है।

दर्ज कराए थे दो मुकदमे: उन्नाव में जानमाल का खतरे के चलते पीड़िता रायबरेली में अपनी मौसी के घर रह रही थी। बताते हैं, यहीं उसका मित्र भी रहता था। घटना के बाद वहां सुनवाई न होने पर पीड़िता ने अदालत में शरण ली। उसके आदेश पर दो मुकदमे दर्ज हुए। चार मार्च को बिहार और पांच मार्च को लालगंज थाने में। इन्हीं दोनों मामलों को एक केस में तरमीम कर बिहार थाने से मुकदमा लालगंज कोतवाली स्थानांतरित कर दोनों की समग्र चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है।

अफवाहों से रही गहमागहमी: उन्नाव में जघन्य वारदात के बाद से लालगंज में काफी गहमागहमी का माहौल है। बुधवार को इस प्रकरण से जुड़े एक शख्स की गिरफ्तारी की चर्चा रही। साथ ही लालगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने की बात भी उड़ी। हालांकि इन अफवाहों को लालगंज कोतवाल ने सिरे से खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट दया याचिका के लिए तय करे नियम-कायदे

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट में दया याचिकाओं के समयबद्ध तरीके से निपटारे के लिए एक याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि दया याचिकाओं की स्पष्ट प्रक्रिया, नियमों और दिशा-निर्देशों के लिए केंद्र को आदेश दिया जाए। अधिवक्ता शिवकुमार त्रिपाठी की ओर से दायर याचिका में दया याचिकाओं (मर्सी पेटिशन) को एक तय समयसीमा में निपटाने के लिए केंद्र को दिशा-निर्देश देने की अपील की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि अगर दया याचिका का निपटारा तय समय में नहीं किया गया तो उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। याचिका में कहा गया है कि कुछ ही मामलों में ऐसा हुआ है कि दया याचिकाओं की सुनवाई में खासी देरी हो जाती है। ऐसे मामलों में दोषियों को इस देरी का लाभ मिल जाता है और वह अपनी सजा-ए-मौत को आजीवन कारावास में बदलवा लेते हैं। ऐसे मामलों में पीड़ित और उनके परिजन ठगा हुआ महसूस करते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि चूंकि दया याचिकाओं के निपटारे के लिए कोई तय प्रक्रिया नहीं है, इसलिए समयबद्ध तरीके से इनके निपटारे की व्यवस्था होनी चाहिए।

अनुच्छेद 370 हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सवाल किया कि तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य से अनुच्छेद-370 हटाने के लिए प्रदेश की संविधान सभा के पुनर्गठन के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन हो सकता था।

जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। नौकरशाह से राजनेता बने शाह फैसल, शहला रशिद और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा ही राज्य के दर्जे में बदलाव करने की कोई सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकती है। इस पर पीठ ने सवाल किया कि जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के पुनर्गठन के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन हो सकता था? इस पर रामचंद्रन ने कहा कि अनुच्छेद 370 में यह अधिकार जम्मू-कश्मीर के लोगों को दिया था, इसलिए आखिरी फैसला उन्ही का होना चाहिए। इस पर पीठ ने फिर सवाल किया, 'अगर ऐसा है तो क्या यह जनमत संग्रह, सहमति या विचार-विमर्श से होगा?'

जवाब में रामचंद्रन ने कहा कि राष्ट्रपति सिर्फ राज्य के लोगों के प्रतिनिधित्व वाली संविधान सभा की सिफारिश पर ही अनुच्छेद 370 हटा सकते थे।

तमिलनाडु को 2011 की जनगणना के अनुसार निकाय चुनाव कराने को कहा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्य चुनाव आयोग से स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराने के लिए कहा है। विपक्षी पार्टी द्रमुक ने 1991 की जनगणना के आधार पर चुनाव कराने का आरोप लगाया है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने द्रमुक की नई याचिका पर अपने आदेश में कहा कि न्याय के हित में यह निर्देश देना उचित रहेगा कि राज्य में आगामी सभी चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर ही होंगे।

जम्मू-कश्मीर में वकीलों की मनमानी पर बरसीं चीफ जस्टिस

जेएनएफ, जम्मू : जमीन की रजिस्ट्री के मुद्दे पर जारी हड़ताल के दौरान कुछ वकीलों की ओर से की जा रही मनमानी पर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने कड़ी फटकार लगाई है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट परिसर के भीतर कानून की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस गीता मित्तल व जस्टिस राजेश बिंदल ने जानीपुर स्थित कोर्ट परिसर के मुख्य गेट पर ताला जड़ने के आरोप में एडवोकेट बलदेव सिंह, नितिन बख्शी, अजहर उस्मान खान व महेंद्र पाल पल्ली को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर पक्ष रखने का निर्देश दिया है। बेंच ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को भी पहली नवंबर से अब तक की सभी सीसीटीवी फुटेज व फोटो पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बेंच ने रजिस्ट्रार आइटी को वकीलों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए संदेशों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। वकीलों की हड़ताल से आम लोगों को हो रही परेशानी का संज्ञान लेते हुए डिवीजन बेंच ने बुधवार को इस पर स्वयं सुनवाई शुरू की।

बहुचर्चित हनी ट्रैप से जुड़े मामले में फरार जीतू सोनी के अखबार की इमारत भी गिराई गई

नईदुनिया, इंदौर

▶ बंगले व होटलों सहित कई अवैध निर्माण पहले ही गिराए जा चुके हैं

▶ सोनी पर अब तक 55 से ज्यादा केस हो चुके हैं दर्ज

जीतू के कैबिन से निकली हजारों सीडी व हार्ड डिस्क नष्ट

'संझा लोकस्वामी' की इमारत के पिछले हिस्से में बने टीवी स्टूडियो और जीतू सोनी के केबिन में पुलिस को कैमरे के अलावा हजारों सीडी, पुरानी कैसेट और हार्ड डिस्क आदि मिलीं। अधिकारियों ने इन्हें ताबड़तोड़ नष्ट करवा दिया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी सादी वर्दी में खड़े थे।

ढाई लाख का कैमरा भी नष्ट

सूत्रों ने बताया कि चार से पांच हजार सीडी-कैसेट आदि नष्ट किए गए। स्टूडियो के जिस कैमरे को तोड़ा गया, उसकी कीमत दो-ढाई लाख रुपये आंकी गई है। सीडी-कैसेट नष्ट करके मजदूरों से उसे फिंकवाया गया और उस पर पोकलेन मशीन चढ़ाकर उसे चकनाचूर किया गया। जब अधिकारियों ने तसल्ली से देख लिया कि सारी वस्तुएं पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, तब दूसरे काम शुरू किए गए।

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप से जुड़े मामले के 55 से ज्यादा केसों में वांछित जीतू सोनी के इंदौर से प्रकाशित होने वाले 'संझा लोकस्वामी' अखबार की इमारत को भी जिला प्रशासन ने बुधवार को ढहा दिया। इससे पहले जीतू का आलीशान बंगला, उसकी चर्चित 'माय होम होटल' समेत कुछ अन्य होटलों को भी ढहाया जा चुका है।

इंदौर के प्रेस कॉम्प्लेक्स में था अखबार का दफ्तर : बुधवार को ढहाई गई 'संझा लोकस्वामी' की इमारत व दफ्तर इंदौर के प्रेस कॉम्प्लेक्स में स्थित थी। इस दो मंजिला इमारत को जिला, पुलिस और नगर निगम प्रशासन की टीम ने जेसीबी व पोकलेन मशीनों व बड़ी संख्या में मजदूर लगाकर गिरा दिया।

30 हजार वर्गफीट जमीन मुक्त : इस कार्रवाई से जो जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है, वह दो प्लॉटों में बंटी है। उसका क्षेत्रफल करीब 30 हजार वर्गफीट बताया गया है। इसकी कीमत करोड़ों में है। 23 और 24 प्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर के इन प्लॉटों में से 23 नंबर पर करीब दो हजार वर्गफीट और 24 नंबर प्लॉट पर 22 हजार वर्गफीट आकार का भवन बनाया गया था। अवैध निर्माण हटाने के लिए नगर निगम और आइडीए ने सात दिन पहले नोटिस दिए थे। जवाब नहीं आने पर कार्रवाई की गई। सुबह सात बजे से चार पोकलेन मशीनों और एक बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई।

इंदौर की जिप्सी और मुंबई की बोलेरो जब्त : इमारत परिसर में एक जिप्सी और बोलेरो खड़ी थी। दोनों गाड़ियों पर पुलिस ने छह दिसंबर को जब्ती की पर्ची चस्पा कर दी थी। बुधवार को कार्रवाई के दौरान दोनों गाड़ियों को क्रेन की मदद से थाने भेजा गया। कुछ अधिकारियों ने बताया कि जिप्सी में जीतू सोनी के बाउंसर घूमते थे।

जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को पूर्वोत्तर भेजा गया

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ बिगड़ी कानून व्यवस्था को देख केंद्र सरकार ने उठाया कदम

▶ आरपीएफ की चार, सीआरपीएफ की 21 कंपनियां जल्द जाएंगी

नागरिक संशोधन बिल के मुद्दे पर पूर्वोत्तर में बिगड़ी कानून व्यवस्था को देखते हुए केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में तैनात अर्धसैनिकबलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को हटाकर उन्हें असम और त्रिपुरा में तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से रैपिड प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) की चार कंपनियों के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 21 कंपनियों को असम में तैनात किया जाएगा। इनके लिए जम्मू से असम तक विशेष ट्रेन भी चलाने की योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस बीच, बुधवार को जम्मू कश्मीर से 10 कंपनियों को पूर्वोत्तर के लिए रवाना किया गया। वहीं कश्मीर में हालात पूरी तरह सामान्य हैं।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू करने से पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर अगस्त माह के शुरुआती हफ्ते तक बड़ी संख्या में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ, सीआइएसएफ, एसएसबी और आइटीबी की देश के विभिन्न हिस्सों से अतिरिक्त टुकड़ियों को भेजा था। हालात में बेहतरी के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिकबलों की टुकड़ियों को गत माह वापस उनके मूल नियुक्ति स्थलों पर फिर से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। 25 नवंबर से तीन दिसंबर तक करीब 20 कंपनियों को झारखंड, कर्नाटक के अलावा पूर्वोत्तर में भेजा गया था। इनके अलावा 30 और कंपनियों को 31 दिसंबर तक भेजा जाना है।

जम्मू कश्मीर में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए नोडल अधिकारी की भूमिका निभा रहे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात आरपीएफ की चार व सीआरपीएफ की 21 कंपनियों को पूर्वोत्तर भेजा जा रहा है। ये सभी कंपनियां पूर्वोत्तर के राज्यों से ही यहां भेजी गई थीं। राज्य के विभिन्न हिस्सों की सुरक्षा परिस्थितियों की समीक्षा के आधार पर ही संबंधित इलाकों से अर्धसैनिकबलों को हटाकर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। फिलहाल, हमने 10 कंपनियों को चिन्हित कर वापस भेज दिया है। इन्हें हवाई जहाज और सड़क के जरिए भेजा गया। जम्मू या फिर पठानकोट से इनके लिए एक विशेष रेलगाड़ी भी चलाने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि इन 10 कंपनियों में से सात को मणिपुर में ऑपरेशनल ड्यूटी संभालनी है। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों को दीमापुर पहुंचने के लिए कहा गया है। संकेत है कि यह असम में जाएंगी।

बिहार में अपशिष्ट प्रबंधन में नाकाम 219 अस्पताल होंगे बंद

राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की अनुशंसा के बाद बिहार सरकार ने पटना स्थित राजकीय आयुर्वेदिक व राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल समेत पटना के 219 स्वास्थ्य संस्थानों को बंद करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग ने पटना के जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि एक समय सीमा के अंदर संबंधित अस्पतालों को बंद करने की कार्रवाई करें।

बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पटना ने हाल ही में एक जांच के दौरान पाया कि पटना के 219 स्वास्थ्य संस्थान जिसमें अस्पताल, नर्सिंग होम, दंत चिकित्सालय, लैब, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स सेंटर हैं जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। यह स्वास्थ्य संस्थान मेडिकल वेस्ट (अपशिष्ट) तो उत्पादित कर रहे हैं परन्तु उसके निस्तारण के लिए इनके पास कोई समुचित व्यवस्था नहीं। मेडिकल वेस्ट जहां-तहां फेका जा रहा है जिससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है।

अपना ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं : खुद के मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट न होने के बावजूद इन संस्थानों ने कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसलिटी से संबद्धता भी नहीं ली है। जो नियमों का घोर उल्लंघन हैं। जांच में यह बात सामने आने के बाद प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने इन सभी स्वास्थ्य संस्थानों को 'क्लोजर डायरेक्शन' जारी किए।

अमेरिकी विशेषज्ञ ने जताई भारत पर आतंकी हमले की आशंका

राज्य ब्यूरो, मोहाली

▶ डॉ. पीटर चाक ने आइएसआइ से किया सचेत

▶ सोशल मीडिया से कश्मीर में जेहादियों की भर्ती की आशंका

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कश्मीर में जेहादियों की भर्ती और आतंकी हमले कराने की साजिशों को अंजाम दे सकती है। यह आशंका आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा मामलों के अमेरिकी विशेषज्ञ डॉ. पीटर चाक ने जताई है। उन्होंने कहा कि आइएसआइ सोशल मीडिया पर गुप्त संकेतों और ऑनलाइन मैपिंग के जरिये आतंकी गतिविधियों को समर्थन दे सकती है। पाकिस्तान सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमला करने के लिए भी कर सकता है।

मोहाली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में दूसरे केपीएस गिल मेमोरियल लेक्चर में डॉ. पीटर चाक ने कहा कि कश्मीर में भारत विरोधी दलों को शह देने का पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है। इससे निपटने के लिए सहयोगी व पड़ोसी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है।

अमेरिका की दोहरी नीति स्वीकारी

डॉ. चाक ने कहा कि अफगानिस्तान में अपने रणनीतिक हितों के लिए पाकिस्तान के संबंध में अमेरिका दोहरी नीति अपनाता है। यही कारण है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका सख्त स्टैंड नहीं लेता।

ड्रोन तकनीक का पंजीकरण जरूरी

आतंकी हमलों में ड्रोन के इस्तेमाल को रोकने के लिए डॉ. चाक ने तकनीक के पंजीकरण को आवश्यक बनाने व कानूनी प्रावधान किए जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि सिर्फ ऑनलाइन संदेशों के माध्यम से ही कट्टरवाद को बढ़ावा देने की 100 फीसद गतिविधियां नहीं की जा सकती। इसके लिए मानवीय संपर्क आवश्यक हो जाता है। आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए लोगों को विश्वास में लेना जरूरी है।

अस्थिरता लाने के लिए रेफरेंडम-2020 का प्रचार

रेफरेंडम-2020 पर डॉ. चाक ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तान समर्थक आतंकी, अमेरिका, यूके और कनाडा में नौजवानों को कट्टरवाद के प्रति आकर्षित करने के प्रयास कर रहे हैं। इससे कश्मीर व पंजाब में भी अस्थिरता लाने का अभियान होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। डॉ. चाक ने कहा कि गूगल, वॉट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी उन पर आतंकी सरगर्मियां होने की संभावना को स्वीकारा है।

पंजाब को काले दौर में धकेलने की इजाजत नहीं दे सकते

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आतंकवाद के लिए अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक सीमाएं निरर्थक हो गई हैं। पंजाब नशे के बढ़ते आतंक से भी जूझ रहा है। कैप्टन ने आधुनिक पुलिसिंग और तकनीक को उन्नत व पेशेवर बनाने की जरूरत जताई। कैप्टन ने कहा, 'हम किसी भी सूरत में पंजाब को बीते हुए काले दौर की तरफ धकेलने की इजाजत नहीं दे सकते, हम सबको पता है कि अब फिर क्या घट रहा है।' इसलिए जरूरी है कि हम लोगों का ध्यान रखकर कोई नियम बनाएं।

गूगल पर छाए रहे अनुच्छेद 370, अयोध्या मामले से संबंधित सवाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस साल गूगल पर भारतीयों ने सबसे ज्यादा 'अनुच्छेद-370' क्या है, 'अयोध्या मामला क्या है' और भारत की नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) क्या है सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए सवालों में शामिल रहे। गूगल 2019 वर्ष की सर्च रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इंटरनेट यूजर्स ने अनुच्छेद-370, एक्जिट पोल, ब्लैक होल और 'हाउडी मोदी' जैसे कई सवाल प्रमुखता से पूछे।

गूगल पर पूछे गए शीर्ष 10 सवालों में 'अयोध्या मामला क्या है' और 'एनआरसी' क्या है, भी शामिल थे। गूगल ने कहा कि सर्च ट्रेंड में लोकसभा चुनाव और इसके परिणामों से संबंधित सवाल भी छाए रहे।

'हाउ टू' सूची में 'मतदान कैसे करें', 'मतदाता सूची में नाम कैसे ढूंढें' पहले और तीसरे स्थान पर रहे। रोचक तौर पर कुल सर्च ट्रेंड में लोकसभा चुनाव परिणाम सर्च ट्रेंड में दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा चंद्रयान-2, अनुच्छेद 370, नीट परिणाम, प्रधानमंत्री किसान योजना जैसे विषयों की भी खूब जानकारी ली गई।

फीचर फिल्मों में 'कबीर सिंह', 'अवेंजर्स : एंडगेम', 'जोकर' और 'कैप्टन मार्वेल' समूची सर्च सूची में शीर्ष 10 में शामिल रहे। वहीं, विंग कमांडर अभिनंदन भारत में सर्वाधिक सर्च की गई हस्तियों में शामिल रहे। उनके बाद लता मंगेशकर, युवराज सिंह, आनंद कुमार और विकी कौशल रहे।

बढ़ी ठंडक

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड, हवाई सेवाएं ठप, गुलमर्ग में चार इंच, सोनमर्ग में सात इंच बर्फ गिरी, उत्तराखंड में भी केदारनाथ समेत हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी

पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरा मैदानी राज्यों का तापमान

जेएनएन, नई दिल्ली

जम्मू कश्मीर और लद्दाख कड़ाके की ठंड की जकड़ में है। उत्तराखंड में भी केदारनाथ समेत हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। यही हाल हिमाचल प्रदेश में रहा। वहां कुल्लू के रोहतांग दर्रे में बुधवार को करीब आधा फीट हिमपात हुआ। इससे लाहुल घाटी कुल्लू से फिर कट गई है। लाहुल के कोकसर व मनाली के मढ़ी में बर्फ के फाहे गिरे। रोहतांग दर्रे सहित अन्य ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई। हल्की बर्फबारी के बीच एक महिला सहित नौ लोगों ने रोहतांग दर्रा पैदल पार कर मनाली में दस्तक दी। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में दिखने लगा है। बुधवार को पंजाब के लुधियाना 3.8 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। पहाड़ों पर बर्फबारी के असर दिल्ली भी अछूती नहीं रही। बुधवार के यहां का न्यूनतम तापमान 7.4 दर्ज किया गया।

मनाली जिले में रोहतांग में सड़क से बर्फ हटाती बीआरओ की टीम। प्रेट्र

श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड फिर बंद : बुधवार को भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड फिर बंद हो गया। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकतरफा यातायात जारी है। घने कोहरे के कारण छह दिन से श्रीनगर के लिए हवाई सेवाएं ठप हैं। दिल्ली से जम्मू के लिए हवाई सेवाएं सुचारु रहीं। जम्मू और श्रीनगर में दिनभर बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को भारी हिमपात व बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मंगलवार रात से हो रही बर्फबारी शुरू हो गई थी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटनस्थल गुलमर्ग, पहलगाम व सोनमार्ग समेत जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों और लद्दाख में रातभर हिमपात हुआ। कई संपर्क मार्ग कट गए। बिजली आपूर्ति ठप है। गुलमर्ग में चार इंच, सोनमर्ग में सात इंच बर्फ गिरी। जम्मू का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री और श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

हिमाचल में बर्फीला तूफान चलने की चेतावनी

हिमाचल के छह जिलों में 12 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फीला तूफान चलने व अन्य छह जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। 13 दिसंबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने सभी जिला उपायुक्तों को चेतावनी जारी कर सुरक्षा के कदम उठाने को कहा है।

पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में मोर्टार और तोप से दागे गोले

जागरण न्यूज नेटवर्क, श्रीनगर

पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा (आइबी) पर भी गोलाबारी तेज कर दी है। पाकिस्तान ने कठुआ के हीरानगर सेक्टर से लेकर उत्तर कश्मीर में उड़ी तक भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर मोर्टार के साथ-साथ कुछ जगह तोपों का भी इस्तेमाल किया। इसमें चार ग्रामीण घायल हो गए। करीब 15 घर क्षतिग्रस्त हो गए। उड़ी में प्रशासन ने पाकिस्तानी गोलाबारी के बीच 13 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इस बीच, भारतीय सेना ने भी जवाबी प्रहार करते हुए पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया। इससे एलओसी पार भी नुकसान की सूचना है।

उड़ी में गोलाबारी : सुबह करीब नौ बजे पाकिस्तानी सैनिकों ने उड़ी सेक्टर के चरुंडा और सिलीकोट में सैन्य और नागरिक ठिकानों पर गोलाबारी शुरू कर दी। इससे तीन मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। दो ग्रामीण भी घायल हो गए, जिन्हें सेना ने निकटवर्ती अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। शुरू में संयम बरतने के बाद भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तानी ठिकानों पर जवाबी प्रहार किया। दोपहर तक दोनों तरफ से रुक रुककर गोलाबारी जारी थी। पाकिस्तान ने शाम को पुंछ के शाहपुर किरनी सेक्टर में भी एलओसी पर गोलाबारी शुरू कर दी। वह इसकी आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराने का प्रयास कर रहा था, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। देर शाम पाकिस्तान ने पुंछ के बांडिचेचीया में भी गोलाबारी शुरू कर दी। इसमें दो ग्रामीण मुहम्मद सलीम और तनवीर अखतर घायल हो गए।अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दो दिन की शांति के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने मंगलवार रात कठुआ के हीरानगर सेक्टर के रठुआ गांव पर भारी गोलाबारी की।

न्यूज गैलरी

पंजाबी जागरण के पूर्व संपादक शंगारा सिंह भुल्लर नहीं रहे

चंडीगढ़ : पंजाबी जागरण के पहले संपादक शंगारा सिंह भुल्लर (74) का बुधवार शाम बीमारी के कारण निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी अमरजीत कौर भुल्लर, बेटे चेतन पाल सिंह और रमनीक सिंह हैं। वह कुछ समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत तमाम लोगों ने भुल्लर के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। (राब्यू)

शंगारा सिंह भुल्लर। फाइल फोटो

अकबर मामले में निजी टिप्पणी न करे मीडिया : कोर्ट

नई दिल्ली : पूर्व मंत्री एमजे अकबर की तरफ से पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अकबर की तरफ से वकीलों की टीम ने अदालत को बताया कि एक पोर्टल की मीडिया कर्मी इस मामले को लेकर निजी टिप्पणी कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अदालत ने कहा कि मीडिया को निजी टिप्पणी से बचना चाहिए। इस मसले को लेकर अदालत के बाहर पोर्टल की रिपोर्टर और वकीलों में बहस भी हो गई। (जासं)

दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को आठ दिन में सुनाई सजा

रुद्रप्रयाग : उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले की सुनवाई मात्र आठ दिन में करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी को सात वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन सिंह चौधरी ने बताया कि 16 अक्टूबर को पंचायत चुनाव में मतदान के लिए दादी के साथ आई एक नौ वर्षीय बच्ची से गांव के ही अधेड़ तिब्बू लाल ने खेत में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया था। शोर मचाने पर वहां से गुजर रही एक महिला ने किसी तरह बच्ची को बचाया। पीड़िता ने घर जाकर दादी को सारी बात बताई। दादी ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपित को 17 अक्टूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 30 नवंबर को पुलिस ने जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले में अदालत में छह गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश गोयल की अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। (जासं)

मुंबई में 20 हजार के प्याज चोरी के आरोप में दो गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई पुलिस ने डोंगरी मार्केट में दो दुकानों से 20 हजार रुपये से ज्यादा के प्याज चोरी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों दुकानों से कुल 168 किलो प्याज चुरा ली गई थी। यह घटना पांच और छह दिसंबर की दरमियानी रात में हुई। पुलिस ने एक बयान में कहा है, 'मुंबई पुलिस ने डोंगरी थाने में आइपीसी के अनुच्छेद 379 के तहत प्याज चोरी का मामला दर्ज किया है। चोरी गए कुल 168 किलो प्याज की कीमत 20,160 रुपये के आसपास आंकी गई है।' करीब 112 किलो अकबर शेख की दुकान से और इमरान शेख की दुकान से 56 किलो प्याज चोरों ने चुरा ली। (एएनआइ)

कॉल सेंटर की आड़ में विदेशी नागरिकों से ठगी, सात गिरफ्तार

कोलकाता : बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित सॉल्टलेक में कॉल सेंटर की आड़ में विदेशी नागरिकों से ठगी के आरोप में सीआइडी ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी मंगलवार रात की गई। इसके पास से कई कम्प्यूटर, डिस्क, मोबाइल फोन और डेटा जब्त किया गया है। डीआइजी सीआइडी (विशेष) मिथेस जैन ने बताया कि जो ठगों का मुख्य निशाना कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका आदि देशों के नागरिक होते थे। यहां रहने वाले जो लोग कम्प्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे या टेक्नोलॉजी को लेकर जिनका ज्ञान कम होता था, उन्हीं लोगों को ये अपना शिकार बनाते थे। आरोपित विभिन्न पते से खुद के लिंक भेजने थे। खुद ही समस्या पैदा करते थे और उसके निवारण करने के नाम पर रुपये ऐंठ लिया करते थे। कुछ समय में ही इन लोगों ने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था। (जासं)

आइआइटी के छात्र बीच में बदल सकेंगे कोर्स

जागरण संवाददाता, वाराणसी

एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की आइआइटी से हजारों छात्रों ने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। इसके लिए कठिन कोर्स को जिम्मेदार ठहराया गया। इस समस्या को हल करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आइआइटी छात्रों के लिए एक प्रस्ताव दिया है। इसके शीघ्र अमल में आने की संभावना है।

लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब के मुताबिक पिछले पांच साल में देशभर की आइआइटी से 7248 छात्रों ने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। यह गंभीर हालत देश के सबसे अहम संस्थान की है। इसके पीछे सबसे जिम्मेदार कारक कोर्स के बीच में ही रुचि का न होना या उसमें अपेक्षा अनुरूप प्रदर्शन न कर पाना है।

इस समस्या को लेकर आइआइटी बीएचयू के छात्रों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ड्राप आउट की समस्या बीटेक में नहीं बल्कि एमटेक कोर्स में सबसे ज्यादा है। यहां पर लगभग दो से तीन फीसद छात्र ड्राप आउट कर जाते हैं क्योंकि इसमें अध्ययन करने वाला छात्र कोर्स पूरा करते-करते किसी दूसरे क्षेत्र में सफल हो जाता है। देश की आइआइटी में अभी यह व्यवस्था है कि अगर आपको बीटेक करते वक्त बीच में ही अपनी ब्रांच बदलनी हो तो पहले सेमेस्टर के बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा बीटेक के तीसरे साल में छात्र अगर चाहें तो वे इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री में भी अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। इसमें बीटेक व एमटेक दोनों ही कोर्स समाहित होते हैं।

एग्जिट ऑप्शन पर हो रहा विचार: जो छात्र बीटेक के पाठ्यक्रम से परेशान या ऊब जाते हैं तो वे बीएससी इंजीनियरिंग या किसी अन्य कोर्स में अपना दाखिला करा सकते हैं। सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है।

आइआइटी बीएचयू में इस तरह की कोई भी समस्या सामने नहीं आई है। न ही इस तरह का कोई मामला हमारे संज्ञान में अभी तक है।

-प्रो. प्रमोद कुमार जैन निदेशक, आइआइटी बीएचयू

कानपुर में पीएम की गंगा बैठक का होगा बड़ा संदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- गंगा में वैठक के जरिये विहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी कमर कसने का संकेत
- प्रधानमंत्री 14 दिसंबर को जा रहे हैं कानपुर

यह सहज ही समझा जा सकता है कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर की प्रस्तावित यात्रा को लेकर राज्य सरकार और अफसरों में कितनी अफरा-तफरी होगी। जिस तरह आनन-फानन में सब कुछ दुरुस्त दिखाने के लिए काम किए जा रहे हैं वह इसका साक्ष्य है। सच्चाई तो यह है कि शुरुआत में प्रधानमंत्री की कानपुर यात्रा को लेकर अफसरों में उत्साह नहीं दिख रहा था। टालने की कोशिश हुई ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संकोच बहुत ज्यादा था। बहरहाल जनजागरण के जरिये स्वच्छता अभियान को सिरे चढ़ा चुके प्रधानमंत्री यह तय कर चुके थे कि गंगा की सफाई भी तभी परवान चढ़ेगी जब वह खुद इसके लिए उतरेंगे। दरअसल कानपुर का चुनाव ही इसलिए किया गया, क्योंकि गंगा यहीं सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। माना जा सकता है कि यह शुरुआत है। प्रधानमंत्री अब खुद गंगा की निगरानी भी रखेंगे और जरूरत हुई तो ऑन स्पॉट बैठकें भी करते रहेंगे।

नरेंद्र मोदी। फाइल

प्रधानमंत्री के इस निर्णय के पीछे पृष्ठभूमि है। साढ़े पांच साल पहले मोदी जब वाराणसी से नामांकन करने गए थे तो कहा था कि 'मुझे गंगा माता ने बुलाया है।' दरअसल यह संकल्प था कि वह गंगा की पीड़ा अब दूर करेंगे। 2014 में सरकार बनते ही उन्होंने नमामि गंगे के नाम से योजना शुरू कर तत्काल बड़ी राशि भी आवंटित कर दी थी। पहले उमा भारती को इसकी जिम्मेदारी थी और जब लगा कि कार्य अपेक्षा अनुरूप सिरे नहीं चढ़ रहा है तो नितिन गडकरी जैसे अनुभवी मंत्री को लगाया। पिछले कुछ वर्षों में जाहिर तौर पर काम बढ़ा है, लेकिन तय समयसीमा में काम पूरा करने के आदी प्रधानमंत्री इससे संतुष्ट नहीं हैं। वह इसी कार्यकाल में गंगा को किया गया वादा पूरा करना चाहते हैं, जहां गंगा अपने गौरव में दिखे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने कानपुर का चुनाव किया जहां गंगा का पानी आचमन तो दूर नहाने लायक भी नहीं माना जाता है। टैनरी को हटाने और दूसरी जगह स्थानांतरित करने का काम बहुत गति नहीं पकड़ पाया, इस काम में लगाए गए अफसरों का उत्साह कभी भी परिलक्षित नहीं हुआ। सूत्रों की मानें तो पीएमओ को अहसास होने लगा था कि कहीं न कहीं सुस्ती है और वह शिथिलता तभी जाएगी जब प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतरेंगे।

बताते हैं कि इस क्रम में प्रदूषित करने वाली फैक्ट्रियों को पूरी तरह नियम-कायदे की हद में लाने और जहां तक संभव हो उसे गंगा से दूर स्थापित करने की भी कोशिश होगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी संयंत्रों को चालू किया जाएगा, लेकिन गंगा के किनारे बसे लोगों को विस्थापित नहीं किया जाएगा। उन्हें केवल जागरूक बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गंगा स्वच्छ रहे। दरअसल पूरी कवायद है कि कानपुर और उन्नाव से आगे भी गंगा का पानी उतना निर्मल रहे जितना ऊपर से आता है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने कानपुर में गंगा के बीच ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक करने का निर्णय लिया है वह संकेत भी है कि सभी राज्यों को उचित कदम उठाने होंगे। केवल कानपुर के सिर पर ठीकरा फोड़कर बचा नहीं जा सकता है। अभी सरकार के महज छह महीने पूरे हुए हैं और प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ही ऑन स्पॉट बैठक करने का निर्णय लेकर स्पष्ट कर दिया है कि अब देरी उन्हें बर्दाश्त नहीं है।

अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा विचार

सुनवाई ▶ संविधान पीठ में पांचवें सदस्य के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना हुए शामिल

- याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की जरूरत पर होगा निर्णय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को विचार करेगा। कोर्ट तय करेगा कि याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की जरूरत है कि नहीं। कुल 18 याचिकाएं गुरुवार की सूची में सुनवाई के लिए लगी हैं। इस बीच बुधवार को निर्मोही अखाड़ा ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कोर्ट से कुछ पहलुओं पर फैसले को स्पष्ट करने का अनुरोध किया है।

याचिकाओं में कोर्ट से नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है। नौ नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए अयोध्या में पूरी विवादित जमीन मंदिर बनाने के लिए दे दी थी। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया था। फैसले के खिलाफ कुल 19 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिनमें से 18 गुरुवार को विचार के लिए लगी हैं। नौ नवंबर का फैसला तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया था।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक पुनर्विचार याचिकाओं पर वही पीठ विचार करती है जिसने मूल फैसला सुनाया है। इस मामले में जस्टिस रंजन गोगोई सेवानिवृत हो चुके हैं, इसलिए पीठ में पांच न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने के लिए जस्टिस संजीव खन्ना को शामिल किया गया है। पुनर्विचार याचिका पर फैसला देने वाले न्यायाधीश सर्कुलेशन के जरिये चैंबर में विचार करते हैं। चैंबर में फाइल और रिकार्ड देखकर अगर कोर्ट को लगता है कि मामले पर खुली अदालत में सुनवाई की जरूरत है, तब कोर्ट याचिका पर नोटिस जारी करता है और मामले को सुनवाई के लिए खुली अदालत में लगाने का आदेश देता है। कोर्ट के नियम के मुताबिक किसी भी फैसले पर कोर्ट पुनर्विचार तब करता है, जबकि फैसले में साफ तौर पर कानूनी या तथ्यपरक खामी हो।

अयोध्या मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने वाले पक्षकारों में कुल नौ मूल पक्षकारों की ओर से पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई हैं। बाकी याचिकाएं ऐसे लोगों ने दाखिल की हैं जो मूल मुकदमे में पक्षकार नहीं थे। हिंदू पक्ष की ओर से हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

याचिका में पक्षकारों की मांग

हिंदू महासभा की याचिका में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का विरोध किया गया है। जबकि निर्मोही अखाड़ा ने अपनी याचिका में कोर्ट से मांग की है कि वह ट्रस्ट में उसकी भूमिका और प्रतिनिधित्व के बारे में स्थिति स्पष्ट करे। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि निर्मोही अखाड़ा को ट्रस्ट में उचित भूमिका और उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, लेकिन उसमें भूमिका और प्रतिनिधित्व की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही अखाड़ा ने फैसले में उसका शैबियत राइट्स (सेवा-पूजा का अधिकार) नकार दिए जाने के अंश को चुनौती दी है। अखाड़ा ने कहा है कि उसका सेवा-पूजा का अधिकार न माना जाना गलत है। मुकदमे में किसी भी पक्षकार ने उसके शैबियत राइट्स को चुनौती नहीं दी थी। सुनवाई के दौरान समय की कमी के कारण उन्हें इस मुद्दे पर साक्ष्य रखने और तर्क पेश करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। मुस्लिम पक्ष ने पुनर्विचार याचिकाओं में कहा है कि जब कोर्ट ने माना है कि विवादित ढांचा मस्जिद थी तो फिर उनका हक नकारने का फैसला ठीक नहीं है।

डोभाल ने उप्र की सराहना की

नई दिल्ली, एएनआइ : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य प्रशासन की सराहना की। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को डोभाल ने लिखे अपने पत्र में कहा है, 'अयोध्या फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में स्थिति संभालने में उल्लेखनीय प्रयासों के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। राज्य के सभी अंगों और केंद्र सरकार के साथ सहयोग बनाए रखने और शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में पुलिस के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं।'

1484 सैन्य अधिकारी दे चुकी है गया की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी

जागरण संवाददाता, गया

गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (ओटीए) के बंद करने के रक्षा मंत्रालय के फैसले से सामाजिक, राजनीतिक, किसान-मजदूर संगठनों, बुद्धिजीवी और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। अपने-अपने स्तर से सभी विरोध दर्ज करा रहे हैं। यह बिहार की एकमात्र ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है। देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम ने 1976 में गया में सेना सेवा कोर केंद्र उत्तर (एएससी नॉर्थ) की स्थापना की थी। उस वक्त से लेकर अब तक इस स्थल पर पर्याप्त संख्या में पौधारोपण किया गया। इससे गया शहर का जलवायु, पर्यावरण में काफी बदलाव हुआ। प्राकृति आपदा, सुरक्षा के साथ-साथ अर्थव्यवस्था, व्यवसाय एवं सेना में नौजवानी के बहाली आदि में काफी सुविधा प्राप्त हुई। यहां से पिछले आठ वर्षों में सेना को 1484 अधिकारी मिले। 2011 में एएससी नॉर्थ को हटाकर ओटीए की स्थापना की गई। एएससी सेंटर नॉर्थ को यहां से बेंगलुरु भेजा गया। इसी तरह अब ओटीए गया को बंद कर इसे देहरादून और चेन्नई स्थानांतरित करने की तैयारी चल रही है।

800 के बेरोजगार होने का खतरा : ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक प्रो. विजय कुमार मिट्ठू ने रक्षा मंत्री को पत्र भेजकर इसे रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसे रहते हुए दूसरे रेजीमेंट के जवानों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। भेजे गए पत्र में 11 बिंदुओं का जिक्र किया है। इसमें कहा गया है कि ओटीए स्थानांतरण होने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 800 लोग बेरोजगार होंगे। इससे यहां नागरिक व व्यवसाय जुड़ा हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण पर पुनर्विचार किया जाए।

आठ सौ करोड़ हुए थे खर्च : 2017 की पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट जनरल बीएस नेगी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि यहां तैयार होने वाले आफिसर्स को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे देश के अलग-अलग क्षेत्र में कुशल नेतृत्व प्रदान कर सकें। यहां भारत ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, वियतनाम, भूटान जैसे देशों के युवकों को भी प्रशिक्षण देकर आफिसर्स के लिए तैयार गया था। इसे सशक्त, समृद्ध और बेहतर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 800 करोड़ रुपये खर्च किए थे। फायरिंग रेंज, लांग रेंज सहित अन्य सभी तरह की सुविधाओं से सुसज्जित किया गया था। ओटीए का परिसर प्राकृतिक संसाधनों से आच्छादित व गया अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से सटा है। दो दिशा से पहाड़ों से घिरे होने के कारण यह अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए बेहतर माना जाता है। शूटिंग रेंज, गोल्फ रेंज की आदि की सुविधा ओटीए परिसर के पूरब में है, जबकि अन्य प्रशिक्षण आतंरिक हिस्से में दिया जाता है। एयरपोर्ट नजदीक होने के कारण फ्लाइंग प्रशिक्षण की सुविधा भी यहां उपलब्ध है।

सिख लाइट इंफेंटरी सेंटर के आने की चर्चा जोरों पर

सूत्र बताते हैं कि गया में ओटीए के बंद होने के बाद विशाल भूखंड खाली नहीं रहेगा बल्कि सिख लाइट इंफेंटरी सेंटर, फतेहगढ़ (उत्तर प्रदेश) को लाया जाएगा। हालांकि, अभी इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

माल्या को दिवालिया घोषित कर संपत्ति जब्ती की मांग

- लंदन कोर्ट में भारतीय बैंकों की याचिका पर फैसला सुरक्षित

लंदन, प्रेट्र : भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के मामले में स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों ने लंदन कोर्ट से दिवालिया घोषित कर उसकी संपत्ति जब्त कराने की मांग की है। माल्या इन भारतीय सरकारी बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा लेकर फरार हो चुका है और कई वर्षों से ब्रिटेन में रह रहा है। बुधवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

न्यायाधीश माइकेल ब्रिग्स की अध्यक्षता वाली कोर्ट की बेंच बैंकों की याचिका पर सुनवाई कर रही है। यह याचिका 2018 में दायर की गई थी। माल्या ने बैंकों से यह कर्ज बंद हो चुकी अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था। बैंकों की ओर से पेश वकील मर्सिया शेकरडेमियां ने कहा, हम अपने कर्ज से कम धनराशि स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा हम क्यों करें ? कोर्ट में यह सवाल माल्या की ओर से यह प्रस्ताव आने के बाद उठा कि भारत और दुनिया भर से जब्त माल्या की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। इसलिए अब मामला चलाए जाने की जरूरत नहीं है। बैंकों की ओर से बताया गया कि जब्त संपत्ति का मूल्यांकन उनके दिए कर्ज से कम है। इसलिए ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

बैंकों ने फ्रांस के एक विला, ब्रिटेन में वर्जिन द्वीप और अन्य स्थानों की संपत्ति, कैरेबियाई देश सेंट किट्स एंड नेविस में मौजूद अचल संपत्ति और इंडियन इंप्रेस सुपरयाट की जब्ती के लिए आदेश पारित करने की मांग की है। बैंकों की वकील ने कहा, माल्या की संपत्ति को हम उनके आभासी मूल्य के आधार पर स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि उनमें से कई संपत्तियां निष्प्रयोज्य या जर्जर हो चुकी हैं। भारत में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की उल्लेख करते हुए माल्या के वकीलों ने कहा कि उनके मुवक्किल की बकाएदारी से ज्यादा संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं, इसलिए कोर्ट से ऐसे किसी की आदेश की जरूरत नहीं है। इसलिए बैंकों की याचिका खारिज की जाए।

पांच माह से चीन की हिरासत में पंजाब का मर्चेंट नेवी अफसर

जासं, जगराओं (लुधियाना) : भारतीय मर्चेंट नेवी के अफसर जगबीर सिंह पांच माह से चीनी पुलिस की हिरासत में हैं। मुंबई की मारविन कंपनी का शिप लेकर गए पांच अन्य क्रू सदस्य तो रिहा हो गए, लेकिन जगबीर अब भी नहीं लौटे हैं। परिजनों के मुताबिक चीन रवानगी से पहले कंपनी ने जगबीर को बताया था कि सभी आवश्यक कागजात पोर्ट पर सौंपे जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचते ही चीन की पुलिस ने शिप को घेरे में लेकर स्टाफ को हिरासत में ले लिया। जगबीर पूरे दस्तावेज नहीं दिखा सके। 31 वर्षीय जगबीर सिंह जगराओं के गांव चीमा के अकाली सरपंच परमिंदर सिंह के बेटे हैं।

परिवार ने पीएम और विदेश मंत्री से की अपील : परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विदेश मंत्री एस. जयशंकर से हस्तक्षेप की अपील की है। जगबीर के पिता सरपंच परमिंदर सिंह ने बताया कि जगबीर उनका इकलौता बेटा है। उसने 2009 में मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी। इसी साल उसने मारविन कंपनी ज्वाइन की थी।

सैनिक स्कूल में शिक्षक ने छह माह में 12 बच्चों से किया कुकर्म

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान के झुंझुनूं जिले के दोरासर स्थित सैनिक स्कूल में तैनात एक शिक्षक ने विगत छह माह के दौरान एक दर्जन बच्चों के साथ कुकर्म किया। कुकर्म करने के बाद शिक्षक उन्हें किसी को बताने पर जान से मारने या परीक्षा में फेल करने की बात कह कर धमकाता रहा। सभी पीड़ित बच्चे दस से बारह साल की उम्र के हैं।

मामले का पर्दाफाश तब हुआ, जब एक पीड़ित बच्चे ने पिछले दिनों स्कूल की शिकायत पेटी में अपना शिकायती पत्र डाला। मामला स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंचा तो उन्होंने सात दिसंबर को शिक्षक रवींद्र सिंह के खिलाफ झुंझुनूं के सदर थाने में मामला दर्ज कराया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने आरोपित शिक्षक रवींद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पॉक्सो में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर रहे झुंझुनूं के पुलिस उप अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी ने बताया कि आरोपित शिक्षक झुंझुनूं के ही जयपहाड़ी का रहने वाला है। उसका परिवार बीकानेर में रहता है। उसकी पत्नी भी शिक्षिका है। आरोपित शिक्षक वर्तमान में दोरासर गांव स्थित स्कूल कैंपस में ही रहता है और यहीं पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि बच्चों ने पहले भी इस बाबत शिकायत पेटिका में पत्र डाला था। लेकिन शिक्षक ने उसे गायब कर दिया था। आरोपित शिक्षक को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल : इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। मामला सात दिसंबर को दर्ज हो गया, लेकिन पुलिस ने आरोपित शिक्षक को 10 दिसंबर को गिरफ्तार किया। मामला सार्वजनिक होने पर हंगामा होने के भय से पुलिस ने इस प्रकरण को दबाए रखा। न तो स्कूल जाकर अन्य शिक्षकों से पूछताछ की और न ही पीड़ित बच्चों से बात की। बुधवार को स्कूल के ही शिक्षकों ने जब पूरे प्रकरण की जानकारी स्थानीय लोगों को दी तो मामला सार्वजनिक हुआ।

जम्मू-कश्मीर के सैन्य प्रतिष्ठान व आयुध डिपो के आसपास निर्माण पर रोक

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर में अब प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों और आयुध डिपुओं के आसपास 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर कोई पहले से ही भवन या इमारत मौजूद है तो उसका मालिक मरम्मत भी नहीं करा सकेगा। अलबत्ता, जिला प्रशासन और संबंधित सैन्य अधिकारियों की अनुमति के आधार पर निर्माण या मरम्मत की जा सकती है।

श्रीनगर और कुपवाड़ा जिला प्रशासन ने हाल ही में इस संदर्भ में वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट (वोडा), 1903 के तहत इस संदर्भ में आवश्यक अधिसूचनाओं को भी जारी कर दिया है। जल्द ही जम्मू कश्मीर के अन्य जिलों में भी यह पाबंदी लागू हो जाएगी। राज्य गृह विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि यह पाबंदी सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है। यह नियम पूरे भारत में लागू है। वहीं श्रीनगर स्थित सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम न छापने पर कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार इस तरह की पाबंदी को 2 जुलाई 2004 को एसआरओ-96 के तहत लागू करने का प्रयास किया गया था।

उपलब्धि

अंतराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस पर विशेष डाक कवर रिलीज, आइपीएस अधिकारी अपर्णा सातों महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर भारत का झंडा लहराने वाली प्रथम पुलिस अधिकारी बनी थीं

अपर्णा के दक्षिणी ध्रुव के अभियान पर डाक टिकट जारी

जागरण संवाददाता, देहरादून

दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली आइपीएस अधिकारी और डीआइजी (आइटीबीपी) अपर्णा कुमार के सम्मान में डाक विभाग ने विशेष डाक कवर जारी किया है। सीमाद्वार स्थित आइटीबीपी परिसर में अंतराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसका अनावरण किया। उन्होंने अपर्णा को न केवल महिला सशक्तिकरण, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए मिसाल बताया। बता दें जून 2019 में अपर्णा कुमार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का में स्थित सर्वोच्च चोटी माउंट डेनाली पर तिरंगा फतह करने के साथ ही सातों महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर भारत का झंडा लहराने वाली प्रथम पुलिस अधिकारी बनी थीं। 13 जनवरी 2019 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम आइपीएस अधिकारी होने का गौरव भी उन्हें ही प्राप्त है। उनका अगला लक्ष्य 2020-21 में उत्तरी ध्रुव में तिरंगा लहराकर एक्सक्लूसिव क्लब में प्रवेश करना है, इस कामयाबी के बाद वह इस क्लब में पहुंचने वाली पहली महिला सिविल सर्वेंट व आइपीएस अधिकारी बन जाएंगी। हाल ही में उन्हें तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक विशेष डाक कवर रिलीज किया। यह उनके दक्षिणी ध्रुव के अभियान पर आधारित है।

दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आइपीएस अफसर अपर्णा कुमार की उपलब्धि पर बुधवार को देहरादून में डाक टिकट जारी किया गया। आइटीबीपी के परिसर में अंतरराष्ट्रीय माउंटेन दिवस पर आयोजित समारोह में डाक टिकट जारी करते (बाएं से) उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आइटीबीपी के पूर्व सलाहकार सोनम पल्जोर, उत्तरी फ्रंटियर मुख्यालय के महानिरीक्षक नीलाभ किशोर और डीआइजी अपर्णा कुमार। जागरण

अपर मुख्य सचिव ने अपर्णा को बधाई देते हुए कहा कि उनकी इस सफलता से हम सभी गौरान्वित हैं। अपर्णा ने दिखा दिया है कि बेटियां की किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने आइटीबीपी की भी जमकर प्रशंसा की। कहा कि बेहद सीमित संसाधनों में आइटीबीपी बेहतर कार्य कर रही है। खासकर आपदा के समय। निदेशक डाक विभाग सुनील राय ने कहा कि अपर्णा ऐसी लीडर हैं, जो अपने फॉलोवर नहीं, बल्कि लीडर तैयार करती हैं।

संघर्षों ने दिया बढ़ते रहने का हौसला : बंगलुरु निवासी अपर्णा ने जिंदगी में तमाम-उतार चढ़ाव देखे हैं। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया था, ऐसे में घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां के कंधों पर आ गई। बताती हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी रहीं मां अश्विनी ने उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी।

यहां फहराया तिरंगा : अपर्णा कुमार ने जिन शिखर पर झंडा फहराया है, उनमें माउंट एवरेस्ट (एशिया), माउंट किलिमंजारों (तंजानिया, अफ्रीका), माउंट एल्ब्रस (यूरोप), कार्सटेंस पिरामिड (इंडोनेशिया), विन्सन मैसिफ (अंटार्कटिका), माउंट एकांकागुआ (दक्षिणी अमेरिका), माउंट डेनाली (अलास्का) शामिल हैं। वह दक्षिणी ध्रुव पर भी तिरंगा फहरा चुकी हैं। अब उनका अगला लक्ष्य उत्तरी ध्रुव है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, सरल हो एफआइआर की भाषा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि एफआइआर (प्राथमिक सूचना रिपोर्ट) में कठिन शब्दों के प्रयोग से बचें हालांकि सामान्य उर्दू और फारसी शब्दों का इस्

दैनिक जागरण

हम खुश होने के कारण नहीं हंसते, हंसने के कारण खुश होते हैं

गुमराह राजनीति

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों में उग्र प्रदर्शन और हिंसा यही बताती है कि किसी मसले पर लोगों को गुमराह करने के क्या नतीजे होते हैं? पूर्वोत्तर में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध का औचित्य इसलिए नहीं बनता, क्योंकि इस क्षेत्र के ज्यादातर भाग इस विधेयक के दायरे में ही नहीं आते। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे लोकसभा और साथ ही राज्यसभा में बार-बार स्पष्ट भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्वोत्तर के कुछ उन इलाकों को भी इस विधेयक के दायरे से बाहर करने का स्पष्ट आश्वासन दिया जहां के नागरिक इससे आशंकित थे कि बाहर से आए लोग उनके यहां बस सकते हैं। कायदे से इस सबके बाद असम, त्रिपुरा और अन्य हिस्सों में नागरिकता विधेयक के विरोध में धरना-प्रदर्शन करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसी कारण संकीर्ण राजनीतिक कारणों से लोगों को बरगलाया और उकसाया गया। यह काम पूर्वोत्तर के बाहर भी किया जा रहा है। राजनीतिक शरारत के तहत यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद भारतीय मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

कुछ राजनीतिक दलों के रुख-रवैये से यह साफ है कि वे नागरिकता विधेयक की आड़ लेकर भारतीय मुसलमानों को गुमराह करने के लिए छल-प्रपंच का सहारा लेने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इस छल-प्रपंच में कुछ कथित बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। वे ऐसी फर्जी कहानियां गढ़ने में लगे हुए हैं कि उनके गांव-घर के मुस्लिम आशंकित होकर यह पूछ रहे हैं कि उनके पास कितना समय है अथवा अब उन्हें क्या करना होगा? इस तरह की झूठी कहानियां गढ़ने वाले निंदा और भर्त्सना के पात्र बनाए जाने चाहिए। आखिर जब इस विधेयक का भारत के किसी भी नागरिक से कोई लेना-देना ही नहीं और यह बाहर से प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है, न कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनने का तब फिर यह माहौल बनाने का क्या मतलब कि भारतीय मुसलमानों के लिए खतरा बढ़ने वाला है? यह माहौल बनाने वाले केवल झूठ फैलाने का ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के अमन-चैन से भी खेल रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार को नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर भ्रम फैलने से रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए। उसे भ्रम निवारण का यह काम पूर्वोत्तर में कहीं अधिक तत्परता से करना होगा। हालांकि पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष की हर आपत्ति का जवाब दिया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ विपक्षी दल झूठ का पहाड़ खड़ा करने की तैयारी करते दिख रहे हैं।

खनिज से विकास

झारखंड की पहचान अपनी रत्नगर्भा धरती से पूरे विश्व में है। वैसे तो पूरे राज्य में अलग-अलग किस्म के खनिज के भंडार हैं, लेकिन पूर्वी सिंहभूम से एक खबर उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। वहां स्वर्ण खनिज की उपलब्धता का पता चला है। भूतत्व विभाग की टीम को पोटका क्षेत्र में स्मोकी क्वार्ट्ज में स्वर्ण खनिज के अंश मिले हैं। इलाके में यह पत्थर बहुतायत में है। इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि यदि सही तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए काम किया जाए तो स्मोकी क्वार्ट्ज से बड़े पैमाने पर सोना निकाला जा सकता है। भूतत्व विभाग की इस नवीनतम रिपोर्ट के बाद पूर्वी सिंहभूम समेत उन सभी इलाकों में सघन खोज अभियान चलाया जाना चाहिए, जहां धरती के भीतर स्वर्ण भंडार की संभावना है। स्वर्ण खनिज के व्यावसायिक खनन से झारखंड में विकास नए अंदाज में दस्तक दे सकता है। इससे न सिर्फ सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। सिर्फ स्वर्ण खनिज ही नहीं, अन्य दूसरे खनिजों के संरक्षण, संवर्धन और व्यावहारिक तरीके से खनन करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनना चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह होनी चाहिए कि पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों की पूरी तरह रक्षा करते हुए खनन कार्य का मार्ग प्रशस्त हो। खदानों की नीलामी और इससे जुड़ी सभी प्रक्रिया में पारदर्शिता और कायदे-कानून के अनुपालन की शत-प्रतिशत गारंटी की अनिवार्यता तो सुनिश्चित करनी ही होगी। अमूमन होता यह है कि खनन के एवज में मिलने वाले राजस्व की हिस्सेदारी का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर समानुपातिक तरीके से नहीं हो पाता है। इस सुझाव पर भी अमल किया जाना चाहिए कि प्रखंड स्तर पर किसी ऐसी निष्पक्ष एजेंसी का संचालन किया जाए जो खनन को लेकर मूल निवासियों के हितों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार एवं जवाबदेह हो। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण का खास ध्यान रखते हुए उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का काम करे।

स्वर्ण खनिज के व्यावसायिक खनन से झारखंड में विकास नए अंदाज में दस्तक दे सकता है। इससे न सिर्फ सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। राज्य में खनिजों के संरक्षण, संवर्धन और खनन के लिए एक ब्लूप्रिंट बनना चाहिए

नया इतिहास रचते मोदी-शाह

प्रदीप सिंह

नागरिकता विधेयक के जरिये सरकार ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि वह जिन बातों को देशहित में समझती है उन्हें करने के लिए वह राजनीतिक हित-अहित की चिंता नहीं करती

अवधेश राजपूत

भाजपा विरोधियों का यह आरोप रहा है कि वह देश का संविधान और इतिहास बदलना चाहती है। विरोधी बार-बार ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं जिससे लगे कि उनके आरोप में दम है। विपक्ष का सारा ध्यान संविधान और इतिहास की किताबों, प्रतीकों पर है। उन्हें अब पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह न केवल देश बदल रहे हैं, बल्कि नया इतिहास भी रच रहे हैं। भाजपा और संघ परिवार के एजेंडे को आज जैसी राष्ट्रीय स्वीकृति पहले कभी नहीं मिली। आज मोदी सरकार के काम का विरोध करने वालों को पहले सफाई देनी पड़ती है कि वह राष्ट्रहित के खिलाफ नहीं है। हालत यह है कि पिछले करीब छह साल से सांप्रदायिकता शब्द राष्ट्रीय विमर्श से गायब हो गया है।

मोदी सरकार देश का मानस बदल रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि लोग इस बदलाव के लिए तैयार हैं। वास्तव में यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि वह भारतीय समाज को उसकी जड़ों की ओर वापस ले जा रही है। जो काम आजादी के बाद ही शुरू हो जाना चाहिए था वह अब हो रहा है। इस देश की आत्मा भारतीय संस्कृति में बसती है। पिछले सात दशकों में हिंदू विरोध और धर्म निरपेक्षता पर्यायवाची बन गए थे। नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करने वाले पता नहीं क्यों बांग्लादेश और पाकिस्तान से अवैध रूप से आए मुसलमानों के हक के लिए खड़े हैं?

भाजपा का मानना है कि देश के धर्म के आधार पर हुए बंटवारे का एजेंडा पूरा नहीं हुआ है। यही बात संविधान सभा में सरदार भूपिंदर सिंह मान ने उठाई थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं-सिखों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 19 जुलाई 1948 को कट ऑफ डेट क्यों तय किया गया है? इसके बाद पाकिस्तान में जिन हिंदुओं-सिखों का उत्पीड़न होगा उनके लिए भारत के दरवाजे क्यों बंद किए गए हैं? पीएस देशमुख ने तो यहां तक कहा कि हिंदू और सिख जहां भी हों, अगर किसी और देश के नागरिक न हों तो उन्हें भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए।

देश के बंटवारे के बाद पलायन की समस्या की शुरुआत उस समय हुई जब दिसंबर 1949 में भारत पाकिस्तान के आर्थिक संबंध टूट गए। दस लाख लोगों ने दोनों देशों की सीमा पार की। इसके बाद आठ अप्रैल 1950 को नेहरू-लियाकत समझौता हुआ। तय हुआ कि दोनों देश अपने यहां के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि जो भागकर आए हैं उन्हें लौटकर अपनी संपत्ति बेचने का अधिकार होगा, अपहृत औरतों को लौटाना होगा और जबरन कराया गया धर्म परिवर्तन अमान्य किया जाएगा, लेकिन कुछ ही महीने बाद पाकिस्तान से दस लाख हिंदू भागकर भारत आ गए। तब सरदार पटेल ने पाकिस्तान को धमकी दी कि यह एकतरफा नहीं चल सकता। पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसे नतीजा भुगतना होगा। इसके बाद पलायन का सिलसिला रुका, पर 1950 में सरदार का निधन हो गया। इसके बाद क्या हुआ, यह बताने की जरूरत नहीं है।

अतीत से लौटकर वर्तमान में आते हैं। घुसपैठ का मुद्दा हमेशा से भाजपा के एजेंडे पर रहा है, लेकिन उसके समर्थक भी मानते थे कि इस मुद्दे पर भाजपा जो भी कहती है वह एक राजनीतिक दिखावा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त अमित शाह हर चुनावी सभा में कहते थे कि एक-एक घुसपैठिये को चुन-चुन कर बाहर निकालेंगे। तब भी कम ही लोगों को यकीन था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर से चुनकर आने पर तीन तलाक, कश्मीर में अनुच्छेद 370 एवं 35-ए पर सरकार के कदम के बाद मोदी-शाह की विश्वसनीयता ऐसी हो गई है कि वे जो भी वादा करेंगे, लोग भरोसा करने को तैयार हो जाएंगे।

नागरिकता बिल पर लोकसभा में बहस के दौरान गृह मंत्री ने एक बार नहीं कई बार कहा कि कैब कोई बहाना नहीं है, एनआरसी (नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर) लाने का। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एनआरसी आएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह काम पूरा कर लिया जाएगा। यह करने का हमें जनादेश प्राप्त है।

पिछले साढ़े पांच साल में इस सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आइबीसी, रेरा, तीन तलाक, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 एवं 35-ए हटाने और अब नागरिकता संशोधन विधेयक जैसे बहुत से कदम उठाए हैं। इनके जरिये सरकार ने एक संदेश दिया है कि वह जिन बातों को देशहित में समझती है उसे करने के लिए वह राजनीतिक हित-अहित की चिंता नहीं करती। सरकार और भाजपा पर आरोप है कि नागरिकता संशोधन विधेयक और एनआरसी भारत को हिंदू राष्ट्र या धुर दक्षिणपंथ की ओर ले जा रहा है। वास्तविकता इसके इतर है। दरअसल देश उन नव औपनिवेशिक कुलीनों के प्रभाव से मुक्त हो रहा है, जिन्होंने देशवासियों को भारतीय संस्कृति से दूर रखने का षडयंत्र किया। इस वर्ग को अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आ रहा है। इसकी अभिव्यक्ति कभी कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों, कभी एनजीओ, कभी मुट्ठीभर बुद्धिजीवियों की अपीलों और सुप्रीम कोर्ट में कथित जनहित याचिकाओं के रूप में सामने आती रहती है। मामला कश्मीर में बदलाव का हो या नागरिकता संशोधन विधेयक का, अमित शाह के जिक्र के बिना पूरी नहीं हो सकती। अमित शाह से देश के लोगों का पहला परिचय कांग्रेस सरकार ने करवाया, एक झूठे मामले फंसाकर। उनका दूसरा परिचय 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनने पर हुआ। उनका तीसरा परिचय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हुआ। उनका चौथा परिचय देश के गृह मंत्री के रूप में हुआ। उन्होंने प्रत्येक अवसर पर लोगों को चौंकाया। उनकी बेबाकी से तो लोग परिचित हो चुके थे, लेकिन लोकसभा में आने के बाद एक सांसद के रूप में उनकी क्षमता हैरान करने वाली है। पहले अनुच्छेद 370 और फिर नागरिकता संशोधन विधेयक पर वे जिस स्पष्टता, आत्मविश्वास, दृढ़ता और तथ्यों के आधार पर बोले वैसा कब कौन गृहमंत्री बोला था, याद करना कठिन है। उद्योगपति राहुल बजाज ने एक कार्यक्रम में अमित शाह से पूछा था कि लोग उनसे डरते क्यों हैं? वास्तविकता यह है कि सच और खरी बात कहने वालों से लोग अक्सर डरते ही हैं।

नागरिकता विधेयक के कानून बनने, एनआरसी लागू होने और अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के बहुसंख्यक समाज के मन में अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक होने का दंश निकल रहा है। इनका विरोध करने वालों के एक बात समझ लेनी चाहिए कि इस देश में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं की उपेक्षा करके धर्म निरपेक्ष समाज की स्थापना नहीं हो सकती।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

भूल सुधार है नागरिकता विधेयक

विकास सारस्वत

नागरिकता संशोधन विधेयक विशिष्ट परिस्थितियों से उत्पन्न मानवीय संकट का प्रतिउत्तर है

वर्ष 1979 का जनवरी का महीना था। पश्चिम बंगाल के दलदली सुंदरबन डेल्टा में मरीचझापी नामक द्वीप पर बांग्लादेश से भागे करीब 40,000 शरणार्थी एकत्रित हो चुके थे। मुख्यतः दलित हिंदुओं का यह समूह उस महापलायन का एक छोटा-सा हिस्सा था जिसमें बांग्लादेश बन जाने के बाद से लगभग एक करोड़ उत्पीड़ित हिंदू भारत आ कर विभिन्न स्थानों पर बस चुके थे। जिन विस्थापितों की पैरवी कर कम्युनिस्टों ने पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की थी, सत्ता में आने के बाद उन्हीं शरणार्थियों के प्रति वामपंथी सरकार का रवैया उपेक्षा से हट कर क्रूरता तक पहुंच गया। शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल आने से रोका जाने लगा। इसी क्रम में मरीचझापी में बस गए शरणार्थियों को वन्य कानूनों का हवाला दे कर वहां से भगाने का कुचक्र चला गया। 26 जनवरी को मरीचझापी में धारा 144 लागू कर दी गई। फिर उस टापू को सौ मोटरबोट से घेर लिया गया। दवाई, खाद्यान्न सहित सभी वस्तुओं की आपूर्ति रोक दी गई। पांच दिन बाद 31 जनवरी 1979 को पुलिस फायरिंग में शरणार्थियों का बेरहमी से नरसंहार हुआ। चूंकि करीब 30,000 शरणार्थी मरीचझापी में फिर भी डटे हुए थे इसलिए उन्हें खदेड़ने के लिए मई में एक बार फिर भारी पुलिस दल वहां पहुंचा। इस बार पुलिस के साथ वामपंथी कैडर भी था। करीब तीन दिन तक हिंसा का नंगा नाच चला। दीप हलदर ने अपनी पुस्तक 'ब्लड आइलैंड' में इस घटना का बहुत ही दर्दनाक विवरण दिया है। बचे शरणार्थियों को ट्रकों में जबरन भर कर दुधकुंडी कैंप में भेज दिया गया। बासुदेव भट्टाचार्य विधानसभा पहुंचे और विजयघोष किया कि 'मरीचझापी को शरणार्थियों से मुक्त करा लिया गया है।' बाद में वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने। बंटवारे की विभीषिका के बाद भी जो दोहरी मार हिंदुओं पर पड़ती रही है, मरीचझापी उसकी एक बानगी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरवाद को मिली छूट से त्रस्त हिंदू जब जान बचा कर धर्मनिरपेक्ष भारत में आते तो यहां कभी उपेक्षा मिलती और कभी तिरस्कार। एक तरफ हत्या, दुष्कर्म, अपहरण और जबरन धर्मांतरण की तलवार लटकती तो दूसरी तरफ भारत में जटिल कानूनी प्रक्रिया या कैंपों में नजरबंदी का खौफ सताता।

गौरतलब है कि उत्पीड़न झेल रहे हिंदू, बौद्ध या सिखों ने बंटवारे की मांग नहीं की थी। बंटवारा उन पर थोपा गया था। 1947 से पाकिस्तान और फिर 1971 के बाद बांग्लादेश में चल रहा जातिसंहार बंटवारे की त्रासदी का ही विस्तृत संताप है। भारत ने इन प्रताड़ित समूहों को अब तक किसी प्रकार की विधिक सहायता प्रदान न कर अनाथ बना कर छोड़ दिया था। नागरिकता विधेयक इस भूल का देर से हुआ प्रायश्चित है। जिन स्वयंभू धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने आज से पहले कभी किसी समूह को सहायता प्रदान करने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने इस विधेयक के आते ही लाभार्थियों की पात्रता पर प्रश्न खड़े कर दिए। अनुच्छेद 14 और 15 का हवाला देकर बिल की संवैधानिकता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विशेषकर अनुच्छेद 14 के दो सिद्धांतों 'इंटेलिजिबल डिफरेंशियल' और 'रीजनेबल नैक्सस' को उद्धृत कर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यह बिल दोनों सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरता। कानूनी भाषा में 'इंटेलिजिबल डिफरेंशियल' का अर्थ वह भेद है जो कारणों की विशिष्टता को स्पष्ट करे। इसी तरह 'रीजनेबल नैक्सस' का अर्थ है विशिष्ट भेद के चलते प्रभावित वर्गों के लिए कानूनी प्रावधान बनाने का तर्कसंगत आधार। नागरिकता विधेयक इन दोनों कसौटियों पर खरा उतरता है। इसी विशिष्ट भेद के चलते कानून में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं।

नागरिकता संशोधन विधेयक विशिष्ट परिस्थितियों से उत्पन्न मानवीय संकट का प्रतिउत्तर है। यदि इतनी बड़ी विभीषिका से प्रभावित लोगों के लिए विशिष्ट भेद के अंतर्गत कानून बनाने का तर्कसंगत आधार नहीं माना जाएगा तो फिर किसे माना जाएगा? इसीलिए विधेयक में सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में त्रस्त अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। जो अनुच्छेद 14 की दुहाई देकर विधेयक का विरोध कर रहे हैं उनके तर्क को माना जाएगा तो फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति को स्वतः भारतीय नागरिकता पाने का हकदार हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों की मनमाफिक व्याख्या करने वाले आलोचक वे लोग हैं जो या तो भारत को संप्रभु, स्वायत्त राष्ट्र न मान कर एक सराय मानते हैं या फिर इन तीन देशों में बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा अल्पसंख्यकों के धार्मिक उत्पीड़न को नकारते हैं।

नेहरू के समय बनाए गए नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा-5 की विभिन्न उपधाराओं में अविभाजित भारत में पैदा हुए नागरिक, उनके विवाहित या नाबालिग बच्चे और पहली पीढ़ी, जो कि एक वर्ष से भारत में रह रही हो, को भी इन्हीं परिस्थितियों वश नागरिकता का प्रावधान मिला था। घुसपैठ को रोकने और अन्य शरणार्थियों की मदद करने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में 1986, 1992, 2003 और 2005 में संशोधन लाए गए। चूंकि समस्या जस की तस रही इसलिए एक और संशोधन पूरी तरह न्यायोचित है।

संविधान की संवेदनहीन शाब्दिक व्याख्या तक सिमटे विरोधियों को विभिन्न अनुच्छेदों से पहले संविधान की प्रस्तावना पर भी जाना चाहिए। संविधान के प्रारंभिक शब्द 'इंडिया दैट इज भारत...' भारतीय गणतंत्र को राष्ट्र-राज्य की मान्यता देते हैं। राष्ट्र-राज्य वह अवधारणा है जिसमें राज्य पुरातन सभ्यता और सांस्कृतिक पहचान का उत्तराधिकारी होता है और उसके ऊपर पुरातन पहचान को बनाए रखने का उत्तरदायित्व होता है। इसी उत्तरदायित्व के पालन में नागरिकता विधेयक द्वारा पड़ोस में प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई धर्मावलंबियों को राहत देना भारतीय संघ की नैतिक एवं संवैधानिक बाध्यता है। संसद द्वारा इस विधेयक का अनुमोदन भारतीय सभ्यता के एक गहरे घाव पर मरहम का काम करेगा। साथ ही यह मरीचझापी में इस्लामी कट्टरवाद द्वारा खींची गई सीमाओं के बीच अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जान देने वालों को हमारी श्रद्धांजलि भी होगी।

(लेखक इंडिक अकादमी से संबद्ध हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

दुखानुभूति

ईश्वर ने जीवन की भिन्न-भिन्न रंगों से अभूतपूर्व रचना की है। मनुष्य कितना भी चाहे कि उसके हिस्से में केवल आनंद ही आनंद रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जहां सुख की लालसा हो, वहां कष्ट झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए। पीड़ा एक सच्चाई है। जहां सुख का सदैव स्वागत होना सर्वथा निश्चित है, वहीं दुख और पीड़ा के आने पर अपने भाग्य को धिक्कारना या दूसरों को उसके लिए उत्तरदायी ठहराना कहां तक तर्कसंगत है? टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर चलने से ही जीवन के कठिनतम पाठ कंठस्थ हो पाते हैं जो जीवनयापन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ करते हैं। जिसने इस संघर्ष को चुनौती के रूप में स्वीकारा हो, उसे झेले गए कष्टों की पीड़ा कम होगी।

दुखानुभूति तो अपनी मनःस्थिति पर निर्भर है। वह निराकार होते हुए भी अति प्रचंड रूप ले सकती है। यह भ्रांति कि समस्त दुख बाह्य परिस्थितियों की देन हैं, और उसका निराकरण चारों ओर के प्रभामंडल को बदलने से ही हो सकता है, उपयुक्त नहीं है। यदि ऐसा होता तो समस्त सुख सुविधाओं से लैस व्यक्ति संसार में सबसे सुखी होता। हमने तो गरीब की झुग्गी-झोंपड़ी से फूटती किलकारियों को सुना है। छोटे से बच्चे को सस्ते से खिलौना पाते ही आनंदविभोर होते और दूसरी ओर वैभव-संपन्न व्यक्ति को बिलखते देखा है। हम अपने कष्टों के प्रति जितने संवेदनशील होंगे, दुख की अनुभति का आभास उतने ही अनुपात में होना निश्चित है। जीवन है तो सुख-दुख आते जाते रहेंगे। जैसे हम आनंद को सहर्ष स्वीकारते हैं, उसी तरह पीड़ा को भी अदम्य साहस से भोगना आना होगा, वरना उससे पार पाना बेहद कष्टकारी होगा।

यह सही है कि जो व्यक्ति दुख से जूझ रहा है, उसकी पीड़ा तो वही समझ सकता है। उसका विश्लेषण दूसरा नहीं कर सकता है, पर दुख के प्रति सकारात्मक सोच व्यक्ति को जीवन के सहज मार्ग पर चलने में सहयोगी अवश्य हो सकती है। दुखानुभूति को चुनौती मान आगे बढ़ने से प्राप्त सफलता फिर एक नई चुनौती को स्वीकारने के लिए तैयार कर देती है।

छाया श्रीवास्तव

रामराज्य की स्थापना की उम्मीद

उदय प्रकाश अरोड़ा

राम के शासन की विशेषता यह थी कि जो जितना त्यागी, निःस्वार्थ था, राम का प्रेम उसके लिए उतना ही अधिक था

गांधी जी का सपना था कि हिंदुस्तान जब आजाद हो तो यहां भारतीय परंपरा के अनुकूल रामराज्य अर्थात रामलला के राज्य की स्थापना हो। भारत के लिए रामराज्य से बेहतर लोकतंत्र का कोई दूसरा नमूना नहीं हो सकता। देशवासियों को रामराज्य और रामलला शब्द भले ही बहुत प्रिय हों, किंतु हमारे तथाकथित प्रगतिशील बंधु ये शब्द सुनते ही भड़क जाते हैं। वे इन्हें उस व्यवस्था को समझते हैं जो राजाओं, सामंतों और पुरोहितों के अधीन हो, स्त्रियों के साथ जहां गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता हो तथा दलितों का उत्पीड़न हो।

फिर गांधी जी ने सुशासन के लिए राम का नाम क्यों लिया? इसका उत्तर है कि वे भारत की आम जनता से जुड़े थे। आम जनता की शब्दावली का प्रयोग उन्होंने इसलिए किया, ताकि वे लोगों के दिलों तक पहुंच सकें। रामराज्य अर्थात ईश्वर का राज्य। ईश्वर केवल राम ही नहीं, रहीम भी हैं। ईश्वर का शासन यानी कि इंसाफ का शासन। राम के शासन में सभी धर्मों के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान रहता था। लोग पहले अपनी गलती मानते थे बाद में किसी दूसरे की। राम का संदेश है कि जो व्यक्ति पहले अपने धर्म की प्रशंसा तथा दूसरे की निंदा करता है, वह स्वयं अपने धर्म की हानि करता है। राम ऐतिहासिक पुरुष थे अथवा भगवान, यह चीज कोई मायने नहीं रखती है। महत्वपूर्ण था तो वह मानववाद, जो राम के राज्य में हमें वाल्मीकि और तुलसी के माध्यम से जानने को मिलता है।

रामराज्य अर्थात स्वराज्य! स्वराज्य में निर्णय सत्ताधिकारी के आधीन न रहकर न्याय और सत्य के अधीन होता है। दूसरे धर्म के लोग राम के अर्थ का अनर्थ न करें इसलिए गांधी जी ने रामराज्य को धर्मराज्य भी कहा। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि रामराज्य, स्वराज्य का चरमोत्कर्ष है। ऐसा रामराज्य होना आज भी संभव है। राम के राज्य में शासक प्रजा के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहता था, पर जो चीज रामराज्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, वह थी राम का दलित प्रेम। राम के शासन की विशेषता यह थी कि जो जितना त्यागी, निःस्वार्थ और दलित था, राम का प्रेम उसके लिए उतना ही अधिक था। चारों वर्णों के लोग एक साथ राजघाट पर स्नान करते थे।

राम के राज्य को एक कल्याणकारी अर्थात सुराज्य के चरमोत्कर्ष का उदाहरण माना जाता है। तुलसी राजा को प्रजा का प्रतिनिधि मानते थे। उन्होंने उसी को सच्चा शासक माना जो पद को प्रजा की सेवा का एक माध्यम मात्र मानता है। कल्याणकारी राज्य का सर्वोत्तम आदर्श है रामराज्य अर्थात धर्म का राज्य, न्याय का राज्य, कर्तव्य पालन का राज्य और सबसे बढ़कर सत्ता का नहीं सेवा का राज्य।

अहिंसा और सहिष्णुता के बिना हिंदू धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। रामलला की स्थापना के बाद हमें पूर्ण विश्वास है कि अहिंसा और 'वसुधैव कुटुंबकम' का जो संदेश भारत ने दुनिया को दिया है वह अब और अधिक मजबूत होगा। रामलला का जहां मंदिर बने वहां सर्वधर्म भाव का संदेश उत्कीर्ण होकर सारी दुनिया में फैले।

(लेखक जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर हैं)

नागरिकता बिल का विरोध क्यों

'उचित आधार वाला नागरिकता बिल' शीर्षक से लिखे अपने लेख में अद्वैता काला ने नागरिकता संशोधन बिल के उद्देश्यों का उल्लेख किया है। विरोधियों को भी इस पर विचार करना चाहिए। विरोध के पीछे इनका तर्क यह है कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 25 में वर्णित आस्था के अधिकार तथा अनुच्छेद 21 में वर्णित दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। वहीं कुछ लोग इसे मुस्लिम समुदाय के साथ भेद-भाव का नाम दे रहे हैं। उनके अनुसार यह समानता के मूल अधिकार का सरासर उल्लंघन है, परंतु विरोधियों को यह बात अवश्य ही समझ लेनी चाहिए कि समानता का नियम कोई जड़ अवधारणा नहीं है। न्याय के अन्य सिद्धांतों की भांति इसमें भी संशोधन हो सकते हैं। किसी वर्ग के साथ यदि जातिगत भेदभाव हो रहे हों तब समानता का सिद्धांत अपने दायरे से बाहर निकलकर समाज के प्रताड़ित लोगों को बराबरी में लाने के लिए आरक्षण के सिद्धांतों को स्वयं में समाहित कर लेता है। इसके अतिरिक्त संविधान में पूर्वोत्तर के कुछ जनजातियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। यह बात निरधार नहीं कि जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान स्वयं को इस्लामिक देश घोषित किए थे तब वहां काफी संख्या में अल्पसंख्यक मौजूद थे, परंतु धीरे-धीरे उनके अधिकारों का हनन होने लगा। ऐसे में इन्हीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मदद देने के लिए इस बिल को लाया गया है। हालांकि यह बिल शरणार्थियों के लिए लाभदायक अवश्य है, लेकिन इसको लेकर सरकार के समक्ष कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। इससे भारत की जनसंख्या तो बढ़ेगी ही साथ ही जिस राज्य में वे शरणार्थी जाएंगे वहां की सांस्कृति प्रभावित होगी एवं कुछ नई समस्याएं भी उभरकर सामने आ सकती हैं। अतः राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस बिल का विरोध करने के बजाय इन चुनौतियों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराएं ताकि इसे सफल बनाया जा सके।

बिन्नी कुमारी, सारण

मेलबाक्स

खतरनाक गलियां

अभी हाल में दिल्ली के अनाज मंडी में स्थिति एक फैक्ट्री में हुए अग्नि कांड में कई श्रमिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतने बड़े अग्निकांड के बाद भी इन घनी बस्तियों में फैक्ट्री आदि चलाने वाले एवं प्रशासन के लोग कोई सबक लेते नहीं दिख रहे। हर घटना के बाद यही होता है। कुछ दिन शोर मचता है फिर सब वैसा ही चलने लगता है। इन होलसेल बाजारों में बिजली के तारो के काफी जंजाल बने हुए हैं। काफी तंग और खतरनाक गालियां हैं, यहां आग बुझाने वाली गाड़ियां भी नहीं जा सकतीं हैं। आखिर ऐसी स्थिति दिल्ली में क्यों है? क्यों नहीं इन फैक्टरियों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया जाता? आखिर कब तक यूं ही लोग मरते रहेंगे? सरकार और प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

बालकृष्ण अमरसरिया, दिल्ली

सुधार की आवश्यकता

दैनिक जागरण के 10 दिसंबर के अंक में प्रकाशित प्रकाश सिंह का लेख, समस्या की जड़ में जाने से इन्कार, पढ़ा। इसमें लेखक ने कई विंदुओं पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। हाल ही में हैदराबाद में महिला चिकित्सक को सामूहिक दुष्कर्म के बाद जिंदा जला देना, उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जला देना, राजस्थान के टोंक जिले की दुष्कर्म पीड़िता की दुष्कर्म के बाद हत्या ऐसी घटनाएं हैं जो जनमानस को झकझोरती ही नहीं, बल्कि यह सोचने पर विवश करती हैं कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। आए दिन महिला उत्पीड़न की घटनाओं की वृद्धि और जनाक्रोश विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करते जा रहे हैं। इसके मूल में प्रशासन तथा पुलिस सुधार तो आवश्यक है ही साथ ही न्यायिक व्यवस्था में भी मूलभूत सुधार की महती आवश्यकता है। मुकदमे का निर्णय विलंब से होना जनमानस में आक्रोश पैदा करता है। हमारे सामने निर्भया केस का मामला है, सात वर्ष हो गए, किंतु अब तक आरोपियों को सजा नहीं मिल सकी। आखिर हम किन परिस्थितियों में मजबूर हैं जो वादों के त्वरित निस्तारण के लिए समयबद्ध योजना नहीं बना पा रहे हैं। मुख्यरूप से महिला उत्पीड़न के मामलों में सुनवाई समयबद्ध होनी ही चाहिए। दीवानी के प्रकरणों में भी वर्षों का समय निर्णय में लग जाना एक प्रकार से पक्षकारों का मानसिक उत्पीड़न और न्याय से इन्कार की परिधि में ही आता है।

munishpawan@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्र

3.7 प्रतिशत खर्च करती है केंद्र सरकार शिक्षा के मद में अपनी जीडीजी का, जबकि मानव विकास सूचकांक में अपना स्थान अधिक सुदृढ़ करने के लिए देश को शिक्षा और स्वास्थ्य के मद में खर्च बढ़ाने की जरूरत है।

आजकल

डाटा सुरक्षा हेतु सख्त कानून की तैयारी

लोकसभा में बुधवार को निजी डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 को पेश कर दिया गया। यह विधेयक सरकार को फेसबुक व गूगल समेत अन्य कंपनियों से गोपनीय निजी डाटा और गैर-निजी डाटा के बारे में पूछने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस विधेयक का कई विपक्षी दलों ने विरोध किया और इसे नागरिकों के 'मूलभूत अधिकारों का हनन' बताया। वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि इस विधेयक से भारतीयों के अधिकारों की रक्षा होगी। ऐसे में इस मामले को समग्रता से जानना जरूरी है

कैलाश बिश्नोई
अध्येता, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रतीकात्मक

हाल के वर्षों में इंटरनेट के उपयोग में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। इससे डाटा चोरी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इसलिए सरकार देश में पहली बार डाटा संरक्षण कानून लाने जा रही है। भारतीय अर्थव्यस्था का जिस तरह से डिजिटलीकरण हो रहा है और पूरी दुनिया में डाटा की सुरक्षा को सशक्तीकरण, प्रगति और नवाचार की कुंजी माना जाने लगा है, उससे यह विधेयक काफी महत्वपूर्ण है। डाटा प्रोटेक्शन विधेयक में डाटा के स्थानीय भंडारण पर बल दिया गया है। इसके लिए देश भर में कई डाटा केंद्र बनाने होंगे। इसके माध्यम से देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इकोसिस्टम बन पाएगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

निजी डाटा संरक्षण विधेयक में निजी डाटा की चोरी करने वाली कंपनियों पर सख्ती बढ़ाने की बात कही गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 15 करोड़ रुपये या वैश्विक कारोबार के चार फीसद तक के जुर्माने के साथ ही जेल का प्राविधान है। अगर उल्लंघन का मामला छोटा है तो पांच करोड़ रुपये या वैश्विक कारोबार का दो फीसद तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इन सब नियमों के कारण फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को भारत में ही सूचनाओं को संग्रहित और संसाधित करने हेतु बाध्य किया जा सकता है। अभी भारतीयों का डाटा प्राप्त करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज (एमएलएटी) की व्यवस्था है जिस पर अमेरिकी कंपनियों का नियंत्रण है। परंतु डाटा सुरक्षा कानून लाकर केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर डाटा स्थानीयकरण को बढ़ावा देना चाहती है जिससे विदेशों से होने वाली जासूसी आदि को रोका जा सके। ऐसी उम्मीद है कि इस विधेयक से कंपनियां देश में ही डाटा प्रोसेसिंग करने को प्रोत्साहित होंगी और भारत दुनिया की सबसे बड़ा डाटा रिफाइनरी का केंद्र बन सकेगा।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में डाटा को देश की संपत्ति के रूप में देखा जाने लगा है। ऐसे में भारत अपने नागरिकों को उन कंपनियों से बचाना चाहता है, जो डाटा के बदले सेवाएं प्रदान करती हैं जिससे उनके डाटा के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती हैं। भारत में डाटा प्रोटेक्शन के लिए कोई अलग कानून नहीं है और ना ही कोई संस्था है जो डाटा की गोपनीयता को सुरक्षा प्रदान करती हो। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-43ए के तहत डाटा संरक्षण हेतु उचित दिशा-निर्देश दिए गए हैं, पर यह धारा नाममात्र का संरक्षण प्रदान करती है। असल में डाटा के संदर्भ में कई आयाम महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे इसका संग्रह कहां होता है, इसे कहां भेजा जाता है, इसे कहां उपयोगी डाटा में बदला जाता है, डाटा तक किनकी पहुंच है, कौन डाटा से लाभ कमाता है? दरअसल एप्पल, गूगल, फेसबुक, ट्विटर एवं वाट्सएप जैसी कंपनियां व्यापार के माध्यम से बड़े पैमाने पर लाभ कमा रही हैं, परंतु भारत में इन कंपनियों के दफ्तर नहीं होने से उन पर भारत के कानून लागू नहीं होते।

अलग-अलग माध्यमों से साझा किए गए भारतीयों के डाटा को सुरक्षित रखे जाने पर बहस तेज हुई है। इसकी गंभीरता 'क्या आपका डाटा निजी है' से 'आपका डाटा कितना निजी है' तक बढ़ गई है। हाल के दिनों में सोशल साइट कंपनी वाट्सएप पर डाटा की सुरक्षा में लगी सेंध के बाद सरकार भी और सतर्क हो गई है। इस मामले को लेकर काफी बवाल भी मचा था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार निजता को गंभीरता से लेती है और सूचना की गोपनीयता इसी का हिस्सा है। इससे पहले भी एक बार फेसबुक ने डाटा गोपनीयता की बात को स्वीकार किया था कि भारत के ही लगभग साढ़े पांच लाख उपभोक्ताओं के डाटा को कैंब्रिज एनालिटिका के साथ अनधिकृत तरीके से साझा किया गया। हमारे देश में फेसबुक का उपयोग करने वाले लगभग 24 करोड़ लोग हैं। डाटा सुरक्षा के अभाव में इतने लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां दांव पर लगी हुई हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एटीएम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, नेट-बैंकिंग में फर्जीवाड़ा होने की घटनाओं में हालिया वर्षों में तेजी आई है। इन घटनाओं का असर इंटरनेट के उपभोग की विश्वसनीयता पर पड़ रहा है। इसके अलावा चुनाव और नीति निर्धारण के संदर्भ में सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा भी इस प्रकार के डाटा में रुचि दिखाई जाती है। इसलिए डाटा संरक्षण को वैधानिकता प्रदान करना जरूरी हो चला है।

हालांकि कई विशेषज्ञ डाटा संरक्षण विधेयक को दोधारी तलवार की संज्ञा दे रहे हैं, जिसमें एक तो भारतीयों के डाटा को सुरक्षित रखने की बात की गई है, वहीं दूसरी ओर यह केंद्र सरकार को रियायत देकर नागरिकों की निगरानी करने की मंजूरी देता है। इसी तरह की चिंता कई नागरिक समाज संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी जाहिर की है, ऐसे में जरूरी है कि इस कानून को पारित करने से पहले सभी हितधारकों से विमर्श कर विधेयक में व्याप्त कमियों को दूर किया जाए।

पूरी दुनिया में इस समय डाटा के प्रवाह (हस्तांतरण) पर बहस चल रही है और इसकी सुरक्षा से जुड़ी हुई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित और विकासशील देशों की सरकारें अपने घरेलू कानूनों को विकसित कर रही हैं। चीन ने अपने घरेलू कानूनों को इस तरीके से विकसित किया है जो विदेशी कंपनियों को घरेलू बाजार में प्रवेश करने से ना केवल रोकती हैं, वरन डेटा सेंटरों और डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर एक समृद्ध घरेलू अर्थव्यवस्था का संवर्धन करती हैं। यही कारण है कि कई भारतीय कंपनियां डाटा स्थानीयकरण का समर्थन करती हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय संघ ने भी डाटा सुरक्षा को लेकर कठोर कानून बनाया है। इसके साथ ही सभी देश वैश्विक मंचों पर एक-दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और गोपनीयता से जुड़े मूल्यों का संवर्धन हो सके। ऐसे में हमारे देश में इसे प्रभावी बनाने के लिए एक सशक्त नियमन ढांचा चाहिए। यह ऐसा हो, जो भले ही जटिल डिजिटल सेटअप वाला हो, जिसमें चाहे सहमति के लिए अनेक स्तर रखे जाएं, परंतु वह हमारे मूल अधिकारों की हर हाल में रक्षा करे। इसके अलावा हमें हमारे शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को बिग डाटा साइंस और डाटा सेंटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।

इंटरनेट पर निजता की होगी सुरक्षा!

मुकुल श्रीवास्तव
प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय

सोशल मीडिया इतना तेज और जन-सामान्य का संचार माध्यम बन गया कि इसने हर उस व्यक्ति को जिसके पास स्मार्ट फोन है और सोशल मीडिया पर उसकी एक बड़ी फैन फोलोविंग है, एक चलता फिरता मीडिया हाउस बना दिया है। और यहीं से शुरू हुआ इंसान के डाटा बन जाने का खेल जिसमें इंटरनेट की कई कंपनियां भी शामिल हैं। जब सोशल मीडिया को लोगों के 'आधार' से जोड़ने का मामला तमिलनाडु हाई कोर्ट पहुंचा तो उसी से जुड़े कई अन्य मामलों को फेसबुक ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की ओर से केके वेणुगोपाल ने पहले कहा था, 'सोशल मीडिया यूजर्स की प्रोफाइल को आधार से जोड़ना फर्जी खबरों पर लगाम के लिए जरूरी है।' कहा गया कि इससे अश्लील व एंटी-नेशनल कंटेंट पर भी लगाम लगेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह ऑनलाइन निजता और देश की संप्रभुता के हितों को संतुलित करके सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के बारे में एक हलफनामा दायर करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का काम अदालतों का नहीं है। नीति केवल सरकार तय कर सकती है। कोर्ट उसकी वैधता पर निर्णय ले सकता है।

फेसबुक और वाट्सएप जैसी कंपनियां इस तरह की सोच को नागरिकों के निजता के अधिकार के खिलाफ बता रही हैं। समस्या का एक बड़ा पहलू है व्यावसायिक पक्ष- इंटरनेट की बड़ी कंपनियां। सोशल मीडिया पर आने से जिस तथ्य को हम नजरअंदाज करते हैं वह है हमारी निजता का मुद्दा और हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी। जब हम किसी सोशल मीडिया से जुड़ते हैं तो हम अपना नाम, पता, फोन नंबर, ई-मेल उस कंपनी को देते हैं। समस्या यहीं से शुरू होती है। सोशल मीडिया पर लोगों का डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। उधर इंटरनेट के फैलाव के साथ आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। लोगों के बारे में संपूर्ण जानकारियों को एकत्र कर उसे बेचना व्यवसाय बन चुका है और इनकी बड़ी कीमत चुकाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। कई बार एक गलती किसी कंपनी की उस लोकप्रियता पर भारी पड़ जाती है जो उसने एक लंबे समय में अर्जित की होती है। 'टेकक्रंच' की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई में लाखों मशहूर और प्रभावशाली व्यक्तियों का पर्सनल डाटा इंस्टाग्राम के जरिये लीक हो गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन लोगों का डाटा लीक हुआ है उसमें उनके फॉलोवर्स की संख्या, बायो, पब्लिक डाटा, प्रोफाइल पिक्चर, लोकेशन और पर्सनल कॉन्टैक्ट भी शामिल थे।

फेसबुक ने यह भी स्वीकार किया था कि उसके प्लेटफॉर्म पर अनेक ऐप के माध्यम से डाटा माइनिंग व डाटा का कारोबार होता है। वाट्सएप अपने सिस्टम में की गई कॉल, चैट, ग्रुप चैट, इमेज, वीडियो, वॉइस मैसेज और फाइल ट्रांसफर को इंक्रिप्टेड बताते हुए अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बताता रहा है, पर यह भ्रम भी टूट गया कि वाट्सएप अपने उपभोक्ताओं की निजता की सुरक्षा करता है और उनके डाटा का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसका बड़ा कारण इंटरनेट द्वारा पैदा हो रही आय और दुनिया भर की सरकारों में अपनी आलोचनाओं को लेकर दिखाई जाने वाली संवेदनशीलता है। कंपनियां अनधिकृत डाटा के व्यापार में शामिल हैं, भले ही वे इसे ना मानें, पर वे अपना डाटा देश की सरकार के साथ नहीं शेयर करना चाहती हैं। वहीं सरकार इस तरह के नियम बना कर अपनी आलोचनाओं को कुंद कर सकती है। फिलहाल देश इंतजार कर रहा है कि सोशल मीडिया पर आने वाला वक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों की निजता के बीच कैसे संतुलन बनाएगा और यह विधेयक क्या लोगों को इंटरनेट पर उस आजादी का एहसास करा पाएगा जिसके लिए लोग इंटरनेट पर आते हैं।

खरी-खरी

बेचैन आत्माओं का धूप स्नान

शशांक दुबे

जिन लोगों की सर्दियां मेथी की सब्जी में रोटी डुबोकर खाने में और और गर्मियां आम का पना पीने में कटती हों, उन्हें पचास की उम्र लगते-लगते डॉक्टर 'कोई मिल गया' का 'जादू' बनने की हिदायत देते हैं। जादू क्या पहनता है, किस ग्रह से आया है, इससे कोई मतलब नहीं, उनकी तो बस इत्ती सी सलाह रहती है कि 'बुढ़ाते बदन में विटामिन की कमी पड़ जाती है। भरपाई के लिए 'जादू' की तरह रोज धूप का सेवन करना चइये।'

पर नौकरीपेशा आदमी धूप ले भी तो कब? एक तो सर्दियों में सूरज महाराज लेट आते हैं, फिर जब तक आदमी 'नहाऊं कि नहीं नहाऊं' के निष्कर्ष पर पहुंचता है, नौकरी का टाइम हो जाता है। जाहिर है, दफ्तरी जीव के लिए मात्र रविवार बचता है, जब बाल रंगाने, गाड़ी धुलवाने, रद्दी बिकवाने आदि से उसे एकाध घंटे धूप खाने को मिल पाते हैं।

मगर धूप मिले तो मिले कहां? आंगन आजकल होता नहीं और बालकनी में बच्चों की पुरानी साइकल और हालिया धुले कपड़ों से टपकती बूंदों का कब्जा होता है। ले-देके बची छत, लिहाजा धूप दर्शन के लिए आदमी वहीं पहुंचता है। वहां रखी पुरानी 'फोल्डिंग कुर्सी' पर बैठते ही उसकी चीख निकल जाती है। एक तो कुर्सी ठंडी, ऊपर से हवा और नमी का साथ पाकर लोहा ऐसा सड़ता है कि वह किसी भी सूरत में बैठने लायक बचा नहीं रहता है। किसी तरह से बैठते हैं कि तभी साथ देने (या नजर रखने) इकलौती सगी पत्नी भी छत पर चली आती है। अब इक्कीसवीं सदी में छत पर बैठे दंपती टाइम कैसे पास करें? पुराना जमाना होता तो पत्नी धूप में बैठे-बैठे मटर छील लेती, स्वेटर बुन लेती या पति की जूं ही देख देती। मगर मटर अब डिब्बा बंद मिल जाते हैं, स्वेटर कोई पहनता नहीं, जिसे देखो जैकेट खरीद लाता है। बची जुएं, तो इक्कीसवीं सदी में वे भी कब की खटमलों के साथ परलोक सिधार चुकीं।

इधर, पति भी टाइम कैसे काटे! अखबार तो वह सुबह ही पढ़ चुका है। तभी मोबाइल पर 'टुचुंग' की ध्वनि बजती है। किसका मैसेज है? मगर धूप में काले धब्बे के अलावा कुछ दिखता नहीं। इस बीच सूर्य देवता जलवा दिखाना शुरू करते हैं। कंबल काटने लगती है, गाल जलने लगते हैं, गला सूखने लगता है। अंततः झक और मन, दोनों मारकर वह नीचे उतर आता है और कोई व्यंग्य लिखने बैठ जाता है।

ट्वीट-ट्वीट

केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन बिल के प्रावधान असंवैधानिक हैं तथा भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ हैं।

सचिन पायलट@SachinPilot

नागरिकता बिल मुस्लिमों सहित किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करता। यह तीन मुस्लिम बहुल देशों में धार्मिक या सामाजिक आधार पर सताए जा रहे लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए है। मीडिया, राजनेताओं और बुद्धिजीवियों को मुस्लिमों के डर को शीघ्र दूर करना चाहिए।

कंचन गुप्ता@KanchanGupta

क्या यह अजीब नहीं? विपक्ष इसके लिए सिर के बल खड़ा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को ही नहीं, वहां के मुसलमानों को भी नागरिकता विधेयक के दायरे में लाया जाना चाहिए। आखिर उसने तब क्या किया जब कश्मीर के हिंदू संहार से दो-चार हुए?

सुशील पंडित@neelakantha

ओमप्रकाश तिवारी
मुंबई ब्यूरो प्रमुख

महाराष्ट्र डायरी

त्वरित फैसले के बावजूद न्याय दूर की कौड़ी

देश भर में आजकल अनेक दुष्कर्म कांड पर बहस जारी है। तरह-तरह के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कई तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं। हैदराबाद में हुए एनकाउंटर के बाद तो यह भी कहा जाने लगा है कि समय रहते न्याय मिलने की उम्मीद होती तो शायद ऐसा नहीं होता। यानी बात सिर्फ न्याय पर आकर अटकती है। प्रश्न यह है कि यह न्याय हर स्तर पर मिले कैसे?

दिल्ली में हुए निर्भया कांड के आठ माह के अंदर ही मुंबई में शक्ति मिल कंपाउंड कांड हो गया था। महालक्ष्मी स्टेशन के बिल्कुल पास एक पुरानी मिल के खंडहर में एक महिला फोटो पत्रकार अपने एक पुरुष साथी के साथ पहुंच गई। विशालकाय भुतही मिल के अंदर बड़ी-बड़ी वनस्पतियां उगी हुई थीं। वहां किसी का आना-जाना था नहीं। चरस पीनेवाले आवारा लड़कों ने शक्ति मिल को अपना ठिकाना बना लिया था। वह उनके लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुकी थी। एक लड़की को अपने पुरुष साथी के साथ देख उनके मन का शैतान जाग उठा, और वह महिला पत्रकार उन आवारा लोगों की शिकार बन गई। चूंकि महिला और उसका साथी दोनों पत्रकार थे, इसलिए उन्होंने आवाज उठाई। पहले उसका साथी लड़की को अस्पताल ले गया। फिर मामला पुलिस तक पहुंचा। हाथ मीडिया पर डाला गया था, इसलिए मीडिया का भी दबाव बढ़ा। मामला अखबारों की सुर्खियां बना। पुलिस को समय पर सक्रिय होना पड़ा। समय पर फोरेंसिक जांच हुई। दुष्कर्मी पकड़े गए।

महिला पत्रकार के साथ दुष्कर्म की यह घटना 22 अगस्त, 2013 को हुई थी। इस मामले की जांच चल ही रही थी कि एक और लड़की पुलिस के पास पहुंची और बताया कि उसी शक्ति मिल कंपाउंड में कुछ लोगों ने उसके साथ भी 31 जुलाई, 2013 को दुष्कर्म किया था। वह भी अपने पुरुष साथी के साथ उस मिल के अंदर गई और

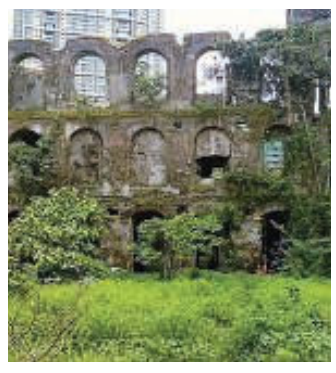

मुंबई स्थित शक्ति मिल कंपाउंड। फाइल फोटो

उन आवारा लोगों के चंगुल में फंस गई। वह 21 वर्षीय लड़की एक साधारण टेलीफोन ऑपरेटर थी। सामूहिक दुष्कर्म का शिकार होने के बाद वह महिला पत्रकार जितनी हिम्मत नहीं जुटा सकी। इसलिए वह और उसका साथी हताशा ओढ़े मुंबई छोड़कर चले गए। जब उन्होंने महिला पत्रकार के साथ हुई घटना के बाद शक्ति मिल के आवारा लड़कों की गिरफ्तारी की खबर अखबारों में पढ़ी तो उनकी भी हिम्मत जागी, और उसने मुंबई पुलिस के पास पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई।

पुलिस ने यह मामला भी दर्ज किया। आरोपियों की पहचान परेड में टेलीफोन ऑपरेटर लड़की ने पहले मामले के चार में से तीन आरोपियों की पहचान अपने साथ हुए दुष्कर्म के आरोपियों के रूप में की। पत्रकार लड़की का मामला 22 अगस्त को सामने आया था। टेलीफोन ऑपरेटर तीन सितंबर को पुलिस के पास पहुंची थी। पुलिस ने जांच में तीव्रता दिखाते हुए 16 दिनों के अंदर दोनों मामलों में 600 पन्नों की संयुक्त चार्जशीट दायर कर दी। 12 मार्च, 1993 के सिलसिलेवार विस्फोट कांड एवं 26 नवंबर, 2008 के मुंबई आतंकी हमले जैसे मामलों में कई आरोपियों को फांसी की सजा दिलवा चुके मशहूर वकील उज्ज्वल निकम को सरकार की तरफ से इन दोनों मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 14 अक्टूबर को मामले की सुनवाई शुरू हुई। निर्भया कांड से सबक लेकर केंद्र सरकार दुष्कर्म के मामलों में आइपीसी में एक नई धारा 376 ई शामिल कर चुकी थी। यह धारा दुष्कर्म के मामले में सजा पा चुके व्यक्ति द्वारा पुनः वही अपराध दोहराने वाले आरोपी को मृत्युदंड का प्रावधान करती है।

ट्रायल कोर्ट ने 21 मार्च, 2014 को इस मामले के चार आरोपियों- विजय जाधव, मोहम्मद बंगाली, मोहम्मद अंसारी एवं अशफाक शेख को दोषी ठहराया एवं उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसी दिन फोटो पत्रकार मामले में भी जाधव, बंगाली और अंसारी के साथ एक अन्य आरोपी सिराज खान को दोषी करार दिया। उज्ज्वल निकम शायद इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसी दिन कोर्ट से दोनों मामलों में दोषी करार दिए गए जाधव, बंगाली और अंसारी के लिए धारा 376 ई के तहत मृत्युदंड की मांग कर दी। क्योंकि ये तीनों दुष्कर्म के मामले में ही दो बार दोषी करार दिए जा चुके थे। ट्रायल कोर्ट ने निकम की मांग को तर्कसंगत मानते हुए चार अप्रैल, 2014 को दोनों मामलों में दोषी करार दिए गए जाधव, बंगाली एवं अंसारी को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

यानी इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र 16 दिन में पेश कर दिया और ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई शुरू होने से लेकर मृत्युदंड सुनाने तक का सफर सिर्फ 178 दिन में पूरा कर लिया। उसके बाद से छह वर्ष बीत चुके हैं, दोषी करार दिए गए लोगों का मामला अभी हाईकोर्ट की सीमा भी पार नहीं कर सका है। निराशा का दौर यहीं से शुरू होता है। उज्ज्वल निकम मानते हैं कि दुष्कर्म के मामलों में न सिर्फ पुलिस की विशेष टीमें बनाकर उन्हें फोरेंसिक जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करने की जरूरत है, बल्कि ऐसे मामलों में हर जगह विशेष वकील और विशेष कोर्ट भी चिन्हित करने की जरूरत है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इन मामलों में संवेदनशीलता और सक्रियता की उम्मीद न सिर्फ ट्रायल कोर्ट से, बल्कि उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय से भी की जानी चाहिए।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

कुछ विपक्षी दलों द्वारा यह कहना सही है कि नागरिकता संशोधन बिल संविधान विरोधी है?

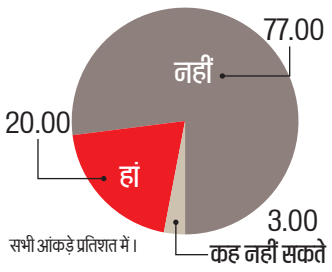

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या नागरिकता संशोधन विधेयक से देश में अवैध घुसपैठ पर लगाम लगेगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y**, **N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बंटवारा किसने किया नहीं खास यह बात,
खास बात है कौन अब करता दिखता घात।
करता दिखता घात सिर्फ वोटों की खातिर,
ओढ़ भेड़ की खाल भेड़िया है जो शातिर!
कर इनकी पहचान सिखाओ सबक करारा,
जो फिर से इक बार चाहते हैं बंटवारा।

– ओमप्रकाश तिवारी

प्रसंगवश

मानव विकास में संभला भारत

हालिया जारी मानव विकास सूचकांक में भारत को एक स्थान की बढ़त मिली है। हालांकि एक स्थान का सुधार एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन सुधार के लिहाज से पर्याप्त नहीं है

रिजवान अंसारी
अध्येता, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

प्रतीकात्मक

संयुक्त राष्ट्र की इकाई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के मुताबिक मानव विकास सूचकांक में भारत ने एक स्थान की छलांग लगाई है। 189 देशों में भारत की रैंकिंग 129 हो गई है। वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग 130 और 2017 में 129 थी। हालांकि श्रीलंका (71) और मालदीव (104) जैसे छोटे पड़ोसी देशों से भारत पिछड़ गया है, लेकिन अन्य पड़ोसी देशों- भूटान (134), बांग्लादेश (135), नेपाल (147) और पाकिस्तान (152) से बेहतर स्थिति में है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी नॉर्वे पहले जबकि नाइजर अंतिम पायदान पर रहा है। वहीं स्विट्जरलैंड दूसरे, आयरलैंड तीसरे और जर्मनी चौथे स्थान पर है।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। तीन बुनियादी पहलुओं- जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर (आय) और शिक्षा की स्थिति के आधार पर मानव विकास का मूल्यांकन किया जाता है। पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया था। तब से हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे प्रकाशित करता है। इस सूचकांक में मानव विकास के आधार पर 189 देशों को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत को पिछले वर्ष की तरह तीसरे वर्ग 'मध्यम मानव विकास' जगह में मिली है। भारत को इस साल 0.647 अंक मिले हैं जबकि पिछले वर्ष 0.640 अंक मिले थे।

एक खास बात यह भी है कि यूएनडीपी ने वर्ष 2005-06 और वर्ष 2015-16 के दौरान 27 करोड़ भारतीयों को गरीबी से आजादी मिलने की बात कही है। अलबत्ता भारत में अभी भी दुनिया के 28 फीसद यानी करीब 35 करोड़ गरीबों के निवास करने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 130 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं। इस लिहाज से देखें तो गरीबी के आंकड़ों में हम भले ही कम हुए हों, लेकिन मौजूदा आंकड़ा भी किसी भयावहता से कम नहीं है। यह अभी भी श्रीलंका, ईरान और चीन जैसे देशों से काफी पीछे है। हालांकि 27.1 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर होने की वजह पिछले तीन दशकों में हुए तेज विकास को बताया गया है। साथ ही जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में इजाफे के कारण भी रैंकिंग सुधरी है।

यह सूचकांक मानवीय विकास का एक औसत पैमाना है जिसका आकलन जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। लिहाजा 189 देशों में 129वें स्थान पर होना इस बात का संकेत करता है कि हम उपरोक्त कसौटियों पर काफी पिछड़े हुए हैं। हम एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जरूर हैं, लेकिन शीर्ष 100 देशों में भी जगह न बना पाना चिंताजनक है। गौर करें तो इसके कई कारण हैं मसलन एक बड़े वर्ग का मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना, धन का असमान वितरण, विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं स्वास्थ्य योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि। खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना गरीबी की बड़ी वजह है। इस कारण शारीरिक अक्षमता उत्पन्न होती है जो कुपोषण और बीमारियों को जन्म देती है। लिहाजा कार्यबल संख्या में कमी आती है और गरीबी को बढ़ावा मिलता है। अगर राजनीतिक कारणों की बात करें तो शिक्षा और रोजगार के लिए बेहतर नीतियों की कमी और कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के अभाव में गरीबी को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, शिक्षा की कमी भी गरीबी की बड़ी वजह है। शिक्षा के अभाव में बेहतर रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पाती जिससे गरीबी बढ़ती चली जाती है। जाहिर है बेहतर जीवन स्तर का अभाव रहता है और इसी कारण जीवन-प्रत्याशा भी प्रभावित होती है। यकीनन इससे बेहतर मानव विकास की उम्मीद हम नहीं कर सकते।

फिर सवाल है कि क्या कुछ किए जाने की जरूरत है? अगर सरकार की कोशिशों की बात करें तो नई स्वास्थ्य योजना के तहत जीडीपी का 2.5 फीसद खर्च करने का फैसला सराहनीय है। लेकिन इसके सही क्रियान्वयन के लिए 'स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं' पर बल देना जरूरी है।

शिक्षा में सुधार के लिए 'संपूर्ण शिक्षा' की अवधारणा को अमल में लाना होगा। प्रतिवर्ष शिक्षा दर में मामूली वृद्धि से खुश होने की बजाय एक चौथाई 'अशिक्षित भारत' के बारे में फिक्र करनी होगी। अशिक्षा के कारण निम्न-स्तर के जीवनशैली से अभिशप्त लोगों को इस दलदल से निकालना होगा। इसके लिए देश भर में शिक्षकों के लाखों रिक्त पदों और निजी विद्यालयों की मनमानी जैसे दो अहम समस्याओं पर सरकार को मंथन करना होगा, क्योंकि इन दोनों ही समस्याओं से गरीबों को ही दो चार होना पड़ता है।

दूसरी ओर गरीबी को दूर करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की प्रासंगिकताओं पर मंथन करने की जरूरत है। इसमें दो राय नहीं कि कल्याणकारी योजनाओं से गरीबी दूर नहीं होती, बल्कि इससे तात्कालिक तौर पर राहत मिलती है। लिहाजा गरीबी को दूर करने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने के प्रयास करने होंगे। जमीनी स्तर पर अभी से अगर काम किया जाए तो दो-तीन दशक बाद इसके बेहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए सरकारों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर पर्याप्त खर्च करने की जरूरत है। मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार शिक्षा पर जहां जीडीपी का महज 3.7 फीसद खर्च करती है, वहीं स्वास्थ्य पर दो फीसद से भी कम। इससे इतर रोजगार के मोर्चे पर भी कमर कसने की जरूरत है। मानव को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की काबिलियत पैदा करने की जरूरत है। हम अपनी रैंकिंग में सुधार जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है।

बहरहाल देश भर में बुनियादी सुविधाओं से वंचित तमाम लोगों तक इन जरूरतों को पहुंचाने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक वंचनाओं को दूर किया जाना बेहद जरूरी है।

3,770 करोड़ रुपये की सालाना बचत हो रही है कोल इंडिया को फ्यूल लिंकेज रेशनलाइजेशन के जरिये कोयले की ढुलाई पर। यह बचत देश के 58 थर्मल पावर प्लांट के लिए होने वाली कोयला आपूर्ति में हो रही है। कोल इंडिया के मुताबिक इस नीति के तहत 6.30 करोड़ टन कोयले की ढुलाई की जा रही है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 12 दिसंबर 2019

बस एक 'सुपर फूड' चॉकलेट खाओ, लंच भूल जाओ

शारदाआनंद गौतम, पालमपुर

- हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर ने तैयार की वेहद पौष्टिक चॉकलेट
- खनिज तत्वों और प्रोटीन से भरपूर, कीमत 40 रुपये, शुगर भी होगी नियंत्रित

जी हां, हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर द्वारा ज्वार, बाजरा, रागी, मक्की, भूरे चावल, शहद, स्टीविया व गुड़ से तैयार इस चॉकलेट को खाने के बाद आपको चार घंटे तक भूख नहीं लगेगी। कीमत है 40 रुपये।

स्वस्थ समाज

खनिज तत्वों और प्रोटीन से भरपूर इस एक चॉकलेट को खाने से आप दोपहर का भोजन न भी करें तो चलेगा। इतना ही नहीं यह चॉकलेट आपकी शुगर की मात्रा को नियंत्रित करेगी और कुपोषण को भी दूर करने में सहायक होगी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान के विज्ञानियों ने भारत के परंपरागत अनाजों की खूबी और शक्ति को इसका आधार बनाया है।

संस्थान का कहना है कि बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करना इसका ध्येय है। बच्चों को दवा और विटामिन की बजाए यह चॉकलेट देने से उनका स्वास्थ्य संवरेगा। कुछ फर्मों ने संस्थान से इस चॉकलेट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए करार किया है।

यह है खूबी... : करीब चालीस ग्राम की इस चॉकलेट में एक गिलास दूध के बराबर प्रोटीन है। साथ ही दो रोटी और दाल की एक कटोरी के बराबर कैलोरी, तीन से चार ग्राम फाइबर की मात्रा इसमें है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार चॉकलेट। जागरण

कुपोषण के शिकार बच्चों में प्रोटीन की कमी यह चॉकलेट पूरा करेगी। सुबह चॉकलेट खाने से आपको लंच की जरूरत नहीं रहेगी। संस्थान ने मिल्ट्स एंड ओट्स बार चॉकलेट की तकनीक 2018 में तैयार की थी। दिल्ली की फर्म से समझौता पत्र हस्तांतरण के बाद इसे बाजार में उतारा है। चॉकलेट में खनिज और प्रोटीन की भरपूर मात्रा है।

-डॉक्टर संजय कुमार, निदेशक, हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर

स्वास्थ्य के लिहाज से यह चॉकलेट काफी महत्वपूर्ण है। इसमें प्रयोग किए गए अनाज को सुपर फूड कहा जाता है। रागी में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। इन खाद्यान्नों में फाइबर की प्रचुरता होती है, जो पाचन के लिए उपयुक्त है। पौष्टिक होने के कारण वजन भी नहीं बढ़ता है।

-डॉ. अनुराग विजयवर्गीय, आयुर्वेद विशेषज्ञ

हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार की गई चॉकलेट। जागरण

सूखे व बाढ़ में भी होगी सब्जी-चारे की सस्ती पैदावार

जागरण विशेष ▶ बिहार कृषि विश्वविद्यालय जल्द ही सुलभ कराने जा रहा किफायती और कारगर युक्ति

प्राकृतिक आपदा से जूझते राज्य व कम जोत वाले पशुपालक और किसानों को होगा लाभ

ललन तिवारी, भागलपुर

सूखे और बाढ़ से जूझने वाले क्षेत्रों के कम जोत वाले पशुपालक और किसानों को कम लागत, कम पानी, बिना जमीन और मिट्टी के भी सब्जी और चारा का उत्पादन मुहैया हो सके, इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय पॉली हाउस आधारित सस्ती और कारगर कृषि तकनीक सुलभ कराने पर काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का कहना है, सामयिक आवश्यकता की पूर्ति के क्रम में बिहार में इस तरह का अनुसंधान पहली बार हो रहा है।

सबौर, भागलपुर स्थित इस विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. आर के सोहाने ने बताया, राज्य में 2.72 करोड़ पशु हैं, पर कुल कृषि क्षेत्र के 0.21 फीसद जमीन पर ही चारे का उत्पादन हो पाता है। राज्य का अधिकांश इलाका सूखा या बाढ़ से ग्रसित रहता है। ऐसे में इस तरह की युक्ति की यहां सख्त दरकार है, जिससे बिना जमीन या मिट्टी के भी पशु चारा उपलब्ध हो सके। हम जल्द ही इसे सुलभ कराने जा रहे हैं।

इस तरह ट्रे में होगा फसल का उत्पादन। सौजन्य से - बीएयू

आबादी बढ़ रही है और जमीन कम हो रही है तो इस तरह के अनुसंधान किसानों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। विशेषकर बिहार में जहां, सूखा और बाढ़ बड़ी चुनौती रही हैं। विश्वविद्यालय इसी दिशा में प्रयास कर रहा है ताकि कम जोत वाले और कठिन हालात वाले क्षेत्र के पशुपालक और किसानों को सस्ता समाधान सुलभ कराया जा सके।

-डॉ. अजय कुमार सिंह, कुलपति बीएयू, सबौर, भागलपुर

दरअसल, पॉली हाउस (नियंत्रित ताप) आधारित इस विधि में ट्रे में फसल उत्पादन में किया जाता है। यह युक्ति नई नहीं है किंतु इसे सस्ता और सुलभ बनाने को शोध किया जा रहा है। पॉली हाउस में स्थापित एक ट्रे में एक किलो अंकुरित बीज डालने पर सप्ताह भर में सात-आठ किलो हरा चारा मिल सकेगा। ट्रे में चारे के पौधे की ऊंचाई एक फीट की होगी। सभी पौधों की जड़ें एक दूसरे से गुच्छे के रूप में जुड़ी रहेंगी, ताकि फसल खड़ी रह सके।

छोटे स्तर पर प्रतिदिन एक ट्रे से आठ-दस किलो चारा मिल सकेगा। पहली ट्रे खाली होते ही नई फसल होने तक दूसरी ट्रे तैयार हो जाएगी। रोटेशन प्रणाली से हर दिन चारा मिलता रहेगा। बड़े स्तर पर यह प्रतिदिन हजार किलो तक उत्पादन होगा।

सब्जी की फसल के लिए उच्चस्तरीय तकनीक से सस्ते और टिकाऊ पॉली हाउस और ट्रे का निर्माण किया जा रहा है। इसमें बेमौसम में भी मौसमी सब्जी का भी उत्पादन होगा, जो ज्यादा गुणवत्तापूर्ण होगी। इसमें भी मिट्टी की जरूरत नहीं होगी। एक जालीनुमा फ्लोर का निर्माण किया जाएगा। इसी में सब्जी की जड़ें लटकती रहेंगी। चारे और सब्जी दोनों ही फसलों के लिए विशेष घोल बनाए जाएंगे। इसी में वे सारे पोषक तत्व होंगे, जो मिट्टी में उपलब्ध होते हैं, ट्रे में घोल की नियंत्रित मात्रा पहुंचेगी।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

लाइसेंस पहनकर राफ्टिंग के लिए नहीं उतरे तो नपेंगे

दविंद्र ठाकुर, कुल्लू

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग पैराग्लाइडिंग के बाद अब राफ्टिंग के लिए भी कड़े नियम बना रहा है। पैराग्लाइडर पायलट के आधार पर ही राफ्टिंग के दौरान राफ्टर व गाइड को लाइसेंस पहनने (गले में) होंगे। बिना लाइसेंस के राफ्टिंग करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

राफ्टिंग के लिए बनाए इस नए नियम का शत-प्रतिशत पालन करवाने के लिए पर्यटन विभाग और पर्वतारोहण संस्थान मनाली की टीम बजौरा से मनाली तक के राफ्ट संचालकों, राफ्टर व गाइड्स के लाइसेंस की जांच करेगी। कुल्लू जिला के कुछ स्थलों पर कुछ रिवर राफ्टिंग एजेंसियां बिना अनुमति के इस साहसिक गतिविधि को अंजाम देकर सैलानियों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसी लापरवाह रिवर राफ्टिंग एजेंसियों पर अब पर्यटन विभाग कोई नरमी बरतने के मूड में नही है।

लापरवाही पर हुई है कार्रवाई : कुछ समय पहले से बारिशिंग में बिना अनुमति और लाइसेंस रिवर राफ्टिंग करवाने पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दो राफ्ट सीज किए थे। ऐसे मामले सामने आने पर अब कोई राफ्टर व गाइड इस तरह की दोबारा लापरवाही न बरते, इसके लिए पर्यटन विभाग इस साहसिक गतिविधि में लापरवाही पर मौके पर ही लाइसेंस रद करने पर भी विचार कर रहा है।

अटल विहारी पर्वतारोहण संस्थान मनाली से प्रशिक्षण करने वालों को ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जल्द ही बजौरा से मनाली तक मार्च में जांच की जाएगी। जिन राफ्टर व गाइड को लाइसेंस मिले हैं, उन्हें राफ्टिंग के दौरान इन्हें पहनना अनिवार्य है। लापरवाही पर कार्रवाई होगी।

- नीरज राणा निदेशक पर्वतारोहण संस्थान मनाली

जिला में है 93 एजेंसियां और 363 हैं पंजीकृत राफ्ट : जिला कुल्लू में तीन जगहों पर राफ्टिंग करवाई जाती है। इसमें रायसन, बबेली, पीरड़ी शामिल है। यहां पर 288 लाइसेंसधारक गाइड हैं, जबकि 93 एजेंसियां है। इसमें रायसन में 12, बबेली में 53 और पिरड़ी में 28 एजेंसियां कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत व रेस्क्यू राफ्ट 363 हैं। इसमें रायसन में 31, बबेली में 198 और पिरड़ी में 134 राफ्टें है।

मौत देने वाले हाथ संवार रहे 'जिंदगी'

पूनमदास मानिकपुरी, कोंडागांव

- दुर्दांत महिला नक्सली आत्मसमर्पण के बाद पुलिस जवानों के बच्चों को पढ़ा रही ककहरा
- संहार की दुनिया को त्यागकर सृजन की दुनिया से नाता जोड़ उसे मिल रहा है सुकून

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव स्थित पुलिस लाइन में जवानों के बच्चों को पढ़ाती आत्मसमर्पित महिला नक्सली। जागरण

कहते हैं, ज्ञान की सार्थकता तभी है, जब उसका उपयोग संहार की बजाए सृजन में किया जाए। आत्मसमर्पित महिला नक्सली (सुरक्षा दृष्टि से नाम छुपाया गया) को आज इस बात बड़ा सुकून मिलता है कि जिन हाथों में गरजती बंदूकों से कभी वह मौत देती थी, उन्हीं हाथों में चॉक थामकर आज वह बच्चों को ककहरा पढ़ाकर उनकी जिंदगी संवार रही है। वही लोग जो कभी उससे घृणा करते थे, आज सम्मान देते हैं।

पिता की मौत के बाद नक्सल संगठन से उसका मोहभंग हुआ और मुख्यधारा में लौटकर अपनी जिंदगी, अपने ज्ञान को सार्थक बनाने में लगी हुई है।

वह जिस गांव में पैदा हुई, वहां लोकतंत्र की बजाए क्रांति के गीत ही गूंजते थे। ऐसे माहौल में दसवीं कक्षा में पढ़ने के दौरान ही उसने बंदूक थाम ली थी। खेलकूद में तेज थी। दसवीं तक पढ़ी थी। इसलिए संगठन में उसे अक्षर ज्ञान से वंचित नक्सलियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मिली। इतना ही नहीं, वह नक्सलियों के उस स्कूल में भी पढ़ाती थी, जहां बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ क्रांति का भी पाठ पढ़ाया जाता था। वह आज भी पढ़ा रही है, लेकिन लक्ष्य संहार नहीं बल्कि सृजन है।

रेडियो से पता चला पुनर्वास नीति के बारे में : पिता की मौत के बाद जब उसने हिंसा छोड़ने का निर्णय लिया तो रेडियो ने राह दिखाई। समाचार के जरिये उसे सरकार की पुनर्वास नीति के बारे में पता चला। इसके बाद वह जंगल से भाग आई। सितंबर 2018 में उसने कोंडागांव एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 25 जून 2019 को उसे गोपनीय सैनिक बना दिया गया, जिसमें एवज में उसे कुछ मानदेय मिलता है।

बहुत खुश है दोहरी भूमिका से : आज वह अपनी दोहरी भूमिका से बहुत खुश है। आत्मसमर्पण के बाद नक्सलियों के निशाने पर आ जाने से डर नहीं लगता? पूछने पर वह शांत भाव से कहती है- मरना तो सभी को एक दिन है ही। वहां रहकर मरने और यहां रहकर मरने में बहुत फर्क है। वह आज करीब 50 बच्चों को पढ़ा रही है, जिसमें पुलिस लाइन के अलावा आसपास की बस्तियों के बच्चे भी आते हैं।

काम के प्रति उसके लगन और समर्पण को देखते हुए उसे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा दिया गया है। आगे रायपुर की तर्ज पर कोंडागांव में भी पुलिस विभाग द्वारा विद्यालय खोला जाएगा। वहां उसे बतौर शिक्षक नियुक्त करेंगे।

-सुजीत कुमार, पुलिस अधीक्षक, कोंडागांव

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

दो हजार के नोट बंद होने का दावा फर्जी

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

विश्वास न्यूज, जेएनएन: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 31 दिसंबर 2019 से दो हजार रुपये के नोट बंद हो जाएंगे। विश्वास न्यूज की टीम की पड़ताल में यह पोस्ट फर्जी साबित होती है।

पड़ताल: विश्वास न्यूज की टीम ने सबसे पहले वायरल पोस्ट को ध्यान से देखा तो पता चला कि यह किसी अखबार की क्लिपिंग थी। ध्यान से देखने पर टीम को अखबार के मास्टहेड पर **dainikpurvoday.com** लिखा हुआ नजर आया। क्लिपिंग में एक दिसंबर लिखा हुआ था। इसके बाद टीम **dainikpurvoday.com** पर गई। एक दिसंबर 2019 के संस्करण में टीम को एक खबर मिली। खबर में विस्तार से बताया गया था कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में यह अफवाह है कि 31 दिसंबर के बाद 2000 का नोट नहीं चलेगा।

खबर में यह भी बताया गया कि यह सिर्फ एक अफवाह है। पड़ताल के दौरान टीम को पता चला कि वायरल क्लिपिंग मूल ईपेपर का सिर्फ एक छोटा-सा पार्ट है। किसी ने मूल खबर में से इसे अलग से क्रॉप करके गलत दावे के साथ वायरल कर दिया। पड़ताल के अगले चरण में टीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट **rbi.org.in** पर गई। यहां टीम को कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली, जिसमें दो हजार के नोट को 31 दिसंबर 2019 के बाद बंद करने की बात की गई हो। पड़ताल के दौरान टीम राज्यसभा की वेबसाइट पर भी गई। वहां उसे 3 दिसंबर को 2000 रुपये के नोट को लेकर पूछे गए प्रश्न और उसका उत्तर मिला। वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने तीन दिसंबर को राज्यसभा में बताया कि 2000 रुपये के नोट को बंद करने की कोई योजना नहीं है। आरबीआइ के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल ने दो हजार के नोट को लेकर चल रही अफवाहों पर कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

क्या है वायरल पोस्ट में?
फेसबुक पर संतोष झा नाम के एक यूजर ने 6 दिसंबर को एक पोस्ट अपलोड करते हुए दावा किया कि 31 दिसंबर 2019 के बाद आप अपने 2000 के नोट बदल नहीं पाएंगे।

झूठी खबर और अफवाहों की हकीकत जानने के लिए वाट्सएप करें:
9205 270 923

हिमाचल में भारतीय इंजीनियरों ने बनाई आकर्षक सुरंग

सुनील शर्मा, सोलन

हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजों द्वारा बनाई वर्ल्ड हेरिटेज शिमला-कालका रेलवे लाइन पर बड़ोग सुरंग को अब भारतीय इंजीनियरों ने मात दी है। 116 वर्ष बाद इस पहाड़ पर भारतीय इंजीनियरों ने उससे भी आकर्षक और आधुनिक सुरंग तैयार कर दी है। देश व विदेश के पर्यटकों को अब यहां दो आकर्षक सुरंगें देखने को मिलेंगी।

एक सुरंग रेल मार्ग के माध्यम से देखी जा सकेगी, दूसरी सड़क के माध्यम से। परवाणू-शिमला फोरलेन के निर्माण में लगी ग्रिल कंपनी ने इस सुरंग को तैयार कर लिया है। 100 करोड़ से तैयार इस सुरंग में कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं ही इसे अंग्रेजों द्वारा बनाई सुरंग से आगे कर रही हैं।

बड़ोग रेल सुरंग : ऐतिहासिक बड़ोग रेल सुरंग विश्वभर में प्रसिद्ध है। इसके निमार्ण में 1896 से 1903 तक सात वर्ष लगे। कर्नल बड़ोग ने इसका निर्माण शुरू किया था। जब इसके दोनों सिरे नहीं मिले तो ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर एक रुपये जुर्माना लगा दिया। इसे कर्नल सह नहीं सके और उन्होंने रिवॉल्वर से पहले अपने कुत्ते को गोली मारी और बाद में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद चायल स्थित एक भेड़ पालक बाबा भलखु ने इसे बनाने में अंग्रेजी हुकूमत की मदद की। कालका शिमला रेलमार्ग पर यह 33 नंबर सुरंग सबसे लंबी है। इसे यूनेस्को ने 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। इसकी चौड़ाई 10 से 12 फुट व लंबाई 1143 मीटर है।

भारतीय इंजीनियरों द्वारा तैयार की गई इस आधुनिक और आकर्षक सुरंग में दोनों तरफ पैदल पथ भी हैं। जागरण

दिसंबर के तक सुरंग के कार्य को पूरा करने का समय दिया था। सुरंग का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाए।

-एके स्वामी, डायरेक्टर, नेशनल हाइवे अथारिटी

सुरंग को 15 जनवरी, 2020 को शुरू किया जा सकता है। फिलहाल इसके अप्रोच मार्ग को काम शेष है। यह सुरंग शमलेच और कलोल गांव को आपस में जोड़ेगी।

-राजीव पठानिया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जीआर इंफ्रा कंपनी

हिमाचल में एनएचए की पहली सुरंग

हिमाचल में इस सुरंग से पहले राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोई भी सुरंग नेशनल हाइवे अथारिटी (एनएचए) द्वारा तैयार नहीं की गई है। कुल्लू में 1300 मीटर रोहतांग सुरंग को बीआरओ यानी बार्डर रोड आर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जा रहा है। हालांकि अन्य प्रदेश में एनएचए की ओर से कई जगह सुरंगों का कार्य जारी है, लेकिन बड़ोग में पहली तैयार सुरंग होगी।

सुरंग में खास

- 100 करोड़ रुपये से तैयार हुई।
- 08 मीटर सड़क वाहनों के लिए
- 03 तीन गाड़ियां निकल सकेंगी।
- 11 मीटर सुरंग के अंदर कुल चौड़ाई। दोनों तरफ फुटपाथ है।
- 936 मीटर कुल लंबाई।
- 04 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा।
- 100 वर्ष है सुरंग की उम्र।
- 10 इंजीनियर और 100 से अधिक मजदूरों ने निमार्ण किया
- 02 वर्ष में सुरंग का निर्माण पूरा हुआ।
- यह सुरंग शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए इस्तेमाल होगी। वनवे है सुरंग।
- सुरंग के अंदर ऑटोमेटिक एलईडी लाइट हैं।
- फायर सेफ्टी, जैट फैन और सीसीटीवी कैमरे स्थापित।
- सुरंग में आधुनिक सेंसर लगाए गए हैं जो खतरे को पहले ही भांप सकेंगे।
- सुरंग के बाहर कंट्रोल रूम होगा, जिसमें सीसीटीवी कैमरों और सेंसर का कंट्रोल होगा।
- सुरंग को न्यू ऑस्ट्रिया टनलिंग मैथड तकनीक से तैयार किया गया है।

व्यथा

अतिक्रमण की भेंट चढ़कर खोह नदी की जननी लंगूरगाड व सिलगाड गिन रही हैं अंतिम सांसें, सरकार की नजर सिर्फ खोह पर, सिलगाड व लंगूरगाड में उड़ रही नियमों की धज्जियां

कोटद्वार की खोह नदी की पुकार, बचा लीजिए सरकार

अजय खंतवाल, कोटद्वार(पौड़ी गढ़वाल)

सरकार अस्थायी राजधानी देहरादून में दम तोड़ चुकी रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने की तैयारी में है, लेकिन यहां खोह नदी की कोई सुध लेना वाला नहीं है। खोह सदियों से लोगों का जीवन बचाती आई है, लेकिन आज इसका ही जीवन खतरे में है। खोह की जननी नदी लंगूरगाड और सिलगाड भी अंतिम सांसें गिन रही हैं। खोह नदी संरक्षण की बात तो हो रही है, लेकिन कोई यह समझने को तैयार नहीं कि इसका अस्तित्व सिलगाड व लंगूरगाड से है।

इन्हीं दो नदियों के मिलन से पौड़ी जिले के एतिहासिक दुगड्डा कस्बे से खोह नदी निकलती है और वन क्षेत्र से 25 किमी का सफर तय कर कोटद्वार से दस किमी. आगे सनेह में कोल्हू नदी से मिल जाती है। इसके बाद धामपुर (बिजनौर-उत्तर प्रदेश) में राम गंगा नदी में समाहित होकर खोह आगे बढ़ती है।

करीब डेढ़ दशक पूर्व तक जब नलकूप नहीं थे तब यह नदी कोटद्वार नगर के साथ ही आसपास के तमाम गांवों की प्यास बुझाती थी। आज यह नदी लैंसडौन वन प्रभाग के जंगलों में बसे उन बेजुबानों की प्यास बुझा रही है, जिन्होंने इस क्षेत्र की जैवविविधता को पहचान दी है।

पौड़ी में कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य बह रही खोह नदी को बचाने के चुनौती बढ़ गई है। नदी पर बनाया गया चेकडैम भी टूट गया है और बढ़ते अतिक्रमण ने नदी के वजूद को संकट में डाल दिया है। जागरण

सरकारी सिस्टम जो आज इस नदी को बचाने के दावे कर रहा है। नदी को बचाने के लिए चेकडैम बनाने की तैयारी है। जबकि, इस नदी का अस्तित्व उसी सिलगाड व लंगूरगाड से है, जिन पर सरकारी सिस्टम की मिलीभगत से अतिक्रमण कर लगातार व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन रहे हैं, लेकिन उस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।

पौराणिक कथाओं में भी है जिक्र : पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि खोह नदी के तट पर ही अप्सरा मेनका अपनी नवजात पुत्री को छोड़कर वापस स्वर्ग लौट गई थी। जहाँ शकुंत पक्षी ने अपने पंख फैलाकर उस नवजात की तेज धूप से रक्षा की थी। यही नवजात बालिका बाद में शकुंतला के नाम से जानी गई। इसी शकुंतला के गर्भ से भरत ने जन्म लिया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए।

खोह नदी के संरक्षण को सिंचाई विभाग के साथ योजना तैयार की जा रही है। योजना में खोह के साथ ही उसे जीवन देने वाली सिलगाड व लंगूरगाड में भी पानी रोकने के उपायों को शामिल किया जाएगा।

-धीराज सिंह गर्ब्याल, जिलाधिकारी, पौड़ी

उत्तराखंड में महंगी होगी राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों की सैर

केदार दत्त, देहरादून

- संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर शासन में चल रहा मंथन

उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों व कंजर्वेशन रिजर्व की सैर अब महंगी होने जा रही है। वन्यजीव विभाग ने इन क्षेत्रों में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसमें संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश शुल्क व वन विश्राम भवनों में ठहरने की दरों में 25 से 50 फीसद की वृद्धि की सिफारिश की गई है। पहली बार राज्य के चारों कंजर्वेशन रिजर्व में प्रवेश शुल्क की दरों का निर्धारण भी किया गया है। विभाग का तर्क है कि 2009 के बाद दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। बदली परिस्थितियों में वित्तीय संसाधन जुटाने के दृष्टिगत ऐसा करना समय की मांग है। उधर, शासन में इस प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है। छह राष्ट्रीय उद्यान, सात वन्यजीव विहार और चार कंजर्वेशन रिजर्व वाले उत्तराखंड में वन्यजीवन के दीदार को बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। यह संरक्षित क्षेत्रों की आय का अहम जरिया भी है। इसमें प्रवेश शुल्क और वन विश्राम भवनों में ठहरने की दरें महंगी करने की सिफारिश की गई है। कार्बेट व राजाजी टाइगर रिजर्व में दरों में ज्यादा वृद्धि होगी, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों में दरें समान रहेंगी। अभयारणों में अस्कोट में दरें नई होंगी। चारों कंजर्वेशन रिजर्व में भी प्रवेश की दरें निर्धारित की गई हैं। अभी तक आसन व झिलमिल में ही ये दरें लागू हैं।अफसर भी देंगे ज्यादा राशि : वन विश्राम भवनों के विभागीय उपयोग पर अधिकारियों के लिए सौ रुपये प्रतिदिन का शुल्क प्रस्तावित किया गया है। पहले यह 25 रुपये प्रतिदिन था। इनमें नहीं होगा बदलाव : पर्यटकों को ले जाने वाले वाहनों के अलावा छायांकन, कैंपिंग की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा।

दैनिक जागरण

सबरंग

साहित्य के...

नई दिल्ली, गुरुवार, 12 दिसंबर, 2019

सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

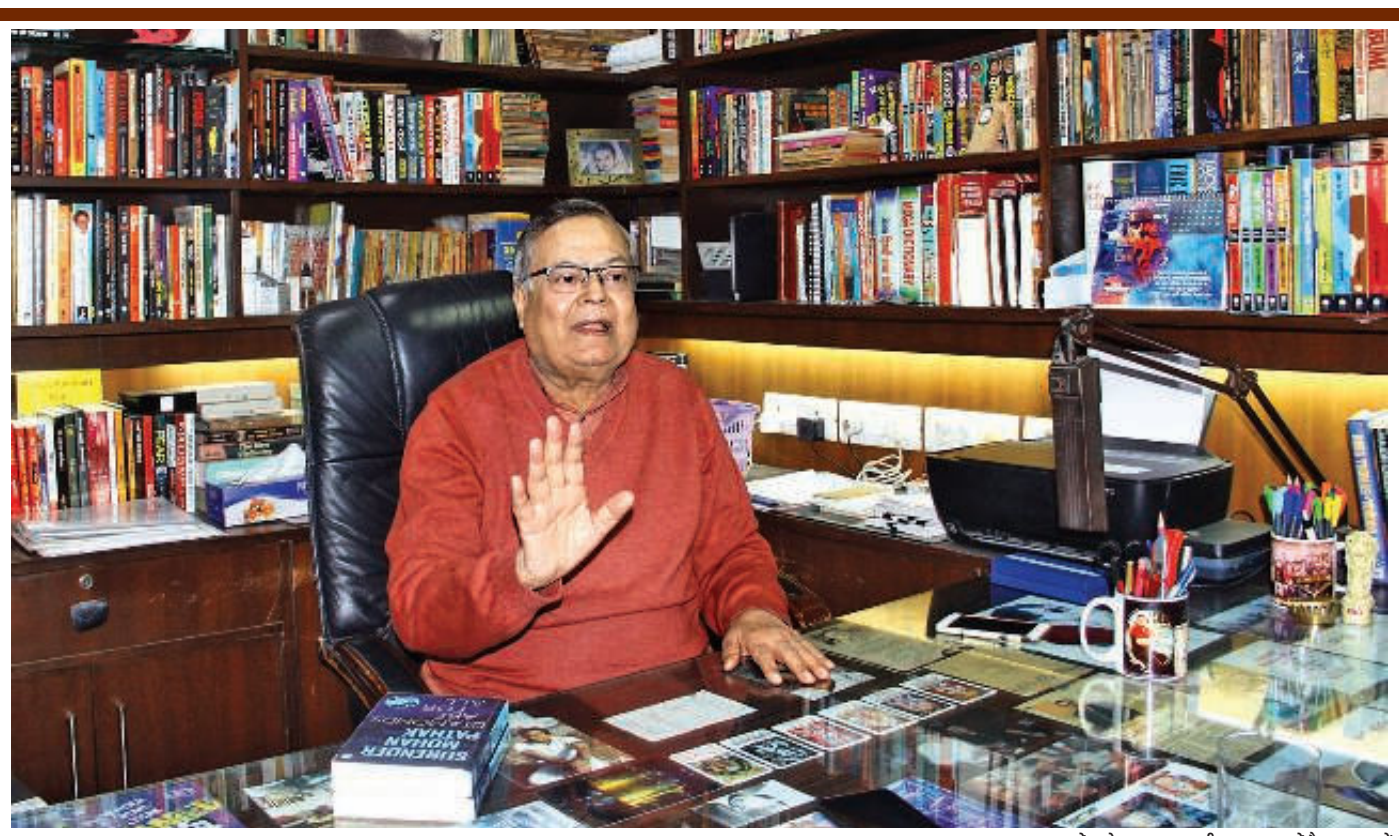

दिल्ली की दिल्लगी ने इतना लिखा दिया

कोशिश तो बहुतों ने की लेकिन फिलवक्त तो क्राइम, थ्रिलर पर लेखन करने वाले एक ही 'ब्रांडेड' लेखक नजर आते हैं जो अब तक 303 किताबें लिख चुके हैं। नाम है सुरेंद्र मोहन पाठक। 20 वर्ष की उम्र में ही प्रसिद्ध उपन्यासकार इयान फ्लेमिंग रचित जेम्स बांड की सीरीज और जेम्स हेडली चेज के उपन्यासों का अनुवाद करना प्रारंभ कर दिया था। 'पैंसठ लाख की डकैती' नामक उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद होने के बाद तकरीबन ढाई करोड़ प्रतियां बिकी थीं। दिल्ली में पले बढ़े पाठक ने पुरानी दिल्ली को अलग ही अंदाज में जिया है। उनके रग-रग में दिल्ली बसी है। साहित्यिक गलियारों से खासा सरोकार नहीं रहा, लेकिन जीवन में बहुत कुछ रोचक जरूर रहा। सुरेंद्र मोहन पाठक ने मनु त्यागी से अनदेखी, कमजानी सी दिल्ली के बहुत से किस्से साझा किए। प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंश :

सुरेंद्र मोहन पाठक, इसी पुस्तकालय में बैठकर पुस्तकें लिखते हैं। जब किताब लिखनी शुरू करते हैं तो रिदम न टूटे इसके लिए कई दिन इसी पुस्तकालय में घंटों बीत जाते हैं, सिर्फ सोने के लिए ही बाहर निकलते हैं।

सभी फोटो : सौरभ राय

लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक के पुस्तकालय की एक दीवार उनके जवां दिनों की गैलरी...शौकिया मिजाज को भी बयां करती है।

बातचीत

● चलिए दरियागंज से शुरू करते हैं आपने वहां 34 साल नौकरी की। आपके युवा दौर में कैसी रही थी वो जगह?

-दरियागंज दिल्ली का सबसे पॉश इलाका होता था। वास्तु में चंडीगढ़ जैसी समानता नजर आती थी। दिल्ली के सभी रईसों को शौक होता था कि यहां एक आलीशान घर हो। जिन्होंने यहां घर बनाए वे चांदनी चौक, खारी बावली के बड़े व्यापारी होते थे। अब सब यहां से उठकर चाणक्यपुरी, ग्रेटर कैलाश, दक्षिणी दिल्ली चले गए हैं। आज भी यहां की हवेलियों का डिजाइन, वास्तु देखो ये उन्हीं रईसों का रुतबा तो बोलता है। अब दरियागंज का हुलिया इसलिए बदला नजर आता है, क्योंकि जो इलाका पहले रिहायशी था अब उसे व्यावसायिक बना दिया गया है। जब रिहायशी था तब वहां रात को 12-1 बजे तक भी चहल-पहल होती थी। अब तो ये हाल है कि 5-6 बजे दफ्तर बंद हुए और रौनक खत्म। जहां अब डबल रोड दिखती है वो भी नहीं होती थी। अब जो ट्रैफिक से जूझता हुआ इलाका नजर आता है वहां ऐसा नहीं होता था, एकदम खाली होता था। बस के लिए भी एक ही स्टैंड हुआ करता था। अब तो दिल्ली गेट से दरियागंज तक पांच स्टैंड बन गए हैं।

● अच्छा, इसके पीछे क्या रहस्य है कि हर प्रकाशक दरियागंज में जरूर दफ्तर खोलना चाहता है?

-सबसे पहले किसने दरियागंज में प्रकाशन संस्थान खेलने की शुरुआत की यह तो मुझे नहीं पता लेकिन यह सवाल तो ऐसा हो गया कि कोई सर्राफ दुकान खोलना चाहता है तो स्वाभाविक है वह सराफा बाजार में ही दुकान खोलेगा, कहीं और के बारे में तो बाद में सोचेगा। दरियागंज के अंसारी रोड पर कुछ नहीं तो कम से कम हजारों प्रकाशकों के दफ्तर हैं। शुरुआत तो एकाध से ही हुई थी लेकिन अब ऐसे हालात हो गए हैं कि यदि प्रकाशक को दिल्ली में कहीं और दफ्तर खोलने के लिए ऑफर किया जाता है तो वह राजी ही नहीं होता। मुंबई का एक प्रकाशक है तारापोर वाला वो लॉ की किताबों का बहुत बड़ा प्रकाशक है। उन्होंने अंसारी रोड पर भी दफ्तर खोलने की कोशिश की लेकिन वहां उतनी जगह मिली नही। उसके बाद प्रकाशक को कनॉट प्लेस, नेहरु प्लेस ऑफर किया गया लेकिन उसने कहीं नहीं स्वीकारा। जगह नहीं मिली तो दिल्ली में उसने दफ्तर खोलने का विचार ही रद कर दिया। पतली-पतली सी जगहों में हर माले पर तीन-चार प्रकाशक के दफ्तर हैं। आपको वहां मैकमिलन, ऑक्सफोर्ड से लेकर भारत के सारे प्रकाशक मिल जाएंगे। आप यकीन करोगे एक यूबीएस वितरक है। कभी कानपुर में उसका छोटा सा स्टॉल होता था। अब यहां अंसारी रोड पर शाम को कभी छुट्टी के वक्त जाइए अचानक 500 कर्मचारी एक छोटी सी जगह से एक साथ निकलते नजर आएंगे। इसी तरह वहां आपको दिल्ली बुक डिपो वाले के यहां एक बोर्ड नजर आएगा जिस पर लिखा हुआ है कि हमारे यहां 90 हजार टाइटल उपलब्ध हैं। दरियागंज गढ़ बन चुका है एक ही जगह प्रिंटिंग, बाइंडिंग, कागज का काम हो रहा है। यह सुविधा भी है।

● सिर्फ प्रकाशक ही नहीं, वहां तो किताबों का भी बड़ा बाजार रहा। नई सड़क पर हर रविवार को लगने वाले किताब बाजार के बारे में कुछ बताइए?

-आप सोचते होंगे 1960 से लगने वाले इस किताब बाजार में किताबें आती कहां से हैं। दरअसल कबाड़ी घरों से 12 आने में रद्दी लेकर आते थे। उनमें किताबें भी होती थीं तो उन्हीं किताबों को यहां बेचना शुरू किया। पहले होता था 'जो पाया वो कमाया', क्योंकि उन्हें ऐसे बेचने में ठीक पैसा मिल जाता था। लोगों को फायदा यह होता था कि बड़े से बड़ा लेखक वहां सस्ते में मिल जाता था। अब ये कबाड़ी भी चतुर हो गए हैं। वे लेखक और किताब के हिसाब से बेचते हैं, वैसे ही मोलभाव करते हैं। ये सब कार में चलने वाले कबाड़ी हैं। हालांकि दो ही ऐसे कबाड़ी हैं जो पांच सितारा होटल और एंबेसी से किताबें लेकर आते हैं वो किताबों भी यहां बिकती हैं। इसी तरह मुंबई से 25 हजार किलो किताब भरकर एक ट्रक यहां आता है। वो किताबें भी बिकती हैं उसमें ज्यादातर विदेशी किताबें होती हैं। पहले उनकी छटनी होती है फिर इस बाजार में बिक्री होती है। जब पहली बार किताब का कंटेनर आया था तो लोग ऐसे टूट कर पड़े थे। वहां तो यह होता है कि यदि आपने मूंगफली खाकर लिफाफा फेंका है और बेचने वाले में इफर्ट है तो उसे पढ़ने वाला ग्राहक भी आपको मिल जाएगा। हालांकि जब कबाड़ी घर-घर से रद्दी लेकर आते थे उसमें जो किताबें होती थीं अब वो पहले जैसी बात नहीं है।

● और दरियागंज स्थित आपके दफ्तर का क्या माहौल होता था? आप चूंकि कर्मचारी के साथ लेखक भी थे साथी किस तरह से देखते थे?

-दरियागंज स्थित एमटीएनएल के आइटीआइ विभाग में 1964 से 98 तक नौकरी की। पैसों के लिए कम लोग मुझसे कुढ़ते थे इसलिए ज्यादा नौकरी की। दरअसल लोग सोचते थे कि मैं दफ्तर में बैठकर काम नहीं करता बल्कि किताब लिखता हूं, क्योंकि दो-चार माह में मेरी नई किताब आ जाती थी और चेक भी मिल जाता था। अकेले मेरे पास ही कार भी होती थी।

● लोग आपकी आत्मकथा पढ़ेंगे तो दिल्ली के और आपके बारे में क्या जानेंगे?

-देखो जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आत्मकथा जैसी चीज लिखूंगा। क्योंकि यह पांच साल पुराना ट्रेंड प्रकाशकों का चलाया हुआ है। उनको चाहिए किसी बड़े चेहरे से, हस्ती से उसके जीवन के बारे में जानो और आत्मकथा लिखवा लो या तो वो खुद लिख दें या किसी लेखक से लिखवा लिया जाए। ऋषि कपूर, संजय दत्त...उसी के तो उदाहरण हैं। मुझे भी प्रकाशक ने कहा दबाव बनाया तो मैंने लिखी। मैंने तो तब भी उससे कहा कि देख लेना 50-60 पेज ही लिख पाउंगा। लेकिन जब लिखने बैठा तो 1200 पेज लिख गया। सब कुछ दिल्ली में ही तो बीता-गुजरा है। दिल्ली के खूब किस्से हैं मेरे नौकरी करने से लेकर पुरानी दिल्ली के गलियारों के बारे में। अब चौथा भाग भी लूप में है। वैसे मेरा मानना है कि आत्मकथा लेखन वाला चलन बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है।

● आपने आत्मकथा लिखी तीन भाग आ गए चौथे की तैयारी है, क्या उसमें भी कुछ छिपाया?

-कौन नहीं छिपाता? महात्मा गांधी सिवाल एकाध को छोड़ दें तो किसने अपनी जीवनी में सारे सच लिखे हैं। कुछ तो छिपाने जरूरी होते ही हैं ताकि समाज में और परिवार में इज्जत बनी रहे। वो सच जानने भी जरूरी नहीं होते, इंसान उन्हें खुद भी गलती ही मानता है तो उनका जिक्र कर आत्मकथा का मजा क्यों किरकिरा किया जाए। पाठक का विश्वास बड़ी चीज होती है।

● पुस्तक लेखन के तीन शतक लगा चुके हैं, अभी आगे क्या इरादा है?

-मैं यदि लगातार सप्ताह भर बगैर लिखे रह जाऊं तो लगता है कि मैं जी क्यों रहा हूं। लिखे बगैर कोई जी सकता है क्या? वैसे भी प्रेमचंद ने तो कहा ही है कि 'जिस दिन लिखता नहीं हूं उस दिन मुझे रोटी का हक नहीं है।' अब 80 का होने जा रहा हूं 303 तक पहुंच गया हूं। आगे भी क्रम तो जारी रहने वाला है। कलम रुकना नहीं चाहती।

● तकनीक के जमाने में भी हाथ से ही लिखते हैं?

-एक राज की बात बताऊं मेरे सारे उपन्यासों के थ्रिलर, क्राइम, सस्पेंस मेरी कलम से ही निकलते हैं। पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति उस वक्त आती है जो कलम के साथ ही चलती है। लैपटॉप पर लिखने बैठो तो कुछ सूझता ही नहीं है। सिर्फ फाउंटेन पेन से लिखता हूं, अब यह पेन और स्याही बहुत कम मिलते हैं इसलिए थोक में लाकर रखे हुए हैं। सिर्फ काली स्याही से ही लिखता हूं। प्रकाशक को छापना है छापे नहीं छापना है न छापे लेकिन मैं तो हाथ से ही लिखूंगा शुरू से यही शर्त रही।

● दिल्ली के साहित्यिक माहौल को कैसे जिया?

-मैं बहुत कम लोगों में उठता बैठता हूं। यार मेरे कम ही हैं। दिल्ली के साहित्यिक माहौल से दूर ही रहा हूं। साहित्यिक ठिए, कॉफी हाउस की चर्चाओं में कभी नहीं गया। किसी ने मेरे लेखन की आलोचना कर दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने तारीफ करी तो भी ठीक है। बस अपने लिखने में ही हमेशा मन रहा। खूब पढ़ता हूं और लिखता हूं। ये जो चारों तरफ किताबों से भरा मेरा पुस्तकालय देख रही हो उसी की देन है। इसमें 300 किताबें तो मेरी ही लिखी हुई ही हैं। घूमने फिरने का समय ही नहीं मिलता था। वैसे भी मेरी आदत है किताब को पूरी करके ही कुछ और करता हूं।

● क्या पहले दृश्यों को सोचते हैं, शोध करते हैं? आखिर क्या करते हैं जिससे हर बार एक अलग ही क्राइम सीन, थ्रिलर, सस्पेंस भरी किताब लिख देते हैं?

-अब ये तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करता हूं। मुझे तो पाठकों से पता चलता है कि मैंने अच्छा लिखा इसलिए लिखे जा रहा हूं। रही बात यह सब मेरे दिमाग में आता कहां से है, तो क्या कभी आपको चांदनी चौक में जो नेमचंद जैन की जलेबी जो 500 रुपये किलो में बेचता है उससे पूछा है कि आखिर भैया आप कैसे बनाते हो, क्या-क्या डालते हो? लोगों को इतनी पसंद क्यों आती हैं कि दुनिया भर में मशहूर हैं। दरअसल कलम तो ईश्वर की देन होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बस जब बैठता हूं कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ होती है और मैं किताब लिखता चला जाता हूं।

● दिल्ली-एनसीआर में आए दिन नए तरीके का अपराध हो रहा है। यह सब आपकी किताबों का हिस्सा बनता है?

-मैं जब छोटा सा था यह बात कोई 1965 की रही होगी। हम किशन नगर में रहते थे। मेरी मां ने मुझे मिट्टी का तेल लेने के लिए भेजा। मैं बहुत जल्दी लौट आया तो बोली इतनी जल्दी कैसे? मैंने कहा अभी हवलदार खड़ा है रास्ते में बाद में जाउंगा। मतलब तब एक हवलदार का भी खौफ होता था। अब तो आठ पुलिस वाले किसी एक को पकड़ने जाते हैं और पिटकर आते हैं। यह सब सरकार की कमी है। सरकार ने सिस्टम को मजबूत बनाने पर काम नहीं किया। दिल्ली-एनसीआर में तो अपराध के तरीकों की हद हो गई है आए दिन अजीबो गरीब घटनाएं हो रही हैं। हां, इन सब घटनाओं पर पुलिस की स्थिति भी मेरी कलम का हिस्सा बनती रही है।

● आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बिकने वाला लेखक कहा जाता है?

-यदि ऐसा है तो 300 किताबें कैसे लिख दीं? सभी जगह पाठकों तक पहुंच रही हैं तभी तो इतना लिखा जा रहा है। वैसे भी अब तो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सिर्फ किताबें कहां मिलती हैं। वो तो पहले एएच व्हीलर कंपनी का कांट्रेक्ट था 280 स्टॉलों पर किताबें होती थीं। इन जगहों को पहले एक निश्चित जरिया माना जाता था कि यहां से लोग किताब खरीदेंगे ही। अब तो सब जगह बिकता हूं।

● साहित्यकारों को मिलने वाले सम्मान को कैसे देखते हैं?

-सम्मान कौन देखता है लोग तो हाथ में चेक देखते हैं कितने का आया। वैसे भी भारत में बड़े से बड़े सम्मान को देख लीजिए कितना सम्मान है उनका। सिर्फ जब मिलता है और जब आदमी मरता है तभी याद किया जाता है कि फलां को फलां सम्मान मिला। हां, विदेश में मिलने वाले ऑस्कर जैसे सम्मानों की अलग ही अहमियत होती है।

● दिल्ली की कोई ऐसी घटना जिसका संस्मरण आज भी बना हुआ हो?

-हां, 1955 में दिल्ली में ऐसी बाढ़ आई थी कि शाहदरा के चारों तरफ आठ-दस फीट पानी भर गया था शाहदरा आयरलैंड की तरह लगता था। लगभग एक महीने ऐसी स्थिति बनी रही। सदर बाजार, चांदनी चौक, खारी बावली, कनॉट प्लेस सब जगह शाहदरा से लोग काम करने जाया करते थे। वे सब 12 किलोमीटर पैदल चलकर जाया करते थे, काम करने के लिए। बाकी जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली के आसपास से आया करते थे उन्हें एक महीने के लिए छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन दिल्ली में रहने वाले सब आते थे। रेलवे ट्रैक डूब गए थे। दिल्ली में अकाल सा पड़ गया था किसी की छोटी-मोटी दुकान में राशन होता था तो मिल जाता था क्योंकि ट्रक वगैरह से ही तो सामान आता था और बाढ़ की वजह से दिल्ली के रास्ते बंद हो गए थे।

कला संगम में जुटते थे साहित्यकार

साहित्यिक धरोहर

देश की आजादी के बाद ही सुंदरी श्रीधरणी ने दिल्ली में एक कला केंद्र का सपना देखा था। सपना था दिल्ली में एक बेहतरीन कला केंद्र का। इस सपने को पूरा करने में उनके पति, गुजराती कवि और पत्रकार डॉ किशनलाल श्रीधरणी ने उनका साथ दिया था। आजादी के तीन साल बाद इस सपने ने आकार लिया था जब 1950 में कनॉट प्लेस के एक कॉफी शॉप के ऊपरी मंजिल पर त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की गई थी। यह ज्ञात तो नहीं है कि इसमें आर्थिक मदद किसने की या सुंदरी के व्यक्तिगत प्रयासों से ही इसकी शुरुआत हुई लेकिन इस संस्था की बेवसाइट पर इतनी जानकारी है कि त्रिवेणी कला संगम की शुरुआत जब कनॉट प्लेस में एक कमरे में की गई थी तो इनको सौ रुपये का डोनेशन मिला था। ये कला संगम दो छात्रों के साथ शुरू किया गया था। बाद में इस कला केंद्र को मंडी हाउस इलाके में जगह दी गई थी और वहां पर इसकी इमारत बनी। जब इसकी इमारत बन रही थी तो सुंदरी के पति की मौत हो गई लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इसको तैयार किया। 1957 में इसकी इमारत बननी शुरू हुई थी और 1963 में बनकर तैयार हुई थी। इसका शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ एस राधाकृष्णन ने की थी।

इस इमारत में एक बेहतरीन लॉन भी है जो उस वक्त साहित्यकारों की बैठकी का अड्डा हुआ करती थी। 1970 के बाद तो यहां साहित्यकारों का नियमित जमावड़ा होता था। जाड़े में लॉन में बैठकर जमकर चर्चा होती थी, साहित्यिक बहस हुआ करती थीं। इस लॉन में साहित्यिक चर्चा के लिए भीष्म साहनी, गंगाप्रसाद विमल से लेकर मोहन राकेश और राजेन्द्र यादव तक जुटा करते थे। उस दौर के साहित्यकार बताते हैं कि उपन्यासकार मोहन राकेश ने अपनी कई कहानियों का पाठ भी इस तरह की साहित्यिक जुटान में किया था। राकेश का ये पसंदीदा अड्डा हुआ करता था। दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक होने की वजह से बाहर से आने वाले साहित्यकारों को भी यहां पहुंचने में सुविधा होती थी और ये एक ऐसी जगह थी जहां दिल्ली के साहित्यकार मिल ही जाया करते थे। गंगाप्रसाद विमल ने बातों बातों में बताया कि उस जमाने में त्रिवेणी में साहित्यकारों का नियमित जुटान तो होता था लेकिन त्रिवेणी में जो कैंटीन थी वहां चाय महंगी मिला करती थी। सस्ती चाय के लिए यहां जुटने वाले साहित्यकार सड़क पार करके जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के गोमती गेस्ट हाउस पहुंच जाया करते थे और वहां की कैंटीन में चाय पीते और फिर विमर्श के लिए त्रिवेणी के लॉन में पहुंच जाते थे। जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय का गोमती गेस्ट हाउस फिक्की की इमारत के पीछे के इलाके में है। विमल जी ने तो एक ऐसी गोष्ठी के बारे में बताया जिसमें अज्ञेय भी थे और गोष्ठी समाप्त होने के बाद सभी लोग चाय पीने के लिए गोमती गेस्ट हाउस तक गए थे। त्रिवेणी कला संगम से कई साहित्यकारों की रूमानी यादें भी जुड़ी हैं। विमल जी बताते हैं कि उस दौर में इस इलाके में इतनी भीड़भाड़ नहीं होती थी तो युवा साहित्यकारों के प्रेम का अड्डा भी होता था। कई लेखक तो उन दिनों अपनी प्रेमिकाओं के साथ त्रिवेणी कला संगम के किसी कोने में दिखाई दे जाते थे।

अनंत विजय

यहां जिम्मेदार नागरिक का भी पढ़ाया जाता है पाठ

फुर्सत का ज्ञान

शाहदरा का नाम लेते ही भीड़भाड़ वाली सड़कें और तंग गलियां...बाजार की भीड़ नजरों के सामने तैर जाती हैं। ऐसे में यहां पढ़ाई के लिए शांत वातावरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (डीपीएल) पहुंचते ही आपकी सोच बदल जाएगी। यहां न केवल पढ़ाई के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध है, बल्कि पुस्तकालय में प्रवेश करते ही बाईं तरफ लिखे एक सुंदर संदेश पर नजर पड़ती है, जिसमें लिखा है 'हिंदी लिखो, हिंदी पढ़ो, हिंदी ही तुम बोलो। हिंदी में सब काम करो, हिंदी में मुख खोलो।' इस पंक्ति को पढ़कर पाठक हिंदी भाषा के प्रति आकर्षित होते हैं। 1964 में स्थापित दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसके अंतर्गत पूर्वी दिल्ली में ही पांच पुस्तकालय हैं, जो सीलमपुर, कल्याणपुरी, नंदनगरी, योजना विहार और विज्ञान विहार में हैं। पाठकों का पुस्तकों के प्रति लगाव बढ़े वे रुचि लेकर किताबों का अध्ययन कर सकें इसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित डीवीडी भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

जवाहरलाल नेहरु लाइब्रेरी बन गई दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी : 1947 से 1964 तक इस पुस्तकालय को जवाहरलाल नेहरु लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। आज भी डीपीएल के साथ यहां जवाहर लाल नेहरु लाइब्रेरी के उद्घाटन का पत्थर लगा हुआ है। संचालक कहते हैं कि पुस्तकालय की शुरुआत कुछ बड़े अधिकारियों ने मिलकर की थी, जिसकी देखरेख शाहदरा के ही लोग करते थे। लेकिन 1964 में इसे डीपीएल को सौंप दिया गया। आज भी पुराने लोग इसे जवाहर लाल नेहरु लाइब्रेरी के नाम से ही जानते हैं।

एक लाख किताबों का संग्रह : यहां हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी व उर्दू साहित्य के अलावा एक लाख से भी अधिक किताबों का संग्रह है। इनमें सामान्य ज्ञान, मनोविज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, हिंदू शास्त्र, सिख धर्म, कानून, लोक प्रशासन, हास्य व्यंग्य, खेल, संगीत, व्यापार, फोटोग्राफी, ललित कला, भारतीय कला, जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कृषि, इंजीनियरिंग, जीवनी, इतिहास समेत कई विषयों पर आधारित पुस्तकों का खजाना उपलब्ध है। पाठकों को एक बार में तीन किताबें 14 दिन के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

बच्चों को मिलता है शांत वातावरण : पुस्तकालय का वातावरण पाठकों के लिए कितना उपयुक्त है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां रोजाना करीब 200 पाठक आते हैं। भू-तल पर पुस्तकालय व प्रथम तल पर पाठकों के लिए रीडिंग सेक्शन है, जिसमें करीब 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यही वजह है कि दूर-दूर से लोग यहां पढ़ाई करने आते हैं। अगर खुले आसमान के नीचे बैठ कर पढ़ाई का आनंद लेना चाहते हैं तो छत पर कुर्सी लगाकर पढ़ाई करने की भी व्यवस्था है। वैसे तो यहां पाठकों की जरूरत की सभी पुस्तकें उपलब्ध है, लेकिन छात्र किसी खास पुस्तक की मांग करते हैं और वह पुस्तकालय में उपलब्ध न हो तो खास तौर पर वह मंगाई भी जाती है। पुस्तकालय को और समृद्ध बनाने के लिए समय-समय पर पाठकों से बुक सजेशन फॉर्म भी भरवाए जाते हैं, इसके बाद उन पुस्तकों को मंगवाया जाता है।

चिल्ड्रन सेक्शन भी है खास : इस पुस्तकालय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां छोटे बच्चों के लिए एक चिल्ड्रन सेक्शन भी है। इस सेक्शन में सैकड़ों की संख्या में हिंदी व अंग्रेजी बाल साहित्य समेत कार्टून व फेरी टेल्स की पुस्तकें तो हैं ही डीवीडी भी उपलब्ध हैं, जिन्हें बच्चे खूब पसंद करते हैं।

जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन : पाठक यहां केवल किताबी ज्ञान ही न लें, उन्हें सामाजिक मुद्दों का भी पता हो इसके लिए स्वच्छता व सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए समय समय पर भाषण, लेखन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं। इसके अलावा रैली व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जाते हैं।

किताबें जो करती हैं आकर्षित : यहां कुछ किताबें ऐसी भी हैं, जिन्हें पाठक रुचि लेकर पढ़ते हैं। कश्मीर डिस्प्यूट, कर्नाटक, अयोध्या रीविजिटेड, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, भारतीय संगीत का इतिहास, इनसाइक्लोपीडिया, ब्रिटानिका, एनिमल लॉज ऑफ इंडिया जैसी किताबें पाठक एक बार जरूर पढ़ते हैं। पुस्तकों के अलावा हिंदी व अंग्रेजी के आठ अखबार सहित 12 पत्रिकाएं भी आती हैं।

रितु राणा

● **ऐसे पहुंचे :** शाहदरा मेट्रो स्टेशन से पैदल रिक्शा लेकर पुस्तकालय पहुंचा जा सकता है।
● **खुलने का समय :** सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक यहां कभी भी आ सकते हैं। रविवार को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं।

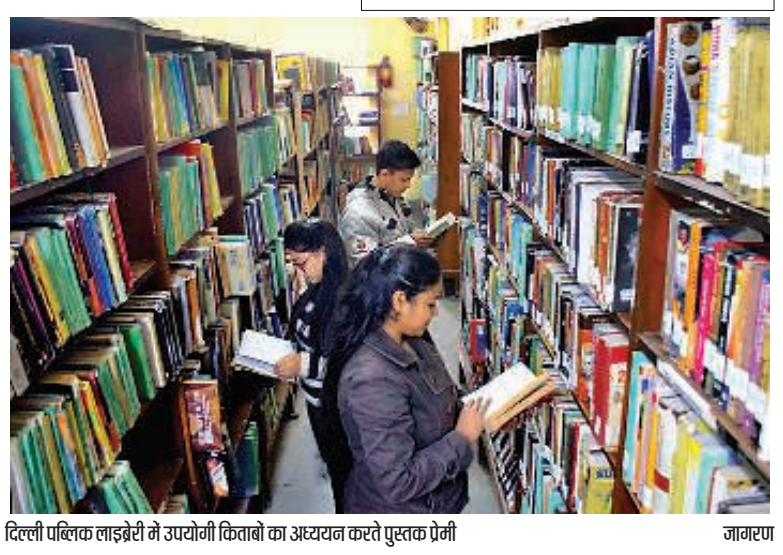

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में उपयोगी किताबों का अध्ययन करते पुस्तक प्रेमी जागरण

शाहदरा फर्श बाजार स्थित दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जागरण

ऐसे लें सदस्यता

अगर आप यहां अध्ययन करना चाहते हैं तो 20 रुपये देकर पांच साल तक की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे भरने के बाद आधार कार्ड व निवास प्रमाण पत्र की कॉपी संलग्न कर उसे किसी राजपत्रित अधिकारी के साक्ष्यांकित (अटेस्ट) कारकर लाइब्रेरी में जमा कराना होगा। इसके बाद पुस्तकालय से एक सदस्यता कार्ड मिलता है। वर्तमान में यहां से करीब 30234 पाठक जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से यहां पढ़ने आते हैं।

घर में चार चांद लगा देंगी पोपली की खूबसूरत वस्तुएं

काम की दुकान

घर की साज-सज्जा की बात हो और पीतल का जिक्र न हो तो सजावट अधूरी है। एक कोने में पीतल के नक्काशीदार फूलदान, पीतल के ग्रामोफोन, एंटीक रोटरी डायलर फोन जैसी एंटीक पीस इन दिनों चलन में है। तो अगर आप भी अपने सपनों के महल आकर्षक और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो जनपथ स्थित पोपली ब्रास शॉप पहुंच जाएं। यहां पीतल की आकर्षक वस्तुएं देख हैरान रह जाएंगे। इनकी दुकान पर उपलब्ध पीतल के हुक्कों पर मुरादाबाद की सुंदर बिदरी कारीगरी ग्राहकों को खासा आकर्षित करती हैं। यहां पीतल, तांबे, कांस्य, एल्यूमिनियम की वस्तुओं का भंडार है।

दुकान को 1973 में सुधीर पोपली ने शुरू किया था, अब उनके बेटे साहिल पोपली इस दुकान को चला रहे हैं। साहिल कहते हैं कि पिता ने जब शुरुआत की थी तब इस दुकान पर ब्रास की महज 100-200 वस्तुएं ही थीं, लेकिन ग्राहकों की मांग को देखते हुए वस्तुओं की संख्या भी बढ़ती चली गई और आज यहां हजारों सजावटी वस्तुएं उपलब्ध हैं।

अरे वाह, इसे तो टेबल पर रखूंगी। पोपली ब्रास शॉप पर सजावटी वस्तुओं को देखती महिला : जागरण

कुछ चीजें देखते ही आ जाएंगी पंसद : समय के साथ-साथ लोगों की पंसद भी बदलती रहती है। इसलिए यहां ग्राहकों को नए-नए डिजाइन के सजावटी सामान उपलब्ध कराए जाते हैं। दुकान पर कई चीजें तो ऐसी है, जिन्हें देखते ही खरीदने का मन कर जाता है। यहां पीतल की वस्तुओं का भंडार तो है ही तांबे और एल्यूमिनियम की भी एक से बढ़कर एक वस्तुएं मिल जाएंगी। सन् 1973 की वस्तुएं भी यहां पर उपलब्ध हैं। यहां विभिन्न आकार में पीतल के सींगिंग बाउल उपलब्ध हैं, जिनकी आवाज से सिर दर्द और नकारात्मकता दूर होती है। इन बाउल में से ब्लैक होल जैसी आवाज निकलती है जो तन व मन को शांत करती है। वहीं, पीतल के सुंदर बुकमार्क भी यहां मिल जाएंगे। दुकान पर आने वाले ग्राहक इसे खूब पसंद करते हैं। इसके अलावा ग्रामोफोन, एंटीक रोटरी डायलर फोन, शू हॉर्न (जूते पहनने वाली स्टिक), टरकिश कैटल (चाय की केतली), वेलकम स्टैंड, कैंडल स्टैंड, चेस के सेट, ताज महल के प्रतिरूप, प्लेट व गिलास, दीवार घड़ियां, टेबलवेयर भी बेहद आकर्षक हैं। विदेशी पर्यटक इसे खूब पसंद करते हैं। कई आकार में गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, गौतम बुद्ध, लाफिंग बुद्धा आदि पीतल की मूर्तियां भी उपलब्ध हैं।

बिदरी कारीगरी है खास : दुकान पर करीने से सजे अलग-अलग आकार के पीतल के हुक्के तो इतने आकर्षक हैं कि ग्राहक रुककर उसे एक नजर जरूर देखते हैं। दरअसल इन पर की गई सुंदर बिदरी कारीगरी इसके आकर्षण का कारण है। साहिल कहते हैं कि यह बिदरी कारीगरी मुरादाबाद की है जिस पर काले व गोल्डन रंग से बारीक कारीगरी की जाती है। ग्राहक की पसंद के साथ-साथ उनके बजट का भी विशेष ध्यान रखा जाता है तभी तो 10 रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक के दस हजार से भी अधिक सजावटी वस्तुओं का संग्रह है।

रितु राणा

नेता-अभिनेता भी कर चुके हैं खरीदारी

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 1994 में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की पत्नी के साथ यहां खरीदारी के लिए आ चुके हैं। वहीं जानी-मानी अदाकारा शबाना आजमी भी यहां कई बार खरीदारी करने आ चुकी हैं। स्वर्गीय शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं तब जनपथ पर किसी उद्घाटन समारोह में आई थीं। उस दौरान वह दुकान पर आईं और यहां की आकर्षक वस्तुओं को देख उसकी खूब प्रशंसा की थी।

यूरिया की कमी नहीं, वितरण पर ध्यान दें राज्य : तोमर

नई दिल्ली, एएनआइ : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि यूरिया की उपलब्धता से संबंधित कोई समस्या नहीं है। जहां तक इसके वितरण का सवाल है, राज्य सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्हें लगता है कि वे इस ओर ध्यान दे भी रहे हैं। तोमर बुधवार को मध्य प्रदेश में यूरिया की किल्लत के सवाल पर बोल रहे थे। यूरिया को लेकर पिछले दिनों मध्य प्रदेश के आशोक नगर में किसानों के बीच झड़प भी हो चुकी है।

आम लोगों के लिए बाइक लांच करने का हमारा फैसला गलत था। सपने और चीजें सही होने के बावजूद हम प्रोडक्ट को सफल नहीं बना पाए।

— आनंद महिंद्रा
चेयरमैन, महिंद्रा एंड महिंद्रा

सेंसेक्स	40,412.57 ▲ 172.69	निफ्टी	11,910.15 ▲ 53.35	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 38,486 ▼ ₹73	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 44,640 ▼ ₹89	$ डॉलर	₹ 70.85 ▼ ₹ 0.07	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 63.92

न्यूज गैलरी

सीजी पावर के खिलाफ एसएफआइओ जांच शुरू

नई दिल्ली : सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड और इसकी 15 सहायक कंपनियों के खिलाफ एसएफआइओ ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीजी पावर ने शेयर बाजारों को बताया कि एसएफआइओ ने सरकार के आदेश पर उसके खिलाफ अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। हालांकि सीजी पावर की ओर से सहायक कंपनियों का नाम उजागर नहीं किया गया है। कंपनी ने जांच में पूरा सहयोग किए जाने की बात भी कही है। (प्रेट्र)

2024-25 से पहले वितरित हो जाएगा स्टार्ट-अप फंड

पणजी : सरकार द्वारा वितरित किया जाने वाला स्टार्ट-अप इंडिया फंड 2024-25 से पहले ही वितरित हो जाने की संभावना है। इंवेस्ट इंडिया की एमडी और सीईओ दीपिका बागला ने बताया कि स्टार्ट-अप्स की बढ़ती हुई संख्या को देखकर कहा जा सकता है कि इसके लिए निर्धारित किया गया फंड समय से पहले ही वितरित हो जाएगा। बागला ने बताया कि सरकार का ध्यान छोटे स्टार्ट-अप्स को फंड देने पर है। (रायटर)

अरैमको की शेयर मार्केट में शानदार शुरुआत

रियाद : सऊदी अरब की तेल कंपनी अरैमको ने स्टॉक मार्केट में शानदार शुरुआत की है। बुधवार को कंपनी ने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कर दी। पहले दिन कंपनी के शेयरों में 10 परसेंट की तेजी दर्ज की गई। इसके साथ ही कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़कर 1.88 लाख करोड डॉलर पहुंच गई है, जो दुनिया की किसी भी सूचीबद्ध कंपनी से ज्यादा है। (एपी)

एडीबी ने भारत का विकास दर अनुमान घटाया

नई दिल्ली : एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने 2018-19 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 5.1 परसेंट कर दिया है। एडीबी ने बताया कि भारत में रोजगार की खराब हालत, खेती से जुड़ी समस्याओं और फाइनेंशियल सेक्टर के संकट को देखते हुए विकास दर कम रहने की आशंका है। हालांकि बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 में विकास दर बढ़कर 6.5 परसेंट हो जाने की उम्मीद जताई है। (प्रेट्र)

खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बनाए जाने की जरूरत

नई दिल्ली : खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने कहा है कि देश में खाने की गुणवत्ता को लेकर आम धारणा अच्छी नहीं है। प्राधिकरण के चेयरमैन पवन कुमार अग्रवाल ने खाद्य कारोबार में लगे उद्यमियों से कहा कि वे अगले चार वर्ष में खाने को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने का लक्ष्य रखें। उन्होंने कहा कि हमें खाने का असुरक्षित स्तर एक परसेंट से नीचे लाना होगा। (प्रेट्र)

ट्राई को इस वर्ष 26,400 शिकायतें मिली

नई दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई ने इस वर्ष जनवरी से नवंबर के बीच टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ 26,400 शिकायतें प्राप्त की हैं। दूरसंचार राज्य मंत्री संजय धोतरे ने संसद को बताया कि 11 महीने की इस अवधि में सरकार को इसी तरह की 44,890 शिकायतें मिली हैं। उन्होंने बताया कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ शिकायतें सुनने के लिए टेलीकॉम लोकपाल बनाने पर विचार कर रही है। (प्रेट्र)

बिजली की मांग लगातार चौथे महीने घटी

नई दिल्ली : नवंबर के दौरान देश में बिजली की मांग 4.28 प्रतिशत घटकर 94.6 अरब यूनिट रही। यह लगातार चौथा महीना है, जब बिजली की मांग घटी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार नवंबर, 2018 के दौरान देश में बिजली की कुल मांग 98.84 अरब यूनिट रही थी। इस साल अक्टूबर में बिजली की मांग पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 12.94 प्रतिशत घटकर 98.36 अरब यूनिट रही। (प्रेट्र)

हलचल ▶ बकाया भुगतान पर संसद में कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने किया हंगामा

जीएसटी बकाया भुगतान पर दबाव बना रहे गैर-भाजपा शासित राज्य

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लिखा केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जीएसटी रेवेन्यू की धीमी रफ्तार के चलते राज्यों को हो रहे नुकसान की भरपाई और आइजीएसटी सेटलमेंट के बकाया को लेकर गैर-भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बुधवार को लोकसभा में टीआरएस, शिवसेना, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस ने सरकार से जीएसटी के बकाया का जल्द भुगतान करने को कहा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीएसटी के बकाया की राशि के भुगतान का आग्रह किया है। इन राज्यों के इस रुख से जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक हंगामेदार हो सकती है।

जीएसटी लागू होने के वक्त राज्यों को आश्वस्त किया गया था कि जीएसटी के चलते उनके रेवेन्यू में होने वाली कमी के अंतर की भरपाई अगले पांच साल तक केंद्र करेगा। उस वक्त राज्यों के रेवेन्यू में हर साल 14 फीसद वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। यानी इस वृद्धि के बाद अनुमानित रेवेन्यू और वास्तविक रेवेन्यू के अंतर का भुगतान केंद्र को करना था। इसके लिए जीएसटी में कंपेंसेशन सेस लगाया गया, जिसके फंड से केंद्र इसका भुगतान कर रहा था।

राज्यों का कहना है कि बीते कुछ महीनों से जीएसटी रेवेन्यू घट रहा है। अक्टूबर का रेवेन्यू तो 19 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था। राज्यों का कहना है कि इसके चलते उनकी वित्तीय हालत खराब होती जा रही है। केंद्र ने वित्त वर्ष 2021-22 तक कंपेंसेशन देने का वादा किया था। जीएसटी लागू हुए करीब ढाई साल बाद भी रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष में केवल चार बार एक लाख करोड़ रुपये को पार कर पाया है। इसे देखते हुए ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कंपेंसेशन अवधि को और पांच वर्ष बढ़ाकर 2026-27 करने की मांग की है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वित्त मंत्री सीतारमण को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य को चालू वित्त वर्ष में जीएसटी कंपेंसेशन के तौर पर शुरुआती चार महीने के लिए केवल 5,635 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। जबकि नवंबर तक के लिए 8,611.76 करोड़ रुपये की राशि इस मद में बकाया है। ठाकरे ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का भुगतान कम होने की बात भी अपने पत्र में कही है।

इससे पहले दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्रियों ने सीतारमण से मुलाकात कर जीएसटी बकाया का मुद्दा उठाया था। आइजीएसटी के सेटलमेंट का मामला भी अटका हुआ है और यह राज्य इस राशि को जल्द से जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं।

राज्यों के इस रुख से स्पष्ट है कि जीएसटी काउंसिल की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में गैर-भाजपा शासित राज्य बकाया राशि के भुगतान के लिए कोई प्रस्ताव ला सकते हैं। लोकसभा में जीएसटी बकाया के जल्द भुगतान की मांग करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने की वजह से राज्यों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उधर राज्यसभा में जीएसटी बकाया को लेकर हुए हंगामे के चलते सदन करीब एक घंटा स्थगित रहा।

अप्रैल-अगस्त 2019 में रेवेन्यू गैप

राज्य	2018-19	2019-20
बिहार	20	21.2
छत्तीसगढ़	25.9	33.3
दिल्ली	18.9	29.7
हरियाणा	13.8	24.8
हिमाचल	36.2	39.9
झारखंड	17.2	20.4
मध्य प्रदेश	16.3	21
पंजाब	36.5	43.5
उत्तर प्रदेश	5	10.8
उत्तराखंड	35.4	34.3
प. बंगाल	7.4	16.4
महाराष्ट्र	4.1	16.7
गुजरात	13.5	22.8
तमिलनाडु	5.2	13

(नोट : आंकड़े प्रतिशत में)

दिवालिया कानून में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पुराने प्रमोटरों के आपराधिक मामले नए प्रमोटरों पर नहीं होंगे लागू
- सरकारी बैंकों को एनबीएफसी और एचएफसी के असेट्स खरीदने की योजना भी स्वीकृत

दिवालिया होने वाली कंपनियों के नए प्रमोटर्स को पुरानी कंपनी या उसके प्रमोटरर्स पर चल रहे आपराधिक मामलों से मुक्त रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कानून (आइबीसी) में इस आशय के संशोधन के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। कैबिनेट ने सरकारी बैंकों को एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस बैंकों के ऊंची रेटिंग वाली संपत्तियां खरीदने के अधिकार को भी मंजूरी दे दी।

आइबीसी में इस बदलाव की उद्योग जगत लंबे अरसे से मांग कर रहा था। सरकार के इस प्रस्ताव का आशय दिवालिया कंपनियों के मामले निपटाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने पर था। सरकार ने अपने एक बयान में कहा है कि इसी वजह से आइबीसी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 का प्रस्ताव किया गया था।

बैठक के बाद अपने बयान में सरकार ने कहा है कि यह कदम कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी के प्रस्तावों के निपटारों में आ रही दिक्कतों को दूर करेगा। जानकारों के मुताबिक दिवालिया प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित कंपनियों में खरीदार इसलिए दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, क्योंकि वे कंपनी के पुराने मामलों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उद्योग इस नियम में बदलाव की लगातार मांग कर रहा था। इन्सॉल्वेंसी मामलों के जानकार और आइसीएआइ के पूर्व काउंसिल सदस्य व सीए विजय कुमार गुप्ता का मानना है कि इससे मामलों को निपटाने की रफ्तार बढ़ेगी और नए प्रमोटर्स की रुचि भी बढ़ेगी। कैबिनेट ने सरकारी बैंकों को मजबूत वित्तीय स्थिति वाली एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की उच्च रेटिंग वाली संपत्तियां खरीदने का अधिकार देने वाली स्कीम को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम के दायरे में पहली अगस्त, 2018 से एक वर्ष पहले तक एसएमए-0 केटेगरी में शामिल एनबीएफसी और एचएफसी आएंगी।

भारत-जापान में स्टील सेक्टर में सहयोग पर समझौते को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच स्टील सेक्टर में सहयोग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक 'इंडिया-जापान स्टील डायलॉग' के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके जरिये देश में उच्च ग्रेड की स्टील मैन्यूफैक्चरिंग की क्षमता विस्तार में मदद मिलेगी। नवगठित डायलॉग स्टील सेक्टर में सतत विकास की दिशा में आपसी सहमति तैयार करने में सहायक साबित होगा।

एयर इंडिया ने सरकार से मांगी 2400 करोड़ की कर्ज गारंटी

नई दिल्ली, प्रेट्र : गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया परिचालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 2,400 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ने सरकार से गारंटी का आग्रह किया है। हालत यह है कि कंपनी ने कर्मचारियों को अभी तक नवंबर का वेतन नहीं दिया है। कंपनी के एक अधिकारी के अनुसार उम्मीद है कि गुरुवार को वेतन जारी हो जाएगा।

कंपनी के एक अधिकारी के अनुसार 2,400 करोड़ रुपये की यह राशि 7,600 करोड़ रुपये की उस गारंटी का हिस्सा है, जो उसे चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने प्रदान करने का वादा किया था। दूसरी ओर कंपनी के प्रवक्ता ने इस पर किसी टिप्पणी से इन्कार किया है। एयर इंडिया को 2018-19 में अनुमानित 8,556.35 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

पुरी ने किया था हितों की रक्षा का वादा : नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने पिछले महीने राज्यसभा में बताया था कि एयर इंडिया

- गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है कंपनी
- कर्मियों को अभी तक नहीं मिला नवंबर का वेतन

के कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी और इसके निजीकरण तक किसी की नौकरी नहीं जाएगी। अगर कंपनी का निजीकरण नहीं किया जाता है तो इसे बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा पुरी ने पिछले सप्ताह लोकसभा में बताया था कि वित्त वर्ष 2011-12 से अब तक कंपनी को 30,520.21 करोड़ रुपये की इक्विटी दी जा चुकी है। 2018-19 के दौरान कंपनी को दिए वित्तीय पैकेज में 3,975 करोड़ रुपये की नकद सहायता भी शामिल है। एक अन्य वित्तीय मदद के तहत 2018-19 में प्रदान की जाने वाली 7,600 करोड़ रुपये की गारंटी में से तीन हजार करोड़ रुपये पहले ही उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। अप्रैल, 2012 में केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के पुनरुत्थान के लिए टर्नअराउंड प्लान (टीएपी) को मंजूरी दी थी।

हीरा खदान के लिए एस्सेल को जमा करने होंगे 27.50 करोड़

भोपाल, नईदुनिया : नीलामी में सर्वाधिक बोली लगाकर मध्य प्रदेश के छतरपुर की 364 हेक्टेयर में फैली बंदर हीरा खदान लेने वाली कंपनी एस्सेल माइनिंग को खनिज साधन विभाग ने खदान आवंटन का आमंत्रण भेज दिया है। अब कंपनी को खदान में संभावित हीरे की मात्रा के मूल्यांकन की आधा प्रतिशत राशि जमा करना होगी। यह राशि तीन किस्तों में दो साल में जमा होगी। इसमें से पहली किस्त 27.50 करोड़ रुपये 10 दिनों में जमा करनी होगी। इसके बाद कागजी प्रक्रिया शुरू होगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कंपनी डेढ़ से दो साल में खदान में खुदाई शुरू कर सकती है।

विभाग ने मंगलवार को बंदर हीरा खदान के लिए ऑनलाइन बोली लगवाई थी। इसमें कुमार मंगलम बिड़ला समूह की एस्सेल माइनिंग कंपनी ने बाजी मारी। राज्य सरकार को इससे 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राशि मिलने की उम्मीद है। नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को कंपनी को खदान आवंटन का आमंत्रण भेज दिया गया है।

चुनौतियों पर उम्मीद भारी दास का सफर जारी

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा कर लिया है। आरबीआइ की स्वायत्तता पर बहस के बीच पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के अचानक इस्तीफे के बाद इस पद पर दास को लाया गया। उन्होंने सबको साथ लेकर चलने व समस्याओं का हल बातचीत के जरिये निकालने का वादा किया था। अभी तक वे उस वादे पर कायम दिख रहे हैं। अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि नहीं होने के बावजूद आर्थिक मामलों में उनका पूरा दखल दिखा।

दास के नेतृत्व में आरबीआइ ने एक तरफ आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए अब तक पांच बार नीतिगत दर में कटौती की। दूसरी तरफ उन्होंने खुदरा लोन के ब्याज को रेपो रेट या किसी अन्य बाहरी बेंचमार्क दर से जोड़े जाने जैसे सुधारों को भी आगे बढ़ाया है। दास ने बैंकों, एनबीएफसी, एमएसएमई, उद्योग जगत और रेटिंग एजेंसियों को साथ लेते हुए आरबीआइ के विचारों को लेकर सहमति बनाने का प्रयास किया।

पदभार संभालने के दो हफ्तों के भीतर दास ने केंद्रीय बैंक के लिए आर्थिक पूंजी के निर्धारण के जटिल मसले पर पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने अगस्त 2019, में अपनी रिपोर्ट सौंपी।

शक्तिकांत दास की प्रमुख उपलब्धियां

रिजर्व बैंक के पास पड़ी अतिरिक्त नकदी का सरकार को हस्तांतरण

संकट में फंसे कुछ सरकारी बैंकों को आरबीआइ की निगरानी से बाहर करना

बैंकों के फंसे लोन यानी एनपीए को लेकर नए नियम लाना

रेपो रेट में लगातार कटौती और अन्य माध्यमों से बाजार के लिए पर्याप्त नकदी का इंतजाम करना

सामने तीन बड़ी चुनौतियां

देश के एनबीएफसी सेक्टर को वापस पटरी पर लाना

बैंकिंग सेक्टर की सेहत को लेकर आम निवेशकों की चिंता का निदान करना

देश की आर्थिक वृद्धि में तेज गिरावट को थामना

अमेरिका ने बढ़ाई भारत को तेल आपूर्ति

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले देशों में अमेरिका बड़ा हिस्सेदार बन गया है। इस मामले में वह कुवैत को पीछे छोड़ते हुए छठे नंबर पर पहुंच गया है। भारत को तेल निर्यात के मामले में फिलहाल इराक सबसे आगे है। चालू वित्त वर्ष (2019-20) में सितंबर तक अमेरिका ने भारत को पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 70 प्रतिशत अधिक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की है। भारत पेट्रोलियम पदार्थों का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

भारत कच्चे तेल की अपनी कुल जरूरत का 83 प्रतिशत आयात करता है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से संसदीय समिति को दिए आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 के शुरुआती छह महीनों के दौरान अमेरिका ने भारत को 54 लाख टन कच्चे तेल का निर्यात किया। एक साल पहले इसी अवधि में उसने 31 लाख टन कच्चे तेल की आपूर्ति की थी।

भारत ने वर्ष 2017 में अमेरिका से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात शुरू किया था। नई दिल्ली ने अपने पेट्रोलियम आयात को तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) से बाहर ले जाकर इसमें विविधता लाने की कोशिश की है। वित्त वर्ष 2017-18 में भारत ने अमेरिका से 19 लाख टन कच्चे तेल का आयात किया, जबकि 2018-19 में यह मात्रा 62 लाख टन के स्तर पर पहुंच गई। चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान अमेरिका से भारत को 54 लाख टन की आपूर्ति की गई।

भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति के मामले में इराक सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है। देश की कुल जरूरत के चौथाई हिस्से की आपूर्ति फिलहाल इराक से होती है। इसके बाद सऊदी अरब, नाइजीरिया संयुक्त अरब अमीरात (यूएसई) हैं। भारत को कच्चे तेल का निर्यात करने के मामले में वेनेजुएला का पांचवां स्थान रहा है। कुवैत अब सातवें स्थान पर फिसल गया है, जबकि अमेरिका छठे स्थान पर पहुंच गया है।

पीएसयू और आइटी स्टॉक्स के बल पर शेयर बाजारों में दिखा थोड़ा सुधार

मुंबई, प्रेट्र : पीएसयू, आइटी और ऑटो स्टॉक्स में तेजी के बल पर बुधवार को प्रमुख भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। पिछले सत्र के दौरान इनमें गिरावट दर्ज की गई थी। बुधवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 172.69 अंक यानी 0.43 परसेंट की बढ़त के साथ 40,412.57 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 53.35 अंक की बढ़त दर्ज करने में सफल रहा। यह 11,910.15 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में एनटीपीसी के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.77 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई। वहीं ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, कोटक बैंक, टीसीएस, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक और टाटा मोटर्स के शेयरों में 2.28 परसेंट तक की बढ़त देखी गई। दूसरी ओर निवेश पर असमंजस के बीच यस बैंक के शेयर 15.33 परसेंट के तक लुढ़क गए। इसके अलावा

- पिछले सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए थे बाजार, सरकारी कंपनियों के शेयरों में रही सबसे ज्यादा चमक

वेदांता, हीरो मोटोकॉर्प, एलएंडटी, एयरटेल और एचयूएल के शेयर 1.63 परसेंट तक की गिरावट के साथ बंद हुए।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर के मुताबिक बड़े स्टॉक्स में तेजी के कारण शेयर बाजार में सुधार देखा गया। अभी बड़े आर्थिक संकेतक जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आने हैं। हालांकि इनमें सुधार की उम्मीद है, लेकिन नकारात्मक खबर शेयर बाजारों को एक बार फिर गिरावट की ओर ले जा सकती है। बुधवार को बीएसई में यूटिलिटी, ऑयल एंड गैस, पावर, रियल्टी और फाइनेंस के शेयरों में तेजी का रुख रहा।

इनमें रही गहमागहमी

वोडाफोन आइडिया : बुधवार को इस टेलीकॉम कंपनी के शेयरों में तीन परसेंट तक की तेजी देखी गई। बीएसई में कंपनी के शेयर 1.98 परसेंट सुधार के साथ 6.69 रुपये के भाव पर बिके। वहीं एनएसई में यह 3.05 परसेंट सुधरकर 6.75 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।

एफएससीएस : कंपनी के शेयर शुरुआती तेजी के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई में यह 0.33 परसेंट की गिरावट के साथ 499.75 रुपये के भाव पर बंद हुए। इंट्रा-डे में यह 6.69 परसेंट तक चढ़ गए थे। वहीं एनएसई में कंपनी के शेयर 2.63 परसेंट तक फिसलकर 486 रुपये के भाव पर बिके।

मजबूत होते कारोबारी रिश्ते

जापान के आर्थिक, व्यापार और निवेश मंत्री हिरोशी काजीयामा (दाएं) ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। जागरण

वजह

वाणिज्य मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने जताई चिंता, गुणवत्तायुक्त उत्पाद के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत

सर्वाधिक ऑर्गेनिक उपज, फिर भी निर्यात में देश फिसड्डी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दुनिया में सर्वाधिक ऑर्गेनिक खेती का रकबा होने के बावजूद वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। कृषि क्षेत्र के इन परस्पर विरोधी आंकड़ों पर संसदीय समिति ने गंभीर चिंता जताते हुए इन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जोन और ई-ऑर्गेनिक बाजार स्थापित करने का सुझाव दिया है। कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और किसानों की आमदनी को बढ़ाने में ऑर्गेनिक उपज का निर्यात सबसे मुफीद साबित होगा। समिति ने बुधवार को राज्यसभा में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने रासायनिक खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को भी मुहैया कराने का सुझाव दिया है, ताकि उनकी लागत घट सके। समिति ने कहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में ऑर्गेनिक खेती के लिए बुनियादी सुविधाएं दी जानी चाहिए। समिति ने ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए वैश्विक बाजार में ब्रांड वैल्यू स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया है।

ऑर्गेनिक (जैविक) खेती के की उपज के मामले में भारत दुनिया का नौवां सबसे बड़ा देश है। यहां सर्वाधिक लघु व सीमांत किसान हैं, जिनके लिए इस तरह की खेती काफी लाभप्रद हो सकती है। लेकिन वैश्विक बाजार में जगह बनाने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जैविक उत्पादों की सर्वाधिक मांग है, जिसके मद्देनजर इस तरह की खेती पर जोर देने की जरूरत है।

राज्यसभा सदस्य वी. विजयदेसाई रेड्डी की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय स्थायी संसदीय समिति ने 'एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स : चैलेंजेज एंड अपॉर्च्युनिटीज' विषय पर अपनी सिफारिशें सदन में प्रस्तुत कीं। इस विषय पर समिति ने लगभग सवा साल में कुल सात बैठकें कीं। इस दौरान उन्होंने कॉमर्स, कृषि व किसान कल्याण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, राज्य सरकारें, जैविक किसान संगठनों और एजेंसियों के साथ रिसर्च, ट्रेड और निर्यात संगठनों से लंबी चर्चा की है। समिति ने देश के पहले ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम का दौरा भी किया।

समिति ने जैविक खेती की चुनौतियों को चिन्हित किया है। इनमें छोटी जोत, अधिक लागत, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड व अन्य बायो खाद का महंगा होना और उपज के लिए उचित बाजार न होना प्रमुख हैं। उपज के लिए सर्टिफिकेट मिलना बहुत महंगा होने के साथ नीतिगत समर्थन का न मिलना जैविक खेती की राह के रोड़े हैं। समिति ने पाया कि विश्व बाजार में जैविक उत्पादों की जबर्दस्त मांग है, जिसके लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जोन (ओपीजेड) बनाया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक जैविक उत्पाद के लिए उचित बाजार मुहैया कराने की दिशा में तत्काल ई-बाजार स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को उपभोक्ता से सीधे जोड़ने में मदद मिलेगी। समिति ने बताया कि पूर्वोत्तर के राज्यों में जैविक खेती की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

किसानों की आमदनी बढ़ाने में ऑर्गेनिक उपज का निर्यात मुफीद साबित होगा। प्रतीकात्मक

बात पते की

मार्च, 2019 के आंकड़ों के हिसाब से जैविक खेती का रकबा 34 लाख हेक्टेयर है

भारत दुनिया का नौवां सबसे बड़ा जैविक खेती वाला देश है

वर्ष 2017-18 में कुल 17 लाख टन जैविक उपज का उत्पादन हुआ था

वर्ष 2018-19 में 6.40 लाख टन जैविक उपज का निर्यात किया गया, 5,150 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई

वैश्विक बाजार में भारतीय उपज की हिस्सेदारी मात्र 0.55 प्रतिशत है

भारत में कुल खेती के सिर्फ तीन प्रतिशत हिस्से में जैविक खेती होती है

कतर ने अडानी इलेक्ट्रिसिटी में खरीदा 25 परसेंट हिस्सा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कतर के सरकारी वेल्थ फंड ने अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल) में 25.1 परसेंट हिस्सेदारी खरीद ली है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (क्यूआइए) और एईएमएल के बीच यह सौदा 3,200 करोड़ रुपये में हुआ है।

अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की सहायक कंपनी एईएमएल की मुंबई के बिजली बाजार में हिस्सेदारी करीब 87 परसेंट है और ग्राहकों के मामले में इसकी भागीदारी 67 परसेंट है। इसके साथ ही कुल बिजली सप्लाई में इसकी हिस्सेदारी 55 परसेंट है। एईएमएल और क्यूआइए के बीच हुए सौदे में बिजली उत्पादन में वैकल्पिक ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात भी हुई है। दोनों कंपनियों ने वर्ष 2023 तक अपनी कुल सप्लाई का 30 परसेंट हिस्सा सोलर और विंड एनर्जी के जरिये उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। दोनों कंपनियों ने ग्रीन एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा देने की बात भी कही है।

10 हजार भारतीयों को हिरासत में लिया था अमेरिका की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पिछले साल। उन्हें अमेरिका में बगैर किसी वैध दस्तावेज के दाखिल होने के आरोपों में पकड़ा गया था। इनमें से 831 भारतीयों को वापस भारत भेज दिया गया था।

ब्रिटेन में पांच साल में तीसरी बार आम चुनाव

आज ब्रिटेन में आम चुनाव हैं और कल नतीजे भी आ जाएंगे। बीते पांच साल यह तीसरा आम चुनाव है। कंजरवेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन और लेबर पार्टी के जेरेमी कॉर्बिन के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ब्रिटेन की कुल आबादी करीब छह करोड़ है। इस आबादी में करीब 2.5 फीसद भारतीय हैं। इस लिहाज से, जीत में भारतीय मूल के मतदाताओं की अहम भूमिका होगी। चुनाव में खड़े हुए 3,322 उम्मीदवारों के लिए 4.6 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे।

हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है?

यह संसद का लोकतांत्रिक रूप से चुना गया सदन है, जिसका दायित्व नीति और कानून बनाना होता है। ब्रिटेन की जनता सांसदों को चुनती है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स (निचले सदन) में उनके हितों और उनकी चिंताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

चुनाव क्षेत्रों की संख्या

650 संसदीय चुनाव क्षेत्र हैं और इनमें से हर क्षेत्र से एक सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

533 इंग्लैंड में चुनाव क्षेत्रों की संख्या

59 स्कॉटलैंड में चुनाव क्षेत्रों की संख्या

40 वेल्स में चुनाव क्षेत्रों की संख्या

18 नॉर्दर्न आयरलैंड में चुनाव क्षेत्रों की संख्या

क्षेत्रवार दलों की स्थिति (मौजूदा)

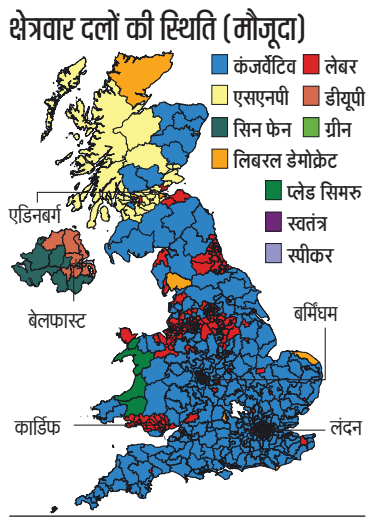

ऐसे चुनते हैं प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री को जनता द्वारा सीधे वोट नहीं दिया जाता है। या तो वह विजेता पार्टी के सांसदों द्वारा चुना जाता है और रानी द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो उनकी सलाह का पालन करने के लिए बाध्य होता है।

कौन दे सकता है वोट?

हर वो व्यक्ति वोट डाल सकता है, जो :

- 18 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति वोट डाल सकता है।
- ब्रिटिश नागरिक हो
- आयरलैंड, कॉमनवेल्थ देशों का नागरिक हो और ब्रिटेन में रह रहा हो

सरकार का गठन

बहुमत के लिए 326 का आंकड़ा है। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। यदि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो सर्वाधिक सीटों वाली पार्टी अल्पसंख्यक सरकार बना सकती है या गठबंधन सरकार बना सकती है।

क्या हैं चुनावी मुद्दे

2015 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) और अप्रवासन मतदाताओं के लिए सबसे बड़े मुद्दे थे। अब ब्रेक्जिट एक बहुत बड़ा मुद्दा है।

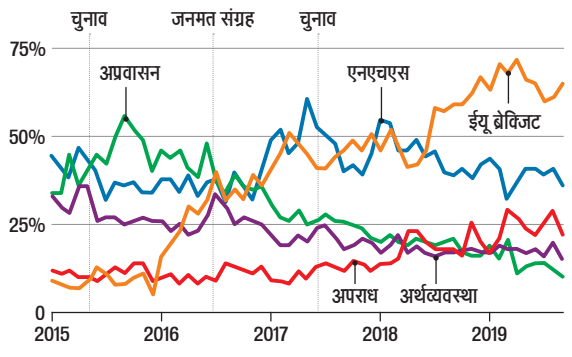

हाउस ऑफ कॉमंस में दलों की स्थिति

650 सदन में कुल सीटें

326 बहुमत के लिए सीटें

कंजर्वेटिव पार्टी 298

लेबर पार्टी 243

एसएनपी 35 | लिब डेम्स 20 | डीयूपी 10

स्वतंत्र 24 | अन्य 20

2017 आम चुनाव में जीती सीटें

टेरीजा मे (चुनाव जीत बनीं पीएम)

318 कंजर्वेटिव पार्टी

262 लेबर पार्टी

35 स्कॉटिश नेशनल पार्टी

68.7 मत फीसद

कई मायनों में अहम

लेबर पार्टी ने भारतीय मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि सत्ता में आने पर वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगेगी। साथ ही स्कूलों के पाठ्यक्रमों में ब्रिटिश राज के अत्याचारों की पढ़ाई को भी शामिल किया जाएगा। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी ने सोशल मीडिया पर हिंदी में वीडियो शेयर किया है, जिसमें बोरिस जॉनसन को जिताने और लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के विरोध में कई बातें सुनाई देती हैं।

कश्मीर भी बढ़ा मुद्दा

ब्रिटेन के अधिकतर सांसद पाकिस्तानी मूल के हैं और लेबर पार्टी के हैं। उनका कहना है कि भारत ने जो अनुच्छेद 370 हटाया है, वह गैर-कानूनी है। वहीं भारतीयों का विचार है कि लेबर पार्टी का झुकाव मुसलमानों की तरफ ज्यादा है और वो भारतीयों के पक्ष में नहीं हैं। लेबर पार्टी ने कश्मीर में कथित तौर पर मानवाधिकार की बहाली को लेकर एक प्रस्ताव पास किया था।

न्यूज गैलरी

चार अमेरिकी सैन्य ठिकाने दक्षिण कोरिया को वापस

सियोल : दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि अमेरिकी सेना द्वारा अपने चार ठिकानों को दक्षिण कोरिया को वापस कर दिया गया है। सैन्य अड्डों के जगह परिवर्तन के लिए दोनों पक्षों के बीच स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट (सोफा) की 200वीं संयुक्त बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। अमेरिकी सेना के ये अड्डे पहले से बंद थे। (एएनआइ)

न्यू जर्सी में हुई गोलीबारी में छह लोगों की मौत

जर्सी सिटी : अमेरिका के न्यू जर्सी प्रांत के जर्सी सिटी में बदमाशों के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़ में छह लोगों की मौत हो गई। इनमें एक पुलिस अधिकारी समेत तीन अन्य लोग शामिल हैं। मेयर स्टीवेन फुलोप ने मंगलवार रात ट्वीट कर बताया था कि शहर के यहूदी बाजार को कुछ बंदूकधारियों ने निशाने पर लिया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस से उनकी कई घंटे मुठभेड़ चली। (एपी)

बॉगनविले की आजादी को लोगों का समर्थन

बैंकॉक : प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश पापुआ न्यू गिनी से आजादी को लेकर इसके बॉगनविले क्षेत्र में बुधवार को हुए जनमत संग्रह में लोगों ने बहुमत के साथ आजादी के पक्ष में मतदान किया। बॉगनविले क्षेत्र को हालांकि पहले से कुछ स्वायत्तता हासिल थी। पापुआ न्यू गिनी की सरकार द्वारा जनमत संग्रह को मंजूर करने की घोषणा की गई है। (आइएएनएस)

ऑस्ट्रेलिया में आग से सेहत को नुकसान को लेकर प्रदर्शन

सिडनी : ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से की जंगलों में लगी भयंकर आग से लोगों को सांस लेने में तकलीफ समेत अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को धुएं से भरे वातावरण के कारण सेहत को हो रहे नुकसान से आगाह कराने के लिए सिडनी में बुधवार को करीब 20 हजार लोगों ने रैली निकालकर विरोध दर्ज किया। (एएफपी)

अमेरिका ने पाक के पूर्व पुलिस अफसर को काली सूची में डाला

वाशिंगटन : अमेरिका ने पाकिस्तान के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी राव अनवर अहमद खान को मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोपों के कारण काली सूची में डाल दिया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मालिर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रहे एनकाउंटर विशेषज्ञ खान पर फर्जी मुठभेड़ के भी आरोप हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस प्रतिबंध की जानकारी देते हुए कहा, मालिर में एसएसपी रहने के दौरान अनवर ने 190 से ज्यादा मुठभेड़ों को अंजाम दिया। इन मुठभेड़ों में 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इनमें ज्यादातर न्यायेतर हत्याएं थीं। इतना ही नहीं अनवर पुलिस, अपराधी और ठगों के नेटवर्क का प्रमुख था, जो वसूली, जमीन कब्जाने, मादक पदार्थों की तस्करी और हत्या जैसे अपराधों में शामिल था। अमेरिका के इस कदम का पाकिस्तान ने वॉइस ऑफ करांची के प्रमुख नदीम नुसरत ने स्वागत किया है। (प्रेट्र)

ब्रिटेन में आम चुनाव आज, अंतिम दिन पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत

तैयारियां पूरी ▶ ब्रेक्जिट के लिए जनमत संग्रह माना जा रहा यह मतदान

मुख्य मुकाबला कंजरवेटिव और लेबर पार्टी के बीच

लंदन, एएफपी : ब्रिटेन में आम चुनाव के मतदान से एक दिन पहले बुधवार को सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। विपक्षी लेबर पार्टी के जेरेमी कॉर्बिन ने जहां इसे पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले चुनाव की संज्ञा दी। वहीं सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि एकमात्र उनकी ही पार्टी है जो देश को ब्रेक्जिट के जाल से निकाल सकती है। ब्रिटेन के निचले सदन की 650 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान होगा।

यार्कशायर और उत्तरी इंग्लैंड में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा, जब तक हम ब्रेक्जिट से बाहर नहीं निकलते तब तक एक देश के तौर पर हमारा भविष्य अनिश्चित है। हमने विभाजन, विलंब और गतिरोध में एक दशक का समय गंवा दिया। आइए अब हम सब मिलकर ब्रेक्जिट को पूरा करें और अवसर व आशा के साथ आगे बढ़ें। इस देश की क्षमता को उजागर करें।

मिडिल्सबरो में एक रैली में लेबर पार्टी के कॉर्बिन (70) ने कहा, यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। जो वोटर अब भी अनिर्णय की स्थिति में हैं, उन्हें मेरा संदेश है कि वह भविष्य में अच्छी उम्मीद के लिए लेबर पार्टी को वोट करें। हम अत्यधिक अमीर और बड़े व्यावसायिक घरानों पर और अधिक टैक्स लगाकर आर्थिक रूप से आपको मजबूत करेंगे क्योंकि आप इसके हकदार हैं।

लेबर पार्टी सार्वजनिक सेवाओं और राष्ट्रीयकरण पर बड़े पैमाने पर खर्च करने की योजना बना रही है। इसका एलान उसने अपने घोषणापत्र में भी किया है। जबकि ब्रेक्जिट के मुद्दे पर पार्टी का रुख लचीला है। वह सत्ता में आने पर एक और जनमत संग्रह की बात करती है। तीसरे प्रमुख दल लिबरल डेमोक्रेट के नेता जो स्विनसन ने मतदाताओं से ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के खिलाफ वोट करने की गुहार लगाई है।

जॉनसन ने कहा, ईयू से बाहर आने तक हमारा भविष्य अनिश्चित है

कंजरवेटिव पार्टी को मिल सकता है बहुमत

मतदान से एक दिन पहले नए सर्वे में कंजरवेटिव पार्टी को 339 सीटें (2017 के आम चुनाव के मुकाबले 22 ज्यादा) मिलती दिखाई गई हैं। लेबर पार्टी को 231 सीटें (2017 के मुकाबले 31 कम) और स्कॉटिश नेशनल पार्टी को 41 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। लिबरल डेमोक्रेट्स के खाते में सिर्फ 15 सीटें जा रही हैं। पिछले सात दिनों के दौरान यूजीओवी संस्था द्वारा कराए गए सर्वे में लगभग एक लाख लोगों से उनकी राय पूछी गई थी।

मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता कोई भी कोशिश आजमाने से नहीं चूकते। ब्रिटेन के आम चुनाव से पहले प्रचार के अंतिम दिन बुधवार को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (दाएं) एक 'मिल्कमैन' के रूप में नजर आए। जॉनसन ने वेस्ट यॉर्कशायर में ग्रीनसाइड फार्म बिजनेस पार्क में वाहन में दूध और जूस की बोतल लोड करने में मदद के साथ दिन की शुरुआत की। यही नहीं गाइजली इलाके में उन्होंने दरवाजा खटखटाकर एक मतदाता के घर पर दूध का क्रेट भी दिया। एपी

रूस को अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी

वाशिंगटन, प्रेट्र : रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी तो अनुरोध भी किया। उन्होंने 2020 के अमेरिकी चुनाव में रूस को किसी तरह का हस्तक्षेप न करने चेतावनी दी। साथ ही यूक्रेन के साथ विवाद को खत्म करने का अनुरोध भी किया। ट्रंप का यह मिला-जुला रुख रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान दिखा।

ट्रंप ने यह चेतावनी तब दी है जब एक दिन पहले ही अमेरिका के न्याय विभाग से जुड़ी संस्था ने दावा किया है कि एफबीआइ को शुरुआती जांच में ट्रंप के चुनाव प्रचार से जुड़े लोगों के रूस से संबंधों के सुबूत मिले थे। ट्रंप ने इस जांच का विरोध किया था। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव में हस्तक्षेप को लेकर रूस को आगाह किया है। लेकिन लावरोव ने इसके उलट कहा कि हमारी मुलाकात में अमेरिकी चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले लावरोव मई 2017 में अमेरिका आए थे। तब उस समय ट्रंप एफबीआइ डायरेक्टर जेम्स कॉमे से चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच शुरू करने के मसले पर बुरी तरह से नाराज थे।

ट्रंप और लावरोव की मुलाकात में अंतरराष्ट्रीय शस्त्र नियंत्रक समझौते पर भी बात हुई। ट्रंप ने इसे दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी बताया। कहा कि भविष्य में होने वाली ऐसी किसी संधि में अमेरिका और रूस के साथ चीन का भी शामिल होने जरूरी है। ट्रंप ने दोनों देशों के सहयोग वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ने पर प्रसन्नता जाहिर की। कहा कि दोनों देशों में गिरफ्तार एक-दूसरे के नागरिकों के हितों को लेकर जिस तरह से तत्परता बरती जा रही है, वह सराहनीय है। ट्रंप ने ईरान के परमाणु हथियारों के विकास को रोकने और उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण में रूस का सहयोग मांगा। दोनों देशों ने चीन के साथ अपने संबंधों की भी चर्चा की।

विपक्ष की महाभियोग की मुहिम बहुत कमजोर

राष्ट्रपति ट्रंप ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश को बहुत कमजोर करार दिया है। कहा कि उन्होंने (ट्रंप ने) कुछ भी गलत नहीं किया। विपक्ष जो कुछ कर रहा है, वह राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है और उसका यह प्रयास सफल नहीं होने वाला। उनके आरोप कमजोर हैं और वे संसद में बहस के दौरान कहीं नहीं टिकेंगे। उल्लेखनीय है कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से जुलाई में हुई उनकी टेलीफोन वार्ता के सिलसिले में लाने की प्रक्रिया चल रही है। आरोप है कि उन्होंने इस वार्ता में राजनीतिक फायदे के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बिडेन के खिलाफ जांच शुरू कराने के लिए दबाव डाला। बुधवार को प्रतिनिधि सभा से जुड़ी उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय समिति ने महाभियोग से जुड़ी चर्चा शुरू कर दी।

पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा बनीं टाइम परसन ऑफ द ईयर

वाशिंगटन, एएनआइ : पर्यावरण सुधार के लिए मुहिम छेड़ने वाली स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग (16) को प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने परसन ऑफ द ईयर 2019 चुना है। पत्रिका की ओर से यह सम्मान पाने वाली ग्रेटा सबसे कम उम्र की शख्सियत हैं। उन्होंने यह स्थान अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नेंसी पेलोसी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हांगकांग के आंदोलनकारियों और ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए सूचना देने वाले व्हिसल ब्लोअर को पछाड़कर प्राप्त किया है। ग्रेटा 2018 में स्वीडिश संसद के सामने पर्यावरण के लिए स्कूल छोड़कर हड़ताल करने के लिए चर्चा में आईं।

पर्यावरण सुधार की मुहिम में रुचि नहीं ले रहे धनी देश : मैड्रिड में बुधवार को ग्रेटा ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में धनी देशों पर हानिकारक गैसों का उत्सर्जन रोकने में रुचि न लेने का आरोप लगाया। कहा, ये देश पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों का उत्सर्जन रोकने से बचने के लिए रास्ते तलाश लेते हैं जिनका दुष्प्रभाव दुनिया की आबादी झेल रही है। पर्यावरण सुधार के उनके उपाय भी भ्रमित करने वाले हैं। ग्रेटा ने कहा, सभी देशों को मिल-जुलकर पर्यावरण सुधार के प्रयासों में रुकावट डालने वाले तत्वों से निपटना चाहिए और अपनी महात्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करना चाहिए।

बड़े फैसले लेने की जरूरत : गुतेरस : सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण पर नजर रखने वाली सहयोगी संस्था आइपीसीसी ने कहा है कि धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले, तेल और गैस के इस्तेमाल को सीमित किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने पर्यावरण सुधार के लिए और बड़े फैसले लिए जाने और उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता जताई।

प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम के कवर पर स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग। एएफपी

अमेरिका ने सऊदी सैनिकों के प्रशिक्षण पर लगाई रोक

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका में सऊदी सैनिकों के प्रशिक्षण पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। उन्हें हालांकि क्लास रूम प्रशिक्षण पहले की तरह मिलता रहेगा। यह कदम पिछले सप्ताह एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर सऊदी सैन्यकर्मी द्वारा की गई गोलीबारी के बाद उठाया गया है।

सऊदी अरब की वायुसेना के सेकेंड लेफ्टिनेंट मुहम्मद अलशमरानी (21) ने पिछले सप्ताह फ्लोरिडा के पेंसाकोला नौसेना अड्डे पर गोलीबारी की थी। इसमें तीन अमेरिकी नौसैनिक मारे गए थे और आठ लोग घायल हो गए थे। बाद में अलशमरानी को भी मार गिराया गया था। इसी के बाद अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहे सभी सऊदी सैनिकों के परिचालन प्रशिक्षण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। पेंटागन के अधिकारी ने बताया कि इस नीति की समीक्षा की जा रही है। इस निर्णय से पायलट का प्रशिक्षण लेने वाले सऊदी सैनिक भी प्रभावित होंगे।

पेंटागन ने अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहे सऊदी सैनिकों की संख्या तो नहीं बताई, लेकिन यह जरूर कहा कि फिलहाल अमेरिका में 5,000 से 5100 के बीच अंतरराष्ट्रीय सैनिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। खास बात यह है कि पश्चिम एशिया में सऊदी अरब अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है।

...और तय हो गए आरोप

हाफिज सईद। फाइल

पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता और आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद और उसके तीन करीबियों के खिलाफ आतंकी फंडिंग के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) लाहौर ने बुधवार को 69 वर्षीय हाफिज सईद, हाफिज अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद, मुहम्मद अशरफ और जफर इकबाल को दोषी पाया है। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई हमले के लगभग 11 साल बीतने के दौरान हाफिज के खिलाफ क्या कुछ हुआ।

26 नवंबर, 2008 : लश्कर के दस आतंकियों ने मुंबई में कई स्थानों पर हमला करके 166 लोगों की हत्या कर दी।

दिसंबर, 2008 : भारत ने सुरक्षा परिषद में हाफिज सईद और उसके संगठनों जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध की औपचारिक अपील की।

26 अगस्त, 2009 : भारत की अपील पर इंटरपोल ने हाफिज के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किया।

3 अप्रैल, 2012 : अमेरिका ने जमात और लश्कर को काली सूची में डाला। हाफिज सईद पर एक करोड़ डॉलर का इनाम रखा।

30 अगस्त, 2012 : अमेरिका ने हाफिज सईद को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया।

22 जनवरी, 2015 : पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा और हक्कानी नेटवर्क को प्रतिबंधित सूची में डाला।

24 नवंबर, 2017 : लाहौर हाईकोर्ट के आदेश पर हाफिज रिहा।

03 दिसंबर, 2017 : हाफिज ने चुनाव लड़ने का एलान किया। 2018 में चुनाव लड़ा।

22 फरवरी, 2019 : पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने सईद के संगठनों प्रतिबंध लगाया।

04 जुलाई, 2019 : लश्कर के लिए फंडिंग में सईद और उसके 12 साथियों पर 23 केस दर्ज।

07 अगस्त, 2019 : पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी विभाग ने सईद और जमात को दोषी करार दिया।

27 सितंबर, 2019 : अमेरिका ने सईद और मसूद अजहर पर मुकदमा चलाने को कहा।

11 दिसंबर, 2019 : लाहौर में एक अदालत ने हाफिज और उसके तीन करीबियों पर आरोप तय कर दिए।

मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के ट्रंप के प्रयासों को कोर्ट से झटका

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेक्सिको सीमा पर 450 मील लंबी दीवार बनाने के प्रयासों को जोरदार झटका दिया है। टेक्सास की अल पासो जिला अदालत ने इस दीवार के लिए सैन्य निर्माण फंड से 360 करोड़ डॉलर (करीब 25 हजार करोड़ रुपये) की राशि के हस्तांतरण पर रोक लगा दी। जज डेविड ब्रायोनेस की इसी अदालत ने गत अक्टूबर में भी अमेरिकी रक्षा विभाग से दीवार निर्माण के लिए फंड लेने की कोशिश को गैरकानूनी करार दिया था। इस संघीय अदालत में ट्रंप प्रशासन के आदेश के खिलाफ मानवाधिकार समूहों ने मुकदमा दाखिल किया था।

ट्रंप पिछले राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के समय से ही मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर दीवार खड़ी करने की बात कह रहे हैं। इसके लिए अमेरिकी संसद से पर्याप्त धन नहीं दिए जाने के बाद उन्होंने इस साल फरवरी में आपातकाल की घोषणा तक कर दी थी।

मंगलवार के फैसले पर खुशी जताते हुए अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि अमेरिकी अदालत राष्ट्रपति के मनमाने फैसले को रोकने में सक्षम है। ट्रंप प्रशासन इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा।

सम्मान

भारत में जन्मे अर्थशास्त्री अभिजीत ने पहन रखी थी धोती और बंद गले की जैकेट, पत्नी डुफ्लो ने लाल ब्लाउज के साथ पहनी थी नीली साड़ी

भारतीय परिधान पहन अभिजीत और एस्थर ने लिया नोबेल

स्टॉकहोम, एएनआइ : भारत में जन्मे अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने मंगलवार को यहां भारतीय वेशभूषा में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ग्रहण किया। उन्होंने बंद गले की जैकेट और धोती पहन रखी थी। संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के नोबेल से नवाजी गईं बनर्जी की फ्रांसीसी पत्नी एस्थर डुफ्लो ने भी इस मौके पर नीली साड़ी और लाल ब्लाउज पहन रखा था। उन्होंने लाल बिंदी भी लगा रखी थी। इस पुरस्कार के तीसरे साझीदार माइकल क्रेमर सूट में थे।

नोबेल पुरस्कार समिति ने इस समारोह का एक वीडियो साझा किया है। इसमें अभिजीत, डुफ्लो और माइकल क्रेमर अपना मैडल और प्रशस्ति पत्र लेते दिख रहे हैं। नोबेल पुरस्कार समिति ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, 'इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा किए गए शोध ने वैश्विक गरीबी से लड़ने की हमारी क्षमता में काफी सुधार किया है। उनके प्रयोग आधारित दृष्टिकोण ने केवल दो दशकों में विकास अर्थशास्त्र को बदल दिया है। अब यह अनुसंधान का एक समृद्ध क्षेत्र है।'

एस्थर डुफ्लो अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाली दूसरी महिला : वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 58 वर्षीय अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी फ्रांस की एस्थर डुफ्लो और अमेरिकी माइकल क्रेमर को दिया गया है। 46 वर्षीय एस्थर अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाली दूसरी महिला हैं। तीनों को यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया गया है।

अभिजीत ने जेएनयू से किया था अर्थशास्त्र में एमए : अभिजीत दूसरे भारतीय हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। 1998 में अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया था। कोलकाता में जन्में अभिजीत ने 1983 में दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से अर्थशास्त्र में एमए किया था। बाद में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। फिलहाल वह मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं।

स्टॉकहोम में आयोजित समारोह में स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ (दाएं) के हाथों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते भारत में जन्मे अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी। उनकी फ्रांसीसी पत्नी एस्थर डुफ्लो ने भी साड़ी पहनकर यह सम्मान ग्रहण किया। रायटर

एशिया प्रशांत क्षेत्र में 50 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी के शिकार

- कुपोषण के चलते भारत में 21 फीसद बच्चे कम वजन के
- वर्ष 2030 तक भुखमरी उन्मूलन के लिए लाखों लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाने का अनुरोध

बैंकाक, एपी : भारत समेत पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 50 करोड़ से ज्यादा लोग कुपोषण और भुखमरी के शिकार हैं। इनमें से आधा से ज्यादा लोग दक्षिण एशिया में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने कहा है कि अगर 2030 तक इस क्षेत्र में भुखमरी का उन्मूलन करना है तो लाखों लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाना होगा।

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों द्वारा संकलित डाटा के मुताबिक, कुपोषण के चलते बच्चों का वजन कम हो रहा है और उनकी लंबाई भी उचित मात्रा में नहीं बढ़ रही है। भारत में 21 फीसद से ज्यादा बच्चे कम वजन के शिकार हैं। कमजोर दिमाग वाले बच्चों को संख्या बढ़ रही है।

इस क्षेत्र में असमानता तेजी बढ़ी है। तेज आर्थिक विकास के बावजूद लोगों की आय उचित मात्रा में नहीं बढ़ रही है। इसकी वजह से लोगों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है, लाखों लोग गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं।

रिपोर्ट में हालात को बदलने के लिए सरकार से गरीबी मिटाने के लिए कार्यक्रम चलाने के साथ ही पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार के लिए भी नीतियां लागू करने का अनुरोध किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की क्षेत्रीय प्रतिनिधि कुंधवी कादिरसन कहती हैं कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में कुपोषण को कम करने की गति बहुत कम हो गई है। इस क्षेत्र में 20 फीसद से भी ज्यादा लोगों को साल भर में कई-कई दिनों तक भर पेट भोजन नहीं मिलता या उन्हें भूखे रहना पड़ता है। कभी-कभी तो लगातार कई दिनों तक लोगों को भूखे पेट रहने को मजबूर होना पड़ जाता है।

ये भी जानिए

लोकेश राहुल ने वानखेड़े स्टेडियम में पिछली तीन टी-20 पारियों में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने बुधवार को 91 रन बनाए, जबकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ 100 व 94 रनों बनाए थे।

टीम इंडिया ने जमाया रंग

- वेस्टइंडीज को 67 रनों से हराकर भारत ने टी-20 सीरीज पर जमाया 2-1 से कब्जा
- राहुल, रोहित और कोहली ने जड़े ताबड़तोड़ अर्धशतक, गेंदबाजों का भी शानदार प्रदर्शन

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: लोकेश राहुल, रोहित शर्मा और भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के अंतिम टी-20 मुकाबले में मेहमान गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इन तीनों बल्लेबाजों ने किसी भी गेंदबाज पर कोई रहम नहीं किया और उनके आगे सभी गेंदबाज बेबस नजर आए। इस सीरीज में राहुल और कोहली शानदार फॉर्म में चल ही रहे थे, लेकिन रोहित ने भी अपने घरेलू मैदान पर अपनी फॉर्म को पा लिया। राहुल (91), रोहित (71) और कोहली (70) की पारियों से भारत ने निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट पर 240 रन बनाए। हालांकि राहुल अपने शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने अपनी पारी में 56 गेंदों में नौ चौके और चार छक्के जड़े। वहीं, रोहित ने 34 गेंदों में छह चौके और पांच छक्के जड़े। कप्तान कोहली की बुधवार को शादी की दूसरी सालगिरह थी और इसका जश्न उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेलकर बनाया। उन्होंने 29 गेंदों में चार चौकों के साथ सात छक्के भी लगाए। उन्होंने अपने टी-20 करियर का 24वां पचासा लगाया। उन्होंने 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।

वेस्टइंडीज की टीम इतने बड़े स्कोर के आगे दबाव में आ गई और 20 ओवर में आठ विकेट पर 173 रन ही बनाकर मैच 67 रन से हार गई। मेहमान टीम के लिए सर्वाधिक स्कोर कप्तान कीरोन पोलार्ड ने बनाया। उन्होंने 39 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली। भारत की ओर से दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार, मुहम्मद शमी व कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट लिए। भारत ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की। हालांकि अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप को देखते हुए भारत की विंडीज पर यह जीत महत्वपूर्ण है। विंडीज इस प्रारूप में दो बार की विश्व चैंपियन है और सबसे मजबूत टीम मानी जाती है। इस जीत से भारतीय का हौसला काफी बढ़ा होगा।

रोहित का यह घरेलू मैदान है और वह पिछले दो मैचों में फ्लॉप रहे। इस सीरीज के निर्णायक मुकाबले में भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी और उन्होंने इस बार ऐसा ही किया। वह इस सीरीज के पहले मैच में हैदराबाद में आठ रन और तिरुअनंतपुरम में 15 रन ही बना पाए थे। वहीं, राहुल ने क्रमशः 62 व 11 रन बनाए, जबकि विराट ने नाबाद 94 व 19 रनों की पारी खेली थी।

इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सलामी बल्लेबाजों रोहित व राहुल ने पावरप्ले के शुरुआती छह ओवर में किसी भी गेंदबाज पर रहम नहीं किया व आसानी से चौके-छक्के जड़े।

बचे शर्मा जी: पांचवें ओवर की दूसरी गेंद पर स्पिनर खारे पियरे की गेंद को इविन लुइस ने सीमा रेखा के पास एक हाथ से रोककर छह रन बचाए। रोहित को लगा कि छह रन हो जाएंगे, लेकिन जैसे लुइस ने गेंद विकेटकीपर को फेंकी तो वह तेजी से डाइव लगाकर क्रीज पर पहुंच गए। लुइस के हाथ में गेंद फंस गई थी, लेकिन वह अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाए और गेंद मैदान के अंदर फेंक दी। दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर बिना विकेट गंवाए 72 रनों पर पहुंचा दिया। रोहित ने आठवें ओवर की पांचवीं गेंद पर पियरे पर छक्का जड़कर अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने इस ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर क्रमशः छक्का, छक्का और चौका लगाया। इस चौके के साथ भारत के 100 रन भी पूरे हुए। उन्होंने अपने करियर का 19वां अर्धशतक लगाया। वहीं, राहुल ने 29 गेंदों में अपने टी-20 करियर का आठवां अर्धशतक पूरा किया। शुरुआती 10 ओवर में भारत ने बिना विकेट गंवाए 116 रन कूट डाले। हालांकि, खतरनाक होते दिख रहे रोहित को तेज गेंदबाज केसरिक विलियम्स ने पवेलियन भेजकर इस साझेदारी को तोड़ा। रोहित, विलियम्स की गेंद को छक्का उड़ाने के चक्कर में वाल्श को कैच दे बैठे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 70 गेंदों में 135 रनों की साझेदारी निभाई।

पंत का जीरो: कोहली ने सीरीज के दूसरे मैच में ऑलराउंडर शिवम दुबे को अपने स्थान तीसरे नंबर पर भेजा था और उन्होंने अर्धशतक लगाकर अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई थी। इस बार कप्तान ने फिर से प्रयोग करके खराब फॉर्म से जूझ रहे रिषभ पंत को भेजा। जिस पाटा विकेट पर अन्य भारतीय बल्लेबाज रन कूट रहे थे तो वहीं, पंत अपना खाता तक नहीं खोल पाए और पोलार्ड की गेंद पर होल्डर को कैच दे बैठे। इस सीरीज में भी पंत को पूरा मौका खेलने को मिला, लेकिन उन्होंने निराश ही किया। वहीं, केरल के संजू सैमसन टूरिस्ट की तरह टीम के साथ घूमते रहे।

कप्तान के लिए विकेट: मैच के दौरान एक समय ऐसा आया जब राहुल अपना विकेट कप्तान कोहली के लिए उपहार के तौर पर दे देते। पारी का 15वां ओवर डाल रहे होल्डर की गेंद राहुल के पैड पर लग गई और राहुल ने कोहली को रन लेने के लिए मना भी कर दिया, लेकिन भारतीय कप्तान भागते हुए राहुल के पास पहुंच गए, जबकि राहुल धीरे से अपने छोर पर पहुंच रहे थे क्योंकि वह स्टंप से बहुत दूर थे। लेकिन, होल्डर सीधी थ्रो स्टंप पर नहीं लगा पाए। विलियम्स ने कोहली के साथ राहुल के खिलाफ 16वें ओवर में शॉर्ट गेंद डाली। हालांकि कोहली ने पारी का 18वां ओवर डाल रहे विलियम्स की गेंद पर छक्का जड़कर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। पारी के 19वें ओवर में दो कप्तान आमने-सामने हुए। कोहली ने पोलार्ड की जमकर धुनाई कर दी। उन्होंने तीन छक्कों और एक चौके के दम पर 27 रन बना डाले। हालांकि पारी के आखिरी ओवर में राहुल को कॉटरेल ने पवेलियन भेज दिया।

रोहित के 400 छक्के

भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा ने अपने करियर में एक खास उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में 400 छक्के पूरे किए। मेहमान टीम के बायें हाथ के तेज गेंदबाज शेल्डन कॉटरेल ने पारी के तीसरी ओवर की पहली गेंद रोहित को फेंकी और उन्होंने डीप मिडविकेट के ऊपर से छक्का जड़कर यह उपलब्धि हासिल की। टीम इंडिया के ओपनर रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित विश्व में ऐसे तीसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 400 छक्के दर्ज हो गए हैं। रोहित (404) से पहले पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी (476) और क्रिस गेल (534) यह मुकाम छू चुके हैं।

अंतरराष्ट्रीय करियर में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले शीर्ष-पांच भारतीय बल्लेबाज

बल्लेबाज	मैच	छक्के
रोहित शर्मा	354	404
महेंद्र सिंह धौनी	538	359
सचिन तेंदुलकर	664	264
युवराज सिंह	402	251
सौरव गांगुली	424	247

वेस्टइंडीज के खिलाफ अर्धशतक पूरा करने के बाद रोहित (बायें) को बधाई देते राहुल ● एपी

स्कोर बोर्ड

टॉस: वेस्टइंडीज (गेंदबाजी) **मैन ऑफ द मैच:** लोकेश राहुल
मैन ऑफ द सीरीज: विराट कोहली / **परिणाम:** भारत 67 रनों से जीता

भारत 240/3 (20 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
रोहित शर्मा का वाल्श बो. विलियम्स	71	34	06	05
लोकेश राहुल का. पूरन बो. कॉटरेल	91	56	09	04
रिषभ पंत का. होल्डर बो. पोलार्ड	00	02	00	00
विराट कोहली नाबाद	70	29	04	07
श्रेयस अय्यर नाबाद	00	00	00	00

अतिरिक्त: (बा-1, लेबा-2, नोबॉ-1, वा-4) 8, **कुल:** 20 ओवर में तीन विकेट पर 240 रन, **विकेट पतन:** 1-135 (रोहित, 11.4), 2-138 (पंत, 12.2), 3-233 (राहुल, 19.4)

गेंदबाजी: कॉटरेल 4-0-40-1, जेसन होल्डर 4-0-54-0, खारे पियरे 2-0-35-0, विलियम्स 4-0-37-1, हेडन वाल्श 4-0-38-0, कीरोन पोलार्ड 2-0-33-1

वेस्टइंडीज 173/8 (20 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
लेंडल सिमंस का. अय्यर बो. शमी	07	11	01	00
ब्रेंडन किंग का. राहुल बो. भुवनेश्वर	05	04	01	00
हेटमायर का. राहुल बो. कुलदीप	41	24	01	05
निकोलस पूरन का. दुबे बो. चाहर	00	01	00	00
पोलार्ड का. जडेजा बो. भुवनेश्वर	68	39	05	06
होल्डर का. सब (पांडे) बो. कुलदीप	08	05	01	00
हेडन वाल्श जूनियर बो. शमी	11	13	01	00
खारे पियरे का. जडेजा बो. चाहर	06	12	00	00
केसरिक विलियम्स नाबाद	13	07	01	01
शेल्डन कॉटरेल नाबाद	04	04	01	00

अतिरिक्त: (लेबा-5, वा-5) 10, **कुल:** 20 ओवर में आठ विकेट पर 173 रन, **विकेट पतन:** 1-12 (किंग, 1.5), 2-17 (सिमंस, 2.6), 3-17 (पूरन, 3.1), 4-91 (हेटमायर, 9.3), 5-103 (होल्डर, 11.1), 6-141 (पोलार्ड, 14.6), 7-152 (वाल्श, 16.5), 8-169 (पियरे, 19.2)

गेंदबाजी: दीपक चाहर 4-0-20-2, भुवनेश्वर 4-0-41-2, शमी 4-0-25-2, दुबे 3-0-32-0, कुलदीप 4-0-45-2, वाशिंगटन सुंदर 1-0-5-0

कुलदीप की वापसी

भारतीय अंतिम एकादश से नजर अंदाज किए जा रहे वाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को अंतिम एकादश में मौका मिला। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज के शुरुआत दोनों मैचों में कुलदीप को अंतिम एकादश में शामिल नही किया गया था, लेकिन तीसरे मैच में उन्हें शामिल किया गया। उन्हें युजवेंद्रा सिंह चहल के स्थान पर शामिल किया। इसके अलावा रवींद्र जडेजा की जगह तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी को जगह मिली। वेस्टइंडीज के कप्तान पोलार्ड ने दूसरे मैच की टीम को वानखेड़े में खिलाने का फैसला किया। कुलदीप ने अपना पिछला टी-20 मैच इस साल फरवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में खेला था, जहां कीवी टीम चार रन से जीती थी। टीम इंडिया भले ही वह मैच हार गई, लेकिन कुलदीप ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे। उन्होंने अपने कोटे के चार ओवर में 26 रन देकर दो विकेट लिए थे।

1000 रन टी-20 अंतरराष्ट्रीय में घरेलू सरजमीं पर पूरे करने वाले विराट कोहली (1064) पहले भारतीय बल्लेबाज बने। उनसे पहले न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल (1430) व कोलिन मुनरो (1000) ऐसा कर चुके हैं

बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे चोटिल लुइस

नई दिल्ली: वेस्टइंडीज के ओपनर इविन लुइस को तीसरे टी-20 मैच में घुटने में चोट लगने पर स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। 12वें ओवर में बाउंड्री पर फील्डिंग करते समय लुइस बायीं ओर भागते हुए घुटने के बल गिरे। लुइस को स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनके दायें घुटने में चोट है जिससे वह दौड़ नहीं सकेंगे। उनकी जगह कीमो पॉल ने फील्डिंग की थी। लुइस बल्लेबाजी करने भी नहीं उतर पाए और ब्रेंडन किंग ने लेंडल सिमंस के साथ पारी का आगाज किया।

सुमित का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव होने से राष्ट्रीय कोच हैरान

नई दिल्ली, प्रेट्र: एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता सुमित सांगवान के डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने से राष्ट्रीय कोच सीए कटप्पा सहित भारतीय मुक्केबाजी जगत हैरान है।

अक्टूबर में 26 वर्षीय सांगवान 91 किग्रा वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन बने और जब यह खबर आई कि वह ड्यूरेटिक एसेटाजोलामाइड के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं तब वह अपने पसंदीदा 81 किग्रा वर्ग में वापसी की तैयारी कर रहे थे। नेपाल में हाल में संपन्न दक्षिण एशियाई खेलों से लौटे कटप्पा ने कहा, 'उसने हाल में राष्ट्रीय खिताब जीता। 81 किग्रा में आने के लिए वह सही राह पर था, अब यह हो गया। मैं हैरान हूं, उसका रिकॉर्ड पाक साफ रहा है और मैं मानता हूं कि यह गलती से हुआ है। वह काफी दुर्भाग्यशाली है। 2017 में एशियाई चैंपियनशिप का रजत पदक जीतने के बाद वह चोटिल हो गया जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ी। वह एक बार फिर लय में आया और मुझे बताया गया कि एक गलती के कारण अब यह हो गया।'

भारतीय मुक्केबाजी के हाई परफॉर्मेंस निदेशक सैंटियागो नीवा ने बताया है कि सांगवान पटियाला में राष्ट्रीय शिविर छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा, 'इस मुद्दे से निपटने के लिए उसने छुट्टी ली है। यह स्तब्ध करने वाला है।' लंदन ओलंपिक 2012 में हिस्सा लेने वाले सांगवान की प्रतिकूल रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के एक अधिकारी ने कहा कि इस मुक्केबाज से प्रतिक्रिया नहीं मिली है कि वह 'बी' नमूने का परीक्षण कराना चाहता है या नहीं। अधिकारी ने कहा, 'हमें उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। वह संपर्क नहीं कर रहा है इसलिए हमें नहीं पता कि उसका अगला कदम क्या होगा।' पिछले एक सप्ताह में भारतीय मुक्केबाजी को डोपिंग का यह दूसरा झटका लगा है। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता महिला मुक्केबाज नीरज फोगाट को एनाबोलिक स्टेरायड के लिए पॉजिटिव पाया गया था। 24 वर्षीय नीरज 2020 टोक्यो ओलंपिक की प्रमुख संभावित खिलाड़ियों में शामिल थीं और उन्हें टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में जगह मिली थी। डोप परीक्षण में विफल रहने के बाद उन्हें इस सूची से हटा दिया गया था। कटप्पा ने कहा, 'भारतीय मुक्केबाजी में एलीट मुक्केबाजों का डोप परीक्षण में विफल रहना बेहद असमान्य है। हम इससे स्तब्ध हैं।'

झटका

- राष्ट्रीय पुरुष टीम के कोच ने कहा, सांगवान ने अनजाने में हुई गलती
- भारतीय मुक्केबाज से नहीं हो पा रहा संपर्क

बड़ौदा के खिलाफ 179 गेंदों पर 202 रन बनाए, मुंबई ने दिया 534 रन का लक्ष्य

प्रतिबंध से लौटे पृथ्वी ने जड़ा दोहरा शतक

वडोदरा, प्रेट्र: अपने वादे पर खरा उतरते हुए पृथ्वी शॉ ने बुधवार को अपने 2.0 अवतार की झलक दिखाई और बड़ौदा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में मुंबई के लिए दोहरा शतक लगाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वापसी का मार्ग प्रशस्त किया। आठ महीने के डोपिंग प्रतिबंध के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने वाले पृथ्वी ने रिलायंस स्टेडियम में ग्रुप-बी के मुकाबले में 179 गेंदों पर 202 रन बनाकर मुंबई की जीत की राह तैयार की।

पृथ्वी ने हाल में आश्वासन दिया था कि अब पृथ्वी शॉ 2.0 देखने को मिलेगा और उन्होंने 19 चौकों और सात छक्कों के साथ इसे साबित भी कर दिखाया।

पहली पारी में 431 रन बनाने वाली मुंबई ने बड़ौदा को 307 रन पर समेटते हुए पहली पारी की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। बड़ौदा की टीम एक दिन पहले के अपने स्कोर में सिर्फ छह रन जोड़ सकी। बड़ौदा की ओर से सलामी बल्लेबाज केदार देवधर ने नाबाद 160 रन की पारी खेली। इसके बाद पृथ्वी के दोहरे शतक और कप्तान सूर्यकुमार यादव की नाबाद 102 रन की पारी की बदौलत मुंबई ने चार विकेट पर 409 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित की, जिससे बड़ौदा को जीत के लिए 534 रन का विशाल लक्ष्य मिला। मुंबई की दूसरी पारी पृथ्वी के इर्द-गिर्द घूमती रही, जो निलंबन से लौटने के बाद अपना पहला प्रथम श्रेणी मैच खेल रहे थे और उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया।

पृथ्वी ने बड़ौदा के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, जिसके बाद वह टेस्ट में तीसरे सलामी बल्लेबाज के दावेदारों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, वह न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत-ए टीम में शामिल होंगे। उन्होंने 84 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसे बाद में दोहरे शतक में बदला। पृथ्वी और जय बिस्टा (68) ने पहले विकेट के लिए 190 रन की साझेदारी की। हालांकि, बड़ौदा ने बिष्टा, तीसरे नंबर पर खेलने आए शुभम रंजने (02) और टेस्ट विशेषज्ञ अजिंक्य रहाणे (09) के जल्द विकेट हासिल किए। उन्हें सूर्यकुमार के रूप में एक अच्छा साथी मिला, जिन्होंने 70 गेंदों पर 12 चौकों और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 102 रन बनाए। बड़ौदा को जीत के लिए 534 रन की का लक्ष्य मिला है, लेकिन तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उसने 74 रन पर ही तीन विकेट गंवा दिए। मुंबई के बायें हाथ के स्पिनर शम्स मुलानी ने दो विकेट झटके।

उप्र को 326 रन की जरूरत

मेरठ, जागरण संवाददाता: उत्तर प्रदेश को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप-बी मैच में रेलवे के खिलाफ जीत के लिए 326 रनों की जरूरत है। रेलवे के पहली पारी में 253 रनों के जवाब में उत्तर प्रदेश की पहली पारी 175 रनों पर सिमटी थी। रेलवे ने दूसरी पारी में 270 रन बनाए और उत्तर प्रदेश को जीत के लिए 349 रनों का लक्ष्य मिला। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक उप्र ने 4.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए थे। दिन का खेल खत्म होने के समय ओपनर अल्मास शौकत (नाबाद 10) और आर्यन जुयाल (नाबाद 13) क्रीज पर थे। दूसरे दिन रेलवे ने पांच विकेट पर 58 रनों से आगे पारी बढ़ाई। दिनेश मोर (102) ने शतकीय पारी खेली। अमित मिश्रा (नाबाद 43) ने भी उपयोगी योगदान दिया।

पृथ्वी शॉ ● फाइल फोटो, ट्विटर

हरियाणा के खिलाफ मुश्किल में महाराष्ट्र

रोहतक, जागरण संवाददाता: महाराष्ट्र पर रणजी ट्रॉफी के ग्रुप-सी के मुकाबले में हरियाणा के खिलाफ पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है। लाहली के चौधरी बंसीलाल स्टेडियम में मैच के तीसरे दिन हरियाणा के 401 रन के जवाब में महाराष्ट्र की टीम फॉलोऑन नहीं बचा सकी और 247 रन बनाकर आउट हो गई। फॉलोऑन खेलते हुए 61 के कुल स्कोर तक महाराष्ट्र की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब उसे पारी से हार बचाने के लिए 93 से अधिक रन बनाने होंगे। फॉलोऑन खेलते हुए महाराष्ट्र के बल्लेबाजों पर हरियाणा के गेंदबाज कहर बनकर टूटे। दूसरी पारी के पहले ओवर में ही हर्षल पटेल ने एसएम गुगाले और सीजी खुराना को पवेलियन भेजा।

चोटिल धवन की जगह मयंक भारतीय वनडे टीम में शामिल

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की आगामी वनडे अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए चोटिल शिखर धवन के विकल्प के तौर पर बुधवार को भारतीय टीम में शामिल किया गया। धवन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान सूरत में महाराष्ट्र के खिलाफ खेलते हुए बायें घुटने में गहरा कट लग गया था, जिससे वह अब तक नहीं उबर पाए हैं। वह वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से भी बाहर हो गए थे।

बीसीसीआइ ने कहा, 'बीसीसीआइ की मेडिकल टीम का मानना है कि धवन के टांके कट गए हैं और उनका घाव भी भर रहा है, लेकिन पूर्ण मैच फिटनेस हासिल करने से पहले उन्हें कुछ और समय की जरूरत है। अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए भारतीय टीम में चोटिल शिखर धवन के विकल्प के तौर पर मयंक अग्रवाल को शामिल किया है।' वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत इसी महीने तीन वनडे मैच खेलेगा। अभी डिंडिगुल में तमिलनाडु के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे कर्नाटक के मयंक चेन्नई में पहले मैच से पूर्व भारतीय टीम से जुड़ेंगे। भारतीय टीम में फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल भी हैं, जिन्हें उप कप्तान रोहित शर्मा के साथ वनडे मैचों में पारी का आगाज करने का मौका मिल सकता है। मयंक को इंग्लैंड में वनडे विश्व कप के दौरान चोटिल विजय शंकर के विकल्प के तौर पर भारतीय टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। मयंक टेस्ट क्रिकेट में नौ मैचों में तीन शतक और इतने ही अर्धशतक की मदद से 67 से अधिक की औसत से 872 रन बना चुके हैं।

बदलाव

- भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलनी है सीरीज
- चोट से पूरी तरह से नहीं उबर पाए हैं शिखर

भारत-वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का कार्यक्रम

तारीख	मैच	स्थान
15 दिसंबर	पहला वनडे	चेन्नई
18 दिसंबर	दूसरा वनडे	विशाखापत्तनम
22 दिसंबर	तीसरा वनडे	कटक

टीम: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, रिषभ पंत, शिवम दुबे, केदार जाधव, रवींद्र जडेजा, युजवेंद्रा सिंह चहल, कुलदीप यादव, दीपक चाहर, मुहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार।

यूएफा चैंपियंस लीग | ग्रुप-ई में लिवरपूल ने सल्जबर्ग को 2-0 से हराया, ग्रुप-एच में लिले को हराकर नॉकआउट दौर में पहुंचा चेल्सी

लिवरपूल और चेल्सी ने बनाई अंतिम-16 में जगह

पेरिस, एएफपी: गत चैंपियन लिवरपूल ने ऑस्ट्रियन फुटबॉल क्लब सल्जबर्ग को हराकर यूएफा चैंपियंस लीग के अंतिम-16 में जगह बनाई, जबकि चेल्सी ने भी नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। हालांकि, अजाक्स और इंटर मिलान जैसे दिग्गज क्लबों को ग्रुप चरण से ही बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ा। ग्रुप-ई में मंगलवार को ऑस्ट्रिया में जुर्जेन क्लोप की लिवरपूल टीम को नॉकआउट में पहुंचने के लिए अपने ग्रुप चरण के अंतिम मुकाबले में ड्रॉ की जरूरत थी। उसने दूसरे हाफ में नाबी कीता (57वें मिनट) और मुहम्मद सलाह (58वें मिनट) के गोल की बदौलत 2-0 की जीत दर्ज की और ग्रुप-ई से विजेता के तौर पर अंतिम-16 में प्रवेश किया। सलाह को इस मुकाबले में गोल करने के कई मौके मिले, लेकिन शुरुआत में वह उन मौकों पर भुना नहीं पाए।

नापोली जीता, लेकिन मैनेजर नपे: वहीं, नापोली ने रेसिंग जेंक को 4-0 से हराकर दूसरे स्थान पर रहते हुए इस ग्रुप से नॉकआउट में जगह बनाई। नापोली की ओर से अर्कांडियस मिलिक ने हैट्रिक जमाई, जबकि ड्राइस मर्टेंस ने भी एक गोल करके अपनी टीम को नॉकआउट चरण में पहुंचने में अहम भूमिका निभाई। इटालियन क्लब नापोली ने जीत के बावजूद अपने मैनेजर कार्लो एंसेलोटी को हटाने का फैसला किया है। सल्जबर्ग इस हार के कारण ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहा जिसकी वजह से यूरोपा लीग के नॉकआउट चरण में खेलने का मौका मिलेगा। उधर, ग्रुप-जी में भी नाटकीय खेल देखने को मिला, जहां मंगलवार को ल्योन ने दो गोल से पिछड़ने के बाद आरबी लीप्जिग को 2-2 की बराबरी पर रोककर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। वहीं, सेंट पीटर्सबर्ग को 3-0 से हराने के बावजूद बेनफिका अंतिम-16 में नहीं पहुंच पाई। ग्रुप-जी में लीप्जिग शीर्ष पर रहते हुए अगले दौर में पहुंचा।

ग्रुप-एच का रोमांच: ग्रुप-एच में मंगलवार को खेले गए मुकाबले खासे रोमांचक रहे। वेलेंसिया ने पिछले सत्र में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली अजाक्स की टीम को एम्सटरडम में 1-0 से हराकर इस ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करके अंतिम-16 में जगह बनाई। स्पेनिश क्लब वेलेंसिया की ओर से इकलौता गोल रॉड्रिगो मोरेनो ने किया। वहीं, फ्रैंक लैंपार्ड की चेल्सी टीम ने लिले को 2-1 से हराकर ग्रुप-एच से दूसरी टीम के तौर पर नॉकआउट में जगह बनाई। चेल्सी की ओर से टैमी अब्राहम और सीजर एजपिलिक्यूटा ने पहले हाफ में गोल दागे। चेल्सी ने पूरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया।

चैंपियंस लीग में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने फाती

ग्रुप-एफ में बार्सिलोना ने इंटर मिलान को 2-1 से हरा दिया जहां अंशु पाती चैंपियंस लीग में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। इस मुकाबले से बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी को आराम दिया गया था, लेकिन उनकी कमी टीम ने ज्यादा महसूस नहीं होने दी। कार्लोस पेरेज (23वें मिनट) ने बार्सिलोना को शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन रोमेलू लुकाकू (44वें मिनट) ने गोल करके इंटर को बराबरी दिलाई। इसी बीच इंटर को गोल करने के कई मौके मिले और उनकी टीम ने कई गोल भी किए, लेकिन ऑफ साइड होने की वजह से उन्हें अयोग्य करार दिया गया। उधर, निर्धारित समय से चार मिनट पहले अंशु फाती ने लुइस सुआरेज के क्रॉस पर गोल करके बार्सिलोना को बढ़त दिलाई, जो अंत में निर्णायक साबित हुई। 17 साल 40 दिन की आयु में फाती चैंपियंस लीग में गोल करके वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 1997 में घाना के पीटर ओफरी क्यू द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा। ग्रुप-एफ में ही बोरुसिया डोर्टमंड ने स्लाविया पराग को 2-1 से हराकर दूसरी टीम के तौर पर इस ग्रुप से नॉकआउट में जगह बनाई।

चैंपियंस लीग में इंटर मिलान के खिलाफ गोल करने के बाद जश्न मनाते बार्सिलोना के अंशु फाती ● रायटर

13 अंक लेकर ग्रुप-ई में लिवरपूल शीर्ष पर रहा जहां उसने अपने खेले छह मुकाबलों में से चार जीते, एक हारा और एक ड्रॉ खेला

11-11 अंक ग्रुप-एच में वेलेंसिया और चेल्सी ने हासिल किए, लेकिन हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में बेहतर स्थिति की वजह से वेलेंसिया ने ग्रुप में पहला स्थान हासिल किया

यूएफा चैंपियंस लीग में सल्जबर्ग के खिलाफ पेरिस में मुकाबले के दौरान लिवरपूल के स्टार स्ट्राइकर मुहम्मद सलाह। उन्होंने इस मैच में शानदार गोल किया है। ● एएफपी

यामागुची से हारीं सिंधू

ग्वांग्जू प्रेट्र: खराब फॉर्म से जूझ रही गत चैंपियन भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधू सत्र के आखिरी बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर बैडमिंटन फाइनल्स के पहले ही मैच में जापान की अकाने यामागुची से हार गई।

सिंधू ने दूसरे गेम में 11-6 की बढ़त बनाने के बावजूद मुकाबला 21-18, 18-21, 8-21 से गंवा दिया। यह मैच 68 मिनट तक चला। दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी यामागुची की यह सिंधू पर लगातार तीसरी जीत है। सिंधू का इससे पहले यामागुची के खिलाफ 10-6 का रिकॉर्ड था, लेकिन वह पिछले दो मैच उससे हार चुकी थी। अब सिंधू का सामना ग्रुप ए के दूसरे मैच में चीन की चेन यू फेइ से होगा। उसके खिलाफ सिंधू का रिकॉर्ड 6-3 का है, लेकिन इस साल चेन ने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप समेत सभी छह फाइनल जीते हैं। सिंधू पहले हाफ में काफी संतुलित खेल रही थी, लेकिन यामागुची ने उसे जल्दी ही दबाव में ला दिया। इसके बाद सिंधू ने कई गलतियां की। एक समय स्कोर 7-7 था और सिंधू ने बाद में छह अंक की बढ़त बना ली, लेकिन यामागुची ने स्कोर 18-20 कर दिया। सिंधू ने क्रॉस कोर्ट रिटर्न पर पहला गेम जीत लिया। दूसरे गेम में भी दोनों ने लंबी रेलियां लगाई। सिंधू के पास एक समय 11-6 की बढ़त थी। ब्रेक के बाद यामागुची ने आक्रमक खेल दिखाते हुए स्कोर 15-15 कर लिया। इसके बाद से यामागुची ने उसे वापसी का मौका नहीं दिया।

तीसरे गेम में भी वह इस लय को कायम रखने में कामयाब रही। सिंधू की सहज गलतियों का पूरा फायदा उठाकर उसने गेम और मैच जीत लिया।

असगर फिर बने अफगानिस्तान की टीम के कप्तान

काबुल, प्रेट्र : अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने पूर्व कप्तान असगर अफगान को सभी प्रारूपों में फिर कप्तान बनाया है। एसीबी के अधिकारियों ने यह फैसला लिया। सात महीने पहले ही असगर से सभी प्रारूपों में कप्तानी छीन ली गई थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें फिर से कमान सौंपी गई। इससे पहले एसीबी ने रहमान, गुलबदीन व राशिद को क्रमश : टेस्ट, वनडे व टी-20 टीम का कप्तान चुना था।

मैं घरेलू मैचों में ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के खिलाफ खेलना पसंद करूंगा।
– सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी

पहला टेस्ट ▶ 10 साल में पहली बार पाकिस्तान कर रहा है टेस्ट मैच की मेजबानी

अच्छी शुरुआत के बाद श्रीलंकाई टीम लड़खड़ाई

पाकिस्तान की टीम ने मेहमान टीम के 202 रन पर पांच विकेट झटके

रावलपिंडी, प्रेट्र : 10 साल के लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान की धरती पर टेस्ट क्रिकेट की वापसी हुई। मेजबान के लिए यह खेल से ज्यादा खुद को सुरक्षित साबित करने का टेस्ट है। इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसकों के साथ पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर स्टेडियम में मौजूद थे। हालांकि, खराब रोशनी के चलते पहले दिन का खेल समय से पहले रोकना पड़ा। पहले दिन के खेल में मेजबान पाकिस्तान का दबदबा रहा और उसने 68.1 ओवर के खेल में मेहमान श्रीलंकाई टीम के 202 रन पर ही पांच विकेट झटक डाले। दिन का खेल खत्म होने के समय धनंजय डिसिल्वा (नाबाद 38) और विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला (नाबाद 11) क्रीज पर मौजूद थे।

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। पाकिस्तानी टीम चार तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरी। मगर सुबह के सत्र में मिलने वाली मदद का मेजबान तेज गेंदबाज फायदा नहीं उठा सके और श्रीलंकाई ओपनरों कप्तान दिमुथ करुणारत्ने (59) और ओशाडा फर्नांडो (40) ने 96 रनों की साझेदारी कर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दी। इस दौरान शाहीन अफरीदी द्वारा फेंके गए 24वें ओवर की तीसरी गेंद श्रीलंकाई कप्तान करुणारत्ने के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए दूसरी स्लिप के पास से होते हुए बाउंड्री पार कर गई। इसी के साथ करुणारत्ने ने करियर का 24वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। मगर कुछ समय बाद ही अफरीदी ने करुणारत्ने को एल्बीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों ने वापसी करते हुए 31 रनों के भीतर चार विकेट चटकाते हुए अपनी टीम की मैच में वापसी कराई। नसीम शाह ने थोड़ी ही देर बाद फर्नांडो को पहली स्लिप में हैरिस सोहेल के हाथों कैच कराते हुए उन्हें भी बाहर भेज दिया। रोशनी कम हो चली थी, लेकिन मेहमान बल्लेबाज डटे रहे। आखिरकार अंपायरों ने मैच को समय से पहले रोकने का फैसला किया।

श्रीलंका	202/5 (68.1 ओवर)
दिमुथ करुणारत्ने	59 (110 गेंद, 09 चौके)
ओशाडा फर्नांडो	40 (81 गेंद, 06 चौके, 01 छक्का)
नसीम शाह	16-4-51-2

10 साल में पहली बार पाकिस्तान में पहला टेस्ट विकेट शाहीन अफरीदी ने लिया। उन्होंने श्रीलंकाई कप्तान करुणारत्ने (59) को आउट किया

02 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में पदार्पण किया। आबिद अली और उस्मान शेनवारी को यह मौका मिला

96 रन करुणारत्ने और फर्नांडो ने पहले विकेट के लिए जोड़े। पिछली बार टीम के लिए शतकीय ओपनिंग साझेदारी 2016 में करुणारत्ने और कुशल सिल्वा ने की थी

22 खिलाड़ी जो इस टेस्ट में दोनों टीमों की ओर से खेलने उतरे हैं उन सभी का यह पाकिस्तान में पहला टेस्ट मैच है

श्रीलंकाई बल्लेबाज करुणारत्ने को आउट करन के बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह। एपी

न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में कोई बदलाव नहीं

क्रिकेट डायरी

▶ दोनों टीमों के बीच आज से खेला जाएगा डे-नाइट टेस्ट मैच

पर्थ, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार से यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रहे डे-नाइट टेस्ट के लिए अपनी अंतिम एकादश मे कोई बदलाव नहीं किया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार तीसरे टेस्ट में समान अंतिम एकादश के साथ उतरेगी। कोच जस्टिन लेंगर स्थिर एकादश तैयार करने की कोशिशों में जुटे हैं और हाल में दो टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान को रौंदने के बाद उन्हें टीम में बदलाव करने का कोई कारण नजर नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने हालांकि कहा है कि मेलबर्न और सिडनी में होने वाले अगले दो टेस्ट के लिए टीम में बदलाव किया जा सकता है।

टीम इस प्रकार है : टिम पेन (कप्तान), डेविड वार्नर, जो बर्न्स, मार्नस लाबुशाने, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू वेड, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन और जोश हेजलवुड।

सिडनी में प्रदूषण वाली धुंध ने भारत की याद दिलाई : ख्वाजा

सिडनी, एएफपी : ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने कहा है कि देश के जंगलों में लगी आग के कारण शहर में हुई प्रदूषण वाली धुंध ने उन्हें भारत में खेलने की याद दिला दी। ख्वाजा से जब प्रदूषण वाली धुंध के बीच खेलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने शेफील्ड शील्ड मैच के इतर यह तुलना की। ख्वाजा ने कहा, 'बुधवार की सुबह जब हम यहां आए तो इसने मुझे भारत में खेलने की याद दिला दी। सांस लेने में मुश्किल हो रही है, यहां काफी धुआं है। मैं सिर्फ पांच ओवर मैदान पर रहा, लेकिन इससे गले में तकलीफ हो रही है। यह हैरानी भरा है कि गेंदबाज इतने लंबे समय तक गेंदबाजी कर रहे हैं। यह बुरा था, लेकिन खेलना असंभव नहीं है।' भारत के उत्तरी हिस्से में सर्दियां शुरू होने से पहले कई कारणों से प्रदूषण वाली भारी धुंध होती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ओकीफी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा स्थिति भारत से कहीं बदतर है और यह एक दिन में 80 सिगरेट पीने की तरह है।

पर्थ में रिकॉर्ड बनाने को तैयार अंपायर अलीम दार

पर्थ : पाकिस्तान के अलीम दार गुरुवार को जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने उतरेंगे तो वह वेस्टइंडीज के स्टीव बकनर को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में अंपायरिंग करने वाले अंपायर बन जाएंगे। कई वर्षों तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने के बाद अंपायरिंग में आए दार का बतौर अंपायर यह 129वां टेस्ट मैच होगा। उन्होंने 2003 में इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच ढाका में खेले गए मैच में पहली बार अंतरराष्ट्रीय टेस्ट में अंपायरिंग की थी।

हार्दिक ने कहा, हर दिन मजबूत हो रहा हूं

मुंबई, आइएएनएस : अपनी सफल सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन के दौर से गुजर रहे भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वह वापसी की राह पर हैं और दिन-प्रतिदन मजबूत होते जा रहे हैं। हार्दिक ने मंगलवार को कहा था कि न्यूजीलैंड के साथ सीरीज के बीच में उनका भारतीय टीम के साथ जुड़ने का कार्यक्रम है। इसके बाद वह आइपीएल और फिर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप पर ध्यान देंगे। हार्दिक ने कहा, 'मुझे लगा कि यह सही समय था, क्योंकि अगर मैं चार महीने का समय लेता हूं तो मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले वापसी कर पाऊंगा। यह मेरी योजना थी, ताकि मैं कुछ अंतरराष्ट्रीय मैच, आइपीएल और फिर टी-20 विश्व कप में खेल सकूं।' हार्दिक ने बुधवार को अपना एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, प्रत्येक दिन मजबूत हो रहा हूं।

मैंने रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचा था : एनी जैन

साक्षात्कार

अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश के लिए पदक जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है। वर्षों की मेहनत के बाद पोडियम पर खड़े होने का मौका नसीब होता है। मगर इंदौर की मूल निवासी और दिल्ली में पढ़ी एनी जैन के लिए पदक जीतना मानों बच्चों का खेल है। एनी 17 साल की हैं और नेपाल में आयोजित दक्षिण एशियाई खेलों की तैराकी स्पर्धा में भारत के लिए तीन स्वर्ण सहित कुल चार पदक जीते। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। छोटी सी उम्र में राष्ट्रीय स्पर्धाओं में दो दर्जन से ज्यादा पदक जीत चुकीं **एनी जैन** से **कपीश दुबे** ने खास बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश :

● जिस उम्र में बच्चे करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, आप अंतरराष्ट्रीय पदक जीत रही हैं, यह अनुभव कैसा है?

-अच्छा लगता है। मगर इसमें मेरी मेहनत के अलावा मेरी मम्मी साक्षी और पिता समीर का बहुत बड़ा समर्पण व त्याग है। उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने और अपनी पसंद का खेल चुनने के लिए प्रेरित किया।

● तैराकी को करियर के रूप में कैसे चुना?

-मुझे शुरुआत में तैराकी से लगाव नहीं था। मैं स्केटिंग की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। गर्मियों में तैराकी सीखने गई तो मन लग गया। इसके बाद तैराकी को गंभीरता से लेने लगी। मैं कुछ ही महीनों में राज्य स्पर्धाओं में और एक साल के भीतर राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लेने लगी।

● अब तक कितने पदक राष्ट्रीय स्पर्धाओं में जीत चुकी हैं?

-मैं जूनियर वर्ग की खिलाड़ी हूं, लेकिन सीनियर में भी खेलती हूं। सीनियर में कुल पांच पदक, जबकि जूनियर वर्ग में 23 पदक जीते हैं। इसके अलावा स्कूल नेशनल, सीबीएसई नेशनल और आमंत्रण टूर्नामेंट में भी दर्जनों पदक जीते हैं, लेकिन संख्या याद नहीं। मैं हर साल राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीत रही हूं। मैं अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाली मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली महिला तैराक हूं।

● नेपाल में दक्षिण एशियाई खेलों में जाते समय सोचा था कि रिकॉर्ड बनेगा?

-मैंने रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचा था। मैं भारतीय टीम में तीसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हूं। मैंने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 1.13.05 सेकेंड समय के साथ स्वर्ण जीता। यह भारतीय रिकॉर्ड है। मैंने चार गुणा 100 मीटर फ्री स्टाइल रिले और चार गुणा 200 मीटर फ्री स्टाइल रिले में भी स्वर्ण जीते। 100 मीटर फ्री स्टाइल में मुझे कांस्य मिला।

● तैराकी और पढ़ाई के बीच सामंजस्य कैसे बनाती हैं?

-मैं नौ साल से तैराकी कर रही हूं। तीन साल दिल्ली के साई सेंटर में रही और यहीं पढ़ाई की। अब तैराकी के कारण ही मेरा चयन फुकेट के यूडब्ल्यूसी इंटरनेशनल स्कूल में हुआ है। यहां सुबह पांच से 7.30 बजे तक अभ्यास करती हूं। फिर स्कूल जाती हूं जो 3.30 तक होता है और 3.45 से फिर अभ्यास शुरू होता है जो शाम 7.15 तक चलता है। इसके बाद खाना खाकर पढ़ाई करती हूं।

टी-20 क्रिकेट अफगानिस्तान की ताकत : कोच क्लूजनर

काबुल, आइएएनएस : अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच लांस क्लूजनर का मानना है कि टी-20 क्रिकेट अफगानिस्तान की ताकत है और अगले साल होने वाले विश्व कप को ध्यान में रखकर वह इसमें सुधार करना चाहते हैं। अफगानिस्तान की टीम इस समय विश्व टी-20 रैंकिंग में आठवें नंबर पर है। टीम ने हाल में लखनऊ में वेस्टइंडीज को तीन मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 से हराया है। क्लूजनर ने कहा, 'हमने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में शानदार वापसी की। टी-20 क्रिकेट अफगानिस्तान की ताकत है। बड़े स्कोर खड़े करना हमेशा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। यहां पर बेहतरीन प्रतिभा है। ये युवा और ताजा हैं, लेकिन कभी-कभी बड़े मैचों में और बड़ी टीमों के खिलाफ हमारे निर्णय सही नहीं होते हैं, जिससे हमें थोड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है।' क्लूजनर को सितंबर के आखिर में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। क्लूजनर ने फिल सिमंस का स्थान लिया था।

विविध

बिहार की 53 फीसद महिलाओं को नहीं दिखती पति की पिटाई में बुराई

श्रवण कुमार, पटना

- आद्री, इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर और जेंडर रिसोर्स सेंटर का शोधपत्र
- 25 फीसद बेटियां ब्याह के बाद नहीं ले पातीं कोई फैसला

बिहार में बेटियां पढ़ तो रही हैं, पर अधिकारों के लिए लड़ नहीं पा रहीं। सवाल चाहे आर्थिक आजादी का हो या घर चलाने का। आधी आबादी का एक चौथाई से ज्यादा हिस्सा आज भी चूल्हा-चौका को अपनी तकदीर माने बैठा है। चौंकाने वाली बात यह है कि 53 फीसद महिलाओं को कुछ परिस्थितियों में पति की पिटाई में कोई बुराई नहीं दिखती। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीटयूट (आद्री), इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर और जेंडर रिसोर्स सेंटर द्वारा हाल ही में पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञों के शोधपत्र में यह जानकारी दी गई है।

सर्वेक्षण और तथ्यों के आधार पर तैयार यह शोधपत्र स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसर पर केंद्रित है। शोधपत्रों के विश्लेषण के बाद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। राज्य में चलाई जा रही साइकिल, पोशाक, कन्या सुरक्षा जैसी सशक्तीकरण की योजनाओं से बेटियां शिक्षित तो हो रही हैं, पर ब्याह के बाद उनकी तकदीर में चूल्हा-चौका और चारदीवारी ही है। आंकड़े के अनुसार ब्याह के बाद 25 फीसद महिलाएं घर चलाने को लिए जाने वाले निर्णयों में अपनी राय भी नहीं रख पातीं। महज 33 फीसद महिलाएं ही भाग्यवान होती हैं, जिन्हें कुछ पैसे अपनी मनमर्जी से खर्च करने की आजादी होती है।

आंकड़े बताते हैं कि जन धन योजना में महिलाओं के बैंक खाते तो खूब खुले, पर मात्र 26 फीसद ही ऐसी हैं जो खातों का उपयोग मर्जी से कर पाती हैं। राज्य की पांच फीसद महिलाओं को ही माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम के तहत ऋण मिला है। बाल विवाह रोकने के लिए बिहार सरकार ने अभियान चला रखा है। बावजूद इसके जो आंकड़ा विशेषज्ञों ने बताया है, उसके अनुसार राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा संख्या में बाल विवाह बिहार में हो रहे हैं। राज्य में सौ शादियों में से 43 आज भी बचपन में हो रही हैं। जबकि राष्ट्रीय औसत 27 फीसद है।

रेलवे ने लखनऊ में तैनात रहे अफसर समेत 22 को किया जबरन सेवानिवृत्त

जागरण संवाददाता, लखनऊ : आरक्षण केंद्र से मनमाने ढंग से 30 लाख रुपये मंगवाने के मामले में पूर्वोत्तर रेलवे अधिकारी की रेलवे बोर्ड ने छुट्टी कर दी है। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है।

रेलवे बोर्ड के प्रवक्ता आरडी बाजपेई ने बताया कि चिह्नित 32 में से 22 अफसरों को जबरन सेवानिवृत्ति दे दी गई है। बोर्ड के मुताबिक इनमें अकाउंट, पर्सनल, कॉमर्शियल, इंजीनियरिंग और यांत्रिक के अफसर हैं। रेलवे प्रशासन ने जनहित व कार्यक्षमता के मद्देनजर ऐसा किया है। सूत्रों के मुताबिक 2014 में लखनऊ मंडल में तैनात रहने के दौरान उक्त अफसर ने आरक्षण केंद्र से मनमाने ढंग से तीस लाख रुपये लाने के निर्देश रेलकर्मियों को दिए थे।

इस पर रेल कर्मियों ने मना किया था। इसके बाद दो अधिकारियों ने तीस लाख रुपये लिए और उसकी रिसीविंग पीआरएस में दी लेकिन इसमें से एक अधिकारी रकम हैंडओवर करने से पहले रिसीविंग देने की जिद पर अड़ गए। इस पर आला अधिकारी ने रिसीविंग देकर रकम ले ली।

भगोड़े नित्यानंद के समर्थकों ने किया धर्मशाला पर कब्जा

विकास बागी, वाराणसी

- वाराणसी के मणिकर्णिका घाट स्थित भिखारी धर्मशाला का ताला तोड़कर दो माह से जमाया था डेरा

दुष्कर्म के आरोपी भगोड़े स्वयंभू बाबा नित्यानंद की तलाश पुलिस कर रही है। रेड कार्नर अलर्ट नोटिस जारी हो चुका है। नित्यानंद ने खुद का कैलासा नाम का एक देश बनाया है, उसी के समर्थकों ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक धर्मशाला पर कब्जा जमा लिया है।

मणिकर्णिका घाट स्थित भिखारीवाला धर्मशाला जिसे मणिकर्णिका सेवाश्रम काशी के नाम से जाना जाता है, पर बीते दो माह से नित्यानंद के समर्थकों ने कब्जा जमा रखा है। हैरत यह कि 12 वर्ष पहले ही धर्मशाला को जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया था। करोड़ों रुपये मूल्य के चार मंजिला भवन पर ताला चढ़ाकर चाबी चौक पुलिस को थमाई गई थी। बावजूद इसके आज भूतल पर तबेला और अन्य हिस्से पर नित्यानंद के लोगों का कब्जा है। खुद को नित्यानंद के आश्रम का कर्मचारी बताने वाले साधु वेशधारी समर्थक शवदाह में शामिल होने आए लोगों को भवन में आने-जाने नहीं देता। विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाता है। मणिकर्णिका सेवाश्रम काशी जिसे भिखारी धर्मशाला/बाबा धर्मशाला के नाम से भी जाना जाता था, पर अवैध कब्जे को लेकर 2007 में शिकायत हुई। शिकायत में बताया गया कि इस धर्मशाला का कोई ट्रस्टी जीवित नहीं है। देवरिया के रामअनुज, गढ़वासी टोला के साजन यादव ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट वीणा ने जांच कराई तो मामला सही पाया गया। धर्मशाला से संबंधित किसी ट्रस्टी के जीवित नहीं होने के कारण पांच जुलाई 2007 को जिला मजिस्ट्रेट ने आपत्ति मांगते हुए कहा कि कोई दावा नहीं आता तो इसे सरकारी संपत्ति घोषित किया जाएगा।

'पानीपत' के विवादित सीन हटाने को गोवारिकर तैयार

राज्य ब्यूरो, जयपुर

फिल्म 'पानीपत-द ग्रेट बिट्रेयल' में राजस्थान के भरतपुर के महाराजा सूरजमल के गलत चित्रण को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए फिल्म के निर्माता-निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने राज्य सरकार से कहा है कि वह फिल्म से विवादित सीन हटा लेंगे। गोवारिकर की यह पेशकश राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह को मंजूर नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि एक सीन हटाने से जाट समाज संतुष्ट नहीं होगा, सेंसर बोर्ड इस पूरी फिल्म को प्रतिबंधित करे।

मंगलवार को दी थी सफाई : मंगलवार को फिल्म के निर्माता और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की ओर से राजस्थान सरकार को स्पष्टीकरण भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि महाराजा सूरजमल देश के हीरो हैं। हमारी फिल्म में उनके किरदार को लेकर ऐसी कोई मंशा नहीं थी। महाराजा सूरजमल ने मराठाओं की मदद की। उन्हें राशन सामग्री सहित अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाराजा सूरजमल लंबे चौड़े थे, इसलिए हमने उनके कद को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार छह फीट लंबे एक्टर को चुना।

बुधवार को सीन हटाने को तैयार : अपनी सफाई से भी बात नहीं बनती देख गोवारिकर की ओर से बुधवार को फिर राजस्थान सरकार से कहा गया है कि प्रोडक्शन हाउस फिल्म से विवादित सीन हटाने पर सहमत है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने भी फिल्म प्रोडक्शन हाउस की इस सहमति की पुष्टि की।

राजस्थान के मंत्री विश्वेंद्र बोले, पूरी फिल्म बंद करें

फिल्म प्रोडक्शन हाउस के जवाब से जाट समाज संतुष्ट नहीं है। राजस्थान के पर्यटन मंत्री और महाराजा सूरजमल के वंशज विश्वेन्द्र सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि फिल्म 'पानीपत-द ग्रेट बिट्रेयल' में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करते हुए भरतपुर के पूर्व महाराजा सूरजमल जैसे महान पुरुष का चित्रण गलत ढंग से किया गया है। फिल्म में एक सीन बदलने से काम नहीं चलेगा। सेंसर बोर्ड से मेरा निवेदन है कि इस फिल्म को पूरे देश में तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए।

अलीगढ़ में पोस्टर और होर्डिंग फाड़े, आगजनी

जासं, अलीगढ़ : 'पानीपत' फिल्म का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। बुधवार को जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित मीनाक्षी सिनेमा में जमकर हंगामा किया। दीवार पर लगे फिल्म के पोस्टर फाड़ कर आग लगा दी। होर्डिंग भी हटवा दिए। बढ़ते विरोध के चलते संचालक ने फिल्म का प्रदर्शन बंद करा दिया। इसके बाद पदाधिकारी एसीएम द्वितीय को ज्ञापन देकर लौट गए।

जेवर एयरपोर्ट के लिए कटेंगे छह हजार पेड़, लगेंगे साठ हजार पौधे

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए छह हजार पेड़ों को काटा जाएगा। इन पेड़ों के कटने से हुई पर्यावरण की क्षति की भरपाई के लिए दस गुना पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण व उसकी देखभाल की जिम्मेदारी वन विभाग की होगी। पौधारोपण यमुना प्राधिकरण क्षेत्र व वन विभाग की जमीन पर होगा। यमुना प्राधिकरण ने वन विभाग को करीब डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत की गई है। इस जमीन पर लगे छह हजार पेड़ों को काटने की अनुमति वन विभाग ने शर्तों के साथ दी है। हालांकि पेड़ों की कटाई का काम जेवर एयरपोर्ट की डीपीआर तैयार होने पर होगा। छह हजार पेड़ों के कटने से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में दस गुना यानि साठ हजार पौधे लगाए जाएंगे। यह पौधे तीस हेक्टेयर जमीन पर लगाए जाएंगे।

यमुना प्राधिकरण ने पौधारोपण के लिए जमीन चिन्हित की है। यह पौधे प्राधिकरण के हरित क्षेत्र में लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्राधिकरण क्षेत्र में खाली पड़ी वन विभाग की जमीन पर भी पौधारोपण होगा। वन विभाग तीन साल तक पौधों की देखभाल भी करेगा।

1334 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा जेवर एयरपोर्ट।

वन विभाग ने जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिगृहीत जमीन पर लगे छह हजार पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान की है। पर्यावरण की क्षति की भरपाई के लिए दस गुना पौधे रोपे जाएंगे। इन पौधे की देखभाल की व्यवस्था भी की जाएगी।
-डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण व नियाल
प्रतीकात्मक

उत्तराखंड में हवाई पट्टियों के विस्तार को 18 करोड़ का प्रविधान

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- क्षेत्रीय संपर्क योजना के लिए अब तक तीन करोड़ का बजट
- आपदा खोज एवं बचाव कार्यों के लिए 20 लाख का बजट

प्रदेश में हवाई पट्टियों के विस्तार एवं इनके निर्माण के लिए अधिकृत भूमि का मुआवजा देने के लिए सरकार ने 18 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के लिए तीन करोड़ और आपदा, खोज, एवं बचाव कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली हवाई सेवाओं के लिए पहली बार 20 लाख का बजट रखा गया है। पूर्व में इसके लिए कोई बजट नहीं था।

प्रदेश सरकार ने हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में इन तीन योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट में व्यवस्था की है। हवाई पट्टियों के लिए अनुपूरक बजट में 13 करोड़ का प्रविधान किया गया। इससे जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। इससे पूर्व शासन ने इसके लिए पांच करोड़ की व्यवस्था की थी। इस प्रकार इस मद में अभी तक कुल 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा चुकी है। सरकार ने भारत सरकार द्वारा संचालित क्षेत्रीय संपर्क योजना के लिए प्रदेश सरकार के अंशदान के रूप में 50 लाख का प्रविधान किया है। मूल बजट में इसके लिए ढाई करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस तरह इस योजना के लिए अभी तक तीन करोड़ रुपये का प्रविधान किया जा चुका है। सरकार ने पहली बार आपदा, खोज एवं बचाव कार्यों के लिए हवाई सेवाओं के भुगतान के लिए 20 लाख रुपये स्वीकृत किए है। 2013 में आई आपदा के दौरान हवाई सेवाओं के जरिये लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया था।

मौसम विशेष

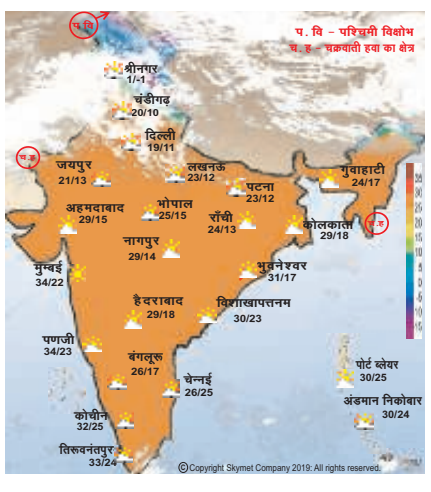

पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम तथा एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा संभव है। दिल्ली तथा उत्तरी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। इन राज्यों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल व लद्दाख में भारी हिमपात संभव है।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/22/व	अहमदाबाद	28/14/आंबा
कोलकाता	28/18/सा	बड़ौदा	30/13/सा
चेन्नई	31/24/आंबा	नागपुर	27/16/व
हैदराबाद	29/17/आंबा	इन्दौर	25/16/सा
बंगलूरू	26/18/आंबा	रांची	28/17/सा
त्रिवेन्द्रम	33/24/सा	पटना	28/18/आंबा
गुवाहाटी	24/15/व	जमशेदपुर	31/19/आंबा
गंगटोक	04/-6/आंबा	पुणे	30/17/आंबा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 12 दिसंबर 2019
आजकल
16
www.jagran.com

दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित हुई

1911 में आज ही उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में आयोजित समारोह में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की ब्रिटिश भारत के राजा और रानी के तौर पर ताजपोशी के दौरान दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था। इससे पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता थी।

चोरी हुई मोनालिसा की अद्भुत पेंटिंग बरामद हुई

1913 में आज ही दो साल तक गायब रहने के बाद मोनालिसा की पेंटिंग बरामद की गई थी। पेरिस के मशहूर लूवर संग्रहालय से चुराई गई यह पेंटिंग एक वेटर के कमरे से मिली थी और उसी वेटर ने पेंटिंग को चुराया था।

उत्तर-दक्षिण का फर्क मिटाने वाले अभिनेता हैं रजनीकांत

दक्षिण भारत में भगवान की तरह पूजे जाने वाले रजनीकांत की लोकप्रियता उत्तर भारत में भी कम नहीं है। 1950 में आज ही बेंगलुरु में पैदा हुए। असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। 1978 में तमिल फिल्म भैरवी में बतौर अभिनेता शुरुआत की। अंधा कानून से हिंदी सिनेमा में आए। रजनीकांत के सीन पर सिनेमाघरों में दर्शकों द्वारा सिक्के उछालने से परदे फटने की घटनाओं के चलते सिक्के ले जाने पर पाबंदी लगानी पड़ी। रजनीकांत हिंदी फिल्म सिनेमा के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं, जो 60 की उम्र के बाद लीड हीरो का रोल कर रहे हैं।

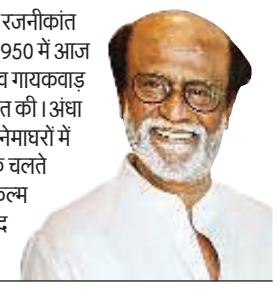

इधर-उधर की

...और भेड़ों का हुआ असामान्य व्यवहार

लंदन, एजेंसी : दक्षिण आयरलैंड की घटना है। यहां के रिंगास्किड्डी हार्बर के पास हजारों भेड़ें चर रही थीं। चरवाहों का कहना है कि हार्बर का पानी पीकर 80 हजार भेड़ें और कुछ मवेशी असामान्य व्यवहार करने लगे। दरअसल माना जा रहा है कि दुर्घटना के तहत एक जानी-मानी दवा कंपनी की हजारों किग्रा यौनवर्द्धक दवाएं उस पानी में घुल गई थीं। इस पानी को पीकर भेड़ें असामान्य यौन व्यवहार करने लगीं। शुरुआत में कंपनी ने गलती मानी कि उसकी चूक से 755 टन दवा यहां के पानी में घुल गई। बाद में कंपनी अपनी बात से मुकर गई। कंपनी ने दावा किया कि वह अपने संयंत्र के पास के पर्यावरण और समुदायों को संरक्षित रखने के प्रति प्रतिबद्ध रहती है। कंपनी पर्यावरण के आदर्श मानकों का पालन करती है और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने के लिए स्वास्थ्य और पर्यावरण विभाग से उसे लाइसेंस हासिल है।

दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने भरी उड़ान

वैंकूवर, एएफपी : दुनिया के पहले पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने मंगलवार को कनाडा के शहर वैंकूवर में उड़ान भरी। इसमें छह यात्री सवार थे। लगभग 15 मिनट तक यह विमान हवा में रहा।

खुद को उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी सीप्लेन कंपनी बताने वाली वैंकूवर स्थित हार्बर एयर और सिएटल स्थित मैग्नी एक्स ने 62 साल पुराने डीएचसी-2 दि हावीलैंड बीवर विमान में 750 हॉर्सपॉवर की इलेक्ट्रिक मोटर लगाकर इसका परीक्षण किया। विमान का परीक्षण वैंकूवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास सूर्योदय के तुरंत बाद फ्रेजर नदी पर किया गया। इस दौरान लगभग 100 लोग मौजूद थे। मैग्नी एक्स के सीईओ रोए गांजार्सकी ने कहा कि इससे साबित होता है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान काम कर सकता है। मैग्नी एक्स ने विमान क मोटर को डिजाइन किया है और हार्बर एयर के साथ मिलकर इस पर काम किया है।

गांजार्सकी ने कहा कि ई-प्लेन के कारण जहां कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा, वहीं लागत कम होगी और ईंधन की बचत होगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि यह इलेक्ट्रिक एविएशन युग की शुरुआत का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन कार्बन उत्सर्जन के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक है, क्योंकि हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो चिंता की भी बात है।

छह यात्री थे सवार, लगभग 15 मिनट तक हवा में रहा विमान

वैंकूवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास फ्रेजर नदी पर किया गया परीक्षण

कनाडा के वैंकूवर शहर में उड़ान के दौरान दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान। एपी

फिलहाल 160 किमी तक उड़ सकता है

हार्बर एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संस्थापक ग्रेग मैकडॉगल ने कहा कि आज हमने इतिहास रच दिया है। हार्बर एयर की योजना है कि उसके बेड़े में शामिल सभी 40 विमान को ई-विमान में तब्दील कर दिया जाए। गांजार्सकी ने बताया कि जिस विमान ने उड़ान भरी है, उसकी गति सीमित है और वह लीथियम बैटरी से 160 किलोमीटर तक ही उड़ान भर सकता है। विश्व की कई अन्य कंपनियां भी इस तरह के विमान पर काम कर रही हैं। इसमें बोइंग और एयरबस भी शामिल हैं।

इसरो के पीएसएलवी का अर्धशतक

उपलब्धि ▶ 50वीं उड़ान में रीसैट-2बीआर1 के साथ नौ विदेशी सेटेलाइट भी लांच

सीमाओं की निगरानी में सहायक होगा यह सेटेलाइट

श्रीहरिकोटा, प्रेट्र : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार को दोहरी उपलब्धि हासिल की। इसरो के सबसे कामकाजी कहे जाने वाले रॉकेट पोलर सेटेलाइट लांच व्हीकल (पीएसएलवी) ने एक महत्वपूर्ण रक्षा उपग्रह की लांचिंग के साथ अपनी 50वीं उड़ान पूरी कर ली है। इस दौरान पीएसएलवी ने नौ विदेशी सेटेलाइट को भी कक्षा में स्थापित किया।

पीएसएलवी ने दोपहर 3:25 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। लांचिंग के 16 मिनट बाद ही इसने रक्षा उपग्रह रीसैट-2बीआर1 को 576 किमी ऊंची कक्षा में स्थापित कर दिया। यह सेटेलाइट सीमाओं की निगरानी में विशेषरूप से मददगार होगा। रीसैट-2बीआर1 को स्थापित करने के पांच मिनट के भीतर पीएसएलवी ने नौ विदेशी सेटेलाइट को भी उनकी संबंधित कक्षाओं में पहुंचा दिया। 10 सेटेलाइट को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने के बाद इसरो प्रमुख के. सिवन और अन्य वैज्ञानिकों ने एक-दूसरे को बधाई दी। यह पीएसएलवी की 50वीं उड़ान थी और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कुल 75वीं उड़ान थी। सिवन ने पीएसएलवी की सफलता के लिए इससे जुड़ी टीम को श्रेय दिया। उन्होंने पीएसएलवी के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले डॉ. श्रीनिवासन, डॉ. माधवन नायर और अन्य सभी अग्रणी लोगों का आभार जताया। उन्होंने इस बात का भी विशेष उल्लेख किया कि डॉ. नायर ने ही पीएसएलवी को परिचालन के लायक बनाया था। सिवन ने रीसैट-2बीआर1 को तैयार करने वाली टीम की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह एक जटिल सेटेलाइट था, जिसे बहुत कम समय में तैयार किया गया। पीएसएलवी ने जिन नौ विदेशी सेटेलाइट को कक्षाओं में पहुंचाया, उनमें छह अमेरिका के और एक-एक इजरायल, इटली और जापान के हैं।

पीएसएलवी का सफर : पीएसएलवी ने सितंबर, 1993 में पहली उड़ान भरी थी। इसकी कुल 50 उड़ानों में से 48 सफल रही हैं। शुरुआत में पीएसएलवी रॉकेट की पेलोड क्षमता 860 किलोग्राम थी। इसका अर्थ है कि यह 860 किलोग्राम वजन तक के सेटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में जा सकता था। फिलहाल इसकी पेलोड क्षमता 1.9 टन हो चुकी है। अब तक यह कुल 52.7 टन के सेटेलाइट अंतरिक्ष तक पहुंचा चुका है। इनमें से 17 फीसद कस्टमर सेटेलाइट थे। संख्या के हिसाब से पीएसएलवी ने अब तक 310 विदेशी सेटेलाइट विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किए हैं। 2008 में चंद्रयान-1 की लांचिंग और हाल ही में एक साथ 104 सेटेलाइट को विभिन्न कक्षाओं में स्थापित करने जैसी कुछ विशेष उपलब्धियां पीएसएलवी के खाते में हैं।

खास है रीसैट-2बीआर1 : यह रीसैट (रडार इमेजिंग सेटेलाइट) सिरीज का चौथा सेटेलाइट है। रीसैट सिरीज के तहत इसरो ने ऐसे सेटेलाइट लांच किए हैं, जो हर मौसम में निगरानी करने में सक्षम हैं। रीसैट-2बीआर1 पूरी तरह स्वदेश निर्मित उपग्रह है, जिसे इसरो ने ही विकसित किया है। सेना के लिहाज से इसे बहुत अहम माना जा रहा है। इसकी मदद से सीमाओं की निगरानी सुदृढ़ हो सकेगी। रक्षा कार्यों के अलावा कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में भी इससे मदद मिलेगी।

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में बुधवार को रडार इमेजिंग पृथ्वी निगरानी उपग्रह रिसैट-2बीआर1 और नौ विदेशी उपग्रहों को पीएसएलवी-सी48 के साथ सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। प्रेट्र

फिल्म रिव्यू

जुमानजी-द नेक्स्ट लेवल

प्रमुख कलाकार : ड्वेन जॉनसन, केविन हार्ट, जैक ब्लैक, डैनी डेविटो, आक्वाफीना
निर्देशक : जैक कासडन
अवधि : दो घंटे तीन मिनट

हॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'जुमानजी' की खासियत है जुमानजी का वीडियो गेम। एक खास आकार के लकड़ी के बक्से को खोलने पर दोस्तों का समूह आसमान से छलांग लगाते हुए काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाता है। जंगल में विचरण करते हुए उन्हें खेल के तरीके बताए जाते हैं। उन्हें नक्शा दिया जाता है, जो उन्हें आगे बढ़ने की दिशा बताता है। सभी दोस्त खेल के पात्रों में बदल जाते हैं। सभी में कुछ खास ताकतें, कमजोरियां होती हैं। खेल को खेलते हुए ये किरदार चुनौतियों से जूझते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यही क्रम द नेक्स्ट लेवल में भी जारी है।

2017 में रिलीज जुमानजीः वेलकम टू जंगल के चार पात्र स्पेंसर, फ्रिज, बेथनी और मार्था अब कॉलेज में हैं। सब अपनी-अपनी जिंदगी में मशगूल हैं। स्पेंसर अकेला है। उसका मार्था के साथ ब्रेकअप हो चुका है। चारों छुट्टियों में एक रेस्त्रां में मिलने की योजना बनाते हैं। स्पेंसर वहां नहीं पहुंचता। तीनों दोस्त उसके घर पहुंच कर पाते हैं कि स्पेंसर लापता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि वह जुमानजी की दुनिया में चला गया है। वे उसे वापस लाने का फैसला करते हैं। इस बार स्पेंसर के दादा एडी और उनके दोस्त माइलो भी इस खेल में आ जाते हैं। द नेक्स्ट लेवल में उन्हें पिछली सीरीज की तरह हैरतअंगेज चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ना है। इस बार मिशन ज्यादा कठिन, जटिल है। सीरीज की खासियत यह है कि किरदार अपनी पसंद के अनुरूप अवतार में नहीं बदल पाते। इस बार स्पेंसर (ड्वेन जॉनसन) के बजाय उसके दादाजी एडी (जैक ब्लैक) डॉ. स्मोल्डर ब्रेवस्टोन के अवतार में आते हैं। एडी के दोस्त माइलो को मूज (केविन हार्ट) का किरदार मिल जाता है। युवा फ्रिज (सरडेरियस ब्लेंइस बार प्रोफेसर शेल्डन शैली (जैक ब्लैक) बन जाता है। इनमें सिर्फ मार्था (कैरन गिलन) अपने पुराने अवतार रूबी राउंडहाउस में लौटती है। रहस्य और रोमांच की यह दुनिया रेगिस्तान, प्राकृतिक सौंदर्य और बर्फीले पहाड़ों की सैर कराते हुए एक्शन और कॉमेडी के साथ कहानी को विस्तार देती है। इस सफर में एडी और माइलो अपने गिले शिकवे बयां करते हैं। वहीं स्पेंसर और मार्था अपने रिश्तों में आई दूरी को लेकर बात करते हैं। जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है अपनी ताकतों के दम पर नोकझोंक के साथ एक-दूसरे की हौसलाअफजाई करते हुए स्पेंसर को खोजने के बाद अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं।

ड्वेन जॉनसन, केविन हार्ट, कैरन गिलन और जैक ब्लैक चारों की जुगलबंदी लुभाती है। खेल के दौरान किरदारों की अदला-बदली अवतार कहानी में नयापन लाता है। कलाकारों को नए व्यक्तित्व में ढलते देखना रोचक लगता है। इस बार स्पेंसर की साइकोलॉजी को भी एक्सप्लोर करने का प्रयास हुआ है। ड्वेन जॉनसन हॉलीवुड एक्शन स्टार के तौर पर पहचान रखते हैं, लेकिन एडी (डैनी डेविटो) के अवतार में प्रभावित करते हैं। जियोलॉजिस्ट के तौर पर केविन हार्ट का जानवरों के बारे में बताने का तरीका उनके किरदार को नया आयाम देता है। आक्वाफीना इस सीरीज से पहली बार जुड़ी हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा जोनास के पति निक जोनास की संक्षिप्त भूमिका है। फिल्म के अंत से उसके सीक्वल का संकेत दे दिया गया है। अगर आपने पिछली सीरीज देखी है तो किरदारों के साथ आपका परिचय होगा, वरना कहीं-कहीं उन्हें समझने में दिक्कत पेश आ सकती है।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

खेल के साथ बढ़ा रोमांच

शोध अनुसंधान

टीवी देखने से बच्चों में मोटापे का सबसे ज्यादा खतरा

कम उम्र बच्चों में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों में मोटापे के लिए अक्सर रहन-सहन का तौर तरीका जिम्मेदार होता है। मोटापे का ऐसा ही एक कारण है टीवी देखना। वैज्ञानिकों ने हाल में शारीरिक गतिविधियों, सोने के समय, टीवी देखने के समय, ताजा शाकाहारी भोजन और प्रोसेस्ड फूड जैसे पांच कारकों से वजन पर पड़ने वाले असर का आकलन किया। अध्ययन में चार साल की उम्र के 1,480 बच्चों को शामिल किया गया था। वैज्ञानिकों ने पाया कि जो बच्चा टीवी देखने में जितना ज्यादा समय बिताता है, उसमें मोटापे का खतरा उतना ही ज्यादा रहता है। बैठे रहकर किए जाने वाले अन्य काम जैसे पढ़ाई, चित्रकारी या पहेलियां सुलझाने आदि से मोटापे का ऐसा खतरा नहीं दिखा। - आइएएनएस

जीन एडिटिंग से दूर हो सकती है दिमाग की जेनेटिक बीमारी

वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग के जरिये एक चूहे में डब्ल्यूएजीआर सिंड्रोम को ठीक करने में सफलता पाई है। यह सिंड्रोम दिमागी अक्षमता और मोटापे का कारण बनता है। चूहे पर प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने एपिजीनोम एडिटिंग की विशेष तकनीक का प्रयोग किया। इसमें जेनेटिक कोड को बदले बिना ही जीन के काम करने के तरीके में बदलाव किया जाता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अभी यह शोध शुरुआती स्तर पर है, लेकिन इससे यह उम्मीद बनी है कि एपिजीनोम एडिटिंग थेरेपी की मदद से दिमाग की अक्षमता से जुड़े ऐसे सिंड्रोम को सही किया जा सकता है, जो आनुवंशिक है। इस बात की पर्याप्त संभावना है कि कुछ जीन और प्रोटीन को लक्ष्य बनाते हुए दिमाग में नर्व कनेक्शन को सही स्वरूप दिया जा सकता है। एपिजीनोम एडिटिंग ऐसे जीन को सक्रिय करते हुए नर्व कनेक्शन से जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं को शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकती है। - प्रेट्र

होलोकास्ट सर्वाइवर को मिली धमकी तो समर्थन में निकला विशाल मार्च

यूरोपीय देश इटली के मिलान शहर में होलोकास्ट (यहूदी नरसंहार) सर्वाइवर (जीवित) और सीनेटर लिलियाना सेगरे के समर्थन में विशाल मार्च निकाला गया। घृणा और जातीयता विरोधी मार्च की अगुआई 89 वर्षीय लिलियाना सेगरे ने की। इसमें इटली के करीब छह सौ शहरों के मेयर और हजारों नागरिकों ने हिस्सा लिया। लिलियाना सेगरे ने नस्लीयता, जातीयता, घृणा और भेदभाव से निपटने के लिए एक संसदीय समिति के गठन का समर्थन किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाते हुए टिप्पणियों और धमकियों की बाढ़ आ गई। एक ही दिन में करीब दो सौ यहूदी विरोधी धमकियां दी गई। ऐसे में लिलियाना के समर्थन में यह रैली निकाली गई। एपी

मिस्र के व्हाइट माउंटेन में मजदूरों का बुरा हाल

यह तस्वीर मिस्र के दक्षिणी शहर मिनिया के पास स्थित 'व्हाइट माउंटेन' की है, जिसमें एक मजदूर धूल से सना नजर आ रहा है। यह माउंटेन चूना पत्थर की खदानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मामूली वेतन के लिए यहां सैकड़ों मजदूर विषम परिस्थितियों में रोज काम करने के लिए आते हैं। कार्यस्थल पर असुरक्षा महसूस करने के साथ-साथ उन्हें कई बार क्रूर परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। तस्वीरें जारी होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मजदूरों की हालत में कुछ सुधार हो सकता है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

ट्रैफिक पुलिस से मिलने पहुंचीं रानी मुखर्जी

फिल्म के प्रमोशन के लिए कलाकार तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हालांकि प्रमोशन फिल्म के विषय से ही जुड़े होते हैं। रानी मुखर्जी ने अपनी आगामी फिल्म 'मर्दानी 2' के प्रमोशन का ऐसा तरीका निकाला, जिससे उनकी फिल्म का प्रमोशन भी हो जाए और ट्रैफिक पुलिस के बारे में लोगों को जरूरी जानकारियां भी मिल सकें। फिल्म में रानी एक निर्भीक और प्रतिबद्ध पुलिस अधीक्षक शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका में हैं। फिल्म से जुड़े मुद्दे और संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए वह पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर रही हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अपराधों जैसे सामाजिक मुद्दे पर बात करने के साथ ही रानी ने इसकी रोकथाम करने वाली पुलिस की सराहना की। रानी ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस से भी मुलाकात की। रानी का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस कई अपराधों को रोकने की एक मुख्य कड़ी है। वे जितनी शिद्दत से अपना काम करते हैं, उसकी वजह से हमारा परिवार और बेटियां सुरक्षित हैं। ट्रैफिक पुलिस से मिलकर रानी ने यह जानने का प्रयास किया कि वह किस तरह से शहर में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए काम करती हैं। रानी का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस चिलचिलाती धूप और बरसात में काम करती है। हमें उनके अथक प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। साथ ही उनके काम करने के तरीकों, जिंदगी की चुनौतियों, समर्पण और बहादुरी को लोगों के सामने लाना चाहिए।

बधाइयों के लिए दिलीप कुमार ने कहा शुक्रिया

हिंदी सिनेमा के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। 11 दिसंबर को दिलीप कुमार के फैंस और इंडस्ट्री ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। दिलीप साहब ने अपने 97वें जन्मदिन पर सोशल माडिया पर अपनी तस्वीर के साथ एक पोस्ट लिखा, '97वें जन्मदिन पर मंगलवार रात से ही कॉल और मैसेजेज आ रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद। जश्न जरूरी नहीं है-आपके असीम प्यार, स्नेह और प्रार्थनाओं से मेरी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से नम हो जाती हैं।' धर्मेंद्र ने दिलीप साहब के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'अनोखा मिलन...मिलाप चंद लम्हों का... फिर...जिंदगी भर...किसी फिल्म में...मौका ना मिला...हैप्पी बर्थ डे दिलीप साहब...'

प्यार सिर्फ एहसास नहीं, उससे कहीं ज्यादा है...

'किसी दूसरे व्यक्ति को प्यार करना ईश्वर के चेहरे को देखने जैसा है।' महान फ्रांसीसी कवि और उपन्यासकार विक्टर ह्यूगो की इन पंक्तियों को अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर लिखा। बुधवार को अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों ने अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर सोशल मीडिया पर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें साझा कीं। अपनी शादी की एक तस्वीर साझा करते हुए अनुष्का ने लिखा, 'प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। यह एक मार्गदर्शक, आगे बढ़ने की ताकत और परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। सच में, इसे पाकर धन्य हूं।' विराट ने सोशल मीडिया पर अपनी और अनुष्का

की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'वास्तव में प्यार के सिवा कुछ नहीं है। और जब भगवान ने आपको किसी ऐसे शख्स से नवाजा हो जो रोज आपको इसका एहसास करवाए। फिर आपके पास सिर्फ आभार का अनुभव होता है।' विराट और अनुष्का ने 11 दिसंबर 2017 को इटली में शादी रचाई थी।

बड़ी बात

भविष्य में नौकरी के लिए कोडिंग को जरूरी मानते हैं अभिभावक, सोशल साइट पर बच्चे दे रहे हैं कोडिंग का ट्यूटोरियल

जिस उम्र में खेलते हैं बच्चे, चीन में सीख रहे कोडिंग

बीजिंग, एएफपी : तकनीक के क्षेत्र में चीन यूं ही अमेरिका से साथ ही यूरोपीय देशों और जापान को चुनौती नहीं दे रहा है। हमारे यहां छोटी उम्र में बच्चे जहां अंग्रेजी, गणित, नृत्य और संगीत का ट्यूशन लेते हैं और गेम खेलते हैं, चीन में उस उम्र के बच्चे जटिल कोडिंग सीखते हैं।

चीन के वीडियो स्ट्रीमिंग साइट बिलीबिली पर वीटा नामक बच्चे ने इस साल अगस्त में कोडिंग ट्यूटोरियल चैनल शुरू किया था। चार महीने में ही उसके 60 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं और 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उसकी साइट को देखा है। वीटा इकलौता नहीं है। चीन में उसकी तरह के बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ये है कि प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेने से पहले ही वहां बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं। इसके पीछे अभिभावकों की बड़ी भूमिका है, जो यह समझ रहे हैं कि चीन सरकार ने जिस तरह से तकनीक को बढ़ावा दे रही है, उस स्थिति में युवाओं को कोडिंग की जानकारी होनी ही चाहिए।

शंघाई में रहने वाले वीटा का कहना है कि कोडिंग आसान नहीं है, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। कम से कम उसे जितना मुश्किल माना जाता है उतना तो नहीं ही है। वीटा अपने चैनल के माध्यम से अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को भी कोडिंग के बारे में बताता है। वह कहता है कि जब वह पढ़ाता है तो उसके साथ कुछ नई बातें सीखता भी है।

चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) में भारी निवेश कर रहा है। लोगों को लग रहा है कि 20 साल बाद नौकरियों में जिनके पास कोडिंग का कौशल नहीं होगा, उनकी जगह रोबोट ले लेंगे। इसलिए लोग अपने छोटे बच्चों को कोडिंग की ट्यूशन दे रहे हैं। कोडिंग कंप्यूटिंग में एक प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्रौद्योगिकी की दुनिया को समझने में मदद करती है।

कंप्यूटर कोडिंग का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और ऐप बनाने में किया जाता है। कोडिंग के प्रति चीन का मौजूदा उत्साह उसे दुनिया में एआइ का पावर हाउस बना सकता है।

कोडिंग के जरिये प्रौद्योगिकी की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। फाइल

- प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेने से पहले ही सिखाई जा रही कोडिंग की एबीसीडी
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारी निवेश कर रहा है चीन
- लोगों का अनुमान, 20 साल बाद नौकरियों के लिए जरूरी होगा कोडिंग का कौशल
- आने वाले वर्षों में दुनिया में एआइ का पावर हाउस बन सकता है चीन

फिल्मों की रिलीज से पहले नर्वस हो जाती हैं सोनाक्षी

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा समझती हैं कि फिल्मों की सफलता या विफलता किसी एक के हाथ में नहीं होती और दर्शक ही फिल्मों का भविष्य तय करते हैं। इसके बाद भी सोनाक्षी अपनी हर नई फिल्म के रिलीज होने से पहले नर्वस हो जाती हैं। वह कहती हैं, 'आपकी जिंदगी में हर फिल्म का अलग स्थान होता है। मैं रिलीज से पहले नर्वस हो जाती हूं।' अभिनेत्री कहती हैं कि वह आज भी नए कलाकार की तरह परेशान हो जाती हैं। वह कहती हैं, 'मैंने अपने करियर में यह पहले ही समझ लिया था कि फिल्मों को लेकर ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका भविष्य हमारे हाथों में नहीं होता। आप अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कीजिए और बाकी दर्शकों पर छोड़ दीजिए।' बता दें कि सोनाक्षी ने 2010 में 'दबंग' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस पर वह कहती हैं, 'दबंग से मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्या करना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सलमान मुझे फिल्म के लिए अप्रोच करेंगे। फिल्म में काम करना मेरे लिए घर वापसी जैसा है।' सलमान खान के साथ अपने रिश्ते पर सोनाक्षी कहती हैं, 'मेरा और उनका रिश्ता को-एक्टर्स के रिश्ते से बढ़कर हो गया है। हमारा परिवार एक-दूसरे को काफी समय से जानता है और अब मैं उन्हें यादा एक दोस्त मानती हूं।'